राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 2 सोलहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का सत्रहवां दिवस संख्या: 9

शुक्रवार,
19 जुलाई 2024

**(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)**

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल के बाद। जो कुछ भी बात होगी, बाद में होगी। प्रश्न काल और जीरो आवर की व्यवस्था देने के बाद आपकी बात सुनूंगा। ...(व्यवधान)... प्रश्न काल आज तक स्थगित नहीं हुआ।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, माइक तो चालू करें।

श्री अध्यक्ष: यह ठीक करवा रहे हैं। आपने ही कल हिला-हिलाकर खराब किया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं,हिलाना नहीं पड़े,ऐसी व्यवस्था रखें आप।

श्री अध्यक्ष: तो करवा रहे हैं। श्री जुबेर खान।

राजकीय महाविद्यालय, रामगढ (अलवर) के भवन का निर्माण

127. श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में राजकीय महाविद्यालय,रामगढ़ (अलवर) के भवन हेतु रामगढ़ नगरपालिका क्षेत्र (ग्राम खेड़ी) में सरकार द्वारा नियमानुसार भूमि का आवण्टन किया गया था? यदि हां तो कितनी भूमि व कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवण्टित भूमि का नामान्तरण/जमाबन्दी इत्यादि राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ के नाम दर्ज हो चुकी है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय के भवन के निर्माण हेतु रुपये 8 करोड़ भी स्वीकृत हो चुके हैं? यदि हां तो स्वीकृति दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त महाविद्यालय के भवन का निर्माण कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा?

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): (1) जी हां। पूर्व में राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ (अलवर) के भवन हेतु जिला कलक्टर अलवर द्वारा दिनांक 21.09.2021 को रामगढ़ नगरपालिका क्षेत्र (ग्राम पंचायत खेड़ी) में 2 हैक्टेयर भूमि का आवण्टन किया गया, जिसके आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न पर है।

(2) जी हां। उक्त आवण्टित भूमि का नामान्तरण/जमाबन्दी इत्यादि राजकीय महाविद्यालय, रामगढ के नाम दर्ज हो चुकी है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्त महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत राशि 551.29 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गयी है।

(4) राजकीय महाविद्यालय, रमगढ़ (अलवर) का भवन निर्माण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन वाद संख्या एस.बी. सिविल रिट पिटीशन 14560/2021 दयाचंद पुत्र श्री भूरसिंह माली बनाम जिला कलक्टर, अलवर में दिये गये स्थगन आदेश के कारण प्रारम्भ नहीं हो पाया। न्यायिक निर्णय उपरान्त भवन निर्माण हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, चूंकि मंत्री जी ने उच्च न्यायालय का हवाला दिया, मैं उस मामले में तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा लेकिन, मंत्री जी, 2021 के बाद 2024 के आज तक इसकी तारीख नहीं पड़ी, स्टे वेकेट कराने की बहस नहीं हुई। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी वकील, चाहे सरकारी हों, चाहे कलक्टर ने किये हों, कलक्टर इसका ऑफिस इंचार्ज है, तहसीलदार को डैप्यूट किया हुआ है और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछली सरकार के टाइम में वकीलों और अधिकारियों ने मिलकर इस काम को नहीं होने दिया। मेरा आपसे निवेदन है, 40 करोड़ की जमीन है, लड़के-लड़कियों का हॉस्टल है, पैसा मंजूर हुआ पड़ा है, एक आदमी, जिसे बेदखल करके सरकार ने अलॉट किया, वह आज बैठा है।

मेरा आपसे निवेदन है, जल्दी से जल्दी, बढ़िया से, डबल एजी या किसी को नियुक्त करके इसका निस्तारण कराइये। उस महाविद्यालय का जो प्रिंसिपल है, आप उसे पाबन्द कीजिये कि जितना कब्जा है, उसके अलावा कब्जा नहीं हो, क्योंकि जमीन सूनी पड़ी है, प्रिंसिपल को कोई परवाह नहीं है, तहसीलदार को कोई परवाह नहीं है, अगर उस पर अतिक्रमण हो जायेगा तो क्या होगा? मेरा आपसे निवेदन है, वहां के बच्चे-बच्चियों के लिए आप इसे जल्दी से जल्दी निस्तारित कराएं।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है, वह निश्चित रूप से वाजिब है। इसमें 09.09.2024 को तारीख है, लेकिन वर्तमान में उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर महोदय विधि प्रकोष्ठ, अलवर के पत्रांक विधि 2024 30/38/56 दिनांक 20.06.2024 की पालना में पूर्व में नियुक्त राजकीय अतिरिक्त महाधिवक्ता महोदय श्री विज्ञान शाह जी से मूल पत्रावली प्राप्त करके नवनियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता

महोदय श्री जी.एस. गिल जी को दिनांक 01.07.2024 को मूल पत्रावली व वकालतनामा सुपुर्द कर प्रभावी प्रतिरक्षण हेतु आदेशित किया गया है। अतः जल्द ही हम हमारे डबल एजी को कहकर सकारात्मक कार्रवाई करवाएंगे।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री बाबूसिंह राठौड़।

ई.आर.सी.पी. की तर्ज पर पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना बनाने की कार्ययोजना

128. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) की घोषणा की गयी थी? यदि हां तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की तर्ज पर पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना (WRCP) लाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): (1) जी हां। वर्ष 2016-17 में, तत्पश्चात राजस्थान सरकार द्वारा बजट भाषण वर्ष 2017-18, 2018-19, 2021-22, 2022-23, 2023-24 व 2024-25 (अन्तरिम बजट) में ईआरसीपी से सम्बन्धित घोषणाएं की गईं।

(2) वर्ष 2023 की बजट घोषणा दिनांक 10.02.2023 संख्या 173.X परिशिष्ट-अ पर संलग्न है, जिसके क्रम में माही नदी को लूणी नदी से जोड़ने हेतु पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना की डीपीआर बनाये जाने हेतु मैसर्स वेपकॉस लिमिटेड को परियोजना की फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के कार्यादेश किये गये। मैसर्स वेपकॉस लिमिटेड द्वारा इसकी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है,जिसका तकनीकी आंकलन कराया जा रहा है।

वर्तमान में परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 में बरसात एवं बाढ़ का पानी व्यर्थ बहकर चला जाता है, इसके सदुपयोग हेतु दीर्घगामी योजना बनाकर Runoff Water Grid स्थापित करने एवं Rajasthan Irrigation Water Grid Mission आरम्भ किया जाकर राज्य के समस्त जिलों में सिंचाई व्यवस्था के साथ जल संचय किये जाने हेतु कार्य किये जाने प्रस्तावित किये गये हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि हमने यह प्रश्न किया कि ईआरसीपी की तर्ज पर डब्ल्यूआरसीपी की कार्ययोजना का विचार रखते हैं क्या, तो आपने जवाब दिया कि जो बरसात का पानी है, बाढ़ का जो पानी व्यर्थ बहकर जाता है, उसकी योजना बनायी जायेगी। अब राजस्थान में कहां बरसात है और कहां बाढ़ है?

मंत्री महोदय, मेरा आपसे प्रश्न यह है कि 1966 में जो गुजरात और राजस्थान के माही जल बंटवारे का समझौता हुआ, उसका एमओयू करके लूणी नदी को जोड़ने का जवाई बांध का पुनर्भरण करके जवाई से जोधपुर नहर आती है, उसके माध्यम से जोधपुर पानी लाने का, इन्दिरा सिंचाई नहर से पानी लाने का और यमुना लिंक का, नर्मदा लिंक का पानी लाकर

मारवाड़ में सिंचाई और पेयजल हेतु डब्ल्यूआरसीपी की योजना बनाने का विचार रखते हैं? यदि हां, तो कैसे? स्पष्ट करें।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, शेरगढ़ से आने वाले माननीय विधायक महोदय को बताना चाहता हूं, जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया, वर्ष 2023 की बजट घोषणा दिनांक 10.02.2023 की संख्या 173.X के अनुसार माही नदी को लूणी नदी से जोड़ने हेतु पश्चिमी राजस्थान नहर परियोना की डीपीआर बनाये जाने हेतु मैसर्स वेपकॉस लिमिटेड को परियोजा की फीजिबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एलओई लेटर अधिशासी अभियन्ता, जालोर द्वारा दिनांक 2908.2023 को जारी किया गया था, लेकिन इस आदेश के अन्तर्गत वेपकॉस कम्पनी माही बांध एवं कडाणा बांध पर जल उपलब्धता का अध्ययन करेगी तथा उपलब्ध जल को इकट्ठा करने के लिए सम्भावनाओं पर अध्ययन करेगी एवं सम्भावित विकल्पों पर सुझाव देगी। डीपीआर की प्रारम्भिक रिपोर्ट आ गयी है। हम इसका अध्ययन करके इसकी विस्तृत डीपीआर बनाएंगे।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस 1966 के जल समझौते को कितना समय हो गया, उसमें आप एमओयू करके पानी नहीं ला रहे हैं, पानी हमारे राजस्थान को मिल नहीं रहा। अब यह मारवाड़ की धरती प्यासी है। वहां के लोग आन्दोलन करेंगे, समय रहते आप हमारी डब्ल्यूआरसीपी योजना लाइये। साथ ही साथ, मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि Runoff Water Grid जोधपुर सम्भाग में कौन-कौन से क्षेत्र लाभान्वित होना प्रस्तावित हैं? समय रहते डब्ल्यूआरसीपी की योजना लाएं। मेरा यह निवेदन है।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शेरगढ़ से आने वाले माननीय विधायक महोदय को बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने वर्तमान में परिवर्तित बजट 2024-25 में बरसात एवं बाढ़ का जो पानी व्यर्थ बहकर चला जाता है, इसके सदुपयोग हेतु दीर्घगामी योजना बनाकर Runoff Water Grid स्थापित करने के लिए 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य कराये जाने की घोषणा की है। इस घोषणा में माही बेसिन व सोम नदी का मानसून अवधि का अधिशेष जल जयसमन्द बांध सहित अन्य बांधों को भरते हुए लूणी बेसिन के जवाई बांध तक लाने सम्बन्धी कार्य लाभान्वित क्षेत्र उदयपुर, सिरोही, पाली व जोधपुर में पेयजल एवं 16 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र की पुनर्स्थापना की जायेगी।

इस हेतु वर्ष 2024-25 में 20 हजार करोड़ रुपये व्यय कर परियोजना की डीपीआर तैयार करायी जायेगी। अनुमानित परियोजना की राशि 7 हजार करोड़ रुपये है। साथ ही, जोधपुर व पाली शहर को जल आपूर्ति हेतु लूणी बेसिन में स्थित जवाई बांध से जोधपुर तक चरणबद्ध रूप से तीन वर्षों में 194 किलोमीटर लम्बी क्षतिग्रस्त फीडर नहर का जीर्णोद्धार कार्य भी 2280 करोड़ से कराया जायेगा।

mkd/rtm/19.07.2024/11:10/1b

श्री अध्यक्ष: श्री रूपिन्दर सिंह।

प्रदेश में धानक व धाणका जाति के प्रमाण पत्र

129. श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में धानक (DHANAK) व धाणका (DHANAKA) जाति निवास करती है? यदि हां, तो इस जाति का जाति प्रमाण पत्र किस वर्ग में बनाए जाने का प्रावधान है? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) धानक (DHANAK) व धाणका (DHANAKA) जाति को किस आधार पर अलग-अलग वर्ग में विभाजित किया गया है? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रदेश में निवासरत धानक (DHANAK) व धाणका (DHANAKA) जाति के अलग- अलग वर्ग में जाति प्रमाण पत्र बनने से कोई विसंगति है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त विसंगति को दूर करने के क्या प्रयास किए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार धानक (DHANAK) व धाणका (DHANAKA) जाति को एक ही वर्ग अनुसूचित जनजाति में रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) जी हां। भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के लिये जारी गजट नोटिफिकेशन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 एवं हिन्दी संस्करण 1979 (परिशिष्ट अ) के अनुसार धाणका (Dhanka) को अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रम संख्या 4 में रखा गया है तथा धानक (Dhanak), धानुक (Dhanuk) एवं धानकिया (Dhankia) जातियों को अनुसूचित जाति में क्रमशः क्रम संख्या 20 व 21 पर अधिसूचित किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) भारत सरकार द्वारा धानक (DHANAK) जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा धाणका (DHANAKA) जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

भारत सरकार द्वारा विभिन्न जातियों को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग में सम्मिलित करने के मापदण्ड संबधित पत्र दिनांक 26.02.1981 परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) किसी भी जाति को अनुसूचित जाति व जनजाति में अधिसूचित किये जाने का कार्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर किया जाता है तथा भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के लिये जारी गजट नोटिफिकेशन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 एवं हिन्दी संस्करण 1979 (परिशिष्ट अ) के

अनुसार धानक (Dhanak) जाति को अनुसूचित जाति में क्रमशः क्रम संख्या 20 पर अधिसूचित किया गया है तथा उक्त गजट नोटिफिकेशन के अनुसार धाणका (Dhanka) को अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रम संख्या 4 में रखा गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): अध्यक्ष महोदय, धानका, धानक, धानुक और धानकिया राजस्थान में एक ही समाज है और एक ही जाति है। इनमें आपस में शादी भी हो रही है, रिश्ते भी हैं लेकिन मात्र शब्दों लिखावट के कारण एक भाई एससी में चला गया और एक एसटी में चला गया।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में जारी गजट नोटिफिकेशन को, जिसमें विसंगति रह गई है, उसको दूर करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया है कि किसी भी जाति को एससी या एसटी के अन्दर अगर परिवर्तित करना हो तो भारत सरकार के माध्यम से किया जाता है। इसमें जब 26.02.1981 को एक पत्र लिखा और पत्र में यह कहा गया, भारत सरकार के सचिव ने समाज कल्याण विभाग को लिखकर दिया कि आप 07.03.1981 तक, मतलब 26.02.1981 को पत्र लिखा और 07.03.1981 को रिपोर्ट मांगी कि एक फ्रेश लिस्ट भेजें, जिसमें किसी जाति को एससी, एसटी में जोड़ना या हटाना। एसटी से एससी में, एससी से एसटी में शामिल करना हो, लेकिन एससी या एसटी में किस जाति को शामिल करना है, इसके बारे में 1981 के बाद में ऐसा कोई प्रस्ताव यहां से नहीं गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय है, जिसके बारे में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि यह जो निर्णय था, इस निर्णय के अन्दर मिलिन्द कुमार व अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्रकरण में, अपने निर्णय दिनांक 28.11.2000 में जो निर्णय दिया गया, उसके बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

इसके पार्ट 3 में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 342 के खण्ड 1 के तहत जारी अधिसूचना, जो अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करती है, को केवल संसद द्वारा बनाये गये कानून द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 342 के खण्ड 1 के तहत जारी अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या किसी जनजाति के किसी भाग या समूह को केवल संसद द्वारा कानून के माध्यम से शामिल या बाहर किया जा सकता है और अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा नहीं। राज्य सरकार, न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या किसी अन्य प्राधिकारी को अनुच्छेद 342 के खण्ड 1 के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित

जनजातियों की सूची को संशोधित, परिवर्तित या बदलने का अधिकार नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक और है। सरकार की तरफ से जिला कलेक्टर की रिपोर्ट, जो आपने बताया है।

श्री अध्यक्षः बस जवाब देना है, संक्षेप में।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): एक और स्थानीय जवाब है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अखिल भारतीय धानका समाज की मांग पर राज्य सरकार द्वारा धानका, धाणका जाति के बाहुल्य वाले सात जिलों यथा- जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर, झुंझुनूं, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ के कलेक्टर को विभिन्न पत्रों एवं प्रमुख शासन सचिव महोदय के पत्रांक 31548 दिनांक 03.06.2020 द्वारा धाणका एवं धानका जाति के एक होने के सम्बन्ध में परीक्षण करवाकर दस्तावेजी साक्ष्य सहित रिपोर्ट चाही गई। परिशिष्ट 'ब' पर उक्त रिपोर्ट चार जिलों यथा- अजमेर, अलवर, जयपुर, श्रीगंगानगर विभाग से प्राप्त हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो रिपोर्ट आई है, प्राप्त रिपोर्ट में जिला कलेक्टर द्वारा केवल धानका एवं धाणका को बोलचाल की भाषा में उच्चारण अलग होना बताया है, परन्तु उक्त जिला जिलेक्टर द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य विभाग को उपलब्ध नहीं करवाये गये।

अतः बिना लिखित दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं है कि धानका एवं धाणका जाति एक है एवं बोलचाल की भाषा में केवल उच्चारण ही भिन्न है।

इस सम्बन्ध में पुनः सम्बन्धित सात जिला कलेक्टरों को निदेशक महोदय की ओर से लिखित साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु विभागीय पत्र दिनांक 10.02.2021 को लिखा गया है, रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही विभागीय परीक्षण किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न।

श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर (करणपुर): मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार प्रस्ताव बनाकर नहीं भेज सकती है?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला कलेक्टर को लिखा है। जब जिला कलेक्टर की रिपोर्ट आयेगी, उसका परीक्षण कराने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री श्रीचन्द कृपलानी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनान्तर्गत पुरुष मुखिया परिवारों का गैस कनेक्शन

130. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को रसोई गैस के कनेक्शन दिए जाते हैं?

(2) क्या सरकार विधुर, अविवाहित व अनाथ तथा बीपीएल श्रेणी के पुरुष मुखिया परिवारों को भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री सुमित गोदारा): (1) वर्तमान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के कनेक्शन ऐसी गरीब महिलाएं, जो उज्ज्वला कनेक्शन की पात्रता को पूरी करती है, को ही दिया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जारी पात्रता एवं मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कनेक्शन की पात्रता का निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा लिया जाता है।

वर्तमान में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के कनेक्शन ऐसी गरीब महिलाएं, जो उज्जवला कनेक्शन की पात्रता को पूरी करती है को ही दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब तो दे दिया है लेकिन मंत्री महोदय आप भी पुरुष हैं, पुरुषों का ध्यान पुरुष नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हम महिलाओं को तो दे ही रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय, आप प्रश्न पूछिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरह से एकल महिला, परित्यक्ता, गरीब महिलाओं को सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। क्या सरकार ठीक उसी प्रकार गरीब एकल पुरुष मुखिया को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का विचार रखती है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, निम्बोहड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न आज के समय में प्रासंगिक हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली होने लगी हैं। एकल परिवार में, जो इनका प्रश्न है, एकल पुरुष होने लग गये हैं, उनके लिए क्या सुविधा हो सकती है।

यह विषय कल सादुलपुर से आने वाले माननीय विधायक ने भी उठाया था और इसकी सभी चर्चा करते हैं पर हम केन्द्र के नियमों से बंधे हुए हैं। माननीय, आप केन्द्र में तीन बार जाकर आ चुके हैं, तो वहां पर भी प्रयास करें, कहीं न कहीं केन्द्र से आपको इस बात में लाभ मिलेगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि आप नियमों से बंधे हैं। यह उज्ज्वला योजना भारत सरकार की है। किसान सम्मान निधि योजना भी भारत सरकार की है, उसमें राज्य सरकार एक्स्ट्रा 6 हजार रुपये दे रही है या नहीं दे रही है? उसी तरह से उज्ज्वला योजना में साढ़े चार सौ रुपये भी आपने ही किया है,

राजस्थान सरकार का। क्या राजस्थान सरकार ऐसे एकल पुरुष को या जो पुरुष, महिला दोनों नहीं हैं, उनको उज्ज्वला योजना में लाभ देने का विचार रखती है क्या? स्टेट गवर्नमेंट व्यवस्था करे, यह मेरा निवेदन है। जिसने शादी नहीं की है, कुंवारे हैं, उनके लिए भी, न स्त्री है, न पुरुष हैं, लिए भी।

श्री अध्यक्षः अभी जो कुंवारे हैं, वे आगे शादी नहीं करेंगे, इस शर्त पर। माननीय मंत्री जी, कुछ कहेंगे।

श्री सुमित गोदारा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, अभी उज्ज्वला योजना में केन्द्र सरकार के नियम ही लिये जाते हैं। यदि भविष्य में इस तरह की कोई बात होगी तो यह बात हम जरूर आगे पहुंचायेंगे और आपने जो समसामयिक विषय पर बात उठायी है, उसके लिए आपको आभार भी देता हूं।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। डॉ. जसवन्त सिंह यादव।

बहरोड़ के वन क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं

131. डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड में स्थिति वन क्षेत्र में विगत दो वर्षों में कहां-कहां आगजनी की घटनाएं हुई एवं कितना नुकसान हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भविष्य में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री संजय शर्मा): (1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड में वन मण्डल अलवर में गत 2 वर्षों में आग लगने की घटनाओं का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 24 में वन क्षेत्र बर्डोद में राशि 50,000 रुपये की लागत से वन क्षेत्र में फायर लाइन बनाई गई है तथा वित्तीय वर्ष 2024 25 में 50,000 रुपये की फायर लाइन प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी पेड़ लगाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं।

श्री अध्यक्षः आप तो प्रश्न पूछिये।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): साहब, प्रश्न ही पूछ रहा हूं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है।

Bhs/Rtm/19.7.24/11.20/1c

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): इतनी मेहनत करके ये पेड़ लगाते हैं, आग लग करके वो सारा बर्बाद हो जाता है। मेरे यहां दो जगह आग लगी मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दोनों जगह गांव के लोग पहुंच गये। गांव के लोगों ने ही सूचना दी। मैं स्वयं भी पहुंच गया पर इनके कर्मचारी/अधिकारी न रेंजर पहुंचा, न कैटल गार्ड पहुंचा, न कोई और पहुंचा, तो

ऐसे लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ क्या मंत्री जी ने जांच भी करायी होगी तो ऐसे कर्मचारी/अधिकारियों के खिलाफ मंत्री जी कोई कार्यवाही करना पसन्द करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने विशेष रूप से अपने विधान सभा क्षेत्र के प्रति जो जागरूकता या चिन्ता व्यक्त की है, विशेष रूप से फोरेस्ट के क्षेत्र में आगजनी की घटना को लेकर के निश्चित रूप से यह दुखद है। जैसा आपने बताया कि यह हुआ है, ग्रामवासी वहां पहले पहुंचे और माननीय सदस्य वहां पहले पहुंच गये और फोरेस्ट के कर्मचारी/अधिकारी वहां बाद में पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से इसकी जांच करायी जायेगी। यदि कोई भी कर्मचारी/अधिकारी इसमें दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): निश्चित रूप से आगजनी की घटना घटी है मंत्री जी तक सूचना पहुंची है, विभाग तक सूचना पहुंची है, तो क्या मंत्री जी यह बता पायेंगे कि कितने पेड़ों का नुकसान हुआ, कितने पेड़ जले और कितना नुकसान हुआ फोरेस्ट में?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो घटना जिसका माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं यह घटना बर्डोद की 18.3.2023 की है और खापरिया की 22.5.2023 की है। जिन पौधों के नष्ट होने की सूचना माननीय सदस्य ने सदन में मांगी है, मैं जानकारी करके माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मनीष यादव।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत देय सहायता

132. श्री मनीष यादव (शाहपुरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:- (1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता राशि को बढ़ाकर 12000/-रुपये करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो वर्तमान में कितनी सहायता राशि दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बढ़ी हुई राशि का भुगतान वर्तमान सरकार के गठन के समय से करने एवं किसानों को शेष राशि का एक मुश्त भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री गोतम कुमार): (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता राशि को प्रति परिवार 6 हजार से बढ़ाकर 8 हजार रुपये वार्षिक करने की घोषणा की गयी है। इस क्रम में ''मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना'' के तहत प्रथम किस्त के रूप में 1000/- रुपये की राशि लाभार्थियों के सीधे ही बैंक खातों में अंतरित की गयी है।

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): आपके संकल्प पत्रानुसार प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि

योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि 12 हजार रुपये प्रति वर्ष करने की घोषणा की थी जिसमें कहीं भी चरणबद्ध रूप से बढ़ाने का उल्लेख नहीं था। किसान के प्रति, अन्नदाता के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए 12 हजार रुपये प्रति वर्ष आप कब कर देंगे?

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): शाहपुरा से आने वाले माननीय विधायक जी का प्रश्न है, मैं निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आजादी के बाद किसानों के नाम पर राजनीति तो बहुत की गई, किसानों के लिए आश्वासन भी बहुत दिये गये, नारे भी बहुत लगाये गये, सपने भी दिखाये गये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न का उत्तर दें।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): लेकिन किसानों को कभी कुछ दिया नहीं गया। आज मैं इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आजादी के बाद पहली बार अन्नदाताओं की पीड़ा को समझ करके पहली बार किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको सीधा लाभ हस्तांतरित करने का काम किया है। मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी आदरणीय भजन लाल जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने प्रधान मंत्री जी की भावना को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के किसानों को किसान सम्मान निधि का हक देने का अपना वादा पूरा किया। पिछली सरकार ने तो किसानों को यह कहा था कि हम दस दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे लेकिन पांच साल उन किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्रश्न का उत्तर दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह भाषण का विषय नहीं है। यह प्रश्न काल है, प्रश्न का उत्तर दीजिये। कौन हटा रहा है आपको मंत्री पद से? मोदी जी, भजन लाल जी-भजन लाल जी कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न का उत्तर दीजिये जो उन्होंने पूछा है।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): आपने घोषणा पत्र में 12 हजार रुपये किया है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न का उत्तर दीजिये।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): इन्होंने किसानों की भावनाओं की बात की थी मैं किसानों की भावनाओं की ही बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न का उत्तर दें।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): निश्चित रूप से हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री सम्मान निधिके लिए इस वित्तीय वर्ष में प्रथम बजट में घोषणा भी की और किसानों को साढ़े छह सौ करोड़ रुपये पैंसठ लाख किसानों को उनके खाते में सीधे देने का काम किया है और चरणबद्ध रूप से उनको 12 हजार रुपये करने का काम हमारी सरकार करेगी।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके संकल्प पत्र में चरणबद्ध रूप से कहीं नहीं लिखा हुआ। मैं यह पूछ रहा हूं कि 12 हजार रुपये आपने कहा है वार्षिक करने का वह कब तक कर देंगे? मुझे यह जवाब चाहिये, वह बताइये आप। ...(व्यवधान)...

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): संकल्प पत्र में जो भी कोई बात कही हुई है निश्चित रूप से हमारी यह सरकार करेगी।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): कब तक करेगी? किसान को गुमराह कर रहे हो आप।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): संकल्प पत्र पांच साल के लिए होता है और निश्चित रूप से उसको पूरा करके हम किसानों को राहत देने का काम करेंगे। आपके जैसे केवल चुनाव के समय घोषणा करके और वादे करके उनसे पीछे नहीं हटेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर के बाद बैठिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि गम्भीर प्रश्न है बड़ी मेजें भी थपथपाई गई हैं। जो घोषणा पत्र है उसमें यह कहा गया था कि प्रति वर्ष देंगे। प्रति वर्ष का मतलब यह है कि पांचों वर्ष देंगे। प्रति वर्ष का मतलब यह नहीं है कि आखिरी वर्ष देंगे। सबसे पहली बात तो आप प्रति वर्ष देंगे तो पहला वर्ष तो आपका निकल गया। आप नहीं दे पाये।

दूसरी बात, आपने बजट घोषणा की कि हम 2 हजार देंगे 6 हजार की जगह और 2 हजार में भी आपने एक हजार रुपये दिये। आप खैरात बांट रहे हो, दो किस्त नहीं तीन कर दी। बची हुई पांच-पांच सौ की देंगे। हो सकता है कि आगे कर दें कि हम सौ-सौ रुपये देंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, मैं तो एक ही बात जानना चाहता हूं आपका स्पेसिफिक जवाब चाहिये मुझे कि बजट घोषणा प्रति वर्ष देने की थी और पहले वर्ष आप नहीं दे पाये। कब से आप 6 हजार रुपये पूरे किसानों को देंगे? यह बताइये।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): हमारे संकल्प पत्र में जो भी कोई बात हमने कही है हम उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे और हम किसानों को जो 6 हजार का हमने वादा किया है उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रोहित बोहरा।

प्रशासन शहरों के संग अभियान में जारी पट्टे

133. श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान की तरह भूमि नियमन के प्रयोजनार्थ कोई अभियान चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत कुल कितने पट्टे जारी किये गये तथा उनसे कितना राजस्व प्राप्त हुआ?

(3) क्या सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न समाजों/संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि का आवंटन किया गया है? यदि हां, तो किस-किस समाज/संस्था को, कहां-कहां पर? क्या सरकार उक्त आवंटित भूमि को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त अभियान के तहत दिनांक 15 मार्च, 2024 से पूर्व प्राप्त आवेदनों में छूट की दर से राशि वसूल की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन (श्री झाबर सिंह खर्रा): (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रशासन शहरों के संग अभियान दिनांक 02.10.2021 से 31.03.2024 तक नगरीय विकास विभाग द्वारा कुल 640060 पट्टे जारी किये गये तथा 5219.82 करोड का राजस्व प्राप्त हुआ एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 667430 पट्टे जारी किये गये तथा 1192 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।

(3) प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किसी भी समाजों/संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि का आवंटन नहीं किया गया है।

(4) उक्त अभियान के तहत दिनांक 15 मार्च, 2024 से पूर्व प्राप्त ऐसे प्रकरण जिनमें डिमाण्ड नोट जारी होकर 31 मार्च से पहले छूट की दर से सम्पूर्ण राशि जमा है, में पट्टे रियायती दर पर जारी किये जाने के निर्देश जारी किए गए है।

अन्य लम्बित प्रकरणों का निस्तारण वर्तमान में प्रचलित नियमों/आदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा। इस संबंध में दिनांक 15.03.2024 एवं 12.07.2024 को आदेश जारी किये गये है, जिसकी प्रति परिशिष्ट ""अ"" पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मेरे दो सवाल हैं मंत्री जी से। एक तो यह प्रश्न पूछने से कम से कम पूरे राजस्थान का भला हो गया कि आपने 12.07.24 को यह ऑर्डर निकाल दिया। मेरा मूल प्रश्न यह था कि चुनाव आचार संहिता जो 15.03.2024 को लगी थी, उससे लोगों ने ऑफलाइन/ऑनलाइन आवेदन मामलों में जो सरकार छूट दे रही है उसकी कार्यवाही हुई है या नहीं, आप करोगे या नहीं? नहीं, तो इसके लिए आवेदक की क्या गलती है? आवेदक की कोई गलती नहीं है उसने तो आवेदन किया और आचार संहिता लग गई और लोक कल्याण की राज्य सरकार है आपकी। आप खुद कहते हैं यह चीज कि लोक कल्याण की सरकार है और आमजन को समानता का अधिकार है और यह समानता का अधिकार कोई आपने या हमने नहीं दिया है, यह हमारे प्रिएम्बल में है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): प्रश्न मेरा यह है कि उनकी जिनकी गलती नहीं है जिन्होंने ऑफलाइन/ऑनलाइन एप्लाई किया और आपने डिमाण्ड नोटिस नहीं दिये क्योंकि आपकी आचार संहिता लगी थी 45 दिन राजस्थान सरकार की और 45 दिन लोक सभा के चुनावों की वजह से ...

Kas/rtm/19.07.2024/11.30/1d

या तो आप 45 दिन में उनको डिमांड नोटिस दे दें, उन्होंने तो अप्लाई कर रखा है, एक प्रश्न तो यह है मेरा।

दूसरा, आपने प्रश्न के खण्ड 3 का जवाब दिया है कि 1.10.2021 से लेकर 15.3.2024 तक हमारा यह अभियान चला। कालीचरण जी ने पहले सत्र में एक प्रश्न पूछा था, जिसमें आपने कहा कि हमने 45 संस्थाओं को एक साल में प्लाट्स अलॉट किये। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने इस अवधि के बीच में किन-किन समाजों को और किस-किस नीति के थ्रू, क्योंकि इसमें नीति बनी हुई है, नियम नहीं बने हुए हैं, किस नीति के थ्रू आपने उनको अलॉटमेंट किया और किन-किन समाजों को यह अलॉटमेंट किया, उसकी सूची पटल पर दें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): यह तो धारीवाल जी से पूछ लो।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आपसे नहीं पूछ रहा हूं, आप चुप रहिए। ...(व्यवधान)... इनको चुप करा दीजिए, बीच में ज्यादा न बोलें। ज्यादा मत बोलिए बीच में।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, बैठिए, बैठिए। यह काम मेरा है। ...(व्यवधान)...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मंत्री जी सक्षम हैं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को और इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इन समाजों को जो भी भूमि आवंटित हुई है मंत्रीमंडलीय एम्पावर्ड समिति के स्तर पर उनका निस्तारण हुआ है और इनकी संख्या अलग-अलग जगह अलग-अलग है। मैं यह सूची टेबल कर दूंगा और एक प्रति माननीय सदस्य को भी प्रेषित करवा दूंगा।

नंबर दो, विधान सभा की आचार संहिता आपके समय में लगी और लोक सभा की आचार संहिता हमारे समय में लगी। 15 मार्च को लोक सभा की आचार संहिता लगी। अगर किसी का आवेदन पहले से लंबित था और किसी भी निकाय को उसने ऑनलाइन डिमांड नोट के लिये आवेदन किया कि मेरा आवेदन फला समय से लंबित है, अब तक मुझे डिमांड नोट नहीं मिला है या ऑफलाइन अगर किसी ने आवेदन किया और उसकी प्राप्ति रसीद उसके पास है, अगर इस प्रकार के कोई प्रकरण आयेंगे तो हम उन पर निश्चित रूप से सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनका निस्तारण रियायती दर पर करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं रखेंगे। ...(व्यवधान)... पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने रोक इसलिए लगाई है, हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें जितनी अनियमितताएं हुईं, उसमें अब तक 260 पट्टे निरस्त किये जा चुके हैं, 25 एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी हैं और दर्जनों शहरी निकायों से पत्र जावक रजिस्टर और सम्बन्धित पत्रावलियां गायब हैं, जिनकी हम जांच करवा कर जो भी कानूनी कार्यवाही हमको करनी है, उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... मैं आपकी एक-एक बात

का जवाब दूंगा।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आपकी नगरपालिका राजाखेड़ा में पिछले दो-तीन दिन से आपके दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी 45 लाख रुपये मजदूरी का भुगतान नहीं मिलने की वजह से हड़ताल पर हैं। डेढ़ करोड़ रुपया ठेकेदारों का बकाया है। मैं आपको एक बात और बता दूं, मुझे इस सदन में कहना तो नहीं चाहिये ...(व्यवधान)...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): यह प्रश्न नहीं पूछा मैंने आपसे। ...(व्यवधान)... यह मैंने नहीं पूछा आपसे। ...(व्यवधान)...

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): ...(व्यवधान)... हमने अभियान आगे क्यों नहीं बढ़ाया ...(व्यवधान)... कारण सदन को अवगत कराना चाहते हैं और सदन की तरफ से अगर कोई सकारात्मक सुझाव आयेगा तो हम उस भी सहानुभूति पूर्वक नहीं, पूरी गंभीरता से विचार करके उसको अमल में लाने का प्रयास करेंगे।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): एक चीज सुन लें, एक चीज सुन लें।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): मैंने कह दिया कि मैं आपकी एक-एक बात का जवाब दूंगा, एक-एक शब्द का जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपको भी अवसर मिलेगा।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): राजाखेड़ा में 31 लाख 17 हजार ...(व्यवधान)...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैंने आपसे यह प्रश्न नहीं पूछा है। राजाखेड़ा का प्रश्न नहीं पूछा है।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): ...(व्यवधान)... बैंक से निकले, रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ, ऑडिट ने पकड़ा, एफ.आई.आर. दर्ज हुई, तीन व्यक्तियों को अपराधी नामित किया गया। पहले अनुसंधान में पत्रावली दूसरे जिले स्थानांतरित हुई। उनमें से एक को बहाल कर दिया और दो के खिलाफ चालान पेश हुआ। न्यायालय ने उसको बरी कर दिया। अपील भी खारिज हो गई और यह पता नहीं चल पाया कि 31,17,172 रुपयों के कोई पंख लगे क्या, जो बैंक से निकल कर कहीं बाहर चले गये और रिकार्ड में नहीं आये, किसी की जिम्मेदारी नहीं। हम इसकी भी जांच करवा रहे हैं। ...(व्यवधान)... सुनिए अभी तो ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न आने दीजिए।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): धोलपुर में पिछले पांच वर्ष में ...(व्यवधान)...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, यह मेरा प्रश्न है क्या? ...(व्यवधान)... यह मेरा प्रश्न है क्या? प्रश्न पूछने के लिये आप क्या सदन को धमका रहे हो या हमको धमका रहे हो? आप धमकाने की कोशिश मत कीजिए, हम आपसे धमकेंगे नहीं। ...(व्यवधान)... आपका संरक्षण चाहिये, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मैंने प्रश्न क्या पूछा है

...(व्यवधान)... प्रश्न पूछने से इनको मिर्ची लग गई। What am I asking you? आप उसका जवाब दीजिए। जो प्रश्न पूछा है, उसका जवाब दीजिए। आप ऑडिट कराइए ना ...(व्यवधान)...क्या बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी। अब बोलिए, दूसरा पूरक प्रश्न पूछना है तो पूछो, नहीं तो अगला प्रश्न।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मंत्री महोदय, मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा उसका जवाब दीजिए, बातों को मत बदलिए। आप तो बातों को बदल रहे हो। आप बताइए किस नीति के थ्रू पिछली ने जमीनें अलॉट कीं? ...(व्यवधान)...यह मत दिखाइए, मैं नीति पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्षः आप बैठो, आप बैठो। माननीय मंत्री जी, इनको पूरक प्रश्न पूछने दो। प्रश्न पूछो।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैं पूछ रहा हूं किस नीति के थ्रू आपने यह जमीन अलॉट की? दूसरा, जो आप इतना लंबा भाषण ...(व्यवधान)... मेरे को लिस्ट नहीं चाहिये, मैं नीति पूछ रहा हूं, लिस्ट नहीं चाहिये।

श्री अध्यक्षः आप तो प्रश्न पूछो। माननीय मंत्री जी।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैं अपने पटल से ले लूंगा, मेरे को मत दीजिए, मैं वहां से ले लूंगा।

श्री अध्यक्षः मैं अगला प्रश्न पुकार रहा हूं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, किस नीति के थ्रू इन्होंने यह अलॉटमेंट किया है, यह प्रश्न है मेरा।

श्री अध्यक्षः बैठिए आप। माननीय मंत्री जी, आप नीति बताइए, नीति पूछ रहे हैं।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): मंत्रीमंडलीय एम्पावर्ड समिति ने निर्णय लेकर किया है और अब उसकी समीक्षा चल रही है। गलत है, उसको निरस्त करेंगे और जो सही है, उसको कर देंगे।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री गोरधन। ...(व्यवधान)... हो गया, हो गया, दो प्रश्न हो गये। श्री गोरधन।

सीकर आगार द्वारा बंद मार्गों पर बसों का पुनर्संचालन

134. श्री गोरधन (धोद): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) परिवहन विभाग द्वारा सीकर में विगत पांच वर्षों में कितने वाहनों के चालान, जब्ती व नीलामी से कितना राजस्व एकत्रित किया गया तथा कितने वाहन जब्त किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सीकर आगार द्वारा उक्त अवधि में किन-किन मार्गों पर बसों का संचालन बंद किया गया? क्या सरकार उक्त बंद मार्गों पर पुनः बसों के संचालन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

msk/rtm/19.07.2024/1140/1e

परिवहन मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): (1) जिला परिवहन अधिकारी सीकर के क्षेत्राधिकार में विगत पांच वर्षों यथा जुलाई 2019 से जून 2024 में कुल 71830 वाहनों के चालान बनाए गये जिनसे कुल राजस्व 3593.66 लाख रुपये प्राप्त हुआ। उक्त अवधि में कुल 2052 वाहन जब्त किए गये, जिनमें से कुल 30 वाहनों की नीलामी से कुल 34.08 लाख रुपये का राजस्व एकत्रित किया गया। अतः उक्त अवधि में वाहनों के चालान, जब्ती एवं जब्त वाहनों की नीलामी से कुल 3627.74 लाख रुपये का राजस्व एकत्रित किया गया।

(2) उक्त अवधि में राजस्थान रोडवेज के सीकर डिपो द्वारा निम्नलिखित मार्गों पर संचालन बंद किया गया है:-

क्र.सं.	मार्ग
1	सीकर-नावां-अजमेर
2	सीकर-रोहतक-देहली
3	सीकर-लाडनूं-कोछोर-चूरू
4	सीकर-लाडनूं-डीडवाना
5	सीकर-फतेहपुरा-शाहपुरा-डीडवाना

उपर्युक्त में से क्रम संख्या 1 एवं 4 पर वर्णित मार्गों पर निगम के अन्य आगारों द्वारा बसों का संचालन किया जा रहा है।

निगम के पास नई बसें उपलब्ध होने पर शेष तीनों मार्गों पर बसें संचालित की जाएंगी।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हूं। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

मेरा यह निवेदन है कि इन्होंने वैसे तो सीकर का जो पांच बसों का विवरण दिया है कि विशेषकर पांच बसें बन्द हो गयीं। मेरा मंत्री महोदय से वैसे तो यह आग्रह है कि पांचों ही चलें। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र धोद में संसाधनों की कमी है, इसलिए मंत्री महोदय से मेरे दो निवेदन रहेंगे। एक तो जो सीकर-फतेहपुरा-शाहपुरा-डीडवाना राजस्थान रोडवेज की बस चलती थी, उसको बन्द कर दिया गया, उसको चालू किया जाये। दूसरा, इसी में है कि इनकी एक बस सीकर डिपो से चोखा का बास वाया गोठणा, तगलान दातारामगढ़, इस बस को भी बन्द कर दिया गया। ये जो दो बसें बन्द हो गयीं, मंत्री महोदय, इनको कब तक चालू करेंगे?

इसी में मेरा एक आग्रह और है, क्योंकि यह विधान सभा क्षेत्र थोड़ा बड़ा है। यहां पर नागौर के उधर जाने वाले यात्री थोड़े ज्यादा रहते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान रोडवेज की बस जो कि जयपुर और सीकर डीपो से, यानी यह जयपुर से चलनी चाहिए, जो धोद मुख्यालय होते हुए अनोखु और जसुपुरा वाया गनाठू-मांडोली और शाहपुरा-डीडवाना होते हुए नागौर तक होनी चाहिए। दूसरी बस के लिए हमने मंत्री महोदय से आग्रह किया है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ही पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह तो बसों का रूट है, यह तो बताना पड़ेगा। इनको वैसे ध्यान में नहीं रहेगा। यह अंकित नहीं होगा तो फिर पता नहीं होगा। हमारी जो दो बसें बन्द हो गयीं और हमें दो बसें नयी चालू करनी हैं। हमारी एक बस सीकर डिपो से वाया खाखोली-सेवतबड़ी होते हुए, सियोड बड़ी शाहपुरा-डीडवाना नागौर तक। हमारी जो दो बसें पुरानी बन्द हो गयीं, उनको चालू करना और दो नयी चालू करना। ये मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है। कब तक करेंगे?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा कि सीकर-नावां-अजमेर, यह वाली 2019 में बन्द हुई है। कांग्रेस सरकार ने बन्द की थी। सीकर-धोद-दिल्ली यह वाली भी 2020 में बन्द की है। सीकर-लाडनूं-कोछोर-चूरू, यह भी 2020 में बन्द की है। सीकर-लाडनूं-डीडवाना, यह भी जनवरी 2022 में बन्द की है। हमने एक 2024 में बन्द की है, जो कि यात्री भार कम होने की वजह से बन्द की है। निश्चित रूप से अगर माननीय सदस्य की वहां पर मंशा है और यात्री भार की संभावना है तो निश्चित रूप से नयी बस चलायी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। समरजीत सिंह।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल एक ही बस दी है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, अब हो गया, जितना बताया, उतना हो गया।

भीनमाल में जल जीवन मिशन के अपूर्ण कार्य

135. श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे/:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में वर्ष 2021 से माह जून, 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत कितने कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा कितने अपूर्ण हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर कब तक पेयजल उपलब्ध करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्य का रखरखाव किस-किस एजेन्सी द्वारा किस आधार पर किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): (1) विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के समस्त 128 ग्राम जल जीवन मिशन के तहत 2 वृहद् पेयजल परियोजनाओं के अन्तर्गत 127 ग्राम एवं 1 ग्राम लघु पेयजल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। 2 वृहद् पेयजल परियोजनाओं के 127 ग्रामों में से वृहद् पेयजल परियोजना नर्मदा ई.आर क्लस्टर में विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के 77 ग्रामों में तथा वृहद पेयजल परियोजना नर्मदा एफ.आर क्लस्टर के अंतर्गत 50 ग्रामों में घर-घर पेयजल का कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है।

परियोजनाओं के कार्यादेशानुसार नर्मदा ई.आर क्लस्टर परियोजना का कार्य दिनांक 12.03.2024 तक पूर्ण किया जाना था। परियोजना की विस्तारित अवधिनुसार माह सितम्बर

2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। इसी प्रकार वृहद् पेयजल परियोजना नर्मदा एफ.आर क्लस्टर का कार्य प्रगति पर है एवं दिनांक 15.06.2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

लघु पेयजल योजना सेवड़ी में स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। ग्राम की ढाणियों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल के कार्य करवाने हेतु संशोधित स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) स्वीकृत वृहद् पेयजल परियोजना ई.आर एवं एफ.आर के अन्तर्गत ग्राम व उनकी ढाणियों को सम्मिलित किया गया है एवं उक्त कार्य चरणबद्ध रूप से माह जून, 2025 तक पूर्ण कर पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है। लघु पेयजल योजना ग्राम सेवड़ी की ढाणियों को लाभान्वित करने हेतु संशोधित योजना की स्वीकृति के प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(3) राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशानुसार वृहद् पेयजल परियोजनाओं के कार्य पूर्ण होने के उपरांत संबंधित ग्रामों के विलेज ट्रांसफर चैम्बर से पहले के आधारभूत संरचनाओं के कार्य का संचालन एवं संधारण विभाग द्वारा किया जायेगा। विलेज ट्रांसफर चैम्बर से आगे का संचालन एवं संधारण संबंधित ग्राम की जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) द्वारा किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने खुद ने स्वीकार किया और मैं आपके मार्फत बताना चाहूंगा कि ये योजनाएं, ईआर प्रोजेक्ट और एफआर प्रोजेक्ट सन 2013 से चालू हैं। इन योजनाओं को दस साल हो गये हैं और आज भी हम तारीख पर तारीख दिये जा रहे हैं। मेरा यह निवेदन है कि सरकारें इधर की भी आयीं, उधर की आयीं, आयीं और गयीं। आज भी आप देखिये, इसमें सितम्बर, 2025 की तारीख दी गयी है। किसी ठेकेदार को तीन महीने का समय दें, उस पर पैनल्टी लगायें, उस पर कार्यवाही करें, ताकि ये कार्य तो पूरे हों।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो जानकारी दी गयी, हमारे एरिये में जो एफआर प्रोजेक्ट है, उसके अन्दर लाइनें तो बिछ गयीं पर अभी तक पानी नहीं जा रहा है। मंत्री महोदय, जिनको पूर्ण बता दिया गया, वहां पर भी ढाणियों के अन्दर पानी नहीं पहुंच रहा है। आप इस चीज को दिखवाकर कार्यवाही करें और ठेकेदारों पर पैनल्टी लगे, इस चीज को भी आप सुनिश्चित करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बताया, वह वास्तव में तकलीफदेह है। परियोजना का कार्यादेश दिनांक 24.09.2013 को राशि रुपये 372 करोड़ का जारी किया गया था। कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित दिनांक 03.10.2016 थी। अब तक राशि 327 करोड़ का व्यय किया गया है। संवेदक द्वारा देरी से कार्य करने पर राशि 20.98 करोड़ की शास्ति रोकी गयी है। कार्य की पूर्णता की संभावित तिथि 30.9.2024 है। यह तो ट्रांसमिशन का काम है। ईआर

ट्रांसमिशन देरी के कई कारण हैं। इसके कारण जमीन के कारण मुख्य हैडवर्क्स पालड़ी सोलंकियान में दिनांक 02.03.2015 को आवंटित की गयी है। गांव डेडवा में दिनांक 01.07.2016 को आवंटित की गयी। इसके अतिरिक्त हैडवर्क्स बीगा को खारा में स्थानांतरित किये जाने का मुख्य रूप से फर्म द्वारा कार्य धीमी गति से किया जाना है। इसके बहुत से कारण हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस कांट्रेक्टर पर अब तक लगभग 26 करोड़ रुपये की पैनल्टी लगायी गयी है, जबकि इसकी पैनल्टी 40 करोड़ लगनी चाहिए। उन अधिकारियों के खिलाफ भी, मैंने कल बैठक की है, डायरेक्शन दिये हैं कि उन्होंने जितनी देरी की है, उस परफार्मेंस में जितनी एलडी कटनी चाहिए थी, उतनी काटे। यह भी मैंने कहा। इसके साथ-साथ जो काम ई-आर क्लस्टर, एफआर, इन्होंने जो 15 महीने आगे बढ़ायी है, यह भी इन्होंने गलत बढ़ायी है। इसके लिए भी मैंने इनको डायरेक्शन दे दिया। इसको आने वाले छह महीने में कैसे पूरा करेंगे, वह नहीं करेगा तो दूसरे कांट्रेक्टर से करायेंगे। यह मैं आपको सदन के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो ढाणियां छूट गयी हैं ओर जो कमेटियां बनी हैं, बीडब्ल्यूएमसी, उनके मार्फत भी कोई सुझाव आयेंगे? क्या उनको लेकर भी लोगों को राहत दी जायेगी? मैं सबसे बड़ा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां नर्मदा से पानी सप्लाई की स्कीम है और ओरीजनली में पीएचईडी डिपार्टमेंट जो स्कीम करता है, इन दो पाटों के बीच में गांव वाले फंस गये हैं। नर्मदा वालों को फोन करें तो वे पीएचईडी वालों की बात करते हैं, पीएचईडी वालों को फोन करें तो नर्मदा के पास है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न पूछें।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि यह लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। एक दूसरे पर डालने से इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, इसके बारे में आप कार्यवाही करें। मैं एक और जोड़ना चाहूंगा। कभी बाबूसिंह जी ने भी सवाल किया। माही प्रोजेक्ट को भी आप आगे लाइये, ताकि लोगों के पीने, खेती और सब में काम आये।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सदस्य, जो कह रहे हैं, सही है। जनता के बीच में जब हमारे जनप्रतिनिधि जाते हैं तो कई चीजों की तकलीफ आती है। इन्होंने जो सवाल उठाया है वह वाजिब है। मैं सबसे पहले जो ढाणियां बच गयी हैं, मैंने पूरे राजस्थान के अन्दर जब वापस सर्वे करवाया तो लगभग 10 हजार करोड़ से ज्यादा के काम अब होने बाकी हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आप लोग नाराज मत होना, बाकी सामने वालों को कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जो भेदभाव बढ़ता गया।

mdp/rtm/19.07.2024/11:50/1f

श्री अध्यक्षः आश्वस्त कर दीजिए।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): एक गांव में जब सर्वे कराया, उस गांव

में जो मत हमारी पार्टी को देते थे, उन्होंने पूरा एस्टीमेट फाइनल करके एनओसी सेन्टर में भेज दी। बाकी उनके अन्दर एक भी पाइप लाइन नहीं डाली गयी।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): लोग तो दोनों पार्टियों को वोट देकर थक गये हैं ...(व्यवधान)... कभी आपको देते हैं, कभी हमको देते हैं। वे दोनों पार्टियों को दे रहे हैं, ...(व्यवधान)... वही के वही रह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न का उत्तर आने दीजिए।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मेरी बात सुनिए ...(व्यवधान)... गलती हुई उसको मानना पड़ेगा। हमने सबका सर्वे कराया है ...(व्यवधान)... मेरे पास सभी माननीय सदस्य आते हैं। इसके लिए अभी सोमवार को केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री जी से हमारे सेक्रेटरी साहब और हमने जाकर बात की है। उन्होंने आवश्वस्त किया है, क्योंकि इसकी समयावधि मार्च, 2024 को कम्प्लीट हो चुकी। राजस्थान जेजेएम में 34वें नंबर पर था। सब राज्य इसको कम्प्लीट कर चुके हैं और अभी तक हमने केवल 50 परसेंट ही टारगेट पूरा किया था। वे अभी कैबिनेट में डिसीजन करेंगे कि आपका समय आगे बढ़ायें या नहीं बढ़ायें? बढ़ायेंगे तो जो भी ढाणियां छूटी हैं, उनको भी जोड़ेंगे। दूसरा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मेंटीनेंस और प्रोजेक्ट वाले जो वे अलग-अलग करते हैं, उसके लिए हम गाइडलाइन बना रहे हैं कि जिस क्षेत्र के अन्दर प्रोजेक्ट का काम हो, चाहे मेंटीनेंस का काम हो, एक ही अधिकारी करे जिससे जन-प्रतिनिधि और जनता को दिक्कत नहीं आये।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री शंकर सिंह रावत। बैठिए, माननीय सदस्य।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूं। चूंकि डिमांड पर पानी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को नहीं लिया गया, मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, एक दिन इस पर पूरा सदन चर्चा करे क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: चर्चा कराएं। माननीय शंकरसिंह रावत।

अजमेर व ब्यावर जिले को ई.आर.सी.पी. से जोड़ने की कार्ययोजना

136. श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर):: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर कितना बजट स्वीकृत किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजना में सरकार द्वारा कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है?

(3) क्या पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में अजमेर एवं ब्यावर जिले भी सम्मिलित हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार अजमेर एवं ब्यावर जिले को भी सम्मिलित करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री(श्री सुरेश सिंह रावत): (1) पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा परियोजना के घटकों नवनेरा बैराज व ईसरदा बांध के निर्माण हेतु अब तक क्रमशः राशि रूपये 1054.45 करोड़ व राशि रुपये 942.08 करोड़ बजट स्वीकृत किया

गया है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के अन्तरिम बजट में योजना की क्रियान्विती हेतु आवश्यक राशि 45 हजार करोड़ प्रस्तावित की गई है।

राज्य में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राशि रुपये 9600 करोड़ के LOA जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के अन्तर्गत 05 महत्वपूर्ण लिंक व चम्बल बेसिन के कार्यो को भी चरणबद्ध रूप से करवाया जाना प्रस्तावित किया गया है ।

(2) संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना (एकीकृत ईआरसीपी) में पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों (नव गठित 21 जिलों) को लाभान्वित क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है ।

(3) संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना (एकीकृत ईआरसीपी) के अन्तर्गत लाभान्वित 13 जिलो (नव गठित 21 जिलों) में अजमेर एवं ब्यावर जिले भी सम्मिलित है।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया है। मैंने पढ़ लिया है। मेरा पूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: पूछिए।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): ई.आर.सी.पी. जो लिखा है, ई.आर.सी.पी. का पूरा नाम क्या है?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): इस नाम को संशोधन करके नरेन्द्र मोदी योजना का नाम रखा जाए, मेरी मांग है। यह एक बात का जवाब दें, मंत्री महोदय। दूसरा, मेरा यह है कि ब्यावर जिले में काश्तकारों के लिए पानी की आवश्यकता है। आप ब्यावर जिले में पानी देंगे, मुझे सवाल पूछने दीजिए।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल पूछिए, सुझाव बाद में देना।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): क्या आप इसका नाम ये रखेंगे? ब्यावर जिले में पानी कहां व किस रास्ते से देंगे, यह बताएं?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ब्यावर से आने वाले माननीय वरिष्ठ सदस्य को बताना चाहता हूं कि ई.आर.सी.पी. का जो नाम है, वह पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है।

जहां तक ब्यावर जिले को ई.आर.सी.पी. का पानी देना है, इसके लिए हमारी संशोधित पीकेसी परियोजना के अंतर्गत अजमेर जिले में पेयजल हेतु बीसलपुर बांध निर्भरता कम करने के क्रम में अजमेर जिले में ही मोरसागर में एक बड़ा कृषि बांध भराव क्षमता लगभग 200 एमसीएम घनमीटर बनाया जाना प्रस्तावित है। यह बांध एक बार भरने पर अजमेर शहर व आसपास के क्षेत्रों की दो साल तक प्यास बुझा सकता है।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मैंने नाम का पूछा था कि यह इंदिरा गांधी परियोजना से रखा है, नरेन्द्र मोदी के समय में हो रहा है, नरेन्द्र मोदी के नाम से नहीं होगा ...(व्यवधान)... इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। अगला प्रश्न। श्री गोपीचन्द मीणा।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): प्रश्न तो पूछने दीजिए। ...(व्यवधान)... देश के प्रधान मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष: आप सरकार को सुझाव भेज दीजिए।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): जवाब दीजिए आप। सुझाव नहीं है, मेरी मांग है।

श्री अध्यक्ष: आपका सुझाव है। प्रश्न नहीं है। आप बैठिए। माननीय मंत्री जी।

जहाजपुर के अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

137. श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र-छात्राओं की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, स्व-रोजगार ऋण योजना तथा विधवा एवं बीपीएल परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु देय राशि के आवेदन लम्बित हैं? यदि हां, तो क्यों व कब से?

(2) क्या सरकार उक्त लंबित आवेदनों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत भुगतान से शेष एवं लम्बित आवेदन पत्रों का योजनावार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं लम्बित के कारण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन पत्र भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय से बजट हस्तान्तरित नहीं होने के कारण लम्बित हैं।

अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण नियमित रूप से किया जा रहा है।

अनुजा निगम भीलवाड़ा द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व वर्षो के 17 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया है।

अनुजा निगम भीलवाड़ा द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में जहाजपुर में अनुसूचित जाति के 3 तथा अनुसूचित जनजाति के 16 अर्थात कुल 19 लाभार्थियों का स्वरोजगार हेतु ऋण के लिए चयन किया गया है। इन लाभार्थियों को ऋण संबंधी सभी दस्तावेजों की पूर्ति करने हेतु कार्यालय अनुजा निगम भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक 4394-5238 दिनांक 28.03.2024 एवं पत्रांक 901-1047 दिनांक 14.06.2024 द्वारा लिखा गया है।

विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में विधवा एवं बीपीएल परिवारों की पुत्रियों को देय विवाह राशि का कोई भी आवेदन वर्तमान में लम्बित नहीं है।

(2) जी, हां। विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का बजट उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार पात्र आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा रहा है।

अनुजा निगम भीलवाड़ा द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में जहाजपुर के सभी 19 चयनित लाभार्थियों/ऋणियों से ऋण सम्बधी दस्तावेज पूर्ण रूप से प्राप्त होते ही लाभान्वित किया जावेगा।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र-छात्राओं की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के 2019 से 2023 तक कुल लंबित 634 प्रकरण हैं, इनका निस्तारण व भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर, भीलवाड़ा जिला और राजस्थान के जितने भी एससी के अनुसूचित जनजाति के जितने भी छात्र-छात्रा हैं, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, इसमें पहले पूर्व में जब मैंने एक प्रश्न के उत्तर में दिया था, कि जो 600 करोड़ से ज्यादा का बजट था, उसमें हमारी सरकार आने के बाद 225 करोड़ हमने भारत सरकार से लिया है, अब एसटी का 438 करोड़ रुपया और ओबीसी का 106 करोड़ रुपया केन्द्र से लाने के लिए हमने पत्र लिख दिया है। हमारी केन्द्र सरकार में जो सेक्रेटरी हैं, उनसे हमारी बात हो गयी है, निश्चित ही बहुत ही जल्दी यह बजट आते ही हम पूरे राजस्थान के सभी को एसटी के जो हैं, उनको छात्रवृत्ति उपलब्ध करवा देंगे।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में विधवा एवं बीपीएल परिवार की पुत्रियों के सामूहिक विवाह हेतु देय अनुदान राशि सामूहिक विवाह सम्मेलन में गरीब की पुत्रियों के विवाह हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने रिजेक्ट किये गये?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य का जो सवाल है, यह महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमने जब हमारे डीएलओ से पता किया, अभी हमारे पास वर्तमान में ऐसा कोई आवेदन लंबित नहीं है, लेकिन जानकारी में आया है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय वहां के तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी के पास ये आवेदन दिये गये थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज ही हम एक आर्डर जारी करके इसका परीक्षण करवा लेंगे। जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री भागचन्द टांकड़ा। प्रश्न संख्या बोलिए।

पॉलीथीन बैग्स पर प्रतिबंध

138. श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पॉलीथीन बैग्स के निर्माण एवं उपयोग पर रोक है? यदि हां, तो कब से? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रतिबंध के उपरान्त भी प्रदेश में पॉलीथीन बैग्स का

निर्माण व उपयोग हो रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पॉलीथीन बैग के उपयोग विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन के लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कार्रवाई करने का प्रावधान है? यदि हां, तो प्रदेश में उक्त अधिनियम के तहत विगत दो वर्षों में कितनों के विरूद्ध कार्रवाई की गई? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रदेश में पॉलीथीन बैग पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू कराने हेतु इसके निर्माण से जुड़ी इकाईयों को बंद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री संजय शर्मा): (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 21/07/2010 द्वारा संपूर्ण राज्य को प्लास्टिक कैरी बैग्स मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया एवं राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन को दिनांक 01.08.2010 से प्रतिबन्धित किया गया। आदेश की प्रतिलिपि परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। पॉलीथीन कैरी बैग्स पर देश भर में पूर्ण प्रतिबंध नहीं होने एवं कैरी बैग्स की मोटाई आधारित आंशिक प्रतिबंध ही होने के फलस्वरूप प्रदेश के पडोसी राज्यों से प्लास्टिक कैरी बैग्स के राज्य में बिक्री हेतु लाने एवं उपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(3) जी हां। प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबंध के क्रियान्वयन हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय /प्राधिकारी में परिवाद प्रस्तुत करने के लिए जिला कलेक्टर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारियों एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है।

प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा औद्योगिक इकाईयो/प्रतिष्ठानों के विरुद्ध गत 2 वर्षो में की गई कार्यवाही का जिलावार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

नगरीय निकायों द्वारा जुलाई 2022 से जून 2024 तक 181.92 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक की जब्ती कर राशि रु. 113.51 लाख की शास्ति आरोपित की गई है।

(4) जी हां। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्लास्टिक कैरी बैग्स के विनिर्माण हेतु किसी भी इकाई को स्थापना/संचालन हेतु सम्मति जारी नहीं की गई है। प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबंध को सुनिश्चित करने हेतु प्लास्टिक कैरी बैग्स के निर्माण से जुडी समस्त चिन्ह्रित इकाईयों को बंद करवाया गया है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उत्तर आ गया है। प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: पूछिए।

श्री भागचन्द टांकड़ा (बांदीकुई): क्या सरकार जो ठेले, छोटे दुकानदार, सब्जी व्यापारी, जिन पर पॉलीथीन की कार्यवाही कर रही है, उनको जो पकड़ने का काम कर रही है, इसमें बाहर से या जो बड़े दुकानदार हैं, जहां पर पॉलीथीन बन रही है, उन फैक्ट्रियों को बंद करने पर विचार रखती है क्या?

श्री संजय शर्मा (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष महोदय बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात सदन के अन्दर रखी है, निश्चित रूप से राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो पिछले दो वर्षों में चार बड़ी फैक्ट्रियों को हमने बंद किया है। पिछले 5 वर्षों में 68 फैक्ट्रियों को बंद किया गया है। यह भी सही है कि प्रतिबंधित पॉलीथीन अन्य राज्यों से राजस्थान के अन्दर आ रहा है। उसको लेकर के मुख्य सचिव द्वारा, स्पेशल टॉस्क फोर्स, जिसमें उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ट्रांसपोर्ट विभाग और वाणिज्यिक कर विभाग को भी ताईद किया गया है इस प्रकार की प्रतिबंधित पॉलीथीन को रोकने के लिए। साथ ही साथ राज्य मंडल द्वारा जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक परितोष स्कीम 27/06/24 को जारी की गयी है, जिसके तहत प्रतिबंधित प्लास्टिक के परिवहन से सम्बन्धित सूचना देने वाले व्यक्ति को इनाम के रूप में सम्मान भी किया जायेगा तथा सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जायेगा।

Ans/rtm 12.00 1g 19.07.2024

राज्य सरकार निश्चित रूप से इस मामले में संवेदनशील है। आने वाले समय में प्रयास किए जाएंगे कि बाहर से आने वाली प्लास्टिक को भी रोका जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से ओरण भूमि को निजी कंपनियों को आवंटित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2. श्रीमती गीता बरबड़, सदस्य की ओर से जोधपुर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 112 पर जोधपुर शहर में स्थित बीजेएस बस स्टेण्ड से बनाड़ तक बारिश के पानी की निकासी न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की ग्राम पंचायतों को षष्टम राज्य वित्त आयोग की सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से बजट भाषण 2024-25 में ई.आर.सी.पी. के अन्तर्गत पाँचना बाँध को शामिल नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. डॉ. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय भरतपुर में कुलपति द्वारा की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्री रामनिवास गावडिया, सदस्य की ओर से पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र परबतसर में उप जिला चिकित्सालय एवं ट्रोमा सेन्टर की घोषणा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ के देवाणी फांटा से छापर तक की शेष सड़क का निर्माण शीघ्र पूर्ण करवाये जाने के संबंध में।

8. प्रदेश में बिजली की कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निम्नांकित सदस्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैः-

1. श्री अमित चाचाण

2. श्री ललित यादव एवं 06 अन्य

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

9. श्रीमती शिमला देवी, सदस्य की ओर से कृषि बाहुल्य श्रीगंगानगर, अनूपगढ एवं हनुमानगढ़ ज़िले में कपास की फसल पर गुलाबी सुन्डी के हमला बोलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

10. डॉ. प्रियंका चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में बिजली के खम्भों से केबल चोरी होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

11. नरेन्द्र बुडानियां, सदस्य की ओर से कार्यालय नगर पालिका तारानगर द्वारा निदेशालय भेजी गई ई-निविदा की पत्रावलियों को वापस नहीं लौटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

12. श्री जुबेर खान (65) सदस्य की ओर से जयपुर शहर के जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर एलिवेटेड रोड बनाये जाने की योजना के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती शिमला देवी (163), डॉ. प्रियंका चौधरी (96), श्री नरेन्द्र बुडानियां (84) एवं श्री जुबेर खान (65) को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएँ

1. श्री देवी सिंह शेखावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में अघोषित बिजली कटौती के संबंध में।

2. श्री सोहन लाल नायक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर के किसानों को स्वीकृत मुआवाज़े एवं फसल बीमा राशि का भुगतान नहीं होने के संबंध में।

3. श्री ललित यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में नकली एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय पर रोक के लिए कानून में आवश्यक संशोधन हेतु राज्य स्तरीय कमेटी का गठन

करने के संबंध में।

4. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से नरेगा अन्तर्गत कार्मिकों के नियमितिकरण एवं मृतक नरेगा कार्मिक के आश्रित को संविदा नियुक्ति देने के संबंध में।

5.डॉ. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना में पशु चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन कर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं रिक्त पदों को भरने के संबंध में।

6. श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से भरतपुर ज़िले के विकास हेतु बयाना वैर- नदबई से निकलने वाले मेगा हाईवे को फोर लेन में क्रमोन्नत करवाए जाने के संबंध में।

7.श्री समरजीत सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीनमाल की कतिपय ग्राम पंचायतों का उपखण्ड जसवन्तपुरा के स्थान पर भीनमाल किये जाने के संबंध में।

8. डॉ. विकास चौधरी (148) सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की पंचायत समिति अराई में आगजनी की घटनाओं को देखते हुए अग्निशमन केन्द्र खोले जाने के संबंध में।

9. श्री लालाराम बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के उपखण्ड बनेड़ा में अवैध रूप से संचालित कोयले की भट्टियों पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

10. सुश्री नौक्षम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कामां में जल-जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन डालने से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में।

11. श्री नाना लाल निनामा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र घाटोल में नवीन जी.एस.एस. स्वीकृति के संबंध में।

12. श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर, सदस्य की ओर से गंग नहर में हरीके वैराज से राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी नहीं छोड़े जाने से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में।

13. श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना में नागौर लिफ्ट परियोजना फेज-द्वितीय के अन्तर्गत संवेदकों को जारी आन्तरिक जल वितरण प्रणाली के प्रमाण-पत्रों की जांच के संबंध में।

14. श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से नवगठित नगरपालिका बालेसर सता में सम्मिलित कतिपय ग्राम पंचायतों. को यथावत ग्राम पंचायत रखे जाने के संबंध में।

15.श्री अभिमन्यु, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ ज़िले में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में।

आज महत्वपूर्ण डिमाण्ड पर विचार है। सदस्यों की संख्या भी पर्याप्त है, इसलिए 295 को पढ़ा हुआ माना जाए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, 295 तो पढ़वा दीजिए।

श्री अध्यक्षः पढ़वा दें? चलो इसको पढ़ने की अनुमति होगी। आपका सुझाव है।

पर्ची

आज दिनांक 19/07/2024 को शून्यकाल में बोलने हेतु 44 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से

शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गई, जो निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	पर्ची संख्या	माननीय सदस्य का नाम	विषय
1.	34	श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल)	संस्थाओं को गलत तरीके से भूमि आवंटन के संबंध में।
2.	11	श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़)	सूरतगढ़ नगरपालिका में 2009 व 2022 के सर्वे को लागू करने व पट्टे जारी करने के संबंध में।
3.	25	श्री सुभाष मील (खंडेला)	प्रदेश में शहीद परिवारों के आश्रितों को नियमों में शिथिलता देकर सरकारी नौकरी देने के संबंध में।
4.	8	श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़)	विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ व सुजानगढ़, बीदासर सहित चूरू जिले में खरीफ एवं रबी फसल 2023 के खराबे का किसानों को मुआवजा देने बाबत।

पहले आप बोलेंगे या स्थगन के बाद? चलिए, बोलिए।

अनुरोध एवं मांग

आसन द्वारा प्रतिपक्ष के संरक्षण की मांग

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों से लगातार सदन के अन्दर जिस प्रकार की परिस्थिति बन रही है, मैं आपका ध्यान उस ओर अवगत करना चाहूंगा।

जब सत्र शुरू हुआ, मीडिया ने बाहर हमसे पूछा कि विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी। विपक्ष हल्ला करेगा या सत्ता पक्ष को कॉ-आपरेट करेगा। मैंने पहले दिन यह कहा था कि जहां सत्ता पक्ष सदन को अच्छे से चलाना चाहेगा तो हम कॉ-आपरेट करेंगे। हम कोई सत्ता पक्ष के दुश्मन नहीं है। संविधान के अन्दर हमारी जिम्मेदारी तय की गई है। विधान सभा के नियम, प्रक्रिया के अन्दर हमारी जिम्मेदारी तय की गई है। हमारा यह अधिकार है कि प्रदेश के अन्दर जो समस्याएँ हैं, उनको लेकर हम मंत्रियों से, सरकार से क्वेश्चन करे।

अध्यक्ष महोदय, लगातार जिस प्रकार का आचरण मिनिस्टर्स के द्वार, विधायकों द्वारा किया जा रहा है, हम क्वेश्चन कुछ लगाते हैं और जवाब कुछ आता है। हम सवाल पूछते हैं, नेता प्रतिपक्ष चाहे मैं हूं या मेरे से पहले कोई भी रहा हो, हर नेता प्रतिपक्ष को यह व्यवस्था दी गई है कि वह हर प्रश्न में प्रश्न पूछ सकता है। मैं हर प्रश्न में नहीं पूछता और पूछना भी नहीं चाहिए, खुद की गरिमा है। लेकिन मान लीजिए, जब हम पूछते हैं तो उसका जवाब नहीं आए, मंत्री का क्या इतना भी नैतिक दायित्व नहीं बनता कि जब नेता प्रतिपक्ष खड़ा होकर कोई बात कहता है तो एक मिनट बैठ जाए। मैं विधायक भी रहा हूं, राज्य मंत्री भी रहा हूं,

कैबिनेट मंत्री भी रहा हूं। यहां से महामहिम कटारिया जी, जो कि आसाम के राज्यपाल है, वे जैसे ही खड़े होते थे, हम बैठ जाते थे।

VPS-RTM-19.07.2024-12.10-1h

वह सम्मान उस पद का है और हम कोई बात कहते हैं, वह आपके सामने ये भी रखेंगे और हम भी रखेंगे पर कल जिस प्रकार की घटना हुई और मैं लगातार यह देख रहा हूं कि अध्यक्षजी, आपका जो झुकाव है वह हमारी तरफ ज्यादा होना चाहिए, यह हमारा अधिकार है, इस सदन की परम्पराएं हैं +++ हम कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो जा नहीं सकते, हम अपनी बात आपको ही कह सकते हैं, आपका ही संरक्षण चाहते हैं।

कल जिस प्रकार का वक्तव्य मंत्रीजी ने दिया, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य। माननीय रफीक खान, ऐसे आप बोलेंगे तो फिर मैं बैठा दूंगा। यह मेरा काम है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब वह ही बात है। वह पहले जिसने शुरूआत की है, +++ ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः पहले इन्होंने की थी शुरूआत। ऐसा नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जो बीच में डिस्टर्ब करता है, +++ ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आसन पर आक्षेप नहीं लगाये। कल भी आपने कई आक्षेप लगाये हैं। यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हम आक्षेप नहीं लगा रहे हैं पर आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? यह तो पूरा सदन देख रहा है कि जब मैं बोल रहा हूं तो वे उधर से बोल रहे थे और वे अब फिर से खड़े हैं आपके सामने। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप इनको बोलने दें, नहीं तो फिर इस पर चर्चा नहीं होगी। आपके कितने लोग बोल रहे हैं? आप पीछे मुड़कर देखो, आपके पन्द्रह लोग एक साथ बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): शुरूआत उधर से होती है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप बैठिये। आपको भी बोलने का अवसर दूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्षजी, जब भी मैं बोलता हूं तो उधर से ये टोकते हैं और फिर हमारे सदस्य खड़े होते हैं, +++ जो शुरूआत करता है, जिसकी वजह से व्यवधान होता है, +++ हम आपसे नहीं कहे तो किससे कहें?

कल जिस प्रकार का अपशब्दों का प्रयोग, असंसदीय शब्दों का प्रयोग यहां पर किया गया। हम सिर्फ अपनी बात रख रहे थे और उसको एक्सपंज करवाना चाहते थे पर +++ हम क्या चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं राजस्थान की विधान सभा को कि किस प्रकार के वक्तव्य यहां के मिनिस्टर बारबार दे रहे हैं? कोई बाहर दे रहा है और कोई यहां पर दे रहा है,

कोई विधायक कुछ बोल रहा है। गांधीजी के बारे में बोल रहे हैं, राहुल गांधीजी के बारे में बोल रहे हैं, जो मर्जी आये वह बोल रहे हो। इस प्रकार की चीजें अध्यक्षजी, हम आपका रिगार्ड करते हैं, सम्मान करते हैं, आसन का सम्मान करते हैं पर हम यह चाहते हैं कि आसन दोनों पक्षों को बराबरी से रखे।

आज जिस प्रकार की स्थिति पूरे प्रदेश के अन्दर हो रही है, कल बिजली के अन्दर क्या स्थिति थी? मंत्री यह जवाब दे रहा है कि 2019 में यह था, 2020 में यह था तो हम वह नहीं चाहते हैं, हम इतनी ही बात रख रहे हैं कि मंत्री यह कहे कि आज यह स्थिति है, हम बिजली दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, उस पर हम आपका संरक्षण चाहते हैं और आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, आप व्यवस्था दीजिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी सत्ता पक्ष के जितने भी माननीय सदस्य हैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता का बहुत ही हृदय से सम्मान, आदर और रिगार्ड करते हैं। हमारा आपसे पहले भी यह निवेदन था और आज भी यह निवेदन है कि हमारी इस राजस्थान विधान सभा की बहुत स्वस्थ परम्पराएं रही हैं। चाहे परसरामजी हो, भैरोंसिंहजी हो या उससे पहले हो या उसके बाद में हो और अंतिम रूप में जैसा कि आपने उल्लेख किया माननीय महामहिम गुलाब चन्दजी कटारिया साहब का तो मैं आज पुनः मेरे सत्ता पक्ष की ओर से आपको यह आश्वासन दोहराता हूं कि कृपया, आप खड़े होते हैं तो हमारा दिल से, हृदय से हम यह चाहते हैं कि आप अपनी कोई बात कहें लेकिन बारबार ज्यादा खड़े हो जाते हैं, हर बात पर खड़े हो जाते हैं तो हम आपका वह सम्मान नहीं कर पा रहे हैं इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप तब ही खड़े हो जब बहुत महत्वपूर्ण कोई विषय हो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये। आपका भी सुना है, आप भी इनका सुनिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): यह फैसला लेंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: यह फैसला तो मैं करूंगा, आप सुनिये तो सही। अबआप देखिये कि कौन बोल रहा है? आप नोट करना अबकी बार। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ऐसे जब भी कोई विषय आये और इन स्वस्थ परम्पराओं को कायम रखने के लिए विषय आये तो आप अवश्य खड़े हो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह मेरा काम है। नहीं तो आप प्रस्ताव ले आओ। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप जब भी कहेंगे तो हमारा सत्ता पक्ष आपका मान और सम्मान करेगा। हमारी यह पुनः रिक्वेस्ट है कि हर विषय में अनावश्यक रूप से आप खड़े होते हैं तो फिर उतना सम्मान नहीं होता है। आज सत्ता पक्ष में आप हैं, मेरा निवेदन आपसे है कि आप सत्ता पक्ष के मुखिया हैं, सॉरी, प्रतिपक्ष के आप मुखिया हैं तो आप अपने सदस्यों को भी कहें। हम सभी साथी भी मानते हैं कि हम आपका रिगार्ड करें, आपके रिगार्ड में कोई कमी नहीं आयेगी लेकिन मेरा विनम्रता से यह निवेदन है कि यह

विक्रमादित्य का आसन है, इस पर जो भी बैठता है, उसकी निगाहें सबके लिए बराबर होती है और आज तक हमने यह फील किया है कि विक्रमादित्य के आसन से, माननीय अध्यक्ष के आसन से किसी का कोई न तो पक्ष किया गया है और न ही कोई ना-पक्ष किया गया है, यथा सम्भव सबके साथ न्याय करने का पूरा-पूरा प्रयास किया गया है, ऐसा हमने फील किया है बल्कि उलटा हमको कभी-कभी हमारे माननीय सदस्य यह कहते हैं कि माननीय स्पीकर साहब थोड़ा सा उनको संरक्षण देते हैं तो हम उनको कहते हैं कि यह ठीक है, प्रतिपक्ष के साथी हैं, उनको विधान सभा में अपनी बात रखने का अधिकार है और हम सत्ता पक्ष में हैं, हम अपनी बात को और कहीं पर भी कह सकते हैं पर उनके कहने का प्लेटफार्म यही है। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि आसन पर कोई किसी तरह की टीका-टिप्पणी नहीं करें। कल अमर्यादित शब्दों का आपकी ओर से प्रयोग किया गया था आसन के लिए। तो मेरा आपसे यह पुनः आग्रह है कि आसन के सम्बन्ध में कोई भी अमर्यादित शब्द न हम कहें और न आप कहें। आसन की गरिमा आप और हम दोनों मिलकर रखेंगे, तब ही रहेगी और हम अगर गरिमा नहीं रखेंगे तो आसन की गरिमा नहीं रहेगी। तो मेरा पुनः निवेदन है सभी माननीय सदस्यों से कि हम सबका लक्ष्य एक है, हम अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र से जीतकर आये हैं, हजारों मतदाताओं ने हमको इसलिए भेजा है कि हम उनका आईना बने, हम उनकी बात विधान सभा में रखें।

दूसरा, मेरा निवेदन आपसे यह है, आपने यह कहा कि मंत्री पूरे जवाब नहीं देते हैं तो यह कथन आपका असत्य है। हमारे सभी मंत्री जो भी प्रश्न पूछा जाता है, अनुकूल रूप से पूरा जवाब देते हैं, आप जितनी सामग्री सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में पूछते हैं तो उसका पूरा जवाब देते हैं और कभी भी आपको कोई हर्ट करने का प्रयास नहीं करते हैं। आप स्वयं कोई न कोई अनावश्यक प्रश्न पूछते हैं तो कभी कोई विवाद होता है। इसलिए हमारे मंत्रियों के सम्बन्ध में भी आपने जो बात कही है, वह सत्य नहीं है। हमारे सभी मंत्री तैयार हैं, पूर्ण तैयारी के साथ आते हैं, पूरा जवाब देते हैं और आप जो भी चाहते हैं वह सामग्री भी हाथों हाथ ही उपलब्ध करवाते हैं। इसलिए आपका यह कहना कि मंत्री तैयार होकर नहीं आते, यह ठीक नहीं है।

हमारे सदस्यों के व्यवहार के सम्बन्ध में भी आपने कहा तो मेरा विनम्रता से यह निवेदन है कि सत्ता पक्ष के जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं, वे अपनी मर्यादा में है, सीमाओं में है। वे अपनी मर्यादा और सीमाओं में रहकर अपनी बात को कहते हैं तो हम सब यह प्रयास करें कि कोई उत्तेजना के क्षण नहीं आये और न आपको कहना पड़े और न ही उनको कहना पड़े, यह मेरा आपसे निवेदन है।

साथ ही साथ कल का जो आपने कहा कि राहुल गांधीजी का नाम, हमारा कोई भी सदस्य नहीं चाहता कि जो हमारा सदन का सदस्य नहीं है, उसका कोई नाम हम नहीं लेना चाहते हैं और न हमारा कोई उद्देश्य ही कभी होता है। अब सम-सामयिक रूप से कोई बात आती है, दृष्टांत आता है और उससे सम्बन्धित कोई बात आती है तो उसके सम्बन्ध में अवश्य यह कहा जाता है।

आइये, हम और आप मिलकर इस राजस्थान की नई और परम्पराएं, स्वस्थ परम्पराएं कायम करें। हमारी जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जिसके लिए हमको यहां पर भेजा है, उसके लिए काम करें। मैं पुनः आग्रह करता हूं प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से और विशेष रूप से आप प्रतिपक्ष के नेता से कि आप अपनी गरिमा को बनाएंगे तो हम आपकी गरिमा को कायम रखने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर आप बहुत ज्यादा कोई बात करेंगे तो फिर हम उतनी गरिमा नहीं रख पाएंगे।

आपसे पुनः आग्रह है कि विक्रमादित्य के आसन पर कोई आक्षेप नहीं लगायें, अमर्यादित टिप्पणी नहीं करें, यह मेरा आप सबसे अनुरोध है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः हो गया। अब और बोलेंगे?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से वापस गेंद हमारे पाले में डाल रहे हैं, यह तो आपको ही देखना है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः मैं देख रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यानी, 70 लोगों की आवाज मैं नहीं उठाऊं? 70 लोगों में से किसी को बोलने की अनुमति नहीं है। उनकी तरफ से मैं बात रखता हूं। यानी, कोई आपसे पूछे ही नहीं, जो मर्जी आये वह आप बोलें, आपसे जवाब ही नहीं मांगें। यह तो कैसे हो सकता है? आप प्रोसीडिंग्स निकलवा कर देख लेना। मैंने कल जरूर मजाक में यह कह दिया था कि किरोड़ीजी का इस्तीफा हुआ है या नहीं? वह मैंने मजाक में कहा था तो हलका-फुलका मजाक इसमें चलना भी चाहिए बाकी एक भी दिन, एक भी वर्ड, एक भी शब्द मैंने गरिमा के खिलाफ कहा हो तो आप बता सकते हैं। कल शुरूआत किसने की? कल शुरूआत किसने की और किस प्रकार के शब्द कहे, उस पर क्या व्यवस्था दी गयी? अध्यक्षजी, आप बता दीजिए।

श्री अध्यक्षः हो गया? आपमें से कोई बोल रहा है? आप बोलेंगे? सचेतक के अलावा और कोई नहीं। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष की भावना का मैं बिलकुल स्वागत करता हूं, आपका सम्मान रहना भी चाहिए और हम रखते भी हैं, कोशिश पूरी करते हैं पर कभी-कभार कोई उत्तेजना में कुछ हो जाए तो बात अलग है बाकी मैं सत्ता पक्ष की तरफ से आपको यह आश्वस्त करता हूं कि हमारा कोई भी सदस्य आपके प्रति असम्मान जैसी कोई स्थिति पैदा नहीं करेगा।

अब रही बात कल की तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी सारी रिकार्डिंग सुनी है, देखी है और मुझे अवगत कराया अध्यक्ष महोदय ने और उसमें जैसा कि आप कह रहे हैं असंसदीय शब्द या कोई अपमानजनक शब्द ऐसा कुछ भी नहीं निकला उसमें से अन्यथा अध्यक्ष महोदय जरूर उसमें एक्सपंज कर सकते थे और अब भी वे कर सकते हैं, उनको अधिकार है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि +++ तो यह उचित नहीं है।

आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय को इधर वाली हलचल बारबार दिखाई देती है तो वह

इसलिए दिखाई देती है क्योंकि अध्यक्ष महोदय की, आसन की कृपा दृष्टि आप लोगों पर ज्यादा है, हम तो उनकी नजर पाने को तरस जाते हैं, वे उधर ही देखते हैं इसलिए ऐसा हो जाता है इसलिए उसको अन्यथा नहीं लें और मैं आपको बिलकुल आश्वस्त करता हूं कि यदि कुछ गलत उसमें होता तो जरूर एक्सपंज किया जाता लेकिन उसमें एक शब्द भी गलत नहीं पाया गया, जैसा कि मेरी जानकारी में आया है बाकी तो आसन, अध्यक्ष महोदय जो आदेश देंगे, वह स्वीकार होगा।

SSY/RTM/19.07.2024/12.20/1j

श्री अध्यक्ष: बीच वाला भी कोई बोले।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): मैं 2 मिनट लूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, इधर सत्ता पक्ष है और इधर विपक्ष है। अभी नेता, प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हम 70 लोग हैं। हालांकि इनके 3 लोग कम हो गये। इधर पूरे 115 हैं। लेकिन उसके अलावा भी 14 लोग और बैठे हैं। कुछ एक दल के हैं, 3 ऐसे हैं जो 3 हैं, बाकी 8 हम निर्दलीय हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन यह है कि माननीय मंत्रीगण बहुत अच्छे लोग हैं। हम इनकी इज्जत करते हैं। लेकिन जब हमारे तारांकित और अतारांकित क्वेश्चन लगते हैं, क्योंकि मैंने यह देखा है, मेरा भी इस हाउस का अनुभव है, मंत्री के रूप में 10 साल का। इनके जो जवाब आते हैं, जो अधिकारी भेजते हैं उस पर अक्षरशः यह हस्ताक्षर कर देते हैं। मेरे पास अभी तक 19 सवालों के जवाब आये। 17 मैं आपके पास खुद प्रस्तुत करुंगा, मतलब इनके गलत जवाब दिये गये हैं कि या तो जान-बूझकर के इनको अधिकारी गुमराह कर रहे हैं या यह पढ़ नहीं रहे हैं। कुछ मंत्रियों के अच्छे जवाब भी आये हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आये हैं। आज सुबह जो सवाल का उत्तर मिला वह बहुत अच्छा था। मेरा आपके माध्यम से आग्रह रहेगा कि जब सरकार से कोई भी सवाल पूछे तो उसका माननीय मंत्री गण अध्ययन करके जवाब दें। यह मेरा आग्रह है। कोई आरोप नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आरोप ही है।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): दूसरा यह है कि, मैंने कहा कि आरोप नहीं है, आग्रह है, आग्रह है। हाथ जोड़कर आग्रह है। आग्रह है, हाथ जोड़ रहा हूं मैं तो।

दूसरा निवेदन यह है कि हम जो 14 लोग बैठे हैं, इनको भी कभी-कभी आप समय दे दीजिये, क्योंकि इधर भी 67 लोग हैं, इधर 115 हैं, इनके पास ताकत है। हमारे पास संख्या बल कम है। लेकिन हम भी किसी न किसी विधान सभा क्षेत्र का रिप्रजेंटेशन करते हैं। इसलिए आप हमें थोड़ा सा समय आप बोलने का दें। इतना ही आग्रह रहेगा धन्यवाद।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक एक्सप्लेनेशन रहेगा कि इन्होंने मंत्रियों पर आरोप लगाये हैं, मैं उसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। हमारे सभी मंत्री जो भी प्रश्न आता है, जो प्रश्न का उत्तर विभाग से आता है, उसका पूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं। अब आपके मन में मंत्रिपरिषद् का सदस्य नहीं होने की नाराजगी है ...(व्यवधान)... वह

हमारे हाथ में नहीं है।

श्री अध्यक्षः मेरे को मौका देने दीजिये। इस मुद्दे पर नहीं, इस मुद्दे पर नहीं, बाकी तो आप बोलिये ना।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): लेकिन हमारे सभी सदस्य पूर्ण रूप से तैयारी के साथ, सम-सामयिक जवाब देते हैं। जो तथ्यों पर आधारित होता है। आपकी यह जो चीज है, वह पूर्ण रूप से गलत है।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): मैं भी कुछ..।

श्री अध्यक्षः नो, बाद में। आप बैठिये। मुझे व्यवस्था देने दें। मैं कनक्लूड कर रहा हूं। अभी विपक्ष के नेता, आपकी ओर से नेता ने बोल लिया। विपक्ष के नेता, संसदीय मंत्री जी और एक-आध सदस्य ने जो अपना विषय रखा, यह सदन बहुत ही पवित्र सदन है। इस सदन में हम लोग अपने-अपने क्षेत्र की लाखों जनता के वोटों से जीतकर के आते हैं। जनता की बहुत बड़ी अपेक्षाएं होती हैं कि हमारी समस्याओं पर वहां चर्चा होगी। इसके कारण से मैंने कई कदम भी उठाये हैं। सर्वदलीय बैठक भी की। पर्ची योजना भी लागू की। कई प्रकार के प्रयोग किये जिसके कारण से सदन में नवाचार करते हुए हम आगे बढ़े हैं।

लेकिन लगभग इस नये सत्र में मैं मन में पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि अभी कहा कि आप इधर ज्यादा ध्यान देते हो, इसका मैं खंडन करता हूं। जितना मैं निष्पक्ष रहता हूं और आपकी बात सुनता हूं, उतना शायद एक पक्ष भी आरोप लगाते हैं कि आप इनकी सुनते नहीं हो। यह सदन नियमों, मर्यादाओं और परंपराओं से चलता है। मेरे से भी पहले कई अध्यक्ष रहे जिन्होंने इस सदन की बहुत गरिमा रखी है। लेकिन कल जिस तरह का दृश्य हुआ और जो आरोप आज अख़बार में छपा है, मेरे बारे में, अध्यक्ष के बारे में, मेरे व्यक्तिगत आप कुछ भी कह देना, धृत राष्ट्र हैं, इस पर आपको माफी मांगनी चाहिए। इस तरह से आप अध्यक्ष को कहो कि आप धृतराष्ट्र हो, शर्म नहीं आती किसी को बोलने की, मैं समझता हूं कि बहुत शेमफुल है। मैं पीड़ा से कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि इधर के बोलते हैं। दोनों ओर से लोग बोल रहे हैं। मैंने दोनों को ही बराबरी से टोका है। आप रिपोर्ट निकालकर के देख लें सदन की। जितना इधर टोका है, उसकी तुलना में कम इधर टोका है।

फिर भी आप यहां पर सदन में आये और कल मैंने एक बार कहा जिस पर आपकी आपत्ति थी, मैंने कहा कि कल इस पर आपके साथ बैठकर के कोई असंसदीय होगा, कोई असंवैधानिक होगा, कोई अमर्यादित होगा, हम उस पर चर्चा करके उस पर कार्यवाही करेंगे। उसके बाद भी आप यहां पर आ गये। पता नहीं क्यों बहुत शौक हो गया है। उसके बाद आप नारे भी लगा सकते हो। विपक्ष नारे लगाता है। लेकिन नारों में जो शब्द उपयोग किये गये, मुझे लगा कि यदि किसी को लगता है कि मैं निष्पक्ष नहीं हूं तो आप प्रस्ताव ला सकते हो। मुझे पद का मोह नहीं है। यह बात स्पष्ट सुन लो।

आप लोगों ने मुझे सर्वसम्मति से निर्वाचित किया है, तब तक नियमों के अनुसार

चलूंगा, परंपराओं के अनुसार चलूंगा और मर्यादाओं के अनुसार चलूंगा। जो भी होगा, इधर का होगा, उधर का होगा, कार्यवाही करने में कहीं भी कमी नहीं छोड़ूंगा। इतना मैं आप लोगों से स्पष्ट कहता हूं। यह सदन की कार्यवाही चले। आज महत्वपूर्ण डिमांड है। इसे जीरो ऑवर के बाद आप और संसदीय मंत्री और सचेतक, तीनों कमरे में आ जाइये, कल की सारी जो स्क्रिप्ट है, वह मंगवायेंगे। कोई भी असंसदीय या अवैधानिक, ऐसी कोई बात होगी तो उसे निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही में विचार करेंगे। धन्यवाद। अब आगे की कार्यवाही शुरू करें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपने जो कहा, आपका हक है। आप हमें जो कह सकते हैं। रही बात यहां कार्यवाही की, इतनी सी बात थी, हमने कहा कि हम हमारा पक्ष रख दें, जो गलत है, उसको आप मना कर दीजिये। जो अखबारों में छपा है, यही बात हम रात को कह रहे थे, उसी समय एक्सपंज हो जाये तो अखबारों में नहीं छपे।

श्री अध्यक्ष: क्या इसका मतलब आप धृतराष्ट्र कहोगे? क्या विपक्ष का नेता धृतराष्ट्र कहेगा? बताइये, कोई भी सदन का सदस्य कह दे, बाहर का कह दे, क्या इसके बाद कोई भी विपक्ष का नेता धृतराष्ट्र शब्द का शासन के लिए उपयोग करता है, मैं उसकी निंदा करता हूं। उसको माफी मांगनी चाहिए। तमाशा हो गया?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आपके मंत्री जी तक, सारे सदस्य चले जाते हैं। क्या गरिमा थी? यानि कि सदन में उस दिन आप सब लोगों के सहयोग से सदन की गरिमा तार-तार नहीं हुई। आज तक किसी सदस्य के पास, मंत्री जी के पास चले जाएं, बाद में व्यक्तिगत तो कहते हैं लेकिन सदन की गरिमा तो भंग हो गयी। क्या उसके लिए आपने डांटा? कौन गये? विपक्ष के नेता तो नहीं गये, पर चलो, गये विपक्ष के गये, विपक्ष के नेताओं पर आपका नियंत्रण आप पूरा रखिये। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

विपक्ष का नेता आप लोगों ने चुना है इस पर विश्वास रखिये और वह जो कहते हैं, मैं इनकी बात, आपके जब स्थगन होते हैं तो भी आपको याद करता हूं। जिसका यह कहते हैं, राय से करते हैं। इतना सम्मान देने के बाद भी यदि विपक्ष आरोप लगाये तो मैं समझता हूं कि फिर मेरे को भी पुनर्विचार करना पड़ेगा। मैं इतना डायल्यूट होकर के सबका सहयोग करूँ, उसके बाद भी यदि आरोप लगें, फिर तो आरोप लगाते रहिये। मैं इन आरोपों का खंडन करता हूं। इन आरोपों की निन्दा करता हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, आसन है, आसन की हम किसी प्रकार की, किसी प्रकार की हमारी मंशा नहीं है। मैंने मेरे पहले भी वक्तव्य में कहा है कि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट थोड़े जायेंगे। आपसे ही तो उम्मीद रखते हैं। आपसे ही कहेंगे। रात को कहने का मकसद यही था कि यहां प्रोसीडिंग में जो चीज आ जाती है, वह बाहर यू ट्यूब के माध्यम से सब जगह छप जाती है। बाद में हम उसको निकालते हैं। फिर निकालने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। एक मिनट आप हमारी बात सुनते और जो गलत शब्द थे, उसी

समय निकाल देते। बात खत्म थी। इतनी बात ही नहीं बढ़ती। जितनी बात बढ़ी है।

श्री अध्यक्ष: पता तो करुंगा पहले।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपके सामने ही, आप आसन पर थे।

श्री अध्यक्ष: ऐसा नहीं होता।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आसन पर विराज रहे थे।

श्री अध्यक्ष: संसदीय मंत्री ने क्या-क्या बात ...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपके सामने सारी बात हुई है। हम कतई नहीं चाहते कि आसन का किसी प्रकार का अपमान हो। कोई निन्दा हो। आसन पर कोई आक्षेप लगे। हम नहीं चाहते। हम आपसे संरक्षण चाहते हैं। अगर हमारी किसी बात से आपको ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि जो सदन है, जो आसन है, वह विपक्ष को ज्यादा प्रोटेक्ट करे। रही बात अविश्वास की, तो कभी जरूरत पड़ी तो वह भी लेकर आयेंगे। अध्यक्ष जी, यह भी मैं कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: हां, तो आप लेकर आइये ना, आपको चुनौती देता हूं। लेकर आइये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): चुनौती की बात नहीं है। बात चुनौती की नहीं है। बात चुनौती की नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आज ही लाइये ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): फिर वही बात ला देते हो ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आसन की बात तो सुननी पड़ेगी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आसन के ऊपर इससे पहले कभी ...(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): यह गलत तरीका है, यह गलत तरीका है ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 5 साल हम भी विपक्ष में रहे थे ...(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आरोप नहीं सहन किया जायेगा ...(व्यवधान)... आसन पर आरोप नहीं सहन किया जायेगा।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हमारे साथ कैसा व्यवहार हुआ था। हम 5 साल विपक्ष के अन्दर थे। सामने वाली सीटों पर हम बैठे थे ...(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): शर्म आनी चाहिए आपको, आसन का ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हम बैठे रहे 5 साल विपक्ष के अन्दर ...(व्यवधान)... हमें पता है कि इस आसन से हमारे साथ कैसा व्यवहार हुआ था ...(व्यवधान)... हमारे साथ कैसा व्यवहार हुआ, यह हम जानते हैं ...(व्यवधान)... 5

साल विपक्ष में हम भी रहे थे। हम भी रहे थे।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.28 बजे 13.28 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

Spp/Rtm/19.07.2024/13:20/1p

(समय : 13.28 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री फूलसिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही 2.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.28 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

...

MLS/RTM/19.07.2024/14:00/2c

(समय: 14.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही 14.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.00 बजे 14.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

mkd/rtm/19.07.2024/14:30/2f

(समय: 14.30 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय सदस्य।

अनुरोध एवं मांग

आसन द्वारा प्रतिपक्ष के संरक्षण की मांग

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में कल शाम को गतिरोध पैदा हुआ। आज फिर नेता, प्रतिपक्ष ने अपनी बात कही और संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी बात कही और फिर किन्हीं कारणों से फिर सदन में गतिरोध उत्पन्न हो गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब सदन के

सदस्य, जो चुनकर के यहां आये हैं, वे सब के सब जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जनता के मुद्दों को लेकर हम हमारी यहां बात रखते हैं और जो हमारे विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम हैं, उनके मुताबिक यहां पर काम होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें अच्छी तरह से ध्यान में है। जब आपका नाम अध्यक्ष के लिए आपकी पार्टी ने आगे किया और घोषणा की, उसके बाद में तमाम प्रतिपक्ष के सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों, सबने एक स्वर में एक बात कही थी कि वास्तव में सुलझे हुए व्यक्ति को यहां पर सदन के अध्यक्ष के रूप में, स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। हमने आगे बढ़ करके सर्वसम्मति से आपका अध्यक्ष के रूप में चयन में सकारात्मक भूमिका निभाई थी। हमने यहां हाउस में कहा भी था कि माननीय स्पीकर का जो पद होता है, वही एक ऐसा पद होता है, जो प्रतिपक्ष को हमेशा संरक्षण भी देता है और सरकारी कार्य को कराने में सरकार का सहयोग करता है और नियम और प्रक्रियाओं के मुताबिक अपना कर्तव्य का निर्वहन करता हैं।

मुझे खुशी है कि आप जब से अध्यक्ष के पद पर विराजमान हुए हैं, हमेशा आपने चाहे वह प्रतिपक्ष हो, चाहे वह सत्ता पक्ष हो, सबका पूरा ख्याल रखा है। आपका सम्मान, आपका सम्मान नहीं है, इस चेयर का सम्मान है। इस चेयर का सम्मान, हम सबका, सत्ता पक्ष का और प्रतिपक्ष का सम्मान है। इसलिए हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि इस चेयर का सम्मान करने से ही हमारा सम्मान और इस सदन की गरिमा बढ़ेगी।

इसलिए हम ऐसा कोई भी वक्तव्य नहीं देना चाहते हैं। बातें हुई हैं, माननीय सदन के नेता यहां पर उपस्थित नहीं रहते हैं, अगर वे रहते तो और ज्यादा अच्छा होता, लेकिन बात एक ही थी कि कल जो माननीय मंत्री महोदय ने, सामाजिक न्याय मंत्री जी ने जो बातें कही थीं, उनके लिए हमारे नेता महोदय ने कल कहा था कि इसको आप एग्जामिन कर लें। आपने कहा था कि मैं इसको एक्सपंज कर दूंगा, अगर कोई बात होगी तो उसकी व्यवस्था अगर आ जाती तो शायद अब तक यह बात, जो थोड़ी बहुत बढ़ी है और जो गतिरोध हुआ है, शायद वह नहीं होता लेकिन चलो जो हो गया सो हो गया।

अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं पूरे प्रतिपक्ष की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस चेयर की गरिमा, हमारी गरिमा है, इस सदन की गरिमा है, इस प्रदेश की गरिमा है। इसको हम बनाकर रखेंगे। इसमें कभी भी किसी भी तरह की कोताही नहीं आयेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री, जो सरकार के, सदन के नेता के बाद में अगर सरकार की तरफ से कोई बात कहता है तो वह संसदीय कार्य मंत्री होता है। अगर संसदीय कार्य मंत्री जब खड़े होकर यह कहें कि आप बार-बार खड़े होंगे तो हम आपकी इज्जत नहीं रख पायेंगे, मैं समझता हूं कि यह ठीक बात नहीं है।

अब इनको अच्छा लगे तो ये दुबारा कर दें। अगर इनको अच्छा नहीं लगे तो इनको यह कहना चाहिए कि मेरा वक्तव्य ठीक नहीं था। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि हम जनता

के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आये हैं। जनता हमारी तरफ देख रही है। हम किसी न किसी बात को लेकर रोजाना गतिरोध पैदा करें और फिर हो-हुल्लड़ में ही हम सदन से चले जायें तो न तो हमारी गरिमा रहेगी, न हमारे सदन की यह परम्परा है।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका, चेयर का पूरा सम्मान रहेगा, लेकिन आप भी थोड़ी इनायत किया करो ना, साहब। हमारे तो आप ही हो। हमारी कौन-सा मुख्य मंत्री सुन रहा है, कौन-से मंत्री सुन रहे हैं, हमारी तो आप ही सुनते हो।

आपके माध्यम से जब बात आये तो आप इतना कर दीजिये कि मंत्री से जो सवाल पूछा गया, उसका जवाब दे दें। उस जवाब के बाद में अनर्गल बातें नहीं करें तो यह सदन सुचारु रूप से चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि वह व्यवस्था भी आप दे दें।

मैं लास्ट में कन्क्लूड करूंगा, चेयर का सम्मान है। राजस्थान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम हैं, इसके मुताबिक हम भी स्वतंत्र हैं, आप भी कार्यवाही करने में स्वतंत्र हों और सत्ता पक्ष भी इसके आधार पर कोई भी कार्यवाही कराने के लिए स्वतंत्र है। इसमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री ने हमारे नेता के प्रति जो बातें कही हैं, मैं समझता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप स्वीकार करें कि हमें यह बात इतनी नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करोगे, हम नेता का सम्मान करेंगे। हम सब मिलकर चेयर का, स्पीकर का सम्मान करेंगे। तभी संसदीय परम्पराओं का सही तरीके से निवर्हन होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ में, मैं चाहता हूं कि यह गतिरोध टूटे। जनता के मुद्दे इस सदन में आयें, चर्चा हो और सरकार की तरफ से उसके समाधान के लिए कोई बात आये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री थोड़ा सा लिबरल होकर, तरीके से, क्योंकि आप बहुत बड़े, जब नेता होते हैं तो नेता होते हैं, उसके बाद में तो आप ही होते हैं। इसलिए आपको भी इस सदन की गरिमा बनाने के लिए उसी तरीके का व्यवहार करना चाहिए, धन्यवाद।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी प्रतिपक्ष के वरिष्ठ साथी ने हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता ने जो भी वक्तव्य दिया है, उसकी सराहना की जा सकती है। उसमें कुछ गलत नहीं है।

मैं आज इस सदन में सत्ता पक्ष की ओर से, सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे लिए आपका आसन विक्रमादित्य के आसन से कम नहीं है। मैं आपको सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों की ओर से यह भी विश्वास दिलाता हूं कि हमने कभी भी आसन के किसी भी आदेश की अवहेलना करने की कोशिश नहीं की और न ही हम भविष्य में करेंगे।

जैसा कि प्रतिपक्ष के साथी ने कहा, उन्हीं शब्दों से, उसी भावना से यह आसन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। इस आसन पर जो विराजता है, वह संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत बैठता है। वह किसी राजनैतिक दल का सदस्य नहीं होता है, वह सभी का होता है। आपने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आपने कभी हमको यह महसूस नहीं होने

दिया कि आप भी कभी हमारे राजनैतिक दल के सदस्य थे। हमने भी धीरे-धीरे प्रयास किया कि अब आप हमारे राजनैतिक दल के सदस्य नहीं, एक निष्पक्ष होकर, विक्रमादित्य के आसन पर विराजमान हैं। आपका बहुत बड़ा दायित्व है।

मैं पुनः मेरे सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों की ओर से आप द्वारा आज तक अभी तक की गई निष्पक्ष, पारदर्शी व्यवस्थाओं को लेकर भी आभार व्यक्त करता है। अभी तक आपने बहुत ही बखूबी से इस विधान सभा का संचालन किया है, पूरी पारदर्शिता से, पूरी निष्पक्षता से पूरा किया है।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करूंगा कि संविधान में प्रदत्त अधिकारों और हमारी स्वच्छ परम्पराओं के अनुसार सदन के नेता के बाद, अगर हमारे लिए कोई सम्मानीय है तो नेता प्रतिपक्ष हैं। हम उन दोनों को बराबर दर्जे की दृष्टि से देखते हैं। मैंने पूर्व में भी अपने वक्तव्य में कहा था कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता बार-बार अगर खड़े हो जाते हैं तो हमारे सम्मान में थोड़ी कमी आ जाती है, लेकिन उसका कोई अदरवाइज मतलब नहीं लेंवे।

मैं आज पुनः दोहराता हूं कि हम आपका उतना ही मान, सम्मान और आदर करेंगे, जितना हमारे नेता का करते हैं या अन्य सदस्यों का भी करते हैं। आप जब भी खड़े होंगे, हमारे सत्ता पक्ष का कोई भी सदस्य आपको टोका टोकी नहीं करेगा। आपके मान-सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचायेगा।

साथ ही साथ, मेरी प्रार्थना है कि नेता प्रतिपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जानते हैं और अपने जिम्मेदारी के साथ, जब भी सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान के हित में कोई विषय होगा तो जरूर अवश्य रखेंगे, अन्यथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे नहीं रखेंगे, रखना भी चाहिए अगर राजस्थान के हित का विषय है। सत्ता पक्ष का आईना हमारा नेता होता है तो प्रतिपक्ष का आईना भी नेता, प्रतिपक्ष होता है।

माननीय अध्यक्ष जी, साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा, भविष्य में हम सब मिलकर पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर के इस सदन की गरिमा को कायम रखेंगे, इस गरिमा को आगे बढ़ायेंगे और ऐसा कोई भी कार्य, वक्तव्य या अहसास नहीं करायेंगे।

Bhs/Rtm/19.7.24/14.40/2g

जिससे लगे कि सदन में गतिरोध हो रहा है। गतिरोध को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों ने जो अपना ठीक से वक्तव्य दिया, अपना सहयोग दिया उसके लिए भी मैं उनका मेरी ओर से और सत्ता पक्ष की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि यह सदन चलना चाहिये। हमारी आठ करोड़ जनता की आवाज इस सदन में आनी चाहिये और प्रतिपक्ष के नेता जो भी प्रश्न के मार्फत है या अन्य किसी मार्फत से नियमों में आयेंगे, हमारा सत्ता पक्ष और विशेषकर हमारे मंत्री परिषद के सदस्य उनका पूर्ण रूप से तथ्यों के साथ जवाब देंगे इसमें किसी की तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, न पहले रही है, न कभी भविष्य में रहेगी। पुनः आपके प्रति, आपके आसन के प्रति हम सब सत्ता पक्ष के सदस्य पूरी नम्रता के व्यवहार के साथ आदर,

मान और सम्मान करते हैं रेस्पेक्ट करते हैं और हमारे नेता, प्रतिपक्ष के प्रति भी उतना ही हम सम्मान रखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जब सदन गठित हुआ और अध्यक्ष का चुनाव हुआ, आप सब लोगों ने जिस रूप में भावनाएं व्यक्त की थी वे मन को प्रफुल्लित करने वाली थी कि सबका विश्वास है इस आधार पर मैंने यह दायित्व किया। मैं कभी भी किसी पद के पीछे नहीं रहा चाहे मंत्री था, चाहे विधायक था, मेरी कभी राजनीति में रुचि भी नहीं थी लेकिन राजनीति में आया और सबकी सेवा करने का मौका मिला और जिस रूप में यहां पर दोनों पक्षों को मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं जब कॉपी जांचता हूं तब किसी का बाहर रोल नम्बर या नाम नहीं होता। निष्पक्ष रूप से जो उसने लिखा है उसके आधार पर अंक देता हूं। यही मैंने व्यवहार में लाने का प्रयास किया और अभी भी आपने जो भावनाएं व्यक्त कीं, मुझे आज भी इधर वाले कहते हैं कि आप इनका पक्ष लेते हो, इधर वाले कहते हैं कि इनका। यह स्वाभाविक है। यह चीज घर में कोई बेटा होता है तो बड़ा बेटा कहता है कि आप छोटे का ज्यादा ध्यान रखते हो और बड़ा कहता है कि आप बड़े की ज्यादा बात मानते हो। यह एक स्वाभाविक है परिवार में तो मैंने कोशिश की कि सबको साथ लेकर चलें। बीच में दो-तीन बार गतिरोध भी आया उसको भी बुला करके मैंने सबसे कहा लेकिन एक मेरा कहना आवश्यक है कि जो 269 अपन देखते हैं, आप सब भी इधर से विपक्ष के नेता और वरिष्ठ लोग और इधर भी संसदीय मंत्री और बाकी मंत्री लोग, माननीय सदस्यों को यह पूरी जानकारी दें कि यह सदन है, गरिमा है, कोई आता है तो हमको उठ कर खड़ा होना पड़ता है। कोई आते हैं तो किसी के आगे से नहीं निकलते हैं। छोटी-छोटी बातें मुझे बार-बार दोहरानी नहीं पड़े। जब कभी कोई नेता भाषण कर रहा हो तो बीच में नहीं टोकते। विपक्ष का नेता कह रहा हो तो इधर के नहीं टोकें लेकिन मुझे ध्यान है कि जब कभी बात होती है तो फिर वित्त मंत्री भी बोलते हैं तो बीच में नहीं करते हैं, लेकिन इस बार चाहे इधर के हों चाहे इधर के हों बीच में जो बात हो रही थी वह उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। आप और हम सबको आठ करोड़ जनता देखती है और उस समय हम यदि सदन का, दायित्य का, पद का सम्मान नहीं करेंगे तो घर में बच्चे भी हमारा सम्मान नहीं करेंगे इसलिए आप सबसे मैं अपील करता हूं कि हम सब एक दूसरे का सम्मान करें। हम सब सदस्य हैं आखिर चुन करके आये हैं लेकिन यदि हम बड़े का सम्मान नहीं रखेंगे, दायित्वों का सम्मान नहीं रखेंगे फिर मैं समझता हूं कि अपन फिर जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते तो आज जो कुछ हुआ उसमें निश्चित रूप से अपन सोचें कि इन बातों को अपन भूल करके आगे के लिए एक नया इतिहास रचें और नयी व्यवस्थाएं करें तो मेरी आप सबसे अपील है कि सदन की मर्यादा को रखते हुए और जो कुछ भी परम्पराएं, मर्यादाएं हैं मान लो कोई बात भी होती है तो कमरे में आकर के कर लें। कल भी मैंने आग्रह किया था कि आप मेरे कमरे में आ जाएं दोनों मिल करके जो भी असंसदीय होगा, असंवैधानिक होगा, अमर्यादित होगा

उसको निश्चित रूप से पहले भी करते आये हैं, अब भी कर लेंगे। आज भी मैंने ये तीनों जो आपने किया श्री अविनाश गहलोत, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में जो कुछ लाइनें कही, विपक्ष के नेता ने भी जो कुछ बातें +++ आदि मैं शब्दों को रिपीट नहीं करता, श्री हरीश चौधरी जी की कोई कविता इन तीनों को मैं अपनी आपत्ति के आधार पर कार्यवाही से निकाल रहा हूं।

अब मैं सोचता हूं कि इस में बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। सदन की कार्यवाही, आज पहले ही काफी भाषण हैं।

सबसे पहले सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा।

सदन पटल पर रखे गए पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम, 2012 की धारा-42 के अन्तर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री कृष्ण कुमार के.के. विश्नोई।

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड

का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

श्री कृष्ण कुमार के. के. विश्नोई (राज्य मंत्री, उद्योग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री गजेन्द्र सिंह।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की प्रस्तुति

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,18,18,31,78,000/- (एक खरब अठारह अरब अठारह करोड़ इकत्तीस लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 27 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28 चिकित्सा शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 54,55,03,08,000/- (चौवन अरब पचपन करोड़ तीन लाख आठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 28 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यों से एक निवेदन है कि आपके सचेतकों ने जो सूची दी है वह लम्बी है। उस पर आप पुनर्विचार करके फाइनल बता दें क्योंकि सदन कब तक चलाना है यह सदन को तय करना है लेकिन अभी बहुत बड़ी सूची है। इधर से तो हैं लगभग 24 नाम विपक्ष के और 17 नाम पक्ष के तो कुल 41 हैं और यदि प्रारम्भिक मिनट अधिक गिनेंगे तो आप देखो कम से कम यह रात के 11-12 बजे तक चर्चा होगी इसलिये पुनर्विचार करके मुझे बता दें लेकिन जिसके लिए जितना समय अलॉटेड है उतने समय में अपने को करें, कोई बढ़ाने की व्यवस्था न करें। पहले और दूसरे के लिए तो इन्होंने कुछ मिनट तय किये हैं ओपनर के, बाकियों के लिए दस-दस मिनट हैं कोई भी ग्यारह मिनट तक न जाये और वहीं अपना वक्तव्य समाप्त करे। ऐसा मेरा सबसे निवेदन है।

श्री कालीचरण सराफ।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष: आप सचेतक से बात कर लें।

मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व

मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा पर विचार

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा पर विचार-विमर्श हो रहा है। मैं भी इन दोनों मांगों पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और उप मुख्य मंत्री वित्त मंत्री का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान के इतिहास में पहली बार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 27 हजार 760 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। पूरे बजट का 8.26 प्रतिशत केवल चिकित्सा और स्वास्थ्य पर खर्च होगा जो पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल के यदि औसत खर्च में माना जाये तो 1.5 प्रतिशत ज्यादा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जैसे आम जनता के जीवन से जुड़े हुए संवेदनशील विषय पर भी विपक्ष द्वारा जनता को यह कह कर गुमराह किया जा रहा है कि हमारे द्वारा चलाये जा रही स्वास्थ्य योजनाओं को बन्द किया जा रहा है तो मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि पूर्ववर्ती सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य

बीमा योजना जो 1 मई, 2021 में लागू की गई थी अब मुख्य मंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से संचालित की जा रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने जो पच्चीस लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज इसके लिए उपलब्ध करवाया था, वर्तमान में भी यह सुविधा जारी है। हैल्थ फोर ऑल के सिद्धान्त पर काम करते हुए स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को और अधिक बेहतर किया जा रहा है।

मुख्य मंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में जो पहले केन्सर जैसी गम्भीर बीमारियों के इलाज के लिए आईपीडी के साथ-साथ डे केयर पैकेज नहीं था, वह हमने जोड़ा है। बच्चों के लिए पीडियाट्रिक पैकेज और अन्य पैकेजेज का भी रेशनलाइजेशन इस बजट के माध्यम से किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, और अब तो हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति ने संसद में अपने भाषण में भी कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ देश के सभी 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिलेगा।

(समयः बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

Kas/rtm/19.07.2024/14.50/2h

माननीय सभापति महोदय, 'मुख्यमंत्री महोदय वाउचर योजना' के माध्यम से गर्भवती महिलाएं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सोनोग्राफी मुफ्त करा सकेंगी, इस प्रकार की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत जिन सरकारी अस्पतालों में किसी कारणवश गर्भवती महिलाओं की सोनाग्राफी नहीं हो पाती, उन अस्पतालों में चिकित्सक के माध्यम से महिलाओं को वाउचर दिया जायेगा। इस वाउचर के माध्यम से वे सरकार से अनुबंधित निजी अस्पतालों में सोनोग्राफी करा सकेंगी। सरकार निजी अस्पतालों को उसका भुगतान करेगी।

इसी प्रकार पूर्ववर्ती सरकार की 'चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना' का नाम बदल कर 'मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना' होगा। इस योजना में बीमा कवर 10 लाख तक का होगा और इस योजना का आकार बढ़ाकर प्रदेश की पांचों बिजली कंपनियों को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा कृषि कार्य के दौरान हुए एक्सीडेंट को भी इस योजना में शामिल करने का काम हमारे मुख्य मंत्री जी ने किया है, इसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने प्रदेश के किन्ही अस्पतालों में जेरिएट्रिक वार्ड रामाश्रय के नाम से खोलने का निर्णय किया है। इससे प्रदेश के बुजुर्गों को अलग से वार्ड की सुविधा मिलेगी और उनका बेहतर उपचार हो पायेगा। माननीय सभापति महोदय, इसके लिये भी मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं सरकार को इस बात के लिये भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि गत तीन वर्षों में जयपुर में पूर्ववर्ती सरकार के समय जो फर्जी अंग प्रत्यारोपण का खेल चल रहा था, गत तीन वर्षों में 2000 से ज्यादा फर्जी एन.ओ.सी. जारी

की गईं। 1000 से ज्यादा फर्जी किडनी ट्रांसप्लांट की गईं। तीन साल से आर्गन ट्रांसप्लांट कमेटी की बैठक ही नहीं हुई। बड़े पैमान पर हुए भ्रष्टाचार पर पूर्ववर्ती सरकार आँख मूंद कर बैठी रही और कोई भी कार्यवाही नहीं की। परंतु जैसे ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनी, इस कांड का भंडाफोड़ हुआ। सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए तुरंत जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारियां कीं। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को बर्खास्त किया और इस्तीफ़े लिये गये। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिये एस.आई.टी. का गठन कर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने के आदेश उन्होंने दिये। इसी प्रकार जे.के.लोन हॉस्पिटल में प्लाज्मा चोरी का मामला सामने आया, उस पर भी तुरंत एक्शन लिया गया और जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की गई।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में आजादी के बाद 2013 तक केवल सात मेडिकल कालेज थे। यह जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और झालावाड़ में थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि 2014 में मोदी जी जब इस देश के प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने इस लक्ष्य के साथ 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास', यह घोषणा की कि हमारे देश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होने चाहिये। उसके प्रथम चरण में 2013-18 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने 8 मेडिकल कॉलेज हमारे प्रदेश को आवंटित किये। इसी प्रकार 2018-23 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के उन्होंने 15 मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की और 3000 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार ने इसके लिये आवंटित किया। परंतु जैसा कि हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी की आदत है कि वह हर चीज में राजनीति करना चाहते हैं, उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि हमारे बार-बार आग्रह के बाद भी तीन जिले, प्रतापगढ़, जालोर और राजसमन्द, बच गये, उनमें मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार ने नहीं दी। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि मैं इन तीनों जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूं और इसके लिये 1000 करोड़ रुपये बजट से आवंटित करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं पूर्व मुख्य मंत्री जी से, जो यहां नहीं हैं, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन 1000 करोड़ रुपये का क्या हुआ? क्या बिना बजटीय प्रावधान के उन्होंने 1000 करोड़ रुपये की घोषणा की थी? क्या असत्य वाह-वाही लेने के लिये उन्होंने घोषणा की थी? आज यदि हम धरातल पर जाकर देखें तो चाहे जालोर हो, राजसमन्द या प्रतापगढ़ हो, कहीं पर भी मेडिकल कॉलेज खोले जाने की कोई सुगबुगाहट नहीं है। केवल फर्जी घोषणा, असत्य वाह-वाही लेने के लिये, चुनाव में वोट लेने के लिये उन्होंने इस प्रकार की बात की। क्या हुआ, क्या इन तीनों जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गये? इतना ही नहीं, नये मेडिकल कॉलेज तो खोल दिये, परंतु राजमेस की 16 मेडिकल कॉलेजों में 62 प्रतिशत पद रिक्त हैं। चूंकि केन्द्रीय सरकार का 3000 करोड़ रुपये आया था तो आपने मेडिकल कॉलेज तो खोल दिये, परंतु वहां पर डाक्टर नहीं, नर्सिंग कर्मी नहीं, पेरामेडिकल स्टाफ नहीं, लैब असिस्टेंट नहीं, फार्मासिस्ट नहीं, 62 परसेंट पद रिक्त।

ऐसे में भविष्य में डाक्टर्स की क्वालिटी शिक्षा का क्या होगा, इसका उन्होंने ध्यान नहीं रखा। आप देखिए, 1896 स्वीकृत पदों में से केवल 725 काम कर रहे हैं, 1171 पद खाली हैं। ऐसे में नेशनल मेडिकल काउंसिल की ओर से मान्यता पर संकट आने का भी अंदेशा था। पूर्ववर्ती सरकार ने केन्द्रीय सरकार की राशि से कॉलेज तो खोल दिये, परंतु स्टाफ नहीं लगाया। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को फिर धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहां मेडिकल काउंसिल के प्रतिनिधि आये, उन्होंने पांच मेडिकल कॉलेज, झुंझुनूं, सवाईमाधोपुर, नागौर और बांसवाड़ा को मान्यता दिये जाने पर अडंगा लगा दिया, परंतु हमारे संवेदनशील मुख्य मंत्री जी ने उसी समय 625 पद, 125 पद एक-एक महाविद्यालय के लिये आवंटित कर दिये। इसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, नर्सिंग कर्मी, पेरामेडिकल स्टाफ, सबकी इन्होंने व्यवस्था की। हमारे मुख्य मंत्री जी की संवेदनशीलता के कारण आज वह पांच मेडिकल कॉलेज मान्यता से वंचित रहने से बच गये। माननीय सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से यह भी चाहूंगा कि जब आप अपना जवाब दें तो जो बाकी पद खाली हैं, उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है, इस बारे में भी आप निश्चित रूप से बतायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में डाक्टर्स, नर्सेज, पेरामेडिकल स्टाफ का जहां तक सवाल है, प्रदेश में 43 हजार डाक्टर्स अभी पंजीकृत हैं और लगभग 1700 लोगों पर एक डाक्टर है। सरकारी अस्पतालों में 11 हजार पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में 9 हजार डाक्टर्स कार्यरत हैं। 2000 डाक्टर्स के पद रिक्त हैं। 34 हजार डाक्टर्स निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। बजट में सरकार ने 1500 डाक्टर्स और 4000 नर्सिंग कर्मियों के नवीन पदों के सृजन की घोषणा की है। राजमेस के अंतर्गत राज्य सरकार के नियमों को इसमें अडॉप्ट किया जायेगा, इसका भी मैं बहुत-बहुत स्वागत करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में करीब 3 हजार छोटे-बड़े सरकारी अस्पताल 2500 छोटे जिलों या दूर-दराज के गांवों में स्थित हैं, जहां करीब 75 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मी, चाहे वह डाक्टर्स हों, चाहे नर्सिंग कर्मी हों, चाहे पेरामेडिकल स्टाफ के लोग हों, उनकी पोस्टिंग इन स्थानों पर होती है।

msk/rtm/19.07.2024/1500/2j

परन्तु हम वहां जो भी पोस्टिंग करते हैं, वह वहां जाना नहीं चाहता है। राजनीतिक रसूखों के चलते वे शहरों में डेपूटेशन पर लग जाते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि दूरदराज के गांवों में जो लोग रहते हैं, उनमें से यदि कोई बीमार हो जाता है तो या तो जिला अस्पताल में आकर अपनी बीमारी का इलाज करवाता है या संभागीय केन्द्र पर आकर अपना इलाज करवाता है और कोई गंभीर बीमारी होती है तो जयपुर में आकर वह अपना इलाज करवाता है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, नये डॉक्टर्स की नियुक्ति करने के समय यह देखा जाये कि जो डॉक्टर नियुक्त

होता है, उसके लिए कम से 25 लाख और 50 लाख का आप बॉन्ड भरवायें और उसको यह पाबन्द करें कि पहली पोस्टिंग पांच साल के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में होगी। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा और मैंने अभी अखबारों में भी पढ़ा है, सरकार की मंशा है कि डॉक्टर्स, नर्सिंग, स्टाफ और पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए आप ट्रांसफर पॉलिसी पर विचार कर रहे हैं। मैं तो यह मांग करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं सफलतापूर्वक चले, हर व्यक्ति को इलाज मिले। जो दूरदराज के क्षेत्रों में रहता है, उसको भी इलाज मुहैया हो, इसके लिए आप यह घोषणा करें कि हम स्थानान्तरण की नीति लायेंगे। जो नया डॉक्टर नियुक्त होगा, उसको निश्चित रूप से दूरदराज के गांवों में पांच साल तक जैसे जालौर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ है, ऐसे स्थानों पर जाकर वे ड्यूटी करेंगे।

इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज बड़ा उलटा हो रहा है। जो डॉक्टर नौकरी करता है, जिसकी शहरों में पोस्टिंग होती है, उसको आप शहरी भत्ता देते हैं, मकान किराया देते हैं, मैं कह रहा हूं कि उनका शहरी भत्ता और मकान किराया बन्द करिये। इसकी जगह जो दूरदराज के गांवों में रहकर जो गरीबों का इलाज करते हैं, उनको आप 15-20 परसेंट अतिरिक्त दीजिये, तनख्वाह के अलावा। मान लीजिये किसी की 1 लाख की तनख्वाह है तो उसको 1 लाख 20 हजार दीजिये, किसी की 1 लाख तनख्वाह है तो उसको 1 लाख 15 हजार दीजिये, तो वह गांवों में टिकेगा। कई डॉक्टर मित्रों से हमारी बात होती है तो वे यह कहते हैं कि हम डॉक्टर बन गये, यदि हमारी गांव में ड्यूटी लग जायेगी तो हमारे बच्चों का क्या होगा? तो मैं यह भी कहना चाहूंगा कि संभागीय केन्द्र पर, जयपुर की राजधानी पर जो बढ़िया स्कूल हैं, उनमें उन डॉक्टर्स के बच्चों का प्राथमिकता के आधार पर एडमिशन हो, इसको भी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, तो डॉक्टर मन लगाकर दूरदराज के गांवों में काम कर पायेगा।

जयपुर शहर में उत्तर भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, एसएमएस हास्पिटल, वहां 10 हजार से ज्यादा का ओपीडी है। जब हमारी सरकार 2013 से 2018 के बीच में आयी थी तो उस समय हमने एसएमएस हॉस्पिटल का भार कम करने के लिए जयपुर के पश्चिम में कांवटियां हॉस्पिटल, जयपुर के उत्तर में गणगौरी हॉस्पिटल, जयपुर के पूर्व में सैटेलाइट हॉस्पिटल, सेठी कॉलोनी और जयपुर के दक्षिण में जयपुरिया हॉस्पिटल, इन चारों को डवलप करने का निर्णय किया था। उसी का यह परिणाम था कि जो सुविधाएं हमने वहां पर मुहैया करायीं, कांवटिया हॉस्पिटल में जो 2 हजार का ओपीडी थी, वह 4 हजार हो गया। गणगौरी हॉस्पिटल में हमने जो सुविधाएं उपलब्ध करायीं, उसका परिणाम यह रहा कि जहां 500 का ओपीडी था, वह 2 हजार का ओपीडी हो गया। इसी प्रकार से सेठी कॉलोनी के हॉस्पिटल में भी ओपीडी की संख्या बढ़ी। विशेषकर जयपुर में जयपुरिया हॉस्पिटल, जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है, वहां आप देखिये कि केवल 300-350 का ओपीडी था, हमने वहां सी.टी. स्कैन की सुविधा करायी, एमआरआई की सुविधा करायी, 2डी ईको की सुविधा करवायी, टीएमटी की सुविधा करवायी, एसएनसीओ का वार्ड बनवाया, ट्रोमा वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, नये

मेडिकल कॉलेज और टाटा ट्रस्ट द्वारा टीआईसीयू कोटेज वार्ड आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवायीं। उसका परिणाम क्या हुआ कि जहां 2013 में हमारा 300 से 350 का ओपीडी था, वह बढ़कर साढ़े तीन हजार - चार हजार का हो गया। पहले 100 बेड थे, उसकी जगह 150 बेड हुए। 2013 में 100 बेड थे, 2015 में 150 बेड हुए और 2017 में 470 बेड हो गये। वहां आप देखिये कि प्रतिमाह 400-500 लोगों की सर्जरी हो रही थी। महिलाओं की 250-300 की संख्या में प्रति माह डिलीवरियां हो रही थीं। जो वहां भर्ती होते थे, उनकी ऑक्यूपेंसी 95 परसेंट थी। परन्तु, क्योंकि राजनीतिक भेदभाव, वहां से भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, राज कांग्रेस का था। हमारे तत्कालीन चिकित्सा मंत्री ने एक साथ, वहां 27 डॉक्टर लगे थे, अधिशेष और 11 डॉक्टर डेपूटेशन पर थे। जब 100 बेड थे, उस समय भी 48 डॉक्टरों के पद स्वीकृत थे। 470 बेड हुए, 48 डॉक्टर वहां थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 27 और 11, इन डॉक्टरों को हटा दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? यह 03.09.2022 को यह आदेश निकाला। इसका परिणाम क्या हुआ कि एनएनसीयू, ट्रोमा वार्ड, एमआरआई, सीटी स्कैन, इमरजेंसी, नये वार्ड बनाये गये, डॉक्टर और स्टाफ की कमी के कारण उनका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार टाटा ट्रस्ट द्वारा जो पीआईसीयू एवं नये वार्ड, डॉक्टर्स एवं स्टाफ की कमी के कारण कार्यशील नहीं हो पा रहे थे। चिकित्सालय में ओल्ड मेडिकल आईसीयू और सर्जिकल आईसीयू कोटेज बन्द पड़े हैं। माननीय सभापति महोदय, यह जयपुर दक्षिण का एकमात्र चिकित्सालय है। इसमें केवल मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र के ही नहीं, इसके साथ-साथ जगतपुरा, सांगानेर, चाकसू, बगरू और टोंक क्षेत्र के भी गंभीर मरीज यहां इलाज कराने के लिए आते हैं। अत: मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहां जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिंग स्टॉफ है, वहां जिस प्रकार से बेड बढ़े हैं, जिस प्रकार से आउटडोर की संख्या बढ़ी है, जिस प्रकार से वहां पर इंटरनल ऑक्यूपेंसी 95 परसेंट हुई, उसी के अनुरूप आप वहां डॉक्टर्स की नियुक्तियां करें, नर्सिंग स्टॉफ की नियुक्ति करें, पैरा मैडिकल स्टॉफ की नियुक्ति करें, तो यह हमारे दक्षिण में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा।

जहां तक हमारे बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जे.के.लोन हॉस्पिटल, इसमें पूरे जयपुर के ही नहीं, पूरे राजस्थान के ही नहीं, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, वहां के लोग आकर वहां अपना इलाज करवाते हैं। वहां केवल 900 बेड हैं। आप यह देखिये कि यदि हम उसके आउटडोर की गणना करें तो पूरे साल में 4 लाख 25 हजार का आउटडोर है। भर्ती की बात करें तो 50 हजार से ज्यादा बच्चे वहां साल भर में भर्ती होते हैं। जब मौसमी बीमारियां होती हैं, उस समय तो स्थिति यह हो जाती है कि वहां एक-एक बेड पर तीन-तीन, चार-चार बच्चों को सुलाना पड़ता है, उनका इलाज कराने के लिए। मैं इस बात के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने वहां 22 करोड़ रुपये की लागत से Centre of Excellence for Medical Genetics की घोषणा इस बजट में की है। इसके लिए तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

mdp/rtm/19.07.2024/15:10/2k

अब सरकार के इस निर्णय से वहां दुर्लभ बीमारियों के साथ-साथ जिन्दगी की जंग लड़ रहे नौनिहालों को भी इलाज मिल पायेगा।

इसके साथ ही मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने 1100 करोड़ रुपये, एसएमएस अस्पताल में आईपीडी टॉवर बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किये, जिसमें 70 परसेंट पैसा केन्द्रीय सरकार का था। जनाना अस्पताल में 75 करोड़ आवंटित किए, महिला चिकित्सालय में 117 करोड़ रुपये आवंटित किये, गणगौरी अस्पताल में 108 करोड़ रुपये आवंटित किये, टीबी अस्पताल में 50 करोड़ रुपये आवंटित किये और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 250 करोड़ रुपये किये, परंतु जे.के.लोन, क्योंकि ये मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में है, यहां एक ही नया पैसा इसके लिए आवंटित नहीं किया।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि हमने इसका पूरा एस्टीमेट बनवा लिया है। 80 करोड़ रुपये की लागत से, मैं समय पर ही खतम करूंगा, आप घड़ी मत देखिए, 80 करोड़ की लागत से इसका आईपीडी टॉवर दस मंजिल का बनेगा। इसमें कांफ्रेस हॉल भी होगा, ये मेडिकल कॉलेज से संलग्न है, इसलिए यहां पर पीजी व यूजी के स्टूडेंट्स भी आते हैं। कांफ्रेस हॉल भी इसमें चाहिए, कैंटीन भी चाहिए। बच्चों की कैपेसिटी के लिए 900 बेड है, उसकी जगह कम से कम 1500 बेड इसमें होने चाहिए। इसके लिए हम आपसे जगह भी नहीं मांग रहे हैं, जगह भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। आप तो जिस प्रकार बाकी हास्पिट्ल्स में आपने आईपीडी टॉवर बनाने के लिए पैसा आवंटित पिछली सरकार ने किया, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जे.के.लोन हास्पिटल, जो हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल है, उसमें आप निश्चित रूप से आईपीडी टॉवर बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान करें तो ये वहां के लोगों के लिए और प्रदेश के लिए बहुत ही अच्छा होगा।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपको आरयूएचएस हास्पिटल के बारे में बताना चाहूंगा। वसुन्धरा जी जब राजस्थान की मुख्य मंत्री थी, उस समय राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सहयोग से आरयूएचएस हॉस्पिटल का निर्माण करवाया और आपको यह जानकर खुशी होगी कि उसमें 1200 बेड की कैपेसिटी है, 200 बेड आईसीयू के लिए रिजर्व हैं। जब कोरोना काल आया था तो वहां के डाक्टर्स ने बड़ा शानदार काम किया, नहीं तो पता नहीं कितनी जानें जाती। चूंकि वह स्थान हमारे पास उपलब्ध था, वहां पूरे प्रदेश से जितने भी कोरोना के मरीज आए, उनका शानदार तरीके से वहां पर इलाज करवाया गया। इतना ही नहीं, उस समय मैं भी वहां भर्ती था। हमारे तत्कालीन चिकित्सा मंत्री थे रघु शर्मा जी, उनके भी जब कोरोना हुआ तो वे भी वही भर्ती थे। वह भी वहां पर इलाज से ठीक हुए और मैं भी इलाज से ठीक हुआ। आज स्थिति क्या है? क्योंकि ये वसुन्धरा जी के समय बना था, इसलिए पूर्ववर्ती सरकार ने वहां किसी भी प्रकार के फैकल्टी को नोमिनेट करने का काम नहीं किया। उसकी उपेक्षा की। अभी आपने वहां 25-30 डाक्टर लगाये हैं, परंतु मैं आपको कहना

चाहूंगा कि 1200 बेड की कैपेसिटी का हास्पिटल और वह फुल-फ्लेज्ड यदि चलेगा, वहां पर डाक्टर्स का अपाइंटमेंट होगा, नर्सिंग स्टॉफ यदि वहां लगेगा, पैरा मेडिकल स्टॉफ लगेगा तो आपके एसएमएस हास्पिटल का भार निश्चित रूप से कम होगा। इसकी तरफ भी आप ध्यान दें।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हमारे पूर्व मुख्य मंत्री मोहन लाल जी सुखाड़िया, उनके नाम से उदयपुर यूनिवर्सिटी का नाम हमने मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कर दिया। पूर्व मुख्य मंत्री हरिदेव जी जोशी, पत्रकारिता यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम से कर दिया। मैं यह चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के तीन बार मुख्य मंत्री रहे और हमारे देश के उप राष्ट्रपति रहे आदरणीय भैरोसिंह जी के नाम से आपका आरयूएचएस हास्पिटल है, आरयूएचएस यूनिवर्सिटी है, उसका नाम यदि आप भैरोसिंह शेखावत यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ एंड साइंसेज कर देंगे तो हमारे पूरे प्रदेश की जनता आपकी वाह-वाही करेगी। बंधुओं, आप देखिए की (समय सूचक घंटी) आरयूएचएस का हास्पिटल पूरे प्रदेश में, हर जिले में।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, समय हो गया है। एक घंटा है हमारा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक मिनट बोलूंगा। आरयूएचएस के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वह एफिलेटेड हैं। नर्सिंग कॉलेज आप हर डिस्ट्रिक्ट में खोलने का एलान कर चुके, वह भी हो जाएगा। आज भी सरकारी फार्मेसी कॉलेज नहीं है। मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब आप जिला स्तर पर नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं, जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं तो कम से कम हर संभागीय स्तर पर यदि फार्मेसी कॉलेज होगा तो जो बच्चे आज निजी महाविद्यालयों में जाते हैं, वहां उनकी फीस भी ज्यादा और जिस प्रकार से उनका शोषण होता है, वह नहीं होगा। मैं मांग करना चाहूंगा कि हर संभागीय स्तर पर आप कम से कम एक-एक फार्मेसी कॉलेज खोलें।

आपने आदेश दिया कि मेरा समय पूरा हो गया। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आशा करूंगा कि आदरणीय मंत्री जी जब जवाब देंगे तो जो मैंने सुझाव दिए हैं, उस पर अमल करेंगे। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापतिः डॉक्टर शिखा मील बराला।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): सदन को नमस्कार। ...(व्यवधान)... सभापति महोदय।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आपके आज 40 वक्ता हैं और हमारा एक घंटा स्थगित होने से समय सबका कटौती करने के लिए नेता, प्रतिपक्ष को भी दिया सत्ता पक्ष को भी दिया है। आप समय पर छोड़ देंगे तो देर रात रुकना नहीं पड़ेगा। आपके हाथ में है। माननीय सदस्य।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे स्वास्थ्य, चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा की अनुदान मांगों पर मेरे विचार रखने का मौका दिया। 'पहला सुख निरोगी काया' तो मैं शुरूआत करना चाहूंगी कांग्रेस सरकार के उन लैंडमार्क निर्णयों से, देश में पहली बार कांग्रेस सरकार द्वारा 25 लाख रुपये की कैशलेस

यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज की योजना लागू की गयी। साकार किया गया वह सपना की आखिरी छोर तक खड़े व्यक्ति को महंगे अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके। इसी के माध्यम से हैल्थ केयर एक्सेस में अंतर कम हुआ और मेडिकल ट्रेजेडी के सबसे बड़े भुक्तभोगी गरीब और वंचित लोगों को कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा मिल सके। एक दौर था जब पैसे के अभाव में इलाज का अभाव था, बीमार परिजनों को मजबूरी में भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता था, परंतु इसी दौर में चिरंजीवी योजना के राजस्थान मॉडल ने अपने आप में एक मिसाल पेश की।

हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने चिरंजीवी योजना में 5 हजार करोड़ रुपये तक का इलाज 50 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचाया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि 25 लाख का इलाज कितने लोगों को मिला? असंवेदनशीलता देखिए कि वह देखना चाहते हैं कि कितने लोगों को नौबत आती है 25 लाख के इलाज की। यह तो मात्र एक सेफ्टी नेट है कि परिवार मेंटली सिक्योर रहे कि हमें अगर कोई परिस्थिति आती है तो जमीन न बेचनी पड़े, घर न बेचाना पड़े। मुख्य मंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के कारण राजस्थान में इंश्योरेंस कवर 93 परसेंट तक पहुंचा जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 42 परसेंट है। पिछले पांच साल में राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में बेड 560 परसेंट तक बढ़े और ऑक्सीजन आईसीयू बेड्स की संख्या लगभग तीन गुना बढ़ी। पोषण को बढ़ावा देने के लिए स्कूल में मिड-डे-मील में बाल गोपाल योजना के तहत दूध उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2015-16 में लिंगानुपात, जो 929 था, वर्ष 2022-23 में बढ़कर 947 हुआ।

इसके साथ ही हमारी सरकार ने आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी पर भी पूरा ध्यान दिया। यही कांग्रेस सरकार थी 2012 में जिसने गर्भवती बहिनों के लिए 104 एम्बुलेंस चला कर मातृ मत्यु दर सुधारने की दिशा में एक बड़ा काम किया। चिरंजीवी योजना, मौजूदा सरकार ने बनते ही 19 फरवरी, 2024 को एक आदेश निकाला जिसमें इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। इसका नाम मां योजना रख दिया गया। कुछ देर पहले हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि ईआरसीपी योजना का नाम मोदी योजना क्यों नहीं रख देते?

Ans/rtm 15.20 2l 19.07.2024

या तो यह किया जाए कि साढ़े चार साल तक आप लोग नामकरण संस्कार कर ले और काम हम साढ़े चार साल बाद, सत्ता में आने के बाद कर लेंगे।

बजट में उल्लेख है कि कैंसर के लिए डे केयर पैकेजेज दिए गए हैं। जबकि 73 पैकेजेज जो पहले से एग्जिस्ट करते थे, करीब-करीब सेम थे, उनको डे केयर पैकेजेज का नाम दे दिया गया। बजट में कहीं भी उल्लेख नहीं था, किसी भी सक्षम पदाधिकारी ने, सक्षम अधिकारी ने, सक्षम मंत्री ने, कभी भी यह उल्लेख नहीं किया कि चिरंजीवी योजना में 5 लाख या 25 लाख का कवरेज दिया जाएगा और 10 लाख दुर्घटना बीमा योजना को जारी रखा जाएगा या नहीं। हालांकि कल रात सरकार ने इसे आदेश निकालकर क्लियर कर दिया।

दुखद दृश्य यह है, पिछली सरकार का भी शायद का भी और मौजूदा सरकार का भी कि गर्भवती महिलाओं को प्राइवेट हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना के अन्तर्गत इलाज से महरूम रखा जा रहा है। मेरी मांग है, मेरा सुझाव है कि प्रसव पैकेजेज को प्राइवेट सेक्टर में लाया जाए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। यह एमएमआर और एनएमआर घटाने की दिशा में कारगर प्रयास होगा। मैं अगर सिर्फ चोमू सीएचसी जो अब एसजीएस में बदला गया है, उसकी बात करती हूं तो जनवरी माह में 310 नोरमल डिलीवरी हुई और 6 सिजेरियन हुए, जून में 210 नोरमल डिलीवरी हुई और 2 सिजेरियन हुए, इसका मतलब यह नहीं कि सरकारी अस्पताल में सभी नोरमल डिलीवरी होती है। कहीं ना कहीं ऑपरेशन की समुचित व्यवस्था ना होते हुए या इच्छाशक्ति का अभाव होते हुए ऐसे मरीजों को जिन्हें ऑपरेशन की जरूरत होती है, उन्हें रेफर कर दिया जाता है। क़स्बे से वह मरीज कहां जाएंगा, या तो चोमू से वह जयपुर सरकारी अस्पताल में आएगा। मरीज के परिजन घबरा जाते हैं, वह आस पास कोई प्राइवेट अस्पताल देखेंगे जहां ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध हो। ऐसे में अल्टीमेटली भार उसी गरीब की जेब पर पड़ता है। मेरा एक यह भी सुझाव है कि बच्चों के टीकाकरण को प्राइवेट सेक्टर में जोड़ा जाए।

बात करे भयावह कोरोना की। कांग्रेस सरकार ने कैपेसिटी बिल्डिंग का एक बेहतरीन मॉटल पेश किया, उस भीलवाड़ा मॉडल को डब्ल्यूएचओ ने भी सराहा था। हीटवेव में हमारी सरकार, मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं इसमें फेल होती दिखाई दी। निपटने के लिए पर्याप्त प्लानिंग की कमी थी। मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगी कि सदन की पटल पर रखा जाए कि ज़िलावार हीटवेव में कितने लोगों की मृत्यु हुई। बजट में कहीं भी उल्लेख नहीं कि ऐसी कंटिंजेंसी में कैपेसिटी बिल्डिंग का सरकार के पास आगे के लिए क्या प्लान है।

बात अगर मॉडल सीएचसीज की करें, तो इसे कुछ लोगों ने कहा कि यह मास्टर स्ट्रोक है। मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मौजूदा सरकार द्वारा पूर्ववर्ती सरकार की पहल पर ही मुहर लगाई जा रही है। 25 अप्रैल, 2022 को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें विधान सभावार माडल सीएचसीज बनाने का आदेश था। गेप एनालिसिस के आदेश दिए गए। गेप फिलिंग की रिपोर्ट भी आई और आगे उस पर कार्यवाही की गई। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि गेप फिलिंग की कहां-कहां, क्या-क्या कार्यवाही हुई और एमएलए लेड से कहां-कहां कितनी राशि इस पर व्यय की गई, उसका ब्यौरा सदन की पटल पर रखा जाए।

मेडिकल एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो राजमेस कॉलेजेज जो फैकल्टी के अभाव से जूझ रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक्सपीरियंस मेडिकल टीचर्स ना होते हुए, क्या हम खाक स्किल डॉक्टर्स तैयार कर पाएंगे? छात्रों का भविष्य और जनता का स्वास्थ्य, दोनों के साथ यहां खिलवाड़ किया जा रहा है। फैकल्टी इसलिए नहीं आना चाह रही क्योंकि उन्हें पे प्रोटेक्शन में कवर नहीं किया जा रहा। हालांकि 15 जुलाई को आदेश निकाला गया है कि 1 अगस्त,

2024 के बाद ज्वाइन करने वाले डॉक्टर्स को राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 के अन्तर्गत प्रावधानों में लगाया जाएगा। उससे पहले के डॉक्टर्स को डाइन कैडर में रखा जाएगा। अपने आप में ही डाइन कैडर है। जो 750 डॉक्टर्स है, असिसटेंट प्रोफेसर, एसोसियट प्रोफेसर के पद तक पहुंच चुके हैं, क्या उन्हें फ्रेश अपॉन्टमेंट करने पड़ेगे और अपने जूनियर डॉक्टर्स के साथ काम करना पड़ेगा? मेरी गुजारिश है, मेरा सुझाव है कि इन सभी डॉक्टर्स को, इनका मान वर्धन करते हुए, इसी नियम के अन्तर्गत कवर किया जाए।

ग्रुप-2 मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं उनका लास्ट ग्रेड पे 8700 रुपये हैं जबकि ग्रुप-1 का 10 हजार रुपये हैं। भले ही समयावधि ज्यादा ली जाए पर इन डॉक्टर्स की भी ग्रेड पे 10 हजार की जाए, क्योंकि यही डॉक्टर्स है जो सुदूर इलाक़ों में स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, स्वास्थ्य प्रबंधन का कार्य करते हैं, यही डॉक्टर्स हैं जिनके जरिए हम एमएनडीवाई, एमएनजीवाई योजनाओं को लागू कर पाए। इन्हीं के जरिए हमने एमएमआर, एनएमआर और इंडिकेटर्स का सुधार किया। इन्होंने ही बीमारू राज्य को स्वस्थ राज्य में लाने हेतु बड़ी भागीदारी निभाई।

अगर रोजगार की बात करते हैं, तो अभी ऑलरेडी कम से कम 400 डॉक्टर्स और पैरामेडीकल स्टाफ एपीओ है, पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कल रात 11-12 बजे आनन फानन में 200 लोगों को पोस्टिंग भी दी गई, पर बाकी 200 लोगों पर कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही है। सीपू की भर्तियां अपॉइन्टमेंट का इंतजार कर रही है। वर्तमान सरकार अटकाने या भटकाने की नीतियों पर काम कर रही है। कभी बहाना मिलता है कि हम डबल एजी से बात करते हैं, कभी कुछ, मैं चाहती हूं कि सरकार इस पर अपना रवैया स्पष्ट करे।

सीएचओज की 5 हजार 261 भर्तियां अभी भी इंतजार कर ही हैं जिसकी वजह से ग्रामीण इलाक़े में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम प्रभावित हो रहा है। यह रोजगार देने के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। एलटी और फॉर्मासिस्ट की विज्ञप्ति कांग्रेस सरकार के समय निकली थी, अब इनकी भर्ती का श्रेय मौजूदा सरकार लेना चाहती है। इन्हें नौकरी देकर आप संविदा कर्मचारियों को हटा रहे हैं, जिनमें से ऐसे बहुत से संविदा कर्मचारी हैं जो 10-15 साल से चिकित्सा जगत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्यों नहीं उन्हें भी सेम प्रवृति या योग्यता के रिक्त पदों पर नियमित किया जाए।

आश्चर्य की बात तो यह है कि विधान सभा चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, कांग्रेस सरकार ने 12 हजार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया अंतिम प्रारूप में पहुंचा दी थी। मौजूदा सरकार की शिथिलता देखिए कि उन्होंने कोई सुध नहीं ली। सरकार चाहती तो 10-15 दिन में स्क्रिनिंग कर, उन्हीं लोगों को नियमित कर सकती थी। इस पर सरकार अपना रुख स्पष्ट करे कि आगे इनका विजन है, उन्हें नियमित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा?

एक तरफ सरकार कहती है कि हम नौकरियों का सृजन कर रहे हैं। आप नौकरियों का सृजन कर रहे हैं या बेरोजगारी का सृजन कर रहे है, आप यह भी स्पष्ट करे। क्या सरकार

समझती है उन लोगों की पीड़ा, जिन्होंने कई सालों तक अपने परिवार की रोजी-रोटी अपनी नौकरी के थ्रू चलाई और आज आप उनको कह देते हैं कि हम आपको नौकरी से हटा रहे हैं। यह सरकार पूरी तरह से बुलडोजर सरकार बन चुकी है। सिर्फ घरों और एस्टेब्लिशमेंट पर ही बुलडोजर नहीं चला रही है, लोगों की नौकरियों पर बुलडोजर चल रहे हैं। लोगों की रोजी-रोटी पर भी बुलडोजर चल रहे हैं।

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): मंत्री महोदय, सुझाव अच्छा है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सुन रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज। सदस्या अच्छा बोल रही हैं, बीच में डिस्टर्ब मत करो।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): अगर हम देखे तो केन्द्र सरकार की तर्ज पर अग्निवीरों की तरह आपने राजस्थान के युवाओं के भविष्य को भी आग में झोंक दिया है। 108 एम्बुलेंस की बात करें तो बहुत सारे ज़िले हैं जिनमें अभी कंडम एम्बुलेंस चल रही है जबकि बेहतर एम्बुलेंस सरकार के पास तैयार है, जो लोकेशन का इंतजार कर रही है।

नये घोषित ज़िलों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए अभी तक कोई रोड मैप तैयार नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसायटी को अभी तक गठित नहीं किया गया है, क्योंकि उसी के जरिए एनएचएम की योजनाएं वहां लागू की जाएगी। केन्द्र की पीएम अभिम योजना जिसके अन्तर्गत हमारे राज्य में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर 33 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनने थे, उसमें से 8 ब्लॉक्स पर यह कार्य चल रहा है, जबकि इस योजना में हमारे राज्य को 700 करोड़ रुपये मिले हैं। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि इन क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स की वर्तमान स्थिति और कार्य पूर्ण होने के समय को भी टेबल किया जाए।

VPS-RTM-19.07.2024-15.30-2m

अब एक इंटरेस्टिंग बात पर हम आते हैं कि सरकारी महकमा पूरा इस राजधानी में बैठा है, सभी मंत्री महोदय इस राजधानी में बैठे हैं और दीये तले अंधेरा है। सरकार की नाक के तले, आर.यू.एच.एस. और एस.एम.एस. की वर्तमान स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। मैं प्रशंसा करती हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय एस.एम.एस. और आर.यू.एच.एस. के औचक निरीक्षण पर गये। एस.एम.एस. के निरीक्षण के दौरान कुछ नर्सिंग ऑफिसर्स को सस्पेंड भी किया गया पर आज की स्थिति क्या है, क्या उसमें फॉलोअप लिया गया है, क्या कुछ सुधार हुआ उस औचक निरीक्षण के बाद या फिर न्यूज बनाने के लिए ही यह कार्यवाही की गयी थी?

एस.एम.एस. के आई.पी.डी. टॉवर की बात अपन अगर करें तो भले ही उसमें मौजूदा सरकार की बात हो या चाहे पूर्ववर्ती सरकार की, बिना प्लानिंग उस आई.पी.डी. टॉवर का काम शुरू किया गया और अभी तक भी यह नहीं पता कि कहां पर पार्किंग होगी, लोग आयेंगे-जायेंगे कैसे? पर इसका सोल्यूशन तो तब हो जब यू.डी.एच. मिनिस्ट्री और हैल्थ मिनिस्ट्री के आपसी झगड़े सुलझें।

आर.यू.एच.एस. को हमने बहुत बड़ा ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है पर वहां जाकर एक बार स्थिति देखें, वहां पर वाड्‌र्स खाली पड़े हैं। दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े वेल इक्विप्ड संस्थान में महीने के दस से पन्द्रह एवरेज एडमिशन होते हैं और ऑपरेशन 135 से 140 महीने के एवरेज, जिसमें भी आधे ऑपरेशन माइनर ऑपरेशंस होते हैं, महज चीरा लगाने जैसे। कोविड में इतनी बेहतरीन सेवाएं देने के बावजूद भी हम ऐसे संस्थान का उपयोग नहीं ले पा रहे हैं। रिसेंटली अभी वहां पर दौरा भी हुआ और चारों तरफ अखबारों में खबरें भी छायी रहीं और फिर 14 जुलाई को एक आदेश निकाला गया जिसमें 16 डाक्टर्स को एस.एम.एस. से आर.यू.एच.एस. में ट्रांसफर कर दिया गया पर मेरा यह मानना है कि इन 16 ट्रांसफर्स से कोई भी कार्य में सुधार आने की सम्भावना नहीं है। अगर आपको कार्य में वहां पर सुधार लाना है तो आपको पूरी यूनिट वहां पर ट्रांसफर करनी पड़ेगी। एक अकेला न्यूरो सर्जन वहां पर जाकर पूरा डिपार्टमेंट नहीं सम्भाल सकता। यह टीम वर्क है इसलिए प्रोपर फंक्शनिंग के लिए, प्रोपर प्लानिंग हो हमारी सरकार की।

पिछले सात से आठ महीने में सरकार ने क्या-क्या काम किये? राज्य की आठ करोड़ जनता ने जिन्हें सिरमौर बनाया, माननीय हमारे मुख्य मंत्री साहब और यहां के उच्चतम अधिकारी वे सिर्फ औचक निरीक्षणों में लगे हुए हैं। वे कभी थाने में जाते हैं, कभी अस्पतालों में जाते हैं, कभी जे.डी.ए. में जाते हैं पर जो उनका मुख्य काम है पॉलिसी मेकिंग, वह कहीं पर नहीं दिख रहा है। न इन संस्थानों के औचक निरीक्षण के बाद कोई स्थिति सुधरी है और न वहां पर मूल कार्य किया जा रहा है, तो मुझे यह लगता है कि अब जनता यह समझ गयी है कि यह पर्ची सरकार होने के साथ-साथ ही एक प्रोजेक्शन सरकार भी है जो मोदीजी के चरण कमलों पर चलकर सिर्फ मार्केटिंग पर ध्यान दे रही है और अपनी ब्रांडिंग पर ध्यान दे रही है।

माननीय सभापति महोदय, बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। आई.एच.एम.एस. 2.0 सॉफ्टवेयर तैयार है परंतु फिर भी प्राइवेट सॉफ्टवेयर को काम में लिया जा रहा है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि सदन को यह बताया जाये कि इस सॉफ्टवेयर को अभी तक काम में क्यों नहीं लिया जा रहा है?

15वें फाइनेंस कमीशन में केन्द्र के द्वारा 2021-22 में हैल्थ डिपार्टमेंट को 152 रुपये सेंक्शन हुए थे जो आज तक फाइनेंस डिपार्टमेंट में अटके हुए हैं, तो यह पैसा सी.एच.सी., पी.एच.सी. और बाकी निर्माण के काम में आता है, उसकी वजह से आज इनका काम प्रभावित हो रहा है। 2021-22 के बाद 2022-23 का पैसा हमारे राज्य को नहीं मिला। 2023-24 का पैसा नहीं मिला क्योंकि जब तक 2021-22 का हम यूटिलाइजेशन सर्टिफ़िकेट आगे नहीं भेजेंगे तो हमारे आगे का पैसा अटका रहेगा पर सरकार को सुध लेने की कोई मंशा ही नहीं है, तो अगर हो सके तो इसका भी प्रजेंट स्टेटस टेबल किया जाये।

आज स्थिति यह है कि प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पद पर बैठकर मंच से यह कहा जा रहा है, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा भी और बाकी हमारे यहां के साथी

सदस्यों द्वारा भी कि कार्य राज्य में वे ही होंगे, विधान सभा क्षेत्रों में वे ही होंगे जो हमारा सांसद, हमारा विधायक चाहेगा, जो हमारा पूर्व सांसद, पूर्व विधायक चाहेगा, जो हमारा कार्यकर्ता चाहेगा। सार्वजनिक मंच से ऐसी बात कहना बहुत ही शर्मनाक है इस राजस्थान की जनता के लिए जिन्होंने आपको इस बार सत्ता पक्ष में बैठाया है। एक सदस्य ने तो मंच से यहां तक कहा कि, भैया, तुम्हारे मामा-भांजे को मत लेकर आना, जिन्होंने वोट नहीं दिया, काम उनका भी नहीं किया जायेगा, तो इससे ज्यादा मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती। आप संगठन को मजबूत करें पर राजकीय कोष से नहीं, आप अपने खुद के पार्टी के कोष से अपने संगठन को मजबूत करें। आप कार्यकर्ता की बात माने पर क्या किसी के माथे पर यह लिखा है कि किसने किसको वोट दिया है? हमें तो जहां तक पता है, वोट देना एक संवैधानिक अधिकार है और वोट सीक्रेट होता है। मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगी कि क्या आप लोग घर चिह्नित करेंगे कि किसे बिजली पहुंचे, किसे पानी पहुंचे, किसे योजनाओं का लाभ पहुंचे और किसे चिकित्सा पहुंचे? क्या जिसने बी.जे.पी. को वोट दिया है, सिर्फ वे ही आपकी जनता है? यहां पर हम 200 सदस्य जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, आज हम उन्हीं ढाई लाख, तीन लाख, साढ़े तीन लाख, चार लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं न कि सिर्फ उन लोगों का जिन्होंने हमें वोट दिया है और जो भी आपको कन्फर्म नहीं है कि इसने वोट दिया या उसने वोट दिया। तो मैं यह उम्मीद करती हूं कि मौजूदा सरकार और हम सभी लोग हमारी जनता के लिए निष्पक्षता के साथ काम करेंगे।

श्री सभापतिः प्लीज, समाप्त करें।

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): माननीय सभापति महोदय, अब मैं मेरे क्षेत्र की डिमांड्स दो मिनट में कहूंगी। हमारे चौमूं में पी.एच.सी., सी.एच.सी. और तथाकथित अपग्रेडेड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डाक्टरों और नर्सिंग कर्मियों के रिक्त पद हैं। वहां पर वर्क लोड इस कदर है कि एवरेज ओ.पी.डी. वहां का एक महीने का 29 से 30 हजार है। हमारे एस.डी.एच. को अभी तक जमीन भी अलॉटेड नहीं है। चौमूं के जाटावाली पी.एच.सी. किराये के भवन में बेसमेंट में चल रही है, तो मेरी सरकार से यह मांग है कि उसके लिए भी नवीन भवन निर्माण के लिए कुछ बजट हमें दिया जाये।

कालाडेरा कस्बा जो एक ऐतिहासिक अपनी महत्ता भी रखता है वहां पर सी.एच.सी. का भवन जर्जर है और नाकाफी है। वर्क लोड, पेशेंट लोड ज्यादा होने की वजह से वह बहुत छोटा प्रतीत होता है, तो मेरी सरकार से यह गुजारिश है कि उस जर्जर भवन की मरम्मत और साथ में नया भवन बनाने के लिए हमें कुछ बजट दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह हिंद, जय संविधान।

श्री सभापतिः श्री संदीपजी शर्मा।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय विधायक को यह कहना चाहूंगा कि चाहे कितना भी लेट हो जाये,

आपको कितनी भी नींद आये, आप मेरा जवाब जरूर सुन कर जाना। फिर आपको यह पता लगेगा कि या तो आपको जो इन्फार्मेशन दी है जो भी आप बोल रही हैं, आप डॉक्टरनी भी हैं, आप मालकिन भी हैं एक हॉस्पिटल की तो जो भी आपके पास रिपोर्ट आयी है वह या तो गलत सोर्स से आयी है, or you're ignorant. आप सुनकर जाना रिप्लाई, प्लीज।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मेडिकल एंड हैल्थ पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, यह सत्य है कि जिस प्रदेश में उत्तम और उच्चस्तरीय चिकित्सा व्यवस्थाएं होती हैं, वह प्रदेश खुशहाल होता है, उन्नत होता है। बहुत आवश्यक है इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने की, संवेदनशील होने की, यह मानवीय संवेदनाओं का विषय है। मेडिकल हैल्थ जैसे विषय को व्यापक और सर्वांगीण डवलपमेंट की आवश्यकता होती है। नीचे तक इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ हो, इस बात की आवश्यकता थी। मुझे अत्यन्त दुःख है यह कहते हुए कि पिछले पांच साल तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान में सत्तारूढ़ रही परंतु कोई आधारभूत सुदृढ़ कार्ययोजना कांग्रेस की सरकार, गहलोतजी की सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं कर पायी। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज, माननीय सदस्य, यह सदन है, थोड़ी आवाज कम करें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): इस संवेदनशील और गम्भीर विषय पर भी सिर्फ बजट में घोषणाएं होती रहीं, जोर-जोर से, हमारे ये बंधु पक्ष में बैठे हुए थे, तालियां बजाते थे, मेजें थपथपाते थे और बड़े जोश के साथ, उत्साह के साथ उन बजट घोषणाओं का स्वागत किया करते थे परंतु जैसी घोषणाएं थीं, माननीय सभापति महोदय, निरोगी राजस्थान, निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क दवाइयां, निःशुल्क जांच, मुख्य मंत्रीजी की चिरंजीवी योजना में पांच लाख, दस लाख, पच्चीस लाख का फ्री उपचार परंतु ये घोषणाएं यही तक सीमित रह गयी थीं।

SSY/RTM/19.07.2024/15.40/2n

कभी इन्होंने वास्तविकता धरातल पर जाकर देखी नहीं। क्या स्थिति है गांव, ढाणी की, उस गांव के व्यक्ति की जो इलाज कराने गांव की डिस्पेंसरी में, सीएचसी, पीएचसी में जाकर इलाज कराने जाता है तो क्या दुर्गति चिकित्सालयों की मिलती है। अस्पताल में चिकित्सक गायब, अस्पताल में कोई नर्सिंग कर्मचारी नहीं, कोई संसाधन नहीं, हालात यह है कि लोग बिना चिकित्सा के तड़पते रहे। पर तालियां बजती और जब यह फ्लाप हो गये तो इन्होंने प्राइवेट चिकित्सालयों का राइट टू हैल्थ बिल लेकर आये और उस बिल के तहत इन्होंने ना तो इनसे कोई बात की, ना कोई सहमति ली, ना कोई उनसे तर्क संगत बात हुई और उनको राइट टू हैल्थ बिल लाकर और धाराएं लगाकर उनको अपनी निरोगी राजस्थान जिसमें यह फ्लॉप हो गये थे, जिसके वादे पूरे नहीं कर पाये थे, उन पर थोपने का इन्होंने प्रयास किया। हालात यह हुए कि राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था कई दिनों तक चरमराती रही।

आपकी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की हम बात करें। जिस तरीके से यह फेल हुई, फ्लॉप हुई, क्योंकि जब लोग प्राइवेट चिकित्सालयों में इलाज कराने जाते थे तो यह हालात थे, चूंकि उनको ना तो उचित समय पर दवाइयों का भुगतान मिल पाता था, ना चिकित्सा के लिए उचित राशि मिल पाती थी। गरीब मरीज जब वहां जाता था तो उसको टरका दिया जाता था। उसको बहला दिया जाता था। निजी चिकित्सालय उसका इलाज नहीं करते थे। मजबूर होकर दुकान, मकान, गहने, खेत बेचकर गरीब व्यक्ति अपना इलाज निजी चिकित्सालय में पैसे देकर कराया करता था। यह सत्य है। यह हकीकत है जो धरातल पर देखी है। इससे बचना नहीं चाहिए।

आप केन्द्र में सबसे ज्यादा समय तक सत्तारुढ़ रहे, लेकिन आपके विजन में कभी समृद्ध और सुदृढ़ चिकित्सा का ख्याल नहीं आया। आजादी के बाद बरसों तक सिर्फ 7 एम्स इस देश में चलते रहे। आज 11 साल में इस देश में 22 एम्स इस देश की धरती पर बन चुके हैं। यह एक विजन, सुदृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ हो सकता है।

कोरोना में क्या हाल हुआ? कोरोना में आप भले ही तालियां बजवाते रहे, खुद की पीठ थपथपाते रहे, लेकिन वास्तविक स्थिति यह थी कि आप लोग चिकित्सालयों में उनको बेड भी उपलब्ध नहीं करवा पाये, दवाइयां उपलब्ध नहीं करवा पाये। तड़फड़ाते हुए लोगों ने सड़कों पर ही दम तोड़ दिया। यह कोरोना के समय आपकी सरकार के समय के हालात हैं। धन्यवाद दो माननीय लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का, जिन्होंने ऑक्सीजन की ट्रेन, ऑक्सीजन के टैंकर्स, दवाइयां, रेमडीसीवर इस राजस्थान की धरती पर भिजवाये। आपके भी मंत्री गये थे उनके पास, हां, हां, तो कर रहे हो आप। उसके बाद इस राजस्थान की धरती पर ऑक्सीजन की ट्रेन भी आई थी, टैंकर भी आये थे, दवाइयों की खेप की खेप आई थी, रेमडीसीवर आये थे। लाखों लोगों की जान बच सकी थी। आप यह बात भूल जाते हो। आपने तो राजस्थान को बिलकुल बेसुध छोड़ दिया था। आप लोग तो माननीय मुख्य मंत्री के साथ सेवन स्टार होटलों में क्वारंटिन हो गये थे। हो गये थे ना? यह स्थिति थी।

सभापति महोदय, मैं आपको सत्य बता रहा हूं। केन्द्र सरकार ने इनको जो राशि भी दी थी ना, उनके वेंटीलेटर भी नहीं खरीद पाये थे। केन्द्र सरकार की राशि का भी यह पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर पाये थे। ना तो इन्होंने किसी भी क्षेत्र में प्रयास किया, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है।

माननीय प्रति पक्ष के नेता, जूली साहब, आप सही कह रहे थे, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बड़ा, आप अच्छे व्यक्ति हो, आपका अच्छा व्यक्तित्व है, मैं आपका सम्मान करता हूं। परंतु आपकी चिंता थी कि वही अधिकारी बजट बना रहे हैं जो गहलोत साहब का बजट बनाते थे। अब माननीय भजन लाल जी का बजट भी वही बना रहे हैं। हमारा बजट ही पूरा नहीं हुआ तो आपका बजट कैसे पूरा होगा? आपकी चिंता निराधार है। आप यह भूल जाते हो कि भारत की सीमा पर वही सैनिक डटा हुआ है जो मनमोहन सिंह जी के टाइम था, जब पाकिस्तान आंखें तरेरा करता था, दादागीरी दिखाया करता था, मनमोहन सिंह जी अमेरिका

जाकर राष्ट्रपति जी से शिकायत करके आते थे और आज वही पाकिस्तान नतमस्तक होकर आपके सामने खड़ा है। घुटनों के बल पर खड़ा है। पूरे विश्व में सबसे कंगाल और बदहाल देश पाकिस्तान बन गया है क्योंकि नेतृत्व कर्ता की क्षमता होनी चाहिए, उसका विजन होना चाहिए। वही अधिकारी रहेंगे ...(व्यवधान)...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसमें यह कहां से आ गया?

श्री सभापतिः प्लीज, प्लीज, माननीय सदस्य। नेता, प्रतिपक्ष, आपके नेता, प्रतिपक्ष नोट कर रहे हैं। जब आप बोल रहे हैं तो कोई उधर से आपको टोक नहीं रहे हैं। आपको नहीं बोलना चाहिए। समय उनका भी कट रहा है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): यह नेतृत्व कर्ता के विजन का प्रश्न होता है। यह उसकी क्षमता का प्रश्न होता है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह कहां से आ गया?

श्री सभापतिः आपके नेता, प्रतिपक्ष सक्षम हैं। आपका भी नंबर आयेगा, तब जवाब दे देना। इनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो?

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सुनो, सुनने की हिम्मत रखो। अधिकारी वही होता है लेकिन उसकी क्षमताओं का, उसका सकारात्मक रूप से उपयोग करके कैसे काम निकाला जाये, यह काम होता है कार्यपालिका का। अब हमारे मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा उसी विजन के साथ, उसी दृढ़ संकल्प के साथ जो 5 साल तक आप आपके बजट की घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाये थे, अब धरातल पर पूरी होती हुई आपको नजर आयेंगी, दिखाई देंगी, आप भी यहीं बैठे हो और हम भी यहीं बैठे हैं।

आपको बहुत संशय है कि कैसे बजट पूरा होगा। संशय मत करो। आपका बजट चुनावी बजट था। चुनावों से 6 महीने पहले घोषणाएं की थी ना, और हमारा यह बजट जब हम चुनाव जीतकर सरकार बनाई, उस सरकार बनने के 6 महीने के अन्दर-अन्दर कर दिया, साढ़े 4 साल हैं। हमारा चुनावी बजट नहीं है। हमारा तो भजन लाल जी का दृढ़ संकल्पित, प्रतिबद्धताओं से भरा हुआ बजट है। यह बजट नहीं है, यह उनका संकल्प पत्र है, माननीय उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी का संकल्प है, माननीय भजन लाल जी का संकल्प है। शत-प्रतिशत पूरा करके दिखायेंगे, हम आपसे वादा कर रहे हैं। 100 परसेंट पूरा करके दिखायेंगे।

2014 से जो क्रांतिकारी परिवर्तन इस देश में आपको नजर आता होगा, हर क्षेत्र में नजर आता होगा। सिर्फ चिकित्सा में नहीं, स्वास्थ्य में ही नहीं, साइंस टेक्नोलॉजी में, सैन्य शक्ति में, हर क्षेत्र में, आर्थिक प्रगति में हम तीसरे स्थान पर, हर प्रकार का, यह कैसे संभव हो पाता है? यह दृढ संकल्प शक्ति से हो पाता है।

आज भारत देश चिकित्सा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो गया है। कभी आपने सपने में भी सोचा था, आजादी के 70 साल तक भी कि आप वैक्सीन बना पाओगे। लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी की दृढ इच्छा शक्ति से 2-2 वैक्सीन भारत ने बनाये। सबसे ज्यादा पूरे विश्व में, सफलतापूर्वक कोरोना का नाश किया तो सबसे पहले भारत की धरती पर किया। इस बात

को आप मत भूला करो।

मनमोहन सिंह जी सरकार के समय मातृ मृत्यु दर 1 लाख पर 130 थी, वह अब घटकर 97 रह गयी है। शिशु मृत्यु दर जो 1 हजार पर 39 थी, अब 28 हो गयी है।

Spp/Rtm/19.07.2024/15:50/2o

माननीय मुख्य मंत्री भजनलाल जी शर्मा ने तो वर्षों तक जनजा के दु:ख-दर्द को समझा है, देखा है। डोटासरा साहब कहां गये? वह पर्ची, पर्ची की सरकार करते हैं न, तो मैं यह बता देना चाहता हूं, वह जहां भी बैठकर सुन रहे हों, आपको तो खुश होना चाहिये था एक मध्यम वर्गीय परिवार का, किसान पुत्र का बेटा आज राजस्थान की धरती का मुख्य मंत्री बना है अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपनी कर्मठता से, अपनी श्रेष्ठता से और यह पर्चियां जूली साहब, यूं ही नहीं खुल जाती हैं, जब बहुत सारे पुण्य कर्म संचित हो जाते हैं तो यहां से नहीं, वहां से पर्चियां खुलती हैं। वहां से पर्चियां खुलती हैं यह गलतफहमी निकाल लें, डोटासरा साहब। इसलिये अच्छे कर्म करते रहो, कभी न कभी किसी की पर्ची खुलेगी। अब काम ही गलत करोगे तो पर्ची नहीं आयेगी। राजस्थान के मुख्य मंत्री बनते ही पहले दिन से ही राजस्थान के नीचे गांव और ढाणी तक आला अधिकारियों को भेजकर पूरी गंभीरता के साथ, एक सुनिश्चितता के साथ डेटाज को ऑनलाइन करके सारा डाटा मंगाकर कहां-कहां क्या कमी थी, उन सब चीजों का अवलोकन करते हुए आज जो बजट दिया है न 27,660 करोड़ का, यह सरकार का पहला बजट है। यह आपके बिगाड़े हुए काम है, जितने भी आपने बिगाड़ा है न चिकित्सा तंत्र में, इस मंत्र को सुदृढ़ करेगा और राजस्थान की जनता को राहत प्रदान करेगा। 15 हजार करोड़ रुपये से मुख्य मंत्री आयुष्मान योजना के द्वारा प्रदेशवासियों का सम्मानपूर्वक और बहुत गुणवत्ता वाला इलाज अब राजस्थान की धरती पर होगा।

माननीय सभापति महोदय, अब प्रत्येक विधान सभा में आयुष्मान मॉडल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से सुगम और बेहतर चिकित्सा व्यवस्थाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। हमारी सरकार ने मेडिकल हैल्थ में आधारभूत ढांचे पर जोर दिया है। हमारी घोषणाएं आपकी तरह हवाई घोषणाएं नहीं हैं। हमारी सरकार RUHS में सुपर स्पेशियलिटी का 200 करोड़ रुपये से काम होगा। पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना, स्पाइन इंजरी, के.आर.रूमिटोलॉजी, कैंसर, हृदय रोग सहित सभी दुर्लभ रोगों पर काम किया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से सम्पूर्ण और समग्र विकास की इस बजट में इबारत लिखी जायेगी। सभी स्वास्थ्य केन्द्रों को 1500 चिकित्सक, 4 हजार नर्सिंगकर्मी मिलेंगे। आप कभी दे नहीं पाये। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं बस दो मिनट में अपनी कोटा की बात बताना चाह रहा हूं।

श्री सभापति: समय का ध्यान रखो।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): बस एक मिनट में कोटा के विषय में कह दूं। आपका संरक्षण चाहिये। कैंसर रोगों के लिये जो बहुत बड़ी आवश्यकता है। पिछले पांच साल कोटा में धर्मादा संस्थाएं भी काम करना चाहती है। भारत विकास परिषद, कोटा कैंसर सोसायटी, लेकिन उनको कोई सहयोग नहीं हुआ। आज कोटा शहर में बढ़ता कैंसर रोग के रूप में बहुत बड़ी चुनौती है, माननीय मंत्रीजी, आप बिराजे हुए हैं। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आज मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में कॉटेज वार्ड के निर्माण की आवश्यकता है। हमारा जो किडनी ट्रांसप्लांट का विभाग है, वह एस एम एस के बाद दूसरा ऐसा राजस्थान में विभाग है, जहां लगातार किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। इसलिये वहां पर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने में हमारा दूसरा स्थान है। इसमें रोबोटिक यूरोलॉजी सर्जरी की अत्यन्त आवश्यकता है जिससे कैंसर रोगियों का इलाज हो सके। मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में बायोप्लेनर कैथलैब कोटा में कैंसर उपचार हेतु लिनियर एक्सलरेटर मशीन, मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय द्वितीय तल चालू हो गया है परंतु वहां नर्सिंगकर्मी और चिकित्सक लगाने की आप कृपा करें। सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय में व कार्डिक थोरोसिस मेडिकल कालेज में ई एन टी विभाग की नियमित रूप से सेवायें उपलब्ध करायें। बहुत बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान).. माननीय सभापति महोदय, कोटा दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज, डेंटल और फार्मेसी कॉलेज खोलने की आवश्यकता है। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे चिकित्सा विभाग की मांग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज बात कर रहे हैं हॉस्पिटल्स की, बहुत हॉस्पिटल्स खोले हैं। राजस्थान में 47 जिला अस्पताल हैं, 78 SDH हैं, 723 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, 102 शहरी डिस्पेंसरीज हैं, 2475 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, 310 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, 15,245 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं। बहुत ऐसे हैं जिनमें, मंत्रीजी ध्यान से सुनना, ऐसी महिलाएं हैं हमारे झुन्झुनूं जिले में जिनको दो-तीन वर्ष से तनख्वाह नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, स्थगन लेकर बैठ गयी और कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। या तो उनको ड्यूटी दी जाये उनको आपको तनख्वाह तो देनी ही चाहिये। सरकार ही स्टे देने वाली एजेंसी है और सरकार ही इसको चला रही है तो इसमें महिलाओं की क्या गलती है? जो सरकारी नौकरी करती है अगर उनको नाजायज ट्रांसफर करेंगे तो वह स्टे लेंगे, लेकिन उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। वह महिलाएं आज तीन-तीन, चार-चार साल से तनख्वाह के लिये तरस रही हैं। नंबर वन तो आप यह ध्यान रखें, आप बहुत बड़े साहसी और हिम्मत वाले, जिसको कहना चाहिये दानी आदमी हो, आप गाड़ियों के लिये मंत्री नहीं बने हो, गाड़ियां तो आपके बुजुर्गों के पास भी थी। मैं इसलिये कह रहा था इससे आपकी पहचान बन जाये।

यूं तो सभी लोग जिंदगी जीते हैं
जिन्दगी ऐसी जीओ मिसाल बन जाये।।

आपको एक ऐसी मिसाल पैदा करना है कि राजस्थान का मुख्य मंत्री आप बने, बिजली का डिपार्टमेंट भी आपके पास था, जब हम इधर हुआ करते थे। पिछली बार बिजली में आपने आमूलचूल परिवर्तन किया तो इसमें भी आपको आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। आपके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा आयेगा, क्योंकि आपकी पार्टी के लोग आपसे गलत काम कराना चाहेंगे पर साहस और हिम्मत के साथ जिस प्रकार आपके बुजुर्गों ने राज किया है, उसी प्रकार राज को निभाना है।

माननीय सभापति महोदय, अभी शिखा जी भी कह रही थीं इतने लोग बीमार हैं। बीमार होने का कारण क्या है? कोई व्यक्ति व्यवधान करता है, सुबह एक बात चल रही थी, व्यवधान पैदा कहां से हुआ? जूली जी ने कहा कि व्यवधान उधर से पैदा हुआ। मैं यह कह रहा हूं कि रोग पैदा होता क्यों है? इसकी मूल जड़ आपको ढूंढना पड़ेगा। अभी कोटा से आने वाले हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि इतनी किड़नी ट्रांसप्लांट हो रही हैं, इतने बीमार हो रहे हैं। बीमार होने का कारण आप और हम हैं। आप देखिये राजस्थान के अलवर में 15 वर्ष पहले सिंथेटिक दूध पकड़ा था खाद से बनाया हुआ और 15 साल में कोई सुधार नहीं हुआ बल्कि उससे ज्यादा बिगाड़ हुआ है। आप देखिये दूध में मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट और जेनेरिक दवाइयों के बजाय जो दिल्ली से तोल की दवाइयां आती हैं, वह मार्केट में दवाई बेचते हैं। सब्जियों में मिलावट, इस प्रकार से मिलावट की जो चीजें मानव खाता है, तो स्वतः ही बीमार हो जाता है। ...(व्यवधान).. नो-नो इंटरफियरेंस, सिट डाउन ..(व्यवधान).. आर्डर-आर्डर।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): मैं आपकी बात का ही समर्थन कर रहा हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं अपने आप कह दूंगा, सक्षम हूं। मैं अपने आप में सक्षम हूं। जब आप जन्मे थे, मैं काम करने लग गया था।

मैं यह कहना चाह रहा था कि दवाइयों में मिलावट है, जेनेरिक दवाइयां बेचते नहीं है। दिल्ली से तोलकर दवाई आती हैं, मैं वही बात कहूंगा जो ओथेंटिक है। आपको मालूम है खाद्य पदार्थों में मिलावट है और आपका ही इंस्पेक्टर, एक-एक जिले में तीन-तीन इंस्पेक्टर होते हैं। वह बाजार में जाते हैं और ईमानदारी से दावे के साथ कहता हूं सदन में खड़ा होकर, वह सेठ को क्या कहते हैं कि, सेठजी, वह सैम्पल दे दो जिसमें मिलावट नहीं है। मेरे को करना तो पड़ेगा क्योंकि मुझे ड्यूटी तो पूरी करनी ही पडेगी पर महीने वाले दिन पैसा भी लूंगा। यह मैं वह बात कह रहा हूं जो ईमानदारी से कह रहा हूं। आपका इंस्पेक्टर बेइमान है और वह जाकर खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वाले को यह सलाह देता है कि पैसा तो लूंगा परंतु वह खाद्य पदार्थ दे दे जिसमें मिलावट नहीं है। आपको इसमें सुधार करना पड़ेगा। आज तक मेरी 44 साल की राजनीति में मैंने कभी नहीं सुना कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले को सज़ा हुई है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता जूली जी कह रहे थे कि हमने पेपर लीक के ऊपर कानून बनाया कि उसकी 20 साल की सज़ा और एक करोड़ का जुर्माना।

MLS/RTM/19.07.2024/16:00/2p

10 करोड़ का शायद। आप देखिये, जब पेपर लीक का सिलसिला आया, हर आदमी के लिए वह दुखद है, वह भी जीवन के साथ खिलवाड़ ही तो है। यह जीवन के साथ खिलवाड़ है, जीवन की मृत्यु है। उसके ऊपर आपने कुछ नहीं सोचा? सरकार को हिम्मत करके कहना चाहिये कि जो मिलावट करने वाला पकड़ा जायेगा, उसे सज़ा-ए-मौत होगी। तब देश का भला हो सकता है। किसी में हिम्मत नहीं है। केवल 5 साल तक ये हिम्मत की बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं। अभी शिखा जी कह रही थीं, ''पहला सुख निरोगी काया'', यह बात सही कह रही थीं, पर इसमें पांच चीजें और भी हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख सतवन्ती नारी, तीसरा सुख पुत्र प्यारा, चौथा सुख घर में माया, पांचवां सुख राज में पासा, छठा सुख अच्छा पड़ोसी और सातवां सुख घर के पास पानी।

पानी आपका वैसे खत्म हो गया, अच्छे पड़ोसी वैसे खत्म हो गये, औरतों का आप जानते हैं, कैसा आज-कल देश में चल रहा है, सुबह शादी की और शाम को डायवोर्स हो गया। यह सारा सिस्टम खत्म होता जा रहा है। कोई भी सदन में आकर यह बात नहीं सोचता कि सिस्टम खत्म क्यों होता जा रहा है। खत्म इसलिए होता जा रहा है कि कोई भी आदमी जो पद पर आता है, चाहे वह मंत्री बने, चाहे एमएलए बने, चाहे सरपंच बने, चाहे प्रधान बने, चाहे आईएएस या आरएएस बने, सारे के सारे लोगों की एक धारणा हो जाती है कि मैं गांव का सबसे बड़ा व्यक्ति कैसे बन सकता हूं। बड़ा वह मानवता से बन सकता है, अच्छे कर्म करके बन सकता है, लेकिन वह कभी चोरी करके बड़ा नहीं बन सकता।

आज कोई डॉक्टर बनता है। डॉक्टर के पास एक हजार की फीस है। डॉक्टर ने अलग-अलग बना रखी है, इतने मरीजों से मेरा घर चलाऊंगा, इतने मरीजों से मेरी गाड़ी चलेगी, इतने मरीजों से मेरा बेटा पढ़ेगा, इतने मरीजों से मेरी अलग से कोठी बनेगी। इस तरह देश का भला नहीं हो सकता। देश का भला तब हो सकता है, जब डॉक्टरों पर अंकुश लगे। हॉस्पिटल में बैठता है, आने वाले मरीजों को क्या कहता है, मेरा मकान नं. 234 है इस गली में, शाम को आ जाना। तू क्यों नहीं देख रहा यहां, तुझे पैसा नहीं मिलता क्या? जब तेरी इच्छा ही नहीं है तो नौकरी छोड़ दे न। बहुत सारे लोग खाली घूम रहे हैं। आप देखिये, जो लोग काम नहीं करते हैं, उन्हें भी कोई कुछ नहीं कहता है।

लोग लुट जाते हैं एक घर बनाने में,
तुम तरस नहीं खाते बस्ती जलाने में।

आप देखिये, एक आदमी मुश्किल से अपना जीवन निर्वाह कर रहा होता है और उसे लोग लूटकर खा जाते हैं, लेकिन ईश्वर की एक कृपा भी है। कृपा यह है-

बख्श देता है ख़ुदा उनको,
बख्श देता है ख़ुदा उनको,
जिनकी किस्मत खराब होती है,
वे हरगिज नहीं बख्शे जाते,

जिनकी नीयत खराब होती है।।

जिनकी नीयत खराब होती है, वे कभी नहीं बख्शे जाते। मैं आज भी कहता हूं, चाहे राजनीतिज्ञ हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा अफसर बने, अगर हिन्दुस्तान की जनता के साथ भ्रष्टाचार करता है, धोखाधड़ी करता है, कर्त्तव्य का पालन नहीं करता है, कर्त्तव्य के प्रति जागरूक नहीं होता है, वह सबसे बड़ा देशद्रोही होता है, इसलिए डॉक्टरों से एक बात कहना चाहता हूं मैं-

कुछ तो शर्म करो कलियुग के भगवान,
कुछ तो शर्म करो कलियुग के भगवान,
गरीबों की सेवा के लिए बने हो,
लूटने के लिए नहीं।
गरीबों की सेवा के लिए बने हो,
लूटने के लिए नहीं।
जरा उस भगवान को जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया है,
मृत्यु सबको आनी है एक दिन,
क्या निर्धन क्या बलवान।।

डॉक्टरों को हमें देखना चाहिये। डॉक्टरों को तो मैं कह रहा हूं, पर सबसे बड़े हिम्मतहीन तो हम हैं न जो उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रण नहीं कर सकते। जिस सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, वह राज चलाने में अपने आप में असमर्थ होती है। सरकार उसे ही चलानी चाहिये, जिसमें नियंत्रण करने की शक्ति और काम करने का माद्दा होता है। जिसमें माद्दा नहीं होता है, वह चाहे बड़े से बड़ा मंत्री बने, संतरी बने, अफसर बने, कुछ अफसरों को मैंने देखा है, टेलीफोन करते हैं, तहसीलदार को कलक्टर टेलीफोन करता है, ''यार वह काम कर देना'', किस बात का यार? I want this kind of work today. तब तो काम बनता है।

तहसीलदार को ''यार'' कहकर कलक्टर टेलीफोन करता है, मंत्री अपने डॉक्टर को टेलीफोन करता है, ''डॉक्टर साहब, आप जरा देख लेना'', क्या देख लेना? आप जब डॉक्टरों की नियुक्ति करते हैं, सीएमएचओ लगाते हैं, कोई उसका क्राइटेरिया नहीं देखते। कल का डॉक्टर आता है, सीएमएचओ बना देते हैं। यह राजनीतिक प्रेशर होता है। कोई बीसीएमएचओ बन जाता है। जब एडमिनिस्ट्रेशन की वह परिभाषा ही नहीं जानता, एबीसीडी ही नहीं जानता, वह क्या सीएमएचओ बनकर काम करेगा? यह आप हिम्मत करें। हमारे परसादी लाल जी ने हिम्मत की थी और उन्होंने सीनियॉरिटी के हिसाब से सीएमएचओ लगाये थे।

आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं। प्रेशर है, ये वोट देंगे। इनके पास कहां हैं वोट? ये तो पैसा कमाएंगे आपका नाम लेकर। वोट नहीं हैं इनके पास। वोट कौन देगा इनके नाम से? ये सुबह से शाम तक लोगों की जेब काटते हैं। कोई वोट देगा क्या इनके कहने से? इनसे वोट की आशा मत करिये। ये कभी भी वोट नहीं दिला सकते। अफसर कभी वोट नहीं दिलायेगा।

अफसर मौका देखकर आपको खुश करके लग जायेगा। जब दूसरा राज आयेगा, रात को साढ़े 11 बजे मैंने देखा, वसुन्धरा जी की फोटो हटा दी और अशोक जी की लगा दी। जब अबकी बार देखा, साढ़े 9 बजे ही हटा दी और भजनलाल जी की लगा दी। तुम्हारी फोटो हट जायेगी। चक्कर में मत पड़ो। यह कोई नहीं जानता।

अफसरों के भरोसे अगर तुम राज करना चाहते हो, नहीं कर पाओगे। जनता के भरोसे राज करोगे, करोगे, करोगे। कोई नहीं रोक सकता। या तो फिर हमारी तरह यहां बैठ जाओगे। ये भी क्या करते थे, सुनते नहीं थे। नशे में चूर थे। परसादी लाल जी के पास मैं गया। परसादी लाल जी कहने लगे, आप कहें तो मैं उठकर बाहर चला जाऊं, मैंने उनसे कहा, उठकर बाहर नहीं जाएंगे, जब चुनाव में जाएंगे तो लोग गलियारों में नहीं खड़ा होने देंगे। वही हुआ न, 50 हजार से हारे। हम 40 हजार से जीतकर आये, क्योंकि हमने कर्म किया है। हम 44 साल से कर्म कर रहे हैं। हम यह नहीं देखते हैं कि कौन बुरा है। किसी शायर ने कहा है-

तू बुरा है तो वह सच ही कहता है,
और तू बुरा नहीं है तो उसे रोकता क्यों है?

तो अगर बुरा नहीं है तो रोकें क्यों, करता रहेगा अपना क्या लेता है? मंत्री जी, आप साहसी हैं, हिम्मत वाले हैं। मैं एक बात आपको कहूंगा, डॉक्टरों पर नियंत्रण करिये। हॉस्पिटलों में जाकर आप देखिये। हॉस्पिटलों के बाहर डस्टबिंस तो हैं ही नहीं, खून से भरी पट्टियां और गन्दी चीजें पड़ी मिलेंगी। मैंने एक डॉक्टर को कहा कि तुम कम से कम एक स्वीपर को बुलाकर ये सब उठवा तो सकते हो। वह बोला, तीन दिन से मैं था नहीं। तू नहीं था तो कोई और तो था ही न। कोई तो था ही, पर किसी की हिम्मत नहीं है। वे बोलकर किसी को कह नहीं सकते। कम से कम जहां स्वच्छता का मामला है, वहां अगर गन्दगी रहती है तो फिर किस बात का इलाज करते हैं?

आपको यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो व्यक्ति काम नहीं करता है, वह केवल अपना शो करता है, काम नहीं करता है। मेडिकल कॉलेजेज बनाईं, कॉलेज हर जिले में बन गईं, फिर भी आज भी गरीब का बेटा, जो कमजोर रह जाता है, अच्छी तरह ट्यूशन नहीं कर पाता है, अच्छी तरह जिसे ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, उसे 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ रुपये तक की डोनेशन देनी पड़ती है। सरकार को कम से कम नीति बनानी चाहिये, जैसे महाराष्ट्र में जब कॉलेज खोलते थे तो 15-20 सीटें अपने अनुदान की रखते थे, जिसमें साढ़े चार लाख, पांच लाख रुपये एक बच्चे से एक साल के रहते थे। वह कॉलेज भी डवलप हो जाती थी और बच्चा भी कम पैसे में पढ़ लेता था।

राजस्थान में किसी की ऐसी सोच नहीं है। वह निम्स में जा रहा है, 80 लाख रुपये दे रहा है, गांधी में जा रहा है, (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) घण्टी बजा दी? कमाल कर दिया? कितनी अच्छी बात चल रही है। आप सुनने के इच्छुक नहीं हैं तो आपकी मर्जी है। सभापति महोदय, आप इतने बहादुर और हिम्मत वाले आदमी हैं, तीन बार लगातार जीतकर आये हैं, अपने कर्मों से जीतकर आये हैं, आप सुनने के आदी तो रहें। घण्टी बजा दी।

श्री सभापतिः आपकी व्यवस्था आपका नेता प्रतिपक्ष करता है। मैंने तय नहीं किया आपका समय।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नेता प्रतिपक्ष कुछ भी नहीं कहेंगे, कोई नहीं कहेगा। आप तो एक बार सुन लें। आप देखिये, यदि कॉलेजों में आप इस तरह की सीट्स कर देंगे तो हमारे गरीब का बेटा कॉलेज में जाकर एडमिशन भी ले लेगा और आपके कॉलेज का डवलपमेंट भी हो जायेगा। आप यह कहेंगे कि आपकी सरकार के पास पैसे नहीं हैं, यह नहीं है, वह नहीं है, फैकल्टी नहीं खोल सकते, अगर यह काम करेंगे तो आपका सबसे बड़ा फायदा होगा।

अभी थोड़ी देर पहले एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि कोरोना में हमने वैक्सीन लगायी। वही वैक्सीन तो हार्ट अटैक करवा रही है न। उसके पैसे ले लिये। ये पैसे से धापते ही नहीं, क्या चक्कर है? हर आदमी का सुनते हैं, हार्ट अटैक आ गया। क्या कहते हैं, शान्त हार्ट अटैक हो गया। इन्होंने शान्ति से ही पैसा लिया, शान्ति का ही इंजेक्शन लगाया और शान्ति से ही हार्ट अटैक हो जाता है। तीनों काम शान्ति से किये। माननीय मंत्री जी, जब बजट आया तो झुंझुनूं जिले का एक भी नाम नहीं लिया, बहादुरों का जिला है, सेठों का जिला है, एजुकेशन का जिला है। कल भी मैं जाकर आया हूं, दो शहीद झुंझुनूं जिले के हुए हैं

mkd/rtm/19.07.2024/16:10/2q

और 78 दिन में 11 घटनाएं हो गई हैं। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अभी कह रहे थे बिरला जी ने सिलेंडर भेजा। हमारी सरकार ने दूसरे राज्यों को भी सिलेंडर दिये हैं। इतने गैस के उपक्रम लगाये थे, वे आज बन्द पड़े है। आप यह मत कहो, बहुत किया है। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अशोक जी ने 25 लाख रुपये का जीवन बीमा करवाया। यह भी गलत था। आवश्यकता से अधिक वस्तु देना भी जीवन का पाप है।

सभापति महोदय, मैं आपका बता रहा हूं, मैं एक हॉस्पिटल में गया और डॉक्टर ने कहा कि कल ही एक आदमी राजगढ़ से आया था। उसने कहा एक लाख का बिल बना दो, पचास आपके और पचास मेरे। जिस देश में भ्रष्टाचार, जिस स्टेट में पाप ठहरने लग जाता है, वह देश कहां से जीएगा? एक व्यक्ति बीमार नहीं है, फिर भी कह रहा है, पैसे की जरूरत है। डॉक्टर साहब ने मुझे टेलीफोन किया, राजगढ़ का ही हॉस्पिटल था। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या कह रहे हो, वह अंकल जी कहता है, बोला अंकल जी, ऐसे आया है। मैंने कहा कि वह मर्डर करके आ गया होगा। राजगढ़ में डेली मर्डर होते हैं, तेरा नाम लगेगा। तुझे एडमिट दिखाना पड़ेगा। बोला, यह भी होता है क्या, मैंने कहा यही होगा।

कहां, कौन इलाज करायेगा, कौन इलाज करेगा, कौन सरकार चलायेगा, कैसे सरकार चलेगी, आप इस प्रक्रिया को बदल दो। यह सारा सिस्टम नियुक्तियों पर आधारित करता है। नियुक्तियों के अन्दर कितने डेली वेजेज के आदमियों को नौकरी नहीं दी? कितनी सीटें खाली पड़ी हैं? डॉक्टर की बात तो यह है, आधे डॉक्टर लोग तो यह सोचते हैं कि कब दिन छिपे और कब मैं घर जाऊ। डॉक्टर के घर पर पेशेंट बैठे रहते हैं। इस देश के अन्दर इससे बड़ी

शर्म की बात क्या होगी? डॉक्टर अपने घर पर बुलाकर इलाज करता है, हॉस्पिटल खाली पड़े है।

इसलिए मैं लास्ट में एक बात कहूंगा, दिल को जलाकर ही हमने जमाने को रोशनी दी है, जुगनू पर हमने उजाला नहीं किया है। हमने जो किया है, प्रेक्टिकली किया है, बातों से नहीं किया और आज भी बातों से नहीं करेंगे। जब तक प्राण रहेंगे, तब तक यही करते रहेंगे।

मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे,
मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे।
लोग टूट जाते हैं, मांझी तेरी कश्ती को तलबगार बहुत हैं,
इस पार कुछ, उस पार कुछ, मगर उस पार बहुत हैं।
शहर में तुमने खोली है शीशे की दुकान,
उस शहर में पत्थर के खरीददार बहुत हैं।
मैं दर्द की हद तक चला गया हूं। मीडिया सुन रहा है।

(समयः बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति जी, मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना और प्रत्येक व्यक्ति को ड्यूटी के प्रति सजग और जागरूक बनाने की महती आवश्यकता है।

हमारे जो मंत्री जी हैं। ये इतने पक्के और दिलदार आदमी हैं। इनको किसी से डर नहीं है और डरने की जरूरत भी नहीं है। जब तक भाग्य में लिखा है, तब तक आप मंत्री रहेंगे और भाग्य टूट जायेगा, उस दिन कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए, बचपन से मैं नंगी तलवार पर चलता हूं। आप तो कह देना, कोई आपको कुछ कहे तो। बचपन से मैं नंगी तलवार पर चलता आया हूं, ये नुकीले पत्थर मेरा क्या बिगाड़ेंगे? अगर कोई कुछ कहे तो आप तो कह दें कि मैं बचपन से ही नंगी तलवारों पर चला हूं, मैं नुकीले पत्थरों से थोड़े ही डरूंगा। यह कह दोगे ना, पक्का। यह आप कह दोगे तो पक्का हो जाओगे, चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि हम सब राजनीति में आये थे तब एक वादा करके आये थे कि-

सदियों बाद उतरा हूं गहरे पानी में, वतन की प्यास बुझा कर रहूंगा।
जो सिर झुके नहीं, झुकाये गये थे, उन सिर को ऊँचा उठाकर रहूंगा।
जाति और धर्म का जो जहर फैला, जहर को मिटाकर रहूंगा।
जिन घर में सदियों से अँधेरा चला, वहां चिराग जला कर रहूंगा।

माननीय सभापति जी, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय श्रवण जी, आप अपने काले बालों के साथ पूर्ण स्वस्थ दिखाई देते हो।

श्री सभापतिः साहब, इनके ओरिजनल काले हैं। श्री बालमुकुन्दाचार्य जी।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): धन्यवाद, सभापति महोदय। मुझे मांग संख्या-27, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा मांग संख्या-28 चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार गरीब और आम जनता के कल्याण के लिए संकल्पित होकर काम करना चाहती है। यह हम सबने इस बजट के माध्यम से देखा है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा साहब एवं उप मुख्य मंत्री महोदया वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने बजट से सिद्ध किया है कि राजस्थान का उन्नत व विकसित करना है।

माननीय सभापति महोदय, कहा गया है कि 'पहला सुख, निरोगी काया।' माननीय सभी सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया और यह बात कही है कि 'पहला सुख, निरोगी काया।' इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बहुत-बड़े कार्य करने की इच्छा शक्ति प्रकट की है। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का और अधिक विस्तार हो। इस वित्तीय वर्ष में बजट में 27 हजार 660 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पूरे बजट का 8.26 प्रतिशत है।

हमारी केन्द्र सरकार ने एवं लोकप्रिय एवं सम्पूर्ण विश्व में इस समय विख्यात, उन्नत, विकसित भारत को अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू कर देश में आम जन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में क्रांतिकारी पहल की है। इसी क्रम में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में उप मुख्य मंत्री वित्त मंत्री और हमारे चिकित्सा मंत्री की देखरेख में आयुष्मान आरोग्य योजना को लागू करने का निर्णय लिया, जिसमें शिशु और छोटे बच्चों के इलाज के लिए पैकेज जोड़े गये।

साथ ही, छोटे और दूर के स्थान पर चिकित्सा सुविधा देने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी नियमों में छूट देकर योजना में शामिल किया। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, मुख्य मंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना लागू किये जाने की घोषणा की है।

आप और हम सब और सम्पूर्ण सदन पूर्णतया धन्यवाद देता है कि अद्वितीय कार्य प्रथम बार पहले बजट के साथ शुरू हुआ है। इसके अलावा प्रदेश की दूर-दूराज की जनता को अच्छी चिकित्सा सुविधा के लिए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक-एक आयुष्मान मॉडल सीएचसी बनाने की घोषणा की, जिसमें जनता को सारी सुविधाएं मिलेंगी और बेहतर चिकित्सा सुविधा होगी। सरकार द्वारा इस पर 125 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 500-1000 चिकित्सकों तथा 4000 हजार नर्सिंग कर्मियों के नये पदों का सृजन किया जायेगा। इन पदों पर भर्ती होने से जो हमारे पद खाली हैं, वे भी भरेंगे। जनता को अच्छी सुविधामिलेगी।

सभापति महोदय, जयपुर स्थित सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय के अधीन

निर्माणाधीन 1 हजार 200 बैड के आईपीडी टॉवर की सुविधा आम जन को उपलब्ध हो सके। इसके लिए आयुष्मान टॉवर को और अधिक सुविधा युक्त बनाने हेतु आवश्यक उपकरणों आदि की खरीद करने तथा मरीजों एवं उनके परिजनों को सुनिश्चित वाहन पार्किंग सुविधा देने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

हमारे जयपुर का एसएमएस अस्पताल, इस राजस्थान की एक लाइफ लाइन के रूप में हैं। आज राजस्थान ही नहीं, अपितु हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि बाहर के प्रदेशों से मरीज आते हैं और उन सबको यहां लाभ मिलता है। आरयूएचएस में सुविधाओं के लिए भी हमारी सरकार 200 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

कोरोना काल में जो स्थितियां थीं, वह आप हम सबको पता है। मैं स्वयं प्रमाण हूं, कोरोना काल में मेरी मां, मेरे कई रिश्तेदार बीमार थे। उस कोरोना काल में मैंने यहां, आज कुछ सदस्य हैं, कुछ हार गये हैं तो इसलिए नहीं हैं, उनके कर्मों से हारे, जैसा अभी श्रवण जी ने कहा। मैंने सब जगह गुहार लगाई थी, सब जगह मदद की मांगी की थी और सिलेंडर तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे।

केन्द्र सरकार का अनगिनत बजट और पूरी योजनाओं को लाभ..। महोदय, मंत्र अपनी जगह है और चिकित्सक अपनी जगह है। अभी जैसा माननीय सदस्य ने चिकित्सक, जो देवतुल्य धरती के भगवान हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं। जिनका भी अपमान अभी यहां सदस्य ने किया। इन धरती के भगवानों को जेब काटने वाला बताकर, जो आपने अपमान किया, मैं उसकी निन्दा करता हूं। इनका अपमान आप यहीं नहीं कर रहे हैं, चौमू से आने वाली सदस्या का भी आप कर रहे हैं, वे भी डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। आप समस्त डॉक्टरों के लिए इस तरीके से नहीं कह सकते, कोई एकाध गलती करे तो।

Bhs/Rtm/19.7.24/16.20/3a

अब पिछले कोरोना काल का मैं बता दूं, मेरी मां तो भगवान को चली गईं और लगभग पन्द्रह हजार रुपये एम्बुलेंस वाले ने मांगे थे उस समय। सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी और पन्द्रह हजार रुपये एम्बुलेंस वाले ने मांगे थे झोटवाड़ा से एसएमएस ले जाओ या झोटवाड़ा से आप महात्मा गांधी ले जाओ पन्द्रह हजार रुपये एम्बुलेंस वाले ने मांगे थे। मैंने चहुं ओर फोन किये थे। बड़े-बड़े मंत्रियों को फोन किये थे। रघु जी को भी फोन किया था उनके पुत्र को भी फोन किया था। मैं स्वयं गवाह हूं और मैं ही नहीं मैं जब गांव से चला था तो अनगिनत ऐसे पेशेन्ट थे उस समय जो हाहाकार मचा था उस हाहाकार में चहुं ओर यही हालत थी कि न एम्बुलेंस थी, न डॉक्टर था, न सुविधा थी, बहुत बुरा हाल था चिकित्सा व्यवस्था का।

आप बात करते हो, तारीफें करते हो असत्य और उस कोरोना काल में आपने जिस तरीके से चाँदी कूटी है और आपके अधिकारियों ने मिल कर जो अव्यवस्थाएं उस समय फैलायी थी उसका ही यह प्रमाण है कि आज आप उधर बैठे हो और हम इधर बैठे हैं और यह जो पाप

आपको लगेगा यह सम्पूर्ण जीवन आपको माफ नहीं कर पायेंगे, माफी आपको मिलेगी नहीं। जनता ने जो उस समय त्रासदी झेली थी आप लोगों के द्वारा। लम्पी में भी यही हाल था और कोरोना में भी यही हाल था क्योंकि मैं स्वयं भी एक गोपालक हूं और एक गोशाला संचालित करता हूं तो वह भी मैंने नजदीक से देखा था यह।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र हवामहल की चिकित्सा सम्बन्धी समस्याओं की ओर भी मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र परकोटे में आता है, अपरा काशी है, प्राचीन शहर है। पूरी दुनिया और यूनेस्को में जाना जाता है। इस परकोट में छोटी-छोटी तंग गलियां हैं और कुछ गलियां तो दो-दो फीट की, तीन फीट की, ढाई फीट की भी हैं। वहां पर एम्बुलेंस आ-जा नहीं सकती कोई अगर समस्या ऐसी आ जाये तो। कुछ क्षेत्र पहाड़ी भी है तो एम्बुलेंस की वहां व्यवस्था कर नहीं सकते क्योंकि एम्बुलेंस वहां आ-जा नहीं सकती। माता-बहनों और बुजुर्गों को कई बार कई प्रकार की परेशानियां एम्बुलेंस की वजह से झेलनी पड़ती है और कई बार नुकसान भी हो जाते हैं। इन तंग गलियों में एक मोटर बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था आजकल हुई है, सुविधा हुई है, मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय के माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी यहां विराजमान हैं कि आप मोटर बाइक की जो एम्बुलेंस की व्यवस्था है वो हमारे परकोटे क्षेत्र में करवायें।

सभापति महोदय, इसके अलावा परकोटे में गणगौरी अस्पताल जो मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक मिनी एसएमएस के रूप में है। गणगौरी अस्पताल जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है। गणगौरी अस्पताल में विधायक बनने के पश्चात यहां बहुत सारे विधायक पचास-पचास साल का अपना अनुभव बता रहे हैं, अपने कार्य का और मुझसे पूर्व विधायक वहां भारी भरकम मंत्री भी रहे हैं। मैं नया हूं लेकिन सच्चाई आपको अवगत कराना चाहता हूं। आप लाइव वीडियो निकाल कर देख सकते हैं। यहां बातें हम कर रहे हैं बड़ी-बड़ी गरीब की, इसकी, उसकी, लेकिन जब केन्टीन में जाकर आप लोग हो-हल्ला करके ताली पीट करके आपस में बात करते हो तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि वह अन्दर जो गरीब के कल्याण की बात करता था वह यहां आकर कैसे भूल सकता है।

सभापति महोदय, मैं अनुभव बता रहा हूं आपको। जब प्रथम बार गणगौरी अस्पताल में गया तो मैंने पाया कि जो पेशेन्ट के साथ परिजन आते हैं वो बाहर खुले में स्नान करते हैं और वहां उनके विडियो बनते हैं, फोटो बनती है। मुझे इस बात का दुःख हुआ, पीड़ा हुई। दूसरा, जब गणगौरी अस्पताल में महिला शौचालय इत्यादि देखे गये तो भारी भरकम करोड़ों रुपये का बजट गणगौरी अस्पताल को रिपेयरिंग के लिए, डवपलमेंट के लिए आता था तो गणगौरी अस्पताल में वहां शौचालयों के गेट भी मुझे नहीं मिले। मेरा पहला ही दौरा गणगौरी अस्पताल का किया था मैंने और मैंने यह चीज पायी और मैंने लाइव करके यह दिखाया।

श्री सभापति: विराजिये, साहब।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): दो मिनट और लूंगा, साहब। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार के समय स्मार्ट सिटी के नाम पर गणगौरी अस्पताल में बहुत सारा बजट

आया था लेकिन बजट का इतना दुरुपयोग हुआ है कि पूरा पैसा बेकार चला गया जो काम स्मार्ट सिटी के तहत गणगौरी अस्पताल में कराया गया है वह बिलकुल रद्दी है, खराब है, उसकी गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरी मांग है कि उसकी गुणवत्ता की जांच करानी चाहिये। गणगौरी अस्पताल में जो भी पैसा पिछली सरकार में डवलपमेंट के लिए रिपेयरिंग के लिए आया, जीर्णोद्धार के लिए आया उसकी जांच होनी चाहिये। मैं चाहूंगा कि इन कामों की जांच करायें, दोषियों को सज़ा हो और भविष्य में ऐसा भ्रष्टाचार न हो।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जयसिंहपुरा खोर बहुत बड़ा इलाका है वहां पर पचास से साठ हजार की जनसंख्या निवास करती है। लोगों को वर्तमान में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। पिछली कांग्रेस सरकार ने इस क्षेत्र को चिकित्सा सुविधा से वंचित रखा इसलिये मेरी मांग है कि जयसिंहपुरा खोर में एक सेटेलाइट अस्पताल खोलना चाहिये।

श्री सभापतिः विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): माननीय सभापति महोदय, एक ही मिनट में। नयों को थोड़ा ज्यादा समय दिया करें। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गणगौरी अस्पताल में चिकित्सकों की बड़ी कमी रहती है। वहां पर विशेषज्ञ के पद खाली हैं और उन्हें भरने की कृपा करें इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर कुछ विशेष विशेषज्ञों की आवश्यकता है जैसे ईएनटी की आवश्यकता है, अस्थी रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता है। इसी के साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में गणगौरी अस्पताल में आमजन को काफी जांच सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, परिस्थितियों को देखते हुए गणगौरी अस्पताल में बड़ी जांचों की, एमआरआई, सीटी-स्केन, हार्ट सम्बन्धी जांच जैसे 2डी ईको, टीएमटी की सभी जांच के साथ-साथ हार्ट सर्जरी की सुविधा की बड़ी मांग है ताकि हमारे प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस का बोझ कम हो सके। जैसा अभी मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वर्तमान सरकार भाजपा जब थी उस समय एसएमएस अस्पताल का लोड कम करने के लिए चहुं ओर चारों तरफ ही काम किया गया। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में परकोटे में भी इस काम को किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापतिः बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री राजेन्द्र पारीक जी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मांग संख्या 27 और 28 पर अपने विचार रखने के लिए मुझे आज्ञा दी।

हमारे शास्त्र कहते हैं कि

'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुखःभाग् भवेतः।'

फिर भी अनायस, अकस्मात कई बार विपदाएं आती हैं। 2020 में हमने देखा कोरोना जैसी एक बीमारी ने केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिस तरह से अपना घातक असर दिखाया उस वक्त हम कितने बेबस लाचार और असहाय थे, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इससे विमति रखता हो। उस वक्त इस बात का अहसास हुआ कि हमारे

संसाधन, हमारे बड़े-बड़े अस्पतालों में इन्फ्रास्ट्रक्चर की कितनी बड़ी कमी है, ढांचागत व्यवस्थाओं की कितनी बड़ी कमी है। अस्पताल में बेड नहीं, ऑक्सीजन की कोई स्थिति नहीं लेकिन एक सुकून भरी बात उस वक्त यह हुई कि माननीय मुख्य मंत्री गहलोत साहब ने उस वक्त जहां एक-एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की परेशानी थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर की परेशानी थी, माननीय गहलोत साहब ने वो सारी व्यवस्थाएं की और मुझे कहते हुए गर्व है इस बात का, मैं स्वयं साक्षी हूं इस बात का कई बार ऐसी स्थितियां बनी कि पचास-पचास हजार रुपये के इंजेक्शन की यदि कभी जरूरत पड़ी तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कभी इस बात के लिए इंकार नहीं किया।

आज इस सदन में जिस गहन विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं यहां बैठ करके हम तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से मैली है और मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा साफ है, यह करने के बजाय हम यह चाहेंगे कि यह सदन हमसे अपेक्षा रखता है, हम कुछ ऐसे सुझाव रखें हम कुछ ऐसी बात रखें जिससे यह हमारा प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी हो। जब सरकार ने 27,660 करोड़ रुपये का बजट रखा है तो निश्चित रूप से सरकार की भी यह मंशा होगी कि हम ढांचागत व्यवस्थाओं को सुधारें। आमजन की भी यह अपेक्षा होगी कि व्यवस्थाओं में सुधार हो लेकिन कुछ जो मूलभूत परेशानियां हैं जो हमें बार-बार इस ओर इंगित करती है कि यदि इन बातों में सुधार नहीं हुआ, यदि वास्तव में हमने कुछ सुधार नहीं किये, कुछ अच्छे उपाय नहीं किये तो यह सारा जो हम बजट में रखते हैं, बजट तो पहले भी सैंक्शन हुए हैं, आगे भी सैंक्शन होंगे, सरकारें आयेंगी, जायेंगी, अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से वो सारा काम भी करेगी लेकिन हमें इस बात की आज महती आवश्यकता है।

मैं इसका छोटा सा नमूना सभापति महोदय, पेश करूं, विगत सरकार ने 16 मेडिकल कॉलेज खोले जो राजमेस द्वारा संचालित हैं। राजमेस के जो नियम हैं वो आरएसआर से भिन्न हैं और उसके चलते फेकल्टीज वहां पर नहीं आ रही है और फेकल्टीज नहीं आने का सबसे बड़ा नुकसान कब हुआ जब अभी इस सरकार ने पांच नये कॉलेज खोले। नेशनल मेडिकल काउन्सिल से उन्होंने इस बात की अपील की कि हमें इजाजत दें।

Kas/rtm/19.07.2024/16.30/3b

नेशनल मेडिकल काउंसिल ने उनकी अपील को ठुकराया। न केवल उनकी अपील को ठुकराया, बल्कि राजमेस की मेडिकल कॉलेजेज पर उन्होंने फाइन लगाया। यह हम लोगों के लिये एक चिंतनीय विषय है। मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिये साधुवाद दूंगा कि इन्होंने अभी इस बार बजट में घोषणा की है कि आर.एस.आर. लागू करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा आर.एस.आर. लागू कब करेंगे, इस पर बड़ी विसंगति है। जिन राजमेस के प्रोफेसर्स, डाक्टर्स ने तीन-तीन साल लगातार कॉलेज चलाया, दोयम दर्जे की सैलेरी ली, आज आप उनको बाहर रख रहे हैं? आज उनमें इस बात के लिये बड़ा आक्रोश है। सारे के सारे मेडिकल कॉलेज के करीब 800

प्रोफेसर्स इस बात के लिये चिंतित हैं कि दोयम दर्जे में रहकर भी राजस्थान की मेडिकल व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिये हमने प्रयत्न किये। आगे बढ़कर उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। आज वह अध्यापक आर.एस.आर. से बाहर रहेंगे और नये अध्यापक आर.एस.आर. के नियमों से संचालित होंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिये और जिन अध्यापकों ने प्रयत्न और कोशिश करके लगातार मेडिकल को संचालित किया है, उनको भी इसमें सम्मिलित करना चाहिये, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, आज फैकल्टीज की कमी का असर न केवल विद्यार्थियों की शिक्षा पर पड़ता है, बल्कि नेशनल मेडिकल काउंसिल भी बार-बार इस बात की चेतावनी देती है कि इस बार यदि आपने फैकल्टीज की व्यवस्था नहीं की तो हम स्टूडेंट की स्ट्रेंथ जो 100 है, उसको कम करके 50 कर देंगे। माननीय सभापति महोदय, यह और भी बड़ी चिंता का विषय हो जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि मेडिकल कॉलेज में आपने प्रोफेसर्स लगा दिये, जैसे मैं आपसे सीकर की ही बात करूं, आपने वहां पर हार्ट के दो डाक्टर लगा दिये। विगत डेढ़-पोने दो साल से पैथलैब के लिये टेंडर प्रोसेस होने के बावजूद भी हम आज इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब टेंडर खुलेंगे और कब सीकर में पैथलैब चालू होगी। आज बीकानेर के बाद जयपुर तक गवर्नमेंट का कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहां हार्ट पेशेंट आकर अपना इलाज करा सकें। उन्हें सरकारी अस्पतालों के बजाय प्राइवेटों में जाना पड़ता है और उनका खर्चा होता है। काफी संख्या में कई बार परेशानी में आदमी कहीं भी जाकर इलाज कराता है। डेढ़-पोने दो साल से लगातार टेंडर प्रोसेस में योजना चल रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अपेक्षा करता हूं कि जल्द से जल्द इस टेंडर प्रोसेस को फाइनल करके सीकर में पैथलैब की व्यवस्था करें। दो अध्यापक इसमें लगे हुए हैं, उन अध्यापकों की चिंता यह है कि हम लगातार प्रेक्टिस में नहीं रहेंगे तो हमारी इस योग्यता, जो उन्होंने चंडीगढ़ पीजी और एम्स से पीजी की है, उनकी इस योग्यता का क्या होगा?

माननीय सभापति महोदय, चूंकि हमारे मंत्री महोदय स्वयं होटेलीयर हैं, वह इस बात को बखूबी समझते हैं, आज हमारे अस्पतालों की स्थिति क्या है? आप बड़े से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां लगा दीजिए, बड़े से बड़े ए.सी. लगा दीजिए, बढ़िया से बढ़िया पर्दे लगा दीजिए, कालीन बिछा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन सफाई की क्या स्थिति है? जो डाक्टर स्वयं वहां सेवा दे रहा है, वह स्वयं अपना नाक-मूंह सिकोड़ता है। मंत्री महोदय, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, सफाई के मामले में आप किसी से भी बेहतर जानते हैं, आप स्वयं होटेलीयर हैं। होटल में जिस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, आज आप एस.एम.एस. की स्थिति देखिए, क्या एस.एम.एस. में जाकर हम टॉयलेट का यूज कर सकते हैं? कब सुधरेंगे हम? हमारी पहली प्राथमिकता सफाई की होनी चाहिये, उसको हमने लास्ट में रखा हुआ है। इसमें

सुधार नहीं करेंगे तो हम चाहे कितना ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, यह व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी। अभी एक नई बीमारी 'चांदीपुरा' हमारे सामने आई है, गुजरात से आ रही है। कोरोना से हम निपटे नहीं, 'चांदीपुरा' का उदयपुर में प्रकोप चालू हो गया। माननीय सभापति महोदय, मेरा यह विशेष निवेदन रहेगा कि मेडिकल कॉलेज खोलना और उनमें व्यवस्थाएं करना, आज बीकानेर के बाद जयपुर तक आप देखें तो एक मात्र एस.एम.एस. है। मेरा निवेदन है सीकर में रेडियोलॉजी, न्यूरो विभाग की व्यवस्था हो। सीकर इतना बड़ा सेंटर हो गया, जहां से इतने पेशेंट केटल होते हैं, माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि सीकर में एक कैंसर और यूरोलॉजी विभाग की आपको निश्चित रूप से घोषणा करनी चाहिये। कई बार पेशेंट जयपुर आते हैं तो रात को 12-12 बजे तक उनको अपनी थैरेपी कराने के लिये रुकना पड़ता है। लीनियर थैरेपी के लिये उनको रुकना पड़ता है, कभी किसी काम के लिये रुकना पड़ता है। इतने भारी-भरकम बजट के बाद भी यदि हम यह व्यवस्थाएं नहीं कर पाये तो माननीय सभापति महोदय, कब करेंगे?

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे एक माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि कोरोना में इस तरह की अव्यवस्थाएं हुईं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री ने न ताली बजवाई, न थाली बजवाई, न टॉर्च जलवाई, उन्होंने व्यवस्था की। उस व्यवस्था का ही परिणाम है कि पूरे हिन्दुस्तान में स्वयं माननीय प्रधान मंत्री जी को भी कहना पडा कि भीलवाड़ा मॉडल श्रेष्ठ मॉडल है, जिसमें कोरोना की व्यवस्थाएं सुदृढ़ हुई।

माननीय सभापति महोदय, मैं बड़े दु:ख के साथ एक बात कहना चाह रहा हूं, सीकर मेडिकल कॉलेज में एक आदिवासी छात्र था हनीवेश। वहां पर उसकी दुर्घटना में मृत्यु हुई और परिजनों ने यह आशंका जाहिर की कि इसका मर्डर किया गया है। आज एक वर्ष होने को आया, आज भी वह मामला पेंडिंग है। बराबर उसके परिजन आते हैं, कोशिश करते हैं, लगातार पुलिस वालों और प्रशासन से मिलते हैं। दु:ख की बात यह है कि एक साल होने के बाद भी उस हनीवेश ने जो फीस जमा कराई थी, वह तक वापस नहीं लोटाई है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि गरीब परिजन अपना बेटा खो चुके और उसके बाद उसकी फीस तक आप नहीं लोटा पा रहे हैं, उसकी जांच पूरी नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे मामले में क्या बीतती होगी?

श्री सभापति: विराजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट और लूंगा मैं। मंत्री महोदय, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, जन औषधि केन्द्र पर जिस तरह से जेनेरिक दवाइयां मिलती हैं, आमजन उन दवाइयों की पहचान कर सके और जन औषधि केन्द्र पर जिस तरह की कीमत लगती है, वैसी की वैसी कीमत आम मेडिकल स्टोर पर यदि उसको उपलब्ध होगी तो जो बड़ा पैसा देकर उनको दवाइयां खरीदनी पड़ती है, उससे मुक्ति मिलेगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जन औषधि केन्द्र पर जिस तरह से जेनेरिक दवाइयां मिलती हैं, उसी तरह से मेडिकल स्टोर्स पर

भी आम आदमी को जेनेरिक दवाइयां एम.आर.पी. के बजाय जो जन औषधि केन्द्र पर मिलती है, उसी कीमत पर मिले। आपने मुझे समय दिया, आपका मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री अर्जुन लाल।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय मंत्री महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मंत्री महोदय, इतनी योजनाएं लागू हो गईं, आयुष्मान योजना, भामाशाह योजना, चिरंजीवी योजना, मां योजना, आम आदमी इस बात से बड़ा कंफ्यूज है। मेहरबानी करके आप एक नोटिफिकेशन निकलवाएं कि इन-इन योजनाओं में इस तरह से इलाज होता है। अख़बार में यदि आयेगा तो आमजन को लाभ मिलेगा, क्योंकि कई बार आदमी पूछता है कि इस योजना में हमारा यह ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा? आपको सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकालना है, अख़बार में आपको पब्लिश कराना है कि सरकार की इन-इन योजनाओं में आम आदमी अपना इलाज करा सकता है, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हमारी भामाशाह योजना को ही आपने चिरंजीवी कर दी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): मैं आप और तुम की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी कमीज आपकी कमीज से ज्यादा सफेद, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक सुझाव दे रहा हूं कि जो भी योजनाएं हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप विराजिए। श्री अर्जुन लाल।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मांग संख्या 28 चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत आभार। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः विराजिए, सुन लिया आपकी बात को, अमल करने वाली होगी तो अवश्य करेंगे। श्री अर्जुन लाल।

msk/rtm/19.07.2024/1640/3c

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): सभापति महोदय, स्वास्थ्य के लिए,

'शरीरमाध्यम खलु धर्म साधनम्'

सब धर्मों का पालन करने के लिए यदि कोई माध्यम है तो शरीर है। शरीर जब स्वस्थ रहता है तो सातों सुख प्राप्त हो जाते हैं। मेरे पूर्व वक्ता ने अभी बात कही थी कि सात सुख में पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धन और माया है। जब धन और माया पास में होती है तो हमने 2020 में कोरोना काल में अनुभव किया कि सबके पास खूब धन था, खूब माया थी, लेकिन स्थितियां वे बनी थीं कि केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में कोरोना की चपेट में आने से एक भयानक दौर आ गया था। वैसे भी कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सच्चा धन है।

इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा

ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए और चिकित्सा सुविधाओं के लिए जो बजट दिया है, वित्तीय वर्ष के बजट में करीब 27 हजार 660 करोड़ दिये हैं और पूरे बजट का 8.26 परसेंट है। जिससे प्रदेश की चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने जो आयुष्मान भारत योजना लागू की है, जिससे आम जन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों। उसी तर्ज पर हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू कर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज कराने के साथ ही आईपीडी व डे-केयर सेंटर पैकेज, छोटे शिशु व बच्चों पीडियाट्रिक पैकेज व अन्य चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु एक बहुत कदम उठाया है।

इस मौके पर जो उन्होंने घोषणाएं की थीं, जिसमें प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक आयुष्मान मॉडल सीएचसी स्थापित करने की घोषणा की थी। इससे पूरे दूरस्थ क्षेत्रों में, जहां हमारा रेगिस्तानी इलाका है, उन क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। साथ ही, जो मॉडल सीएचसी होगी, उसमें मोर्चरी के निर्माण की घोषणा भी इन्होंने की है। साथ ही साथ, इस बजट में छह उप जिला अस्पतालों का जिला अस्पताल में क्रमोन्नयन, दो सैटेलाइट अस्पतालों से जिला अस्पताल में क्रमोन्नयन, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का जिला अस्पताल में क्रमोन्नयन, 42 सीएचसी को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत। इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा को भी उप जिला अस्पताल घोषित किया। दो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नयन, 28 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन, 7 नवीन पीएचसी से सीएचसी में खोलने की घोषणा की। 17 हैल्थ सब सेन्टर का पीएचसी में क्रमोन्नयन, 25 स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन और बेड स्ट्रेन्थ बढ़ाने की भी घोषणा की है। ऐसे 25 नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलना भी प्रस्तावित हैं।

इसके साथ राजस्थान डिजीटल हैल्थ मिशन की घोषणा की, जिससे हमारे अस्पतालों में लंबी लाइनें लगती हैं, कतारें लग जाती हैं। यहां प्रत्येक पेसेन्ट का बीमारी सम्बन्धी रिकॉर्ड का संधारण किया जायेगा और इससे उनको वेटिंग के समय से निजात मिल जायेगी। इसके साथ जो सबसे बड़ा काम किया है, 1500 डॉक्टर्स और 4 हजार नर्सिंग की भर्ती। यह एक बहुत बड़ा सराहनीय और स्वागत योग्य कदम है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी विराजे हैं, इन्होंने परसों प्रश्न में भी यह कहा था कि हमारी सरकार विज्ञप्ति भी निकालेगी, उनके इंटरव्यू भी होंगे और हम उनको भर्ती भी करेंगे। इसके तहत इन्होंने 1758 एलटीएम रेडियोग्राफर की भर्ती की है, इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित बात करना चाहूंगा। पूर्ववर्ती सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो घोषणाएं कीं, तीन साल पहले घोषणाएं कीं। एक तो, जिसको पूर्व मुख्य मंत्री जी अपना दूसरा घर बताते थे। पिपाड़ शहर, वहां पर उप जिला अस्पताल की उन्होंने घोषणा की। उस बात को तीन साल हो गये। वहां न तो जमीन की उपलब्धता है, न वहां पर उनके

लिए कोई पैसा दिया हुआ है, केवल घोषणा रह गयी। आज भी वह सारा मामला लिटीगेशन में चला गया। इसके साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के अन्दर रेडाना पीएचसी की घोषणा की, वहां भी जमीन उपलब्ध नहीं। दो साल हो गये उसके बाद भी आज तक उस पर एक पैसा भी नहीं लगा। न इन अस्पतालों के क्रमोन्नयन में या इनके जो नव सृजित पीएचसी हैं, उसमें एक भी डॉक्टर या कोई स्टाफ नहीं लगा था। जो सब-सेन्टर का स्टाफ था, वह आज भी वही काम कर रहा है। ऐसे ही 2010 के अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र में बोरून्दा की सीएचसी की घोषणा की गयी थी। उसमें 30 बेड का अस्पताल उसको घोषित किया था। पीएचसी में कम से कम एक-दो डॉक्टर होते हैं, लेकिन वहां एक-दो डॉक्टर नहीं है। यह स्थिति बना रखी है। मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो बोरून्दा सीएचसी है, इसमें पता नहीं पदों की कटौती क्यों कर दी गयी। आपके यहां से एक आदेश निकला था। आठ डॉक्टर लगे हुए थे, उनमें से उन्होंने सात पदों की कटौती कर दी। मुख्य मंत्री जी ने जो उप जिला अस्पताल घोषित किया है, उस सीएचसी के पास में ही हमारा ट्रोमा सेन्टर बना हुआ है। वास्तव में, उस ट्रोमा सेन्टर से, मैं मानता हूं कि कम से कम सैंकड़ों लोगों की जान बची है, क्योंकि उनका जो गोल्डन टाइम होता है, उस गोल्डन टाइम में वे जोधपुर पहुंच जाते हैं तो उनकी जान बच जाती है। वहां पर इलाज होता है, लेकिन उस यूनिट को सीएचसी के अण्डर में लगा रखा है। ट्रोमा सेंटर को अलग यूनिट बनाकर उसमें स्टाफ वगैरह भिजवायें। क्योंकि अभी ट्रोमा सेंटर में आर्थोपैडिक्स के डॉक्टर्स हैं, बाकी डॉक्टर्स सीएचसी से बुलाने पड़ते हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि कम से कम इस ट्रोमा सेन्टर को अलग यूनिट बनायी जाये और इसमें अलग से स्टाफ भेजा जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिन गांवों की आबादी 10 हजार से अधिक है, वहां पीएचसी सुचारु रूप से चल रहे हैं, लेकिन उसमें उनको सीएचसी के अन्दर क्रमोन्नत करवायें। जैसे कि कापड़ा, रांसी गांव, खरिया मीठापुर, खेजरला है, भवी है, ये बड़े गांव हैं, 10 हजार से अधिक की आबादी के हैं, इनमें सीएचसी में क्रमोन्नत करवाने की घोषणा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। साथ ही, अभी बात चली थी। सूरजगढ़ से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में कहा था।

mdp/rtm/19.07.2024/16:50/3d

इसमें जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह कम से कम क्योंकि जिला मुख्यालय पर एक या दो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं। सब-डिवीजन लेवल पर एक ड्रग इंस्पेक्टर होना चाहिए ताकि मिलावटी जो खाद्य पदार्थ मिलता है, उनकी जांच हो और उनकी ताकीदी बराबर रहे। अभी इन्होंने कहा था कि वह जांच नहीं करते हैं। जांच होती है, लेकिन हमारे में से ही कुछ लोग प्रभावित कर देते हैं।

श्री सभापतिः समाप्त कीजिए। बहुत हो गया।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): सिर्फ एक मिनट। हमारे धर्मशाला है जो बनी है। हमारी पूर्व

मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने प्रत्येक सीएचसी पर धर्मशालाएं बनायी थीं, जो पेशेंट के परिजन आते हैं, उनके ठहरने के लिए। मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करुंगा कि उन धर्मशालाओं में बीसीएमओ ऑफिस खोल दिए। उनको धर्मशाला के प्रयोजन से काम में नहीं ले रहे हैं। उनको खाली करवाकर बीसीएमओ ऑफिस अलग से बनवाकर परिजनों के लिए उनको खाली करवाएं। मैंने जो मांग की हैं, मंत्री महोदय, इनको पूरा करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः विराजिए, साहब। श्री यूनुस खान।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अनुदान मांगों पर विचार के लिए मांग संख्या 27 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और मांग संख्या 28 चिकित्सा शिक्षा पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जो समय निर्धारित है, उसी में मैं अपनी बात कहने का पूरा प्रयास करूंगा।

कल माननीय मुख्य मंत्री जी का एक बयान आया कि 8 करोड़ राजस्थान के नागरिक मेरा परिवार है। उसका स्वागत है, क्योंकि 8 करोड़ की जनसंख्या माननीय मुख्य मंत्री जी मानते हैं। अगर हम जनसंख्या को आधार बनाए और राजस्थान के अन्दर जो हमारी पीएचसी और सीएचसी हैं, उनकी अगर संख्या जोड़े, अगर इस 8 करोड़ में हम भाग दें इन 3,398 सीएचसी/पीएचसी पर और जो डाक्टर्स की संख्या हैं, उसका हम भाग दें तो 6 हजार लोगों पर एक डाक्टर है, ग्रामीण क्षेत्र में। 6 हजार लोग जहां हैं, वहां एक डाक्टर है। हमारी ग्राम पंचायतों का हम देखें तो साढ़े तीन ग्राम पंचायतों पर या तो एक सीएचसी है या पीएचसी है। हमारे राजस्थान में 48,023 राजस्व ग्राम हैं, लगभग एक लाख ढाणियां हैं। उनका अगर आंकडा देखें तो सवा चौदह गांवों पर एक पीएचसी/सीएचसी है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, इस मंत्रिमंडल के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं। सौभाग्य है इनका कि ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बने हैं, वरिष्ठतम मंत्री हैं। बहुत काबिल और योग्य हैं। मुझे विश्वास है कि ये भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, खींवसर अब जाकर पंचायत समिति बनी है। इनका गांव भी ग्रामीण क्षेत्र में हैं। ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं जिस स्तर की होनी चाहिए थी, वह चिकित्सा सुविधाएं आज तक नहीं हो पायी। उसके बहुत सारे कारण हैं। इनके प्रगति प्रतिवेदन को जब मैंने देखा, इनके जिला चिकित्सालय और उप जिला चिकित्सालय में जो राजपत्रित डाक्टर्स हैं, उनकी स्वीकृत संख्या 18,036 हैं, उसमें 14,073 लोग कार्यरत हैं, लगभग 3,963 पोस्ट आज भी उस क्षेत्र में खाली पड़ी हैं। यानी एक तरफ तो 14 गांवों पर माननीय मंत्री महोदय, एक अस्पताल और उसमें भी पीएचसी, सीएचसी खाली है तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसका अध्ययन करवाकर कम से कम हर अस्पताल में एक डाक्टर तो हो। माननीय मंत्री महोदय, आपके कागजों में है, क्योंकि डेपुटेशन पर चले गये या हमने उसकी पोस्टिंग दिखा रखी है और वह बैठा कहीं और है। इसके बहुत सारे उदाहरण माननीय सदस्य देंगे।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके जो अराजपत्रित अधिकारी हैं, उनकी स्वीकृत

संख्या 1 लाख 1 हजार 404 हैं, जिसमें आप मान लीजिए नर्सिंग अधीक्षक से लेकर नर्सिंग ऑफिसर, लेब टेक्निशियन, वार्ड बॉय सहित इस 1 लाख 1 हजार 404 में कार्यरत 61 हजार 974 हैं। यानी 39 हजार 430 रिक्त पद पड़े हैं। यानी 40 प्रतिशत आपकी उसमें भी खाली हैं। यह कोई आपका दोष नहीं है, माननीय मंत्री महोदय, आप तो अभी आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी क्षमता, योग्यता व कार्य करने की शैली से इस काम को पूरा करेंगे। नये डाक्टर्स की भर्ती करके ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं देंगे।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि समय बहुत कम रहता है, इसलिए प्रदेश की बातें मैं बहुत ज्यादा नहीं करुंगा। मेरे से पहले माननीय पूर्व चिकित्सा मंत्री माननीय कालीचरण जी बता रहे थे कि जो राजमेस है आपका, यानी आपने जो राजमेस बना रखी है, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी, उसमें भी 62 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। सत्ताधारी दल का व्यक्ति, मंत्री रहे हैं वे, मंत्री महोदय, 62 प्रतिशत पद खाली हो तो क्या स्थिति होगी? इस स्थिति को सुधारने के लिए आपसे उम्मीद है। हम आरोप लगाते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने काम नहीं किया तब ही तो ये इधर बैठे हैं। काम करते तो इधर बैठते। उन्होंने ये भी कहा कि निजी क्षेत्र में लगभग 34 हजार डाक्टर पंजीकृत हैं। ये 34 हजार डाक्टर भी सेवाएं दे रहे हैं।

माननीय मंत्री महोदय, आपसे एक निवेदन करूंगा जब आप जवाब दें, यानी ऑफिस दीर्घा में जो अधिकारी बैठे हैं, उनसे आप मंगवा ले कि 2023-24 में बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया था और उस राशि में से खर्चा कितना हुआ है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की परफारमेंस आ रही है। मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि नये डाक्टर्स की भर्ती करें, नया नर्सिंग स्टॉफ की भर्ती करें, पैरा मेडिकल स्टॉफ भी भर्ती करें और उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र का, अगर संभव हो सके तो अलग केडर बना दें। ग्रामीण क्षेत्र की नौकरियां सीएचसी, पीएचसी की नौकरी अलग आप कर देंगे तो मैं सोचता हूं कि बहुत सारी चीजों का समाधान हो जायेगा।

माननीय आपका स्वागत करते हुए, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरे डीडवाना क्षेत्र के लिए, पूर्व मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा जी का बार-बार कि उन्होंने बजट 2017-18 में हमारे बांगड़ राजकीय चिकित्सालय में 8300 शय्याओं का आर्डर निकाला, मतलब बजट घोषणा की थी। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उन 300 शय्याओं को पांच साल तक लटकाए रखा। लटकाने का कारण, आरोप लगाना मेरी आदत नहीं है, लेकिन लटकाने का कारण, उस अस्पताल के चारों तरफ छोटे-छोटे चिकित्सालय खोल दिए। चिकित्सालय खोलने पर भी मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन जीरो सेटबेक पर। वहां न तो डाक्टर्स के बैठने की व्यवस्था है, न और कोई व्यवस्था है। यह काम किया गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय वसुन्धरा जी की जो बजट घोषणा थी, उसको पूरा करने की कोशिश करें।

मैं दो ही मिनट लूंगा। एक मेरा निवेदन है कि जिला बन गया, उस जिले में हमारे जिला चिकित्सालय की जमीन आवंटित की है और आवंटित ऐसी जगह की है, माननीय मंत्री

महोदय, जो सिर्फ एक गांव है और शहर से पांच किलोमीटर दूर, अब परबतसर, मकराना, नावां, डीडवाना और लाडनूं का जिला चिकित्सालय, वहां पांच किलोमीटर कौन जाएगा? मेरा आग्रह है कि जो केन्द्र प्रवर्तित योजना और राज्य सरकार दोनों मिलकर जब वहां मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो वहां पर हमारे पास 400 बीघा जमीन सोडियम सल्फेट की पड़ी है, जो सरकारी जमीन है। उस जमीन में आप जिला चिकित्सालय भी बना सकते हैं, डाक्टर्स के रहने का भी बना सकते हैं और फ्यूचर में आप मेडिकल कॉलेज भी वहां खोल सकते हैं। इसलिए आपको मैंने चिट्ठी लिखी है, माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि उस पर थोड़ा-सा ध्यान दें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे बस दो ही मिनट चाहूंगा।

श्री सभापतिः अतिशीघ्र पूर्ण करें।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): हमारे जो शहरी स्वास्थ्य केन्द्र है डीडवाना में, उसमें एक भी डाक्टर नहीं लगा हुआ है, उनके डाक्टर लगाएं। हमारे गरदेजा, बूडोद, आस की ढाणी, खूंखना, लाड़ाबांस में उप-केन्द्र हैं, उसकी भी सूची मैं आपको भेजूंगा, उनके ऊपर भी आप कार्यवाही करें। एक वसुन्धरा जी 3 मई, 2018 को गयी थी, एक अस्पताल का उद्घाटन करने। उन्होंने उस समय एक सीएचसी की घोषणा, मतलब वहां कहा कि मैं सीएचसी बना दूंगी। दुर्भाग्य की बात है कि पांच वर्ष में न तो वहां डाक्टर, जो पीएचसी के डाक्टर हैं, वह भी नहीं लगने दिए और उसको खाली रखा गया। जबकि उस गांव की शेरानी आबाद की जनसंख्या 12 हजार है। मेरा आपसे निवेदन है कि दो ये वसुन्धरा जी की घोषणाएं, इनको पूरी करें। हमारे गांव नेमीकलां बालिया, इसमें उप-केन्द्र, झाड़ोत भी हमारा एक अस्पताल है, जिसमें डाक्टर्स की कमी हैं। लगाए हैं, लेकिन वे डाक्टर रह नहीं रहे हैं। मेरे यहां 121 डाक्टरों के पद अभी खाली हैं, जिसमें 5 तो हाजिरी दिखा रहे हैं और वहां अनुपस्थित हैं। मेरा आग्रह है कि चाहे वह पीएचसी हो, सीएचसी हो, सब-सेंटर हो या सिटी अस्पताल हो, उसमें बिल्डिंग के साथ-साथ में डाक्टर्स की पोस्टिंग करें। चूंकि मुझे पता है कि आपके पास डाक्टर्स का अभाव है, इसलिए आप डाक्टर लगा नहीं पाएंगे, इसलिए पहले डाक्टर्स की नियुक्ति करें, नर्सिंग स्टॉफ का अपाइंटमेंट करें, उसके बाद में नियुक्ति करें, ये मेरा सरकार से आग्रह है।

Ans/rtm 17.00 3e 18.07.2024

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): यह जरूर बताएं कि पिछली सरकार ने जो बजट प्रोविजन किया था, उसका एक्सपंडीचर कितना है?

श्री सभापतिः श्री सुरेश मोदी।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): सभापति महोदय, आपने समय दिया धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी बहुत सक्षम, योग्य है, पूरे राजस्थान की चिकित्सा सुविधा का सुधार करेंगे, इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यूनुस जी, आज तो आप बड़े भले हो गए।

आराम से, शालीनता से।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय सभापति जी, यह हमारे सबसे लाडले संसदीय कार्य मंत्री हैं।

श्री सभापति: सबके लाड़ले हैं।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): यह पहली बार संसदीय कार्य मंत्री बने है, इनको एक परम्परा डालनी चाहिए, पक्ष-विपक्ष, हम सब लोग हैं, उनको कभी-कभी बुलाकर लंच या डिनर दे दिया, अच्छी व्यवस्थाएं कर दीं। इनको यह भी करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं।

श्री सभापति: माननीय संसदीय मंत्री जी, आप इस बात पर विचार करें।

मोदी जी।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): सभापति महोदय, सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक अपने राज्य की जनता को स्वस्थ रखना है। हर विधान सभा क्षेत्र, चाहे वहां से किसी भी दल का नेता हो, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी के साथ राज्य में चालू चिकित्सा योजना, चाहे वह किसी भी सरकार द्वारा चालू की गई थी, को बंद करने के बजाय और अधिक कामयाब बनाना मौजूदा सरकार का लक्ष्य होना चाहिए।

मुझे इस सदन में यह बताते हुए बहुत दु:ख हो रहा है कि परिवर्तित बजट 2024-25 में मेरे विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना में चिकित्सा के नाम पर एक रुपया नहीं दिया गया। उलटे जो जिला अस्पताल दो साल पहले 50.84 करोड़ रुपये का स्वीकृत हुआ था, जिसका निर्माण कार्य दो साल से चल रहा है, उसे बजट घोषणाओं में शामिल करते हुए जनता को भरमाने का काम किया है। नीम का थाना नया जिला बना है। अत: आने वाले समय में आबादी का दबाव बढ़ने की सम्भावना है। ओमीक्रोन वेरिएंट जैसी महामारी की आहट से चिकित्सा तंत्र को मजबूत किया जाना बहुत आवश्यक है।

मैं आपके माध्यम से चिकित्सा विभाग के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले 3-4 माह में साइलेंट हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक आदि से मरने वालों की संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कैंसर जैसी महामारी से तो पहले ही मरीज बहुत ज्यादा मरते जा रहे हैं, लेकिन इन 4-5 महीनों में इन दो बीमारियों से बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं। जनता इसे कोरोना में लगे वेक्सीन से जोड़कर देख रही है। जहां भी जाते हैं वहां यह बात होती है कि कोरोना का वेक्सीन लगा, उसके बाद से साइलेंट हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से मौतें हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार इन रोगों से बढ़ रही मौतों के कारणों की जांच कराए। इसके लिए डाक्टर्स की एक टीम लगाई जाए जो कारणों की जांच करे और इसे कम करने के उपाय किए जाएं।

मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए दो पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने के लिए निवेदन करता हूं। सर्वप्रथम,

अतिआवश्यक, ग्राम सिरोही की पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करना है, यह मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत है। यहां अल्ट्राटेक की सीमेंट फैक्ट्री है जहां हज़ारों कर्मचारी काम करते हैं। यहां से दो बाईपास भी गुजरते हैं, जिन पर यातायात का बहुत दबाव है, यहां एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहां की ओपीडी 58 हजार 910 एवं आईपीडी 7 हजार 502 हैं। यहां पर दानदाताओं द्वारा अच्छा और बड़ा भवन बनाया हुआ है, जिसमें सीएचसी शुरू की जा सकती है। दूसरी आवश्यक पीएचसी, जिसे सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाना आवश्यक है, वह मांडवाखुर्द है, जो पांच पंचायतों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराती है, जहां भी ओपीडी 26 हजार 726 और आईपीडी 666 है। इसी प्रकार एक नई पीएचसी नाथा के नांगल में खोलने की महती आवश्यकता है। अभी पीएचसी से जिसकी दूरी 10 किलोमीटर है। दूसरी पीएचसी बासरीखुर्द में खोलने की आवश्यकता है, जो कई गाँवों व पंचायतों के निवासियों को लाभ देगी।

मेरे जिला मुख्यालय नीम का थाना में, एमसीएच का एक नया भवन बनकर तैयार है। मेरा निवेदन है कि इसके लिए शीघ्र ही स्टाफ के लिए पदों की स्वीकृति देकर पोस्टिंग दी जाए, कोई भी कमी निर्माण कार्य या सुविधाओं में रह रही है तो स्टाफ के लोग जांच कर ले। स्टॉफ बिठाने के लिए इसी परिसर में पीडब्ल्यूडी के कमरे हैं, जिनको उपयोग में लाया जा सकता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, इस एमसीएच में ब्लड बैंक व ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति भी शुरूआत में कर दी जाएं तो यह एक बहुत उपयोगी संस्थान बन सकता है। चिकित्सा संस्थानों में स्टॉफ की कमी को भी शीघ्र दूर करने का प्रयास करें।

मेरा चिकित्सा शिक्षा के बारे में एक निवेदन है। पिछली सरकार ने हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। अधिकांश ज़िलों में इनका काम चालू भी कर दिया था। अब नये ज़िले बनाए गए हैं। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि उसी तर्ज पर, नये बने ज़िलों में भी मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी जाए। मैं यहां यह बताना आवश्यक समझता हूं कि नीम का थाना जिला मुख्यालय पर एमसीएच हॉस्पिटल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है और जिला अस्पताल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, अतः मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जिन संस्थाओं की आवश्यकता होती है, वे यहां उपलब्ध हैं। शेखावाटी के लोग चिकित्सा सेवाओं में सबसे ज्यादा है, अतः यहां नर्सिंग कॉलेज खोलने से यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा होगी। धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 व 27 पर बोलने की अनुमति प्रदान की, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, इन दोनों ही मांगों पर जब कटौती प्रस्ताव मांगे गए तो कटौती प्रस्ताव देते समय बहुत सारे सुझाव मेरे मन में थे, लेकिन कटौती प्रस्तावों में पांच प्रस्ताव ही दिए जा सकते थे। जब मैंने आज की कार्यसूची देखी, कटौती प्रस्तावों को बारीकी से पढ़ा, तो उन कटौती प्रस्तावों में चिकित्सा शिक्षा की मैं जब बात करती हूं, तब चिकित्सा

शिक्षा में 100 परसेंट, सब माननीय सदस्यों ने जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिए हैं, उन सबके कटौती प्रस्तावों में एक सुझाव तो निश्चित रूप से है कि मेरी पीएचसी और सीएचसी में डॉक्टर लगा दिए जाए या मेरे मेडिकल कॉलेज में प्रोफसर, असिसटेंट प्रोफेसर या एमओ की भर्ती कर दी जाए। इससे स्पष्ट है कि पूरे राजस्थान में जितने मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल फेसिलिटी है, उनमें डाक्टर्स की बहुत कमी है।

मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्री भजनलाल जी और माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने इस बजट में 1500 डॉक्टर्स और 4 हजार नर्सिंग भर्ती की बात की है। परन्तु डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य जब उल्लेख कर रहे थे, अगर उस लक्ष्य को मैं देखूं तो उस लक्ष्य को देखते हुए इस भर्तियों की ओर देखती हूं तो लगता है कि यह नाकाफी है। इन भर्तियों की संख्या हमें और अधिक बढ़ानी चाहिए, तभी हम राजस्थान में डॉक्टर्स की कमी को पूरा कर पाएंगे। हमेशा से ही यह मांग बनी रहती है कि राजस्थान में डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी को पूरा करो।

माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस ओर भी लाना चाहती हूं, जब इंडियन मेडिकल कौंसिल किसी कॉलेज की एफिलिएशन के लिए निरीक्षण करने आती है तो अक्सर मैंने देखा है, जेएलएन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण जब होता है तब एसएमएस मेडिकल कॉलेज से कुछ प्रोफेसर, कुछ डॉक्टर्स की पोस्टिंग कर दी जाती है। जैसे ही निरीक्षण का कार्य पूरा हो जाता है, कौंसिल के अधिकारी या डॉक्टर्स निरीक्षण पूरा कर देते हैं, तो जिनका स्थानान्तरण किया होता है, वह निरस्त कर देते हैं। यह एक तरह से मेडिकल कौसिंल ऑफ इंडिया की आंखों में धूल झोंकने वाली बात होगी कि आप कॉलेज की मान्यता के लिए, आप अस्थाई रूप से उस स्थान पर स्थानान्तरण कर देते हैं, फिर बाद में उस स्थानान्तरण को कैंसिल कर देते हैं। इससे ना केवल उसको धोखा है, बल्कि अपने आपको भी धोखा है।

VPS-RTM-19.07.2024-17.10-3f

इसलिए पी.जी. की कक्षाएं, मैं माननीय मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगी कि जितना अधिक हम पी.जी. की सीटें मेडिकल कॉलेजों में बढ़ा सके, उतनी हमें बढ़ानी चाहिए और जितने हमारे एफिलिएटेड मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल्स की संख्या जब हम देखते हैं, अभी आपने सी.एच.सी. की बात की है कि हर विधान सभा क्षेत्र में आप एक सी.एच.सी. देंगे तो उसके लिए तो आपको धन्यवाद है, परंतु मैं उसके साथ ही एक सुझाव और देना चाहूंगी कि एक-एक सी.एच.सी. आप हर विधान सभा क्षेत्र को दे रहे हैं लेकिन एक-एक सी.एच.सी. के साथ-साथ एक-एक जी.एन.एम. नर्सिंग कोर्स की सुविधा भी यदि एक-एक विधान सभा क्षेत्र पर दे देते हैं क्योंकि जब मैंने सूची देखी तो तीन ही जिले ऐसे हैं जिनमें दो नर्सिंग स्कूल संचालित हैं, बाकी सब एक-एक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर एक-एक नर्सिंग स्कूल है और एक जिला इतना बड़ा जिला होता है कि वहां पर हमारी नर्सिंग की पूर्ति

नहीं हो पाती है। यदि स्किल्ड नर्सिंग स्टाफ हमको मिलेगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और सरकारी हॉस्पिटल्स में हमें उनकी पूर्ति करने के लिए, उनको हम रोजगार भी दे पाएंगे और दूसरी तरफ हम स्किल्ड मैन पावर भी हॉस्पिटल्स में उपलब्ध करवा पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि हम जितने भी उपाय करते हैं, वे कुछ समय पश्चात नाकाफी महसूस होते हैं और ये इसलिए होते हैं क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण से जितने उपाय किये जाते हैं, वे वापस वही लौट आते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या हम इस जनसंख्या को नियंत्रित करने का किसी तरह से विचार कर सकते हैं?

स्वास्थ्य के मानकों में, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की देखभाल के प्रति कोई विशेष उपाय किये जा सकते हैं क्या? विशेषकर महिला स्वास्थ्य की ओर हम ध्यान दे सकते हैं क्या? क्योंकि महिलाओं में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। एनीमिया और पता नहीं किस कारण से, हमारी जीवनशैली के कारण से, हमारी सामाजिक परम्परा के कारण से, हमारा जो सामाजिक जीवन है, उसके कारण से महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती हैं और ऑल ओवर जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इस तरह की परेशानियां हमें दिखाई देती हैं।

अभी डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य यह बता रहे थे कि छह हजार पर एक डाक्टर हमें उपलब्ध है। मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगी कि एक डाक्टर तो हमें छह हजार पर उपलब्ध है लेकिन नर्सिंग कर्मी हमारे को दस हजार की जनसंख्या पर एक नर्सिंग कर्मी हमको उपलब्ध होता है तो हमें नर्सिंग कॉलेज खोलने की और अधिक आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मैं यह निवेदन करना चाहूंगी मेरे अजमेर के बारे में क्योंकि अजमेर का मेडिकल कॉलेज बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है और आर.यू.एच.एस. की बात हमारे मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने की है कि आर.यू.एच.एस. का नाम माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत के नाम से कर देना चाहिए। वास्तव में मैं भी इस बात का समर्थन करती हूं कि वे हमारे बड़े नेता थे और तीन बार मुख्य मंत्री रहे हैं, एक बार वे उप राष्ट्रपति भी रहे हैं तो यह राजस्थान का सौभाग्य है कि राजस्थान से वे उप राष्ट्रपति रहे तो उनके नाम से करना ही चाहिए परंतु मैं साथ में एक सुझाव और दूंगी कि जितने भी एकेडमिक कॉलेज हैं, उन एकेडमिक कॉलेज में यूनिवर्सिटीज, आज आप देखिये कि इन पांच सालों में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत सारी आएंगी, मेडिकल के क्षेत्र में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लेकिन सरकारी क्षेत्र में सिर्फ एक सरकारी यूनिवर्सिटी है तो यदि अजमेर मेडिकल कॉलेज को भी यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया जाये तो वहां की जो हमेशा मैन पावर की समस्या है, उस मैन पावर की समस्या से हम समाधान पाएंगे। आपको धन्यवाद है कि आपने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया है लेकिन वह बहुत ही नाकाफी है, उससे उसकी पूर्ति नहीं होगी।

इसी प्रकार से जयपुर के कैंसर महावीर हॉस्पिटल और एस.एम.एस. में कैंसर के रोगियों

की बहुत तादाद रहती है, दूर-दूर से लोग आते हैं तो मेरा आपको यह सुझाव है कि जो अजमेर का जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज है उसमें भी ऑन्कोलॉजी विभाग बनाया जाये और ऑन्को फिजिशियन और ऑन्को सर्जन की नियुक्ति वहां पर की जाये। एकेडमिक इंस्टीट्यूट की स्थापना वहां पर की जाये।

इसी तरह से माननीय मंत्री महोदय, एम.सी.एच. कोर्स जो अजमेर के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जाता है, इस एम.सी.एच. कोर्स में एन.एम.सी. के नॉर्म्स के अनुसार फैकल्टी की स्थापना की जाये, फैकल्टीज रिक्रूटमेंट की जाये क्योंकि फैकल्टीज नहीं होने के कारण से उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पा रहा है, सम्बद्धता नहीं मिलने के कारण से जो बच्चे एम.सी.एच. का कोर्स करते हैं, उन बच्चों को कोई उसका लाभ नहीं मिलता है तो इससे उन बच्चों को भी उसका लाभ मिल पायेगा। न्यूरो सर्जरी विभाग में फैकल्टी लगायी जाये और एम.सी.एच. का नियमन भी उसके साथ करवाया जाये। न्यूरो फिजिशियन डिपार्टमेंट की स्थापना की जाये। नर्सिंग कर्मचारियों की पूर्ति के लिए पहले ही मैंने आपको निवेदन किया कि नर्सिंग कर्मचारियों की कमी है और नर्सिंग कर्मचारियों की पूर्ति के लिए भी जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाये। रेडियोलॉजी विभाग में फैकल्टी लगायी जाये और साथ ही साथ सी.टी.वी.एस. सर्जरी में भी फैकल्टी लगायी जाये क्योंकि सी.टी.वी.एस. में जब तक आप सर्जन नहीं लगाएंगे तब तक पी.जी. कोर्स वहां पर नहीं हो सकते और जब तक पी.जी. कोर्स नहीं हो सकते तब तक वहां पर बाईपास भी नहीं होगी तो बाईपास के लिए भी लोगों को जयपुर आना पड़ता है या फिर प्राइवेट कॉलेजों में जाना पड़ता है तो मेरा यह निवेदन है कि सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए और मेडिकल हॉस्पिटल्स के लिए मैं यह सुझाव देना चाहूंगी क्योंकि सुपरिटेंडेंट, जो हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट होते हैं, वहां प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक के डाक्टर्स को लगाया जाता है तो वे अपनी प्रेक्टिस करे या पूरे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट ही देखता रहे तो इसलिए हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के लिए तो मैनेजमेंट फील्ड से ही किसी मैन पावर को लगायें, किसी आर.ए.एस. को आप डेप्यूट कर सकते हैं, किसी आई.ए.एस. को भी आप वहां पर डेप्यूट कर सकते हैं ताकि हॉस्पिटल के रख-रखाव, पानी, बिजली और सफाई की व्यवस्था हो सके। अभी सीकर से आने वाले माननीय सदस्य सफाई की बात कर रहे थे। कोई भी डाक्टर सफाई की ओर ध्यान नहीं देता है, उसको यह लगता है कि मेरी प्रेक्टिस छूट जायेगी, मेरा पेशेंट छूट जायेगा इसलिए सरकारी हॉस्पिटल्स में सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है और इसे हमें महसूस करना चाहिए इसलिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अच्छे डाक्टर्स नहीं हैं, नर्सिंग कर्मी अच्छे नहीं है, उनको फीस भी ज्यादा देनी पड़ती है लेकिन फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहां पर व्यवस्था ठीक है, सफाई ठीक है। यदि यह सफाई और व्यवस्था सरकारी हॉस्पिटल्स में ठीक हो जाये तो मैं यह समझती हूं कि सरकारी हॉस्पिटल्स में भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जैसे लोग बहुत अच्छे से आ पाएंगे क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स से ज्यादा स्किल्ड डाक्टर्स हमारे पास हैं। प्रोफेसर और उससे अधिक रैंक के लोग हमारे पास

हैं, मैन पावर हमारे पास है तो ऐसी स्थिति में हमें सरकारी हॉस्पिटल्स में सफाई की व्यवस्था की ओर ध्यान के लिए और बाकी अन्य मेन्टिनेंस के लिए, चाहे वह विद्युत की लाइन हो, चाहे नालियां हो, चाहे शौचालय हो, उन पर ध्यान देना चाहिए। अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य बालमुकुन्दाचार्य जी कह रहे थे कि कितने गंदे शौचालय की व्यवस्था वहां पर है तो ऐसी स्थिति में जहां पर हम सफाई की तो बात करते हैं, वह इसलिए करते हैं कि स्वच्छता से ही स्वस्थ रहते हैं लेकिन हॉस्पिटल्स में ही हम जब यह देखते हैं तो हमें इस प्रकार लगता है कि हॉस्पिटल्स में सफाई नहीं है तो इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरे अजमेर के सैटेलाइट हॉस्पिटल के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगी। जैसा कि अभी चौमूं से आने वाली माननीय सदस्या यह कह रही थीं कि कैश-लेस सुविधा हमने पहले प्रारम्भ की। सीकर से आने वाले माननीय सदस्य, झुन्झुनूं से आने माननीय सदस्य, क्या आप यह बता पाएंगे कि पहले आपने शुरू की या पहले हमने शुरू की? भामाशाह योजना जो इस राजस्थान की पहली कैश-लेस व्यवस्था थी, वह 2013 से 2018 के बीच में, वसुन्धराजी की सरकार में यह कैश-लेस व्यवस्था शुरू की थी और उसके अतिरिक्त अभी आपने कहा, मंत्री महोदय ने अच्छा जवाब दिया कि आप उत्तर सुनकर जाइएगा। आपने यह कहा कि दस-बारह दिन में ही नर्सिंग में जो संविदा कर्मी लगे हैं, वे नियमित हो जाते तो यह घोषणा तो कांग्रेस के घोषणा-पत्र में छपी थी कि हम संविदा कर्मियों को स्थाई नियुक्ति देंगे लेकिन आप पांच साल में नहीं कर पाये और हमसे यह अपेक्षा करते हैं कि दस-बारह दिन में ही हम यह कर लेते तो यह दोनों चीजें कैसे सम्भव हो पाएंगी?

माननीय सभापति महोदय, मैं अन्त में मेरे सैटेलाइट हॉस्पिटल की दो मांग को कहते हुए अपनी बात को पूरा करती हूं। मेरे सैटेलाइट हॉस्पिटल में माननीय मंत्री महोदय, जैसा कि ओ.पी.डी. दस हजार का है और पर मंथ तीन सौ से चार सौ डिलीवरीज वहां पर होती हैं तो ऐसी स्थिति में जितनी पोस्ट्स वहां पर जिला अस्पताल के नाते से होनी चाहिए थीं, उतनी पोस्ट्स वहां पर स्वीकृत तो हैं, लेकिन वहां पर डाक्टर्स के पदस्थापन नहीं है तो इसलिए जल्दी से जल्दी वहां पर डाक्टर्स का पदस्थापन करवाया जाये। उसी कैम्पस में हमने जगह उपलब्ध करवायी है, उस जगह पर डाक्टर्स के रेजिडेंस बनाये जाये और नर्सिंग स्टाफ भी लगाया जाये। जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज के दबाव को कम करने के लिए एक सर्जरी डिपार्टमेंट, एक मेडिकल की यूनिट वहां पर लगायी जाये क्योंकि वह जे.एल.एन. के अंडर में ही है, मेडिकल कॉलेज के अंडर में ही है इसलिए वहां मेडिकल की एक यूनिट स्थापित की जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं अन्त में माननीय वित्त मंत्रीजी को और माननीय मुख्य मंत्रीजी का, माननीय मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने एक-एक सी.एच.सी. हर विधान सभा क्षेत्र को दी है, उस नीति के तहत एक सी.एच.सी. मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी

खुलने वाली है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जितने सुझाव, जितनी डिमांड मैंने की है, उनकी ओर आप ध्यान देंगे और जब आपका रिप्लाई आयेगा तो राजस्थान में एक संदेश जायेगा कि वास्तव में यह सरकार करने वाली सरकार है, कहने वाली सरकार नहीं है। कैश-लेस की सुविधा, भामाशाह को चिरंजीवी नाम दिया गया वह कंफ्यूजन आपके कारण से हुआ, वह कंफ्यूजन जनता को किसी प्रकार का नहीं है क्योंकि जनता को अच्छे से समझ में आ गयी बात कि उस सरकार ने सिर्फ नाम बदलने का काम किया था कि हम जनता क्लिनिक खोलेंगे, जनता क्लिनिक खोलेंगे लेकिन पूरे राजस्थान में सिर्फ जयपुर के अलावा एक भी विधान सभा क्षेत्र में जनता क्लिनिक नहीं खुला। इसीलिए आज हम यहां पर हैं और आप वहां पर है और आप हमेशा वहां रहेंगे, ऐसा ही मेरे को विश्वास है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री अमित चाचाण।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 27- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं मांग संख्या 28- चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SSY/RTM/19.07.2024/17.20/3g

जब इस बार बजट पेश किया गया था तो मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता को बहुत सी उम्मीदें थी। उनको पिछले 5 वर्षों में आदत पड़ गयी थी, लगातार हर बजट में नोहर का ही नहीं नोहर के गांवों का नाम भी आ रहा था। इस बार भी उन्हें उम्मीद थी कि बजट में बहुत से नोहर के नाम आयेंगे, घोषणाएं होंगी। लेकिन शायद क्षेत्र की जनता यह भूल गयी थी कि इस बार सरकार बदल चुकी है। यह जो सरकार अब आई है, यह संकीर्ण सोच की सरकार है। यह छोटी सोच की सरकार है। यह भेदभाव करने वाली सरकार है। इस सरकार का नजरिया सबको समानता से देखने का नहीं है।

जिस तरह से हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने पूरे प्रदेश की जनता को एक समान नजर से देखने का काम किया, सभी विधान सभा क्षेत्रों में अनेकानेक सौगात देने का काम किया। आप पता नहीं मुझे कब किस टाइम बैठा दें, इसलिए पहले मैं मेरे नोहर विधान सभा क्षेत्र की मांग माननीय मंत्री महोदय से करूंगा। माननीय सभी विधायकों ने जिस तरह से मंत्री महोदय की तारीफ की कि यह वास्तव में दरिया दिल हैं। यह जिंदा दिल इंसान हैं। तो मुझे भी लगा कि क्यों ना मैं पहले मेरे क्षेत्र की समस्याएं इनके सामने रख दूं। हो सके कि आने वाले पूरक बजट में कुछ हमें भी मिल जाये। क्षेत्र वासियों को मिल जाये।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि मेरे शहर में एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। जिसे दानदाताओं के द्वारा बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था। करोड़ों रुपयों की वह जमीन है। वह हॉस्पिटल आपकी तत्कालीन सरकार में खुला था। मातृ एवं शिशु रोग के रूप में उसमें इकाई शुरू हो रही थी। लेकिन बाद में केन्द्रीय सरकार द्वारा वह योजना बंद कर दी गई। मेरा आपसे निवेदन है कि उसको शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य

केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाये। जिससे कि भामाशाह, दानदाताओं को भी प्रेरणा मिले और आगे जाकर भविष्य में भी वहां पैसा खर्च कर सकें।

मेरा राजकीय उप जिला चिकित्सालय पूर्व की सरकार में हुआ। जहां 100 बेड में वह क्रमोन्नत हुआ।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप वापस बता दो।

श्री अमित चाचाण (नोहर): वह मैं लिखकर दे दूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): हां, लिखकर दे देना।

श्री अमित चाचाण (नोहर): उसको 150 बेड में क्रमोन्नत करने की मैं मांग करता हूं। क्योंकि मेरे विधायक बनने से पहले मात्र 50 बेड का हॉस्पिटल था। उसमें भी मात्र 47 परसेंट की ऑक्यूपेंसी थी। लेकिन जब यह 100 बेड में क्रमोन्नत हुआ, अन्य चिकित्सा सुविधाएं उसमें उपलब्ध हुई तो आज 80 परसेंट से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी उस स्थिति में है, जबकि वहां पर आंखों का ऑपरेशन थियेटर नहीं है। हड्डियों के काम नहीं हो रहे। उस बिल्डिंग का निर्माण कार्य चालू है। मेरी आपसे यह मांग है कि उप जिला चिकित्सालय को 100 बेड से 150 बेड में क्रमोन्नत किया जाये।

हमारे उप जिला चिकित्सालय में रोजाना 2 हजार मरीजों की ओपीडी है। 300 डिलिवरी हर महीने उस राजकीय चिकित्सालय में होती हैं। वहां सोनोग्राफी मशीन नहीं है। यह भी मेरा निवेदन है कि सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करायें। अगर मशीन नहीं है तो मैं विधायक कोटे से देने के लिए तैयार हूं। आप वहां सोनोग्राफी के लिए डॉक्टर भी लगायें। जिससे कि इलाज हो सके।

मेरे उप जिला चिकित्सालय में 10 करोड़ रुपये से बिल्डिंग का निर्माण कार्य चालू है। लेकिन भारत सरकार की गाइड लाइन है कि उप जिला चिकित्सालय के लिए 40 करोड़ रुपये व्यय करने होते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि शेष राशि है, वह स्वीकृत की जाये। जिससे कि उप जिला चिकित्सालय का भवन बन सके। मेरे क्षेत्र में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पल्लू और फेफाना हैं, जो उप तहसील भी है, उसको 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड का किया जाये। मन्दिरपुरा कुइयां, धानसिया जो पीएचसी है उसको सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाये। मालासर, जबरासर, थालड़का, दलपतपुरा, रायसिंहपुरा उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाये। नोहर में आंखों का डॉक्टर तो है, उप जिला चिकित्सालय होने के बावजूद वहां ऑपरेशन थियेटर, आंखों के ऑपरेशन हेतु सामग्री की जरूरत है। उसकी भी पूर्ति की जाये।

सभापति महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है कि उन हॉस्पिटलों में भारी-भरकम बिजली का बिल आता है। जहां नई-नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसमें सोलर प्लांट की भी स्थापना की जाये।

जिस तरह से पूर्व में बहुत से माननीय सदस्यों ने सफाई का मुद्दा उठाया, सफाई इस बजह से भी नहीं हो पाती कि उन हॉस्पिटल्स में सरकार के द्वारा सफाई का बजट बहुत ही

कम दिया जाता है। उससे आगे बढ़कर के वह सफाई में खर्च नहीं कर पाते हैं। अब सफाई का बजट भी बढ़ाने का मैं आपसे निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने बड़ी-बड़ी बातें की। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले 34 वर्षों में 15 वर्ष कांग्रेस का शासन काल रहा और 19वां साल भारतीय जनता पार्टी के शासन काल का चल रहा है। लेकिन जब-जब भी चिकित्सा की बात आई, क्योंकि भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, मरीज को दवा देना सबसे बड़ी सेवा होती है। दलित का, कमजोर का, गरीब का दर्द वही समझ सकता है जिसने धरातल पर रहकर काम किया हो।

जब-जब भी कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, सबसे पहले हमारे मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने निशुल्क दवा योजना लेकर आये। जिससे कि इस राजस्थान के मरीजों को बहुत राहत मिली। हम उस गरीब व्यक्ति के दर्द को देखें, जिसकी जेब में 100 रुपये नहीं होते, अगर उसके घर में बीमारी आ जाती है, उसकी जमीन, जायदाद सबको गिरवी रखना पड़ता है। वह कर्ज के नीचे दब जाता है। उससे आगे बढ़कर वह मुख्य मंत्री निशुल्क जांच योजना लेकर आये। उससे आगे बढ़कर 25 लाख की मुख्य मंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लेकर आये। पूरे देश के अन्दर उस योजना को सराहा गया। इसके साथ-साथ मुख्य मंत्री दुर्घटना बीमा योजना भी लेकर मुख्य मंत्री अशोक गहलोत लेकर आये क्योंकि वह गरीब का दर्द जानते थे। गरीब की समस्या को जानते थे। वह यह चाहते थे कि राजस्थान प्रदेश की जनता को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक मरीज को उसकी दवा मिलनी चाहिए। उसकी जांच निशुल्क होनी चाहिए। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसमें भी उनको पैसा मिलना चाहिए। यह बड़ी सोच मुख्य मंत्री अशोक गहलोत की थी।

आज बातें कर रहे थे कोरोना काल की, बातें कर रहे थे देश के प्रधान मंत्री की कि कोरोना काल में प्रधान मंत्री जी ने क्या किया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के प्रधान मंत्री ने कोरोना काल में क्या किया? उन्होंने काम किया, उस संकट की घड़ी में जो पूरे विश्व में एक प्राकृतिक आपदा आई थी, उसमें माननीय प्रधान मंत्री जी ने सांसदों के कोटे को फ्रीज करने का काम किया। क्षेत्र की जनता तड़प रही थी। लेकिन सांसद के पास पैसा देने के लिए नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने कहा, चाहे मेरा पूरा खजाना खाली क्यों ना हो जाये, मैं मेरे राजस्थान की जनता को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। जो-जो भी नियमों में राहत देने का काम किया, जिससे विधायकों ने अपने विधायक कोटे के पैसों से क्षेत्र की जनता की सेवा करने का काम किया। पूरे देश की, राजस्थान की जनता से यह आव्हान किया।

माननीय सभापति महोदय, मैंने शुरू में कहा था कि आप टाइम देख लीजिये। मेरा 12 मिनट का समय है। 5 मिनट हुए हैं। यह आप नाइंसाफी इस आसन से ना करें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): 10 मिनट हो गये 10 मिनट।

श्री अमित चाचाण (नोहर): यह मैं आपको एक आईना दिखा रहा हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): एमएलए साहब, एक मिनट, आप गलत सूचना रिकार्ड पर जाने दे रहे हैं। सांसदों का कोटा लैप्स नहीं हुआ था।

श्री अमित चाचाण (नोहर): फ्रीज कर दिया था।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): एक मिनट, वह सारा का सारा प्रधान मंत्री ने अपने हाथ में लेकर के कोरोना में लगाया था। आप यहां गलत तथ्य क्यों दे रहे हैं? हमने भी विधायक कोटा कोरोना में लगाया है।

श्री अमित चाचाण (नोहर): मुझे आप डिस्टर्ब ना करें ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: 2 मिनट में अपनी बात कहें।

श्री अमित चाचाण (नोहर): भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके बाद 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? आपने मात्र 7 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले। हमारी कांग्रेस की सरकार ने 1674 सब सेंटर्स खोलने का काम किया। हमारी सरकार ने कांग्रेस के शासन काल में 353 पीएचसी से सीएचसी करने का काम किया। आपके कार्यकाल में ना तो कोई उप जिला चिकित्सालय खुला, ना कोई जिला चिकित्सालय खुला। लेकिन कांग्रेस के शासन काल में 65 उप जिला चिकित्सालय, 27 जिला चिकित्सालय खोलने का काम किया। आपने मात्र एक सेटेलाइट हॉस्पिटल खोलने का काम किया। वहीं कांग्रेस के शासन काल में 13 सेटेलाइट हॉस्पिटल खोलने का काम किया। आपने मात्र 865 बेड बढ़ाने का काम किया। वहीं हमारे कांग्रेस शासन काल में 11700 बेड बढ़ाने का काम पिछली सरकार में हुआ।

आपके प्रधान मंत्री जहां ताली बजवा रहे थे, थाली बजवा रहे थे, वहीं कांग्रेस के हमारे नेता उन घरों तक भोजन पहुंचाने का काम कर रहे थे। दवाई पहुंचाने का काम कर रहे थे। ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे थे। चार्टर्ड प्लेन से बम्बई से दवाइयां मंगायी गयी। जिससे कि हमारे मरीजों को दवाई मिल सके। आपकी भारतीय जनता पार्टी की जहां-जहां सरकारें थी, वह रेमडीसीवर इंजेक्शन 50 हजार में मिल रहा था। वह हमारे मुख्य मंत्री ने नोहर के, प्रदेश के अंतिम छोर तक उस इंजेक्शन को नि:शुल्क पहुंचाने का काम किया। मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने किया। यह फर्क है आपकी सरकार में और कांग्रेस की सरकार में। पैर में मोच और छोटी सोच व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती।

मैं आपको कहना चाहता हूं कि दरियादिल रखें, बड़ा दिल रखिये क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी एक लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। वह भी आज आपकी तरफ देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे लिए कुछ न कुछ घोषणा करेगी। लेकिन आपने नोहर को कुछ भी नहीं देकर आपके कार्यकर्ताओं का अपमान करने का काम किया है। आप सबसे यह निवेदन करता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा संविदा, 2022 के तहत एनएचएम के संविदा कर्मियों को नियमित करने का, जो 4518 पद सृजित किये थे, उन सेवा नियमों को बनाने की कार्यवाही करें। जिससे कि उन बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। जो सीएचए ने हमारे कोविड के समय काम किया था, उनको भी आप आने वाले समय

में रोजगार देने का काम करें। जहां-जहां भी रिक्त पद पड़ें हैं, जब तक आपकी भर्ती ना हो, आपसे मांग करता हूं कि यूटीबी के माध्यम से या संविदा कर्मियों के माध्यम से हमारे उन बहन, भाइयों को राजकीय चिकित्सालयों में लगायें। जिससे कि आज जो बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार मिलने का काम हो।

सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापतिः बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉ. ऋतु बनावत।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मांग संख्या 27 व 28 पर बोलने का मुझे अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

जैसा कि हम सबको विदित है कि हमारा भारत वर्ष, भारत देश चरक और सुश्रुत का देश है। उन्होंने प्राचीन काल में काय चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया।

Spp/Rtm/19.07.2024/17:30/3h

हम सब आज यहां पर चिकित्सा की चर्चा करने के लिये यहां पर इकट्ठे हुये हैं। मैं बात करूंगी कि सारे सदस्य कह रहे हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं में बहुत सारी कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने के लिये प्रयास इधर से भी और अब उधर से भी होते रहे हैं लेकिन हर बार कुछ न कुछ कमी रह जाती है और उस कमी को पूरा करने के लिये अगर हम अपने प्रयासों को नहीं बढ़ायेंगे तो उनकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं भरतपुर मेडिकल कॉलेज की बात करूंगी। 2017 में यह कॉलेज बना और 2018 में शुरू हुआ। RBM हॉस्पिटल में भी सुविधाएं बढ़ीं, लेकिन आज स्थिति यह है कि कोई भी एक्सीडेंट होता है, अगर बयाना में कोई एक्सीडेंट हुआ तो बयाना से रेफर कर दिया जाता है भरतपुर को और भरतपुर में भी चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में तुरंत जयपुर रेफर कर दिया जाता है। हम अगर कहीं पर जिला अस्पताल बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं तो धरातल पर जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिये, वो उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रही हैं, यह सवाल है। माननीय सभापति महोदय, लगातार यह बात आती है कि जब बयाना से भरतपुर जायेगा, भरतपुर से जयपुर आयेगा कोई पेशेंट तो धन की भी बर्बादी होगी, समय की भी बर्बादी होगी और जान का खतरा तो बना हुआ रहेगा। उस समय में कोई व्यक्ति जान से जा सकता है। मैंने घर जाकर बजट पढ़ा था तो उसमें एक कोटेशन था - 'बेहतर कल के लिये आधारभूत ढांचे में निवेश' । पहले का समय था जब रोटी, कपड़ा और मकान आधारभूत ढांचा हो सकता है या आधारभूत सुविधा व्यक्ति के लिये मानी जाती थी। लेकिन आज के समय में चिकित्सा अपने आप में बहुत बड़ी आधारभूत सुविधा है, आधारभूत आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं चिकित्सा मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने बयाना और रूपबास, दोनों ही उपखण्डों पर हमारी जो CHC है, उनको क्रमोन्नत कर दिया और उप जिला स्वास्थ्य केन्द्र में तब्दील करने की बात बजट में कही। मैं यह कहना चाहूंगी कि मॉडल सी एच सी के रूप में रूदावल को विकसित किया जाना चाहिये। हमारे बयाना का जो परिदृश्य है, तीन तरफ से तीन जिलों की सीमाएं उससे लगती है। एक तरफ से करौली लगता है, एक तरफ से दौसा लगता है और एक तरफ से धौलपुर लगता है। साथ ही माइनिंग का भी एरिया है तो दुर्घटना की संभावना भी ज्यादा है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये सदन में लगातार बात हो रही है। डॉक्टर्स की कमी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में बंशी पहाडपुर CHC का मैंने दौरा किया। दौरे में वहां पर नर्सिंगकर्मी तक पाया नहीं गया और जिस डॉक्टर के भरोसे है, जिसको इंचार्ज बनाया गया है, पूर्ण डॉक्टर कोई अभी अवेलेबल नहीं है, किसी की पोस्टिंग नहीं है, जिस डॉक्टर को इंचार्ज के रूप में लगाया गया है रूपबास से, वह अभी तक अपने कार्यकाल में, जब से उसको इंचार्जशिप मिली है, एक बार भी डॉक्टर विक्रम आनन्द उस CHC पर नहीं आया। इतनी अच्छी बिल्डिंग, इतनी अच्छी सुविधा होने के बाद भी वहां पर स्थिति यह है कि डॉक्टर्स नहीं होने के कारण, नर्सिंग स्टॉफ नहीं होने के कारण यद्यपि अभी आपने एक लैब टैक्नीशियन, जो अभी आपकी भर्ती हुई है, उसमें आपने दिया है, अच्छी बात है। लेकिन सब कुछ इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद भी हमें अगर सुविधाएं नहीं मिल पाये तो वहां पर उस बिल्डिंग का, उस CHC का क्या मतलब रह जाता है? यह मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इस बजट में भी कई सारी योजनाएं महिलाओं के लिये भी आयी हैं और महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिये यह बहुत आवश्यक है कि जो CHC हैं, जो हमारे उप जिला स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जिला स्वास्थ्य केन्द्र हैं, वहां पर स्त्री रोग विशेषज्ञों के लिये आपको विशेष रूप से सोचना चाहिये। हम आधी आबादी हैं और कई बार तो महिलाएं कह भी नहीं पातीं, जो उनकी समस्याएं होती हैं। प्रेग्नेंसी के लिये उनको परेशान होना पड़ता है। अगर CHC पर यह प्रावधान किया जाये कि हर CHC पर एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होगा तो मुझे लगता है कि राजस्थान के महिला स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा काम हो जायेगा। महिलाओं का स्वास्थ्य उच्च स्तर का हो जायेगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि अभी आज ही मेरा एक अतारांकित प्रश्न लगा था जिसका विभाग के द्वारा मुझे जवाब मिला। मैंने पूछा था कि मेरे क्षेत्र में कितने डॉक्टर्स के पद रिक्त हैं? मेरे पास जवाब आया कि 24 चिकित्सकों के पद मेरे यहां पर रिक्त हैं। राजपत्रित कार्मिक के 108 पद रिक्त हैं। ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र से मैं आती हूं। वहां पर शहरी क्षेत्र में व्यक्ति प्रयास कर लेता है, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल के रूप में सुविधा भी मिल जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं मिलना बहुत मुश्किल है। मैं यह

कहना चाहूंगी कि गरीबों की, वंचितों की चिकित्सा सुविधा के लिये हमें गांवों में डॉक्टर्स की पोस्टिंग की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बेहतर कल के लिये जो हमने बात कही, उसके बारे में यही कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों को नहीं जाना पड़े। डॉक्टर्स हों, ए एन एम हों तो हमारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो पायेंगी।।

श्री सभापतिः माननीय सदस्या, समाप्त करें।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय सभापति महोदय, मेरा यही निवेदन है कि हमें आधारभूत सुविधाओं के हिसाब से स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के हिसाब से मंत्रीजी अच्छा काम करें, यह मेरी हाथ जोड़कर विनती है। हर व्यक्ति, जो राजस्थान का है, आपसे एक ही डिमांड करना चाहती हूं कि हमारा स्वास्थ्य आपके हाथों में है, आप अच्छा काम करके दें तो सारे प्रदेश की जनता आपको सेल्यूट करेगी। धन्यवाद।

श्री सभापतिः विराजें प्लीज। श्री जब्बर सिंह सांखला।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 और 28 पर विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज चिकित्सा का महत्वपूर्ण विषय था, उस पर चर्चा हो रही है। बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं और बहुत सारे ज्ञान भी बांटे गये हैं। ज्ञान उस तरफ से बांटे गये जो अभी पांच साल सत्ता में रहकर उधर जाकर बैठे हैं। उनके द्वारा बहुत सारा ज्ञान बांटा गया है। मैं बात करना चाहूंगा यहां इस सदन में भीलवाड़ा मॉडल की बात भी चली थी। भीलवाड़ा मॉडल, जो पूरे देश में कोरोना के समय में चरितार्थ हुआ था, उसमें उस समय जो चीजें थीं, वह हमने हमारी आंखों से देखी। हमारे परिवार के परिवार नष्ट हो गये थे, उसमें मेरा परिवार भी था। आज यहां बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप सर्वे करवायें और कोरोना काल में सबसे ज्यादा क्वारंटाइन इस राजस्थान में कौन व्यक्ति रहा, तो उसमें नाम निकलकर आयेगा पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब का। वह पूरे कोरोना के समय में केवल और केवल मात्र क्वारंटाइन थे और आधे समय में होटलों में जाकर ऐश कर रहे थे। उस समय वहां गाने गा रहे थे और डांस कर रहे थे। ये वीडियो हम सबने देखे हैं। ...(व्यवधान).. सुन लो, सुन लो। आप नहीं थे उस समय, हम थे। थोड़ा सुनना सीखो। ...(व्यवधान).. आप सुन लो पहले। माननीय सभापति महोदय, उस समय कोरोना के समय में पूरी की पूरी सरकार होटलों में नाच-डांस कर रही थी। अगर फील्ड में कोई कार्यकर्ता था तो हमारे विचार परिवार के लोग थे, चाहे वह संघ परिवार के लोग हों, चाहे बजरंग दल के कार्यकर्ता हों, चाहे विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता हों, चाहे भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो। एक-एक कार्यकर्ता उस समय गलियों में था और लोगों की हम सेवायें कर रहे थे। पूरी की पूरी सरकार उस समय होटलों में थी। आज आप ज्ञान बांट रहे हैं। आप कोरोना की बात करते हैं। भीलवाड़ा मॉडल की बात करते हैं। भीलवाड़ा में उस समय के तत्कालीन कलेक्टर साहब जो राजेन्द्र जी भट्ट हुआ करते थे, उन्होंने जो व्यवस्थाएं उस समय संभाली, एक-एक कार्यकर्ता को वहां बुलाकर हम सब लोगों

की वह दिन में दो-दो, तीन-तीन बार मीटिंगें लेते थे और हमको काम देते थे। हम भारतीय जनता पार्टी के, हमारे विचार परिवार के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सब लोगों ने उस समय उनके कहे अनुसार प्रत्येक गांव और ढाणी में जाकर हमने लोगों की सेवा की है। आज आप कोरोना की बात कर रहे हैं।

MLS/RTM/19.07.2024/17:40/3j

आप चिरंजीवी की बात करते हैं, उसका क्या हश्र हुआ है? पांच लाख, दस लाख, पच्चीस लाख का इलाज, बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन धरातल पर यह स्थिति थी कि जब कोई भी पेशेंट बीमार होता था और उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते थे तो गरीब आदमी की वहां कोई सुनवाई नहीं होती थी। हमारे पास फोन आते थे तो हम हॉस्पिटल में बात करते थे। उस समय हॉस्पिटल वालों का यह कहना होता था कि सरकार ने हमें पैसा नहीं दिया है। आप विधायक हैं तो सरकार से पहले हमें पैसा दिलवाएं, उसके बाद हम चिरंजीवी में इलाज करेंगे। ये स्थितियां उस समय थीं।

आज आप चिरंजीवी की बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, चूंकि समय बहुत कम है, मैं इनके पांच साल के बारे में बात करूंगा तो समय पूरा हो जायेगा। इन्होंने जो भी किया, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। यहां सदन में आकर भाषण देने से काम नहीं चलता, धरातल पर आप लोगों ने काम नहीं किया है। तब जाकर आपकी आज यह स्थिति हुई है कि आप वहां बैठे हैं। आदरणीय मंत्री महोदय यहां विराजे हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा, लकवा एक बहुत ही गम्भीर बीमारी है, जो किसी भी समय कभी भी किसी को भी हो सकती है। मेरा निवेदन है, उसका एक इंजेक्शन आता है, जिसकी ट्रेनिंग होती है, पूरे प्रदेश में जितनी भी हमारी सीएचसी हैं, उनमें उस इंजेक्शन को लगाने की ट्रेनिंग करायी जाये, ताकि लकवा जैसी गम्भीर बीमारी से लोगों को निजात दिलायी जा सके।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें आपके सामने रखना चाहूंगा। आसीन्द बहुत बड़ा शहर है। आसीन्द से भीलवाड़ा जिले की दूरी लगभग 58 किलोमीटर होती है। उससे पहले किसी भी तरह की कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। मैंने पहले भी निवेदन किया था, जब आपका रिप्लाई आये तो मेरा निवेदन है कि आसीन्द सीएचसी को आप उप-जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करेंगे तो आपकी अति मेहरबानी होगी। 60 किलोमीटर से पहले किसी भी तरह की कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। आसीन्द सीएचसी को आप उप-जिला अस्पताल अपने रिप्लाई के समय घोषित करें। मेरा एक निवेदन और है, ब्राह्मणों की सरेरी में पीएचसी है और कंवलियास में भी पीएचसी है। दोनों ही हाईवे पर हैं। एक आसीन्द से भीलवाड़ा रोड पर और एक गुलाबपुरा से भीलवाड़ा रोड पर। दोनों पीएचसी को आप सीएचसी में क्रमोन्नत करेंगे तो आपकी अति मेहरबानी होगी।

भादसी एक बहुत बड़ा एरिया है जो अरावली की पहाड़ियों पर बसा हुआ है। वहां मंगरा के अलावा जमीन जैसी कोई स्थिति नहीं है। न वहां बसें चलती हैं, न वहां कोई सुविधा है।

वहां बहुत सारे लोग पहाड़ों के ऊपर बसते हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि भादसी, बरसनी और कटार, वहां केवल सब-सैंटर्स हैं। दूर-दूर तक 20-20 किलोमीटर तक चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। इन तीनों सब-सैंटर्स को आप पीएचसी में घोषित करेंगे तो आपकी अति मेहरबानी होगी।

मरेवड़ा, जो आसीन्द विधान सभा क्षेत्र के बॉर्डर का गांव है, करेड़ा और आसीन्द के बीच में, वहां भी कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं है। मेरा निवेदन रहेगा, जब आप रिप्लाई दें तो वहां एक नवीन सब-सैंटर, बहुत ही छोटा सा गांव है, वहां अगर एक नवीन सब-सैंटर आप मुझे दे देंगे तो आपकी अति मेहरबानी होगी। आसीन्द के लिए आदरणीय एसडीएम साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने एक कमेटी बनायी थी। उस कमेटी ने आसीन्द में सीएचसी की नयी बिल्डिंग के लिए जगह भी देखी है। नगरपालिका ने भी हां भर ली है। वहां जगह हमें मिल सकती है अगर आप नयी बिल्डिंग वहां सैंक्शन करके दे देंगे तो। आपकी मेहरबानी होगी।

मेरा एक निवेदन विशेष तौर से रहेगा। जहां-जहां मेरे एरिया में डॉक्टर्स नहीं हैं, वहां आप डॉक्टरों की भर्ती पूरी करें। जो भी चिकित्साकर्मियों की कमी है, उसकी भी आप पूर्ति करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आसीन्द और गुलाबपुरा, दोनों शहर हैं, दोनों ही जिला हैडक्वार्टर से लगभग 58-60 किलोमीटर की दूरी पर हैं, वहां अगर चिकित्साकर्मी पूरे होंगे तो लोगों को बहुत सुविधा होगी। गुलाबपुरा एरिया एक इंडस्ट्रियल एरिया है। आसीन्द भी माइनिंग का एरिया है। वहां भी अगर आप डॉक्टर्स की कमी की पूर्ति करेंगे तो आपकी अति मेहरबानी होगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। वन्दे मातरम।

श्री सभापतिः बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री समरजीत सिंह।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): सभापति महोदय, आज स्वास्थ्य विभाग की चर्चा पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बजट भाषण में सरकार ने 8.26 परसेंट हैल्थ पर 27660 करोड़ रुपये का आवण्टन किया है। यह आवश्यक भी है, क्योंकि इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत जरूरी हैं। हिन्दुस्तान एक डवलपिंग कंट्री होने के बावजूद मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाएं, इस तरह का प्रयास करता है। हम अगर तुलना करना चाहें, अमरीका में जहां सारा इलाज पैसे से होता है और दूसरी तरफ कनाडा जाएं तो वहां सारा इलाज मुफ्त में होता है।

उसके बावजूद हिन्दुस्तान की सरकारें, चाहे इनकी रही हों, चाहे हमारी रही हों, सबका प्रयास रहा है कि जनता की जो सुविधा है अस्पताल की, गरीब की, जरूरतमन्द की, उसे सरकारी अस्पताल में हर तरह की सुविधाएं मिले। उसके लिए हर सरकार ने प्रयास किया है। अब यहां बैठकर हम कहें, अभी मुझसे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने ज्ञान की बात कही, ज्ञान तो हम सब बिखेरते ही रहते हैं सारे दिन, पर हर सरकार ने प्रयास किया। पिछली सरकार ने चिरंजीवी योजना दी। उसके अन्तर्गत लोगों के 25 लाख तक के इलाज फ्री हुए। हम गांवों में जाते थे, चुनाव के समय जाते थे और हमें पता है कि लोगों के किस तरह

से हार्ट के ऑपरेशन, नी रिप्लेसमेंट वगैरह हुए। इसे हम जितना गिनाएं, उतना कम है। आप मानेंगे नहीं और हम कहने से चूकेंगे नहीं, पर इलाज हुआ है।

अब नाम आप भले ही बदल दें, इस पर कोई एतराज नहीं, नाम आपने अच्छा दिया ''मां'', मां का नाम सुनते ही दिल भर आता है। मैंने तो अभी मां को खोया है, इसलिए समझ सकता हूं, पर योजना चालू रहनी चाहिये, सुविधाएं लोगों की चालू रहनी चाहिये, यही मेरा तो आपसे निवेदन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आम आदमी की, गरीब की, क्योंकि पिछले सालों में मैने देखा है, डायलिसिस जैसी सुविधा जो सरकारी अस्पतालों में नहीं है, आज भी भीनमान के सरकारी अस्पताल में अभी दस दिन पहले ही उद्घाटन हुआ है, दो डायलिसिस मशीनें आयी हैं। हम जाते थे प्राइवेट अस्पतालों में, जहां चिरंजीवी की वजह से इलाज होता था, भीनमाल में नाहर हॉस्पिटल है, वहां पर दस डायलिसिस यूनिट्स लगी हुई थीं। मेरी मां बीमार थीं, आईसीयू में भर्ती थीं, मैंने देखा कि लोगों को बहुत बड़ा फायदा होता था।

इस तरह की डायलिसिस मशीनें सरकारी अस्पतालों में भी लगायी जाएं। आज डायबिटीज का रोग सबसे बड़ा रोग है, जिसमें सबसे ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिये। आपने भीनमाल में उप-जिला अस्पताल की घोषणा की, इसके लिए मैं सरकार का आभारी हूं। पिछले बजट में हमारी सरकार ने 75 से 100 बैड किया था, आपने उप-जिला अस्पताल किया। ठीक है, धन्यवाद, पर जब तक वहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं रहेंगे, तब तक हमारी सुविधाएं अधूरी हैं। आज भी हमारी बहन बोल रही थीं गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में, पीडियाट्रिक्स के बारे में, अगर ये डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो उन सुविधाओं का फायदा क्या? अभी कुछ दिन पहले की घटना है, सरकारी अस्पताल भीनमाल में गायनेकोलॉजी डॉक्टर है, पर उसके बावजूद उसे रैफर प्राइवेट हॉस्पिटल में किया जाता है और उसका वहां शोषण होता है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम आधी आबादी के लिए, महिलाओं के लिए ऐसा कोई नियम बनाया जाये कि अगर सरकारी अस्पताल से उन्हें प्राइवेट अस्पताल में रैफर किया जाये तो वहां भी उन्हें वही सुविधाएं मुफ्त में मिलनी चाहिये। यह प्राइवेट अस्पताल पर कोई अहसान नहीं होगा। ये जितने प्राइवेट अस्पताल हैं, ये सरकारी जमीनें अलॉट कराकर बने हुए हैं। अगर हम पाबन्द करते हैं कि इन सरकारी जमीनों का जो फायदा उन्होंने लिया है और उसके बदले जनता को अगर वे सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं तो यह किसी पर अहसान नहीं है।

मेरे यहां तो मैंने देखा हुआ है कि सारे जितने बड़े-बड़े अस्पताल बने हुए हैं, सब मुफ्त की जमीनों पर बने हुए हैं। सरकार से आपके मार्फत् निवेदन करना चाहूंगा, उन सुविधाओं के लिए अस्पतालों को पाबन्द किया जाये। हमारे यहां तो गुजरात जाना पड़ता था। गुजरात में सारा माइग्रेट होता था अस्पतालों के चक्कर में। हमारी, आपकी, सबकी सुविधाओं से अब माइग्रेशन रुका है। अब हम थोड़ा सा इन प्राइवेट अस्पतालों को अगर चैक कर लें तो आम

जनता को बहुत बड़ा फायदा होगा। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

इसके अलावा जोधपुर में एम्स हॉस्पिटल है, पर उसके अन्दर भी जब रैफरेंस होता है, लोग गांवों से जब वहां जाते हैं तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, आप उसकी सुविधा को अच्छा बनाएं तो फायदा होगा। गुजरात में भी आपकी सरकार है, ऊपर भी है। गुजरात में भी जो मरीज जाते हैं, सचेतक जी विराजे हैं, अपनी तो एक ही समस्या है सबसे बड़ी, वहां पर भी सिविल हॉस्पिटल से, अन्य अस्पतालों से कोई लाइजनिंग करके इस तरह की सुविधा करें कि हमारे लोगों को मूलभूत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो सके।

mkd/rtm/19.07.2024/17:50/3k

सारी एम्बुलेंसेज खराब पड़ी हैं। जरूरत के समय किसी के काम नहीं आती है। इसकी तरफ भी देखा जाये। मेरा निवेदन है कि हर विधान सभा क्षेत्र में एक आईसीयू मेडिकल वैन होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ जब हार्ट अटैक आता है या कोई प्रोब्लम आती है, तो उस समय प्राथमिक चिकित्सा मिल जाये तो सबसे बड़ा फायदा होगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आप जोधपुर एम्स के बारे में कह रहे हैं। मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। वहां बिलकुल सिस्टम से काम होता है। जो बिना किसी सिफारिश के जाता है, उसकी भी अच्छी सेवा होती है और बड़ी से बड़ी सिफारिश आ जाये तो भी लाइन तोड़कर वे आगे नहीं बढ़ने देते हैं। एम्स, जोधपुर का बहुत बढ़िया सिस्टम है। आपको अपने एरिये के ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजना चाहिए।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): मैंने वहां की सुविधाओं में कमी नहीं बताई हैं। आपने ध्यान से सुना ही नहीं है। मैंने यह कहा है कि गरीब आदमी की वहां शिफ्टिंग आसानी से हो जाये, क्योंकि आपको भी पता है कि एम्स में कितना भीड़-भड़का है। उसके अन्दर ईजी मूवमेंट हो जाये, वह हमारे लिए सुनिश्चित करना जरूरी है। रोगी आपके सरकारी अस्पताल जालोर, भीनमाल से जाता है और सरकारी एम्बुलेंस में आता है। उसको वहां टाइम पर एंट्री मिल जाती है तो समय पर सुविधा मिलने का सबसे बड़ा फायदा होता है।

मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूं कि उस एम्स का बहुत बड़ा फायदा है। इसीलिए, मैंने आपको पॉइंट आउट किया कि आप इसमें इंट्रेस्ट लें तो गुजरात में भी राजस्थान हॉस्पिटल है, सारे अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में भी इन सुविधाओं को कराइये। देश तो एक ही है। हम जब सुविधाएं नहीं दे सकते तो मरीज इन्तजार तो करेगा ही नहीं कि भीनमाल में सुविधा मिलेगी तो करेगा, वह तो बाहर की तरफ जायेगा। हम उसको रिलीफ कैसे दे सकते हैं?

आज प्राइवेट हॉस्टिल्स के ये हाल हैं कि सबसे पहले पहुंचते ही यह पूछा जाता है कि मेडिकल पॉलिसी है या नहीं। हम यह तो सब जानते हैं। मैं यहां खड़ा होकर कहूं तो दुकानें बन चुकी हैं। इसके लिए भी सरकार को चाहिए कि हम जनता को कैसे रिलीफ दे सकते हैं।

हर कोई अन्य स्टेटों में भी हायर जगह जाने का प्रयास करेगा।

मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर भी ध्यान जायेगा। मंत्री जी अभी पधारे हैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि मेडिकल कॉलेज जालोर पिछली सरकार ने स्वीकृत किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको स्पीडी करके टाइम से करेंगे। एक नर्सिंग कॉलेज की जालोर जिले में जरूरत है। मेडिकल कॉलेज, जालोर तो आपने दे दिया है। भीनमाल जो जालोर, सांचोर का सेंटर है, नर्सिंग कॉलेज हो तो लोगों को उससे भी फायदा होगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): आप भीनमाल को जिला बना दो, मेडिकल कॉलेज मिल जायेगा।

श्री समरजीत सिंह (भीनमाल): अब आपकी सरकार आ गई है। जिला बनाओ, जो बनाओ, बना दो। हम तो खुश हैं। हम तो आपका इस बात पर समर्थन करेंगे। जिला तो हमारी सबसे बड़ी मांग है। हमारी सरकार से चूक हो गई, आप तो कर दो, हम धन्यवाद देंगे। मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा, यहां खड़ा होकर आपको धन्यवाद दूंगा। आप इसको कराइये।

अभी तो मैं नर्सिंग कॉलेज की मांग कर रहा हूं। मंत्री जी, जो भी सीएचसीज हैं, उनमें ब्लड बैंक की सुविधा होनी चाहिए। देखिए, न तो मेरी आदत है। जब हम इस हाउस में बोल रहे होते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि हम कांग्रेस, बीजेपी की बात करते हैं। हमें जनता बड़े मन से चुनकर भेजती है कि हम उनको रिप्रिजेंट करें। हम एक दूसरे की कमियां और ज्ञान बिखरते रहें। उससे कोई फायदा नहीं है। आप तो काम कीजिये, हम आपको शाबाशी देंगे।

मैं ब्लड बैंक के बारे में आपसे अर्ज कर रहा था कि ब्लड बैंक सीएचसी हैड क्वार्टर पर होना चाहिए। एसडीएम हैड क्वार्टर पर ब्लड बैंक की सुविधा करनी चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ये अपने से सर्टिफिकेट तो ले लेते हैं, लेकिन लोगों को बहुत तकलीफ होती है।

अन्त में, मेरे यहां सेवड़ी में एक अस्पताल बना था, पीएचसी बनी थी। उसकी जर्जर अवस्था है। उसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसकी तरफ देखेगी और उसको गिराकर नई बिल्डिंग बनाने की कोशिश करेगी। पहले आप सदन में नहीं थे। मैं पुन: भीनमाल में उप जिला अस्पताल के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री सभापति: श्री हंसराज मीणा, नहीं हैं। (अनुपस्थित)

श्री विक्रम सिंह जाखल। आप तो प्रखर वक्ता हैं, कभी भी बोल लेना।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित कार्यवाही के समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे और बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व

मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा पर विचार

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): सभापति महोदय, धन्यवाद। मुझे आज मांग संख्या 27 और 28 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से हमारे चिकित्सा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि नवलगढ़ में ढिगाल पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने के लिए आभारी हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में अस्पताल संचालित है, जो एक जिला स्तरीय अस्पताल है। जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 से ब्लड बैंक स्वीकृत हैं।

सभापति महोदय, तत्कालीन विधायक राजकुमार शर्मा ने अपने निजी हितों को साधने के लिए बदराणा जोहड़, जहां पशु मेला भरा जाता था। जिसकी जमीन को खुर्द-बुर्द करने की नीयत से जनता व सरकार दोनों को भ्रमित कर ट्रोमा सेंटर के नाम से 53 करोड़ रुपये का बजट पारित करवाया तथा बदराणा जोहड़ पर कब्जा कर लिया।

बदराणा जोहड़ की भूमि का प्रकरण न्यायालय में विवादित होने के कारण 53 करोड़ का बजट नवलगढ़ अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। जिसमें से 13 करोड़ की राशि जिला अस्पताल में अन्य वार्डों के भवन निर्माण में खर्च हुई है। वर्तमान में जिला अस्पताल, नवलगढ़ में ब्लड बैंक का भवन बनकर तैयार है, परन्तु आज दिनांक तक उक्त ब्लड बैंक उपकरणों के अभाव में सुचारु रूप से संचालित नहीं हुआ है।

श्रीमान, उक्त जिला अस्पताल में लगभग 2500 ओपीडी, 50 आईपीडी है। जिसके लिए आये दिन ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। मरीजों को अन्य प्राइवेट ब्लड बैंकों से ऊंची दरों में भुगतान कर ब्लड लाना पड़ता है।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि जिला अस्पताल, नवलगढ़ के ब्लड बैंक में आवश्यक उपकरण, मैन पावर उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि जिला अस्पताल नवलगढ़ में ब्लड बैंक सुचारु रूप से संचालित हो।

सभापति महोदय, नवलगढ़ जिला अस्पताल एक जिला स्तरीय अस्पताल है। जिसमें प्रतिदिन एक्सीडेंट और नवलगढ़ के आसपास के मंडावा, लक्ष्मणगढ़, सीकर, झुंझुनूं व इस हाइवे के उदयपुरवाटी तक के जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, वे सारे जिला अस्पताल, नवलगढ़ में पहुंचते हैं।

मैं सभापति महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि आपको नवलगढ़ में निश्चित रूप से ट्रोमा सेंटर खोलकर नवलगढ़ की जनता पर कृपा करनी चाहिए। साथ ही, यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे रोगियों के उपचार हेतु इमरजेंसी कक्ष, आइसोलेशन रूम, लैब, मेल वार्ड, फीमेल वार्ड, ओटी, एनसीडी, सोनोग्राफी, डायलिसिस, टीकाकरण इत्यादि

विभाग संचालित हैं, इनमें रोगियों की नर्सिंग सेवा हेतु नर्सिंग छात्रों की आवश्यकता रहती है।

अतः मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिला अस्पताल, नवनगढ में नर्सिंग कॉलेज स्वीकृत करवाने की कृपा करें।

साथ ही, मेरे विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 27 डॉक्टर एवं 44 नर्सिंग स्टॉफ के पद रिक्त हैं। जिससे नवलगढ़ ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवा प्रभावित हो रही है। श्रीमान जी से निवेदन है कि नवलगढ़ ब्लॉक में निम्नानुसार डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की कृपा करें, ताकि नवलगढ़ ब्लॉक की जनता को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके।

महोदय, मैंने नवलगढ़ ब्लॉक में रिक्त पदों की संख्या आपको बता दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुकुन्दगढ़ रिक्त पद 2, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसामपुरा, झाझड, खिरोड़, जाखल, राणासर, जेजुसपुर, बसावा, देवगांव, नुआ, मांडल, टोडपुरा, कोगण कलां, सोथली, रामपुरा पुजारी की ढाणी। यहां पर चिकित्सकों के 27 पद खाली हैं और साथ ही नवलगढ़ ब्लॉक में रिक्त नर्सिंग स्टाफ की सूची, सीनियर नर्सिंग अधिकारी के रिक्त पदों की संख्या 25 है।

Bhs/Rtm/19.7.24/18.00/3I

नर्सिंग अधिकारी-1 रामपुरा में रिक्त पद, एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता-4, एलएचवी महिला स्वास्थ्य विजिटर-14, तो सभापति महोदय के माध्यम से आपसे यही निवेदन है कि हमारी यह मांग जल्दी से जल्दी पूरी की जाये। धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री विद्याधर सिंह।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 व 28 पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। मेरे से पहले काफी लोग राजस्थान के स्वास्थ्य की दुर्दशा के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं और कुछ लोग गुणगान करने से भी नहीं चूके हैं कि हमने यह किया, हमने यह किया और कांग्रेस सरकार ने यह नहीं किया, यह नहीं किया। हम आज इस राजस्थान के सबसे बड़े प्रजातंत्र के मन्दिर में बैठ करके पार्टीबाजी की बात करें कि आपने यह नहीं किया हमने यह किया, मुझे तो यह उचित लगता नहीं है। मेरी तो एक मांग है कि सारा सदन आज जो भी सरकार चल रही है वो इस बात पर ध्यान दे कि हम बढ़िया क्या कर सकते हैं, हम जनता के हित के लिए क्या कर सकते हैं न कि किसी को दोषारोपण देना। दोष तो मैं भी आपको बताऊंगा कि आप लोगों के द्वारा शिखा मील ने और श्रवण जी ने राजस्थान की दुर्दशा के बारे में काफी कुछ कहा है कि राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में क्या है।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने बजट 27,600 का रखा है लेकिन यह बजट इतना बड़ा क्यों रखना पडा, उसके पीछे भी आपको जाना होगा, मंत्री महोदय, क्योंकि जहां से रोग उत्पन्न होता है, जो जड़ है रोग की वह जड़ है अशुद्धि यानी हम खाने

में हर चीज अशुद्ध खा रहे हैं। कोई किसी भी चीज में ऐसा नहीं है कि मिलावट नहीं हो और यह सारी चीजों में मिलावट के कारण से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। अगर हम थोड़ा सा बजट और थोड़ी सी सख्ती अगर इस अशुद्धि पर कर लेंगे तो मुझे लगता है कि अगली साल का बजट आपको कम करना पड़ सकता है, यह खुशी की बात होगी कि पैसा बचेगा राजस्थान सरकार का।

दूसरी बात, अभी सभापति जी कह रहे थे जब खुद बोल रहे थे और गुणगान कर रहे थे बढ़ाचढ़ा कर के हमने यह किया, कोरोना काल में हमने यह किया, हमने वह किया, हमने यह किया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि भीलवाड़ा मॉडल जिसकी मोदी जी ने सराहना की वह देश के प्रधान मंत्री हैं, हमारे प्रधान मंत्री हैं, उसको आप क्यों नहीं मानते? अगर आप इधर की उधर में रहेंगे, हमारी कुछ गलतियां हुई हैं उनसे सुधरो। वरना वह दिन दूर नहीं है 7-8 महीने आपने गंवा दिये आपका नम्बर भी यही आने वाला है जहां हम बैठे हैं। ...(व्यवधान)... बैठिये। मैं नहीं बोला, आप बैठ जाइये।

यहां जितने भी विधायक हैं उनमें ज्ञान भरा पड़ा है, सब फटने को तैयार हैं। ज्ञान मत बांटिये। सब फटने को तैयार हैं। आप तो यह बताइये जब आपने यह आरोप तो लगा दिया कि सरकार होटल में बैठी थी, मानता हूं कि सरकार होटल में बैठी होगी लेकिन यह भी सत्यता है कि किसान कहां बैठा था। उस टाइम किसान कहां बैठा था? आप लोगों ने कभी चिन्ता की उस किसान की कि वह कोरोना काल में कितने शहीद हुए हैं। कहां बैठे थे वो ...(व्यवधान)... जोड़ रहे हैं कोरोना काल था। आप कह रहे थे कि कोरोना काल था तो आप कहां थे, आप जाते उन किसानों के पास, उनकी मदद करते। कहना आसान है करना बहुत मुश्किल है।

दूसरी बात, सुनिये, गांवों में आज के हालात कैसे हैं। यह सही कहा मेरे पहले वक्ता ने, एम्बुलेंस की पोजिशन यह है। सरकार ने कोरोना काल में एम्बुलेंस काफी जगह दी है, मेरे फुलेरा में भी तीन दी हैं। मैं मंत्री जी से अभी कहता हूं कि अभी टेलीफोन घुमायें कि फुलेरा की एम्बुलेंस जयपुर भेजो, अगर वह आ जाये तो, क्योंकि वहां ड्राइवर नहीं मिलेगा या डीजल नहीं मिलेगा, या तो उसमें डीजल नहीं होगा या उसमें ड्राइवर नहीं मिलेगा। आप पता कर लें। मेरे यहां भी तीन-तीन एम्बुलेंस सरकार ने दी है, उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है तो आप इस बहस में मत जाओ कि आपकी सरकार ने किया उसने किया, आज क्या करना है उसके बारे में जाओ।

आज मैं एक ही बात कहता हूं कि अभी बालमुकुन्दाचार्य जी नहीं हैं, क्योंकि हैं नहीं तो मैं थोड़े सोफ्ट शब्दों में कह देता हूं, वो कह रहे थे, मैंने एक बात कही कि हम लोग सेवा कर रहे थे कोरोना काल में, अच्छी सेवा कर रहे थे। मेरे फलाना मेरे यहां गुजर गये तो गुजर गये तो आप तो महात्मा हैं आप मंत्र पढ़ लेते। मैं कह रहा हूं सच्चाई सुनना आप। यह बात मैंने क्यों कोट की, ऐसा नहीं है कि मेरे में दिमाग नहीं है कि मैंने मंत्र क्यों कह दिया। समझो बात को, मंत्र क्यों कह दिया, मंत्र इसलिये कह दिया कि जब आप कोरोना काल में

बात कर रहे थे हम दवाइयों की, इंजेक्शनों की तब वो कहते थे मोदी जी का शाम को आता था कि आज दिये जलाने हैं आज खड़े होकर इतने बजे थाली बजानी है, तो यह अन्धविश्वास किसने पैदा किया, यह मैं पूछना चाहता हूं। इसीलिये मैंने यह शब्द कहे थे, आप करेक्ट कर लें।

दूसरी बात, अब मैं आता हूं क्योंकि यह बहुत बात हो गई। आप कह देंगे समय हो गया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं आपको फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के बारे बताना चाहूंगा क्योंकि पहले सभी वक्ताओं ने राजस्थान के बारे में खूब ज्ञान मंत्री जी को बांट दिया है और इससे भी ज्यादा अगर समझ में नहीं आये तो मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है। अब सुनिये बात, मैं आपको फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा विभाग की अनियमितताओं के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में तीन उप जिला अस्पताल पिछली सरकार ने बनाये हैं। एक सीएचसी बनाई है जो नरेना है, जिसके वर्तमान पदों की स्थिति यह है कुल 198 पद हैं और उनमें 30 प्रतिशत काम कर रहे हैं साठ कर्मचारी हैं सिर्फ।

(समय: बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

देखिये, फुलेरा में 22 चिकित्साकर्मी के पद हैं और 17 हैं, 44 नर्सिंगकर्मी और 10 हैं, सांभरलेक में 22 चिकित्सा अधिकारी, 7 हैं, 15 की कमी है और नर्सिंगकर्मी 44 और 37 की कमी है 7 ही काम कर रहे हैं। इस तरह से 198 पदों पर सिर्फ 60, अब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। हम डॉक्टर्स को दोष देते हैं कि डॉक्टर नहीं बैठते। डॉक्टर बैठ कर करेंगे क्या, हैं ही नहीं। आपके स्वास्थ्यकर्मी ही नहीं है जो एक डॉक्टर को वह भी चाहिये कि तुम यह जांच करवा लाओ यह करवा लाओ तो यह कमी है 138 पद खाली हैं तीनों होस्पिटल्स में। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

देखिये, मैंने टाइम देखा था मैं तीन मिनट पर था और मैं 11 मिनट पर खत्म करूंगा।

श्री सभापतिः हो गया आपका।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): नहीं हुआ, साहब। आपके कहने से सभापति जी, नहीं होगा।

फुलेरा में जिला अस्पताल में लगभगहर पांच सौ से छह सौ डिलीवरी होती है लेकिन वहां बच्चों का डॉक्टर नहीं है। सोनोग्राफी मशीन खराब है। वर्तमान में नरेना में यह जो हमारे दादूपंथी हैं इन दादूपंथियों ने एक होस्पिटल बना कर और सीएचसी के रूप से पूरा होस्पिटल नरेना में दिया है, पूरा होस्पिटल दिया है लेकिन वहां उसका उपयोग नहीं हो रहा है और बधाल की बात आती है, वहां बधाल में पीएचसी होना जरूरी है।

श्री सभापतिः विराजिये, माननीय सदस्य। श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): देखिये, दो मिनट का समय चाहियेगा। माननीय विधायक जी, दो मिनट। बधाल में एक लाख की आबादी...।

श्री सभापतिः अंकित नहीं होगा। छगन जी राजपुरोहित, आपका समय चालू है।

श्री विद्याधर सिंह (फुलेरा): 000

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा विभाग पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

Kas/rtm/19.07.2024/18.10/3m

माननीय सभापति महोदय, इस बार सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय ध्येय वाक्य के साथ बजट आया। जिस प्रकार से अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि 27660 करोड़ का चिकित्सा सेवा में और अधिक सुधार के लिये इतना बजट, कुल बजट का 8.26 प्रतिशत देने के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी एवं चिकित्सा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता के लिये अभूतपूर्व चिकित्सा क्षेत्र में बजट लाये, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद करना चाहूंगा।

पूर्व में भाजपा की सरकार में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही थी, उसको तीन वर्ष तक ठंडे बस्ते में रखकर 2021 में आपने चिरंजीवी योजना शुरू की। आपने तीन वर्षों तक जनता का ध्यान ही नहीं रखा। जिस प्रकार से सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि कोरोना में हालत बहुत खराब हुए थे। भीलवाड़ा का जो बार-बार उदाहरण दिया जाता है, आपके पास एक ही उदाहरण है, जिसकी प्रधान मंत्री जी ने प्रशंसा की थी। उसके बाद क्या कारण रहा कि कहीं न कहीं सेवाओं में आपकी कमी रही, उसको भी आपको बताना चाहिये।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री आयष्मान आरोग्य योजना की शुरूआत की, जिसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी इसमें सम्मिलित किया। साथ ही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में शिशु एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिये पिडियाट्रिक पैकेज जोड़े गये। दूर-दराज के क्षेत्रों में प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने में कई दुविधाएं आती थीं, उसमें भी शिथिलता दी, इसके लिये भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने लगातार इस क्षेत्र में अच्छा काम करने का प्रयास किया।

मैं एक और धन्यवाद दूंगा कि पूरे राजस्थान में प्रत्येक विधान सभा में आयुष्मान मॉडल सी.एच.सी. खोलने के लिये आपने बजट में घोषणा की है। पूर्व चिकित्सा मंत्री जी ने एक मॉडल सी.एच.सी. के लिये लिख कर देने को कहा था, हमने लिख कर दिया। आज भी वह सी.एच.सी. वैसी कि वैसी है, उसमें केवल मॉडल नाम जोड़ा था, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मॉडल सी.एच.सी. की पूर्व की कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी, उस तक सीमित न रह कर, 10 जुलाई, 2024 के बजट में आपने शुरुआती दौर में इस प्रकार की घोषणा की है, मुझे विश्वास है कि मॉडल सी.एच.सी. में आप पूरा-पूरा सहयोग करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम अलग-अलग अस्पताल में

जाते हैं। पहले पी.एच.सी. में जाते हैं, फिर सी.एच.सी. में जाते हैं, फिर जिला अस्पताल में जाते हैं, फिर जयपुर तक भी आते हैं। उसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि रिकार्ड हमारे पास नहीं होता है। कहीं अकस्मात जाना भी पड़ता है और कभी घरवाले भूल भी जाते हैं। आपने राजस्थान डिजिटल हैल्थ मिशन प्रारंभ किया है, इसके लिये भी मैं मुख्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में भी आपने सी.एच.सी. और पी.एच.सी. की घोषणा की। मैं कुछ सुझाव आपको देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी बारिश का समय है, बारिश के समय में अधिकतर किसान खेतों में रहते हैं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्या, पीछे होकर निकलें।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): वहां खेतों में बहुत सांप होते हैं और सांप काटते हैं। स्नेक बाइट की उपलब्धता प्रत्येक पी.एच.सी., सी.एच.सी. पर समय पर कराएं, जिससे हमें कोई जन हानि न हो, यह अतिआवश्यक है, इस ओर मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

मैं एक और विषय रखना चाहूंगा, प्रत्येक ब्लॉक पर एक बीसीएमओ पोस्ट होती है। खाली पोस्ट होती है, लेकिन वहां ऑफिस नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बीसीएमओ खोला जाये, उसकी बिल्डिंग बनाई जाये और उसमें काम करने वाले सब लोग हों। ऑफिस नहीं होने से वहां कई तरह की समस्याएं आती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पूर्व में ओ पी डी में 10 रुपये का चार्ज बंद कर दिया था। आज की तारीख में स्थिति अलग है, 10 रुपये का चार्ज लगने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। मैं निवेदन करूंगा कि 10 रुपये ओ पी डी चार्ज चालू करें, इससे पी.एच.सी., सी.एच.सी. में कुछ धन इकट्ठा होता है, तो उससे वहां कभी कोई लैब टेक्निशियन लगाना है, अन्य कार्मिक लगाने में मदद मिलेगी। वहां फंड नहीं होता है तो अधिकारी वहां किसी को नहीं लगाते। मैं निवेदन करूंगा कि 10 रुपये से किसी पर भार नहीं पड़ता।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे आहोर विधान सभा क्षेत्र में एक मात्र सी.एच.सी. उप खण्ड स्तर पर है, उसको उप जिला अस्पताल बनाया जाये। उसमें आई.सी.यू., ट्रोमा सेंटर और ब्लड बैंक की आवश्यकता है। मेरा विधान सभा क्षेत्र 70-80 किलोमीटर में फैला हुआ है, वहां इसकी अति आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आहोर स्वास्थ्य केन्द्र को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाय।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आपकी समय सीमा समाप्त हो गई है।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): सभापति महोदय, एक मिनट और लूंगा। भाद्राजून, गुडाबालोतारन, भवरानी, चांदराई, हरजी में पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत किया जाय। अजीतपुरा, आईपुरा, मेडा उपरला के उप स्वास्थ्य केन्द्र को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत किया जाय। कुआरडा, गुडारामा, रसियावास और सुमेरगढ़ खेडा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाय। हमारे दयालु मुख्य मंत्री हैं, संवेदनशील मुख्य मंत्री हैं और चिकित्सा मंत्री भी

बहुत दयालु हैं, मुझे विश्वास है कि यह काम आप जरूर करेंगे।

मेरा अंतिम निवेदन है कि 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि बातें तो हम सभी करते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर की कमी है। मेरा निवेदन है जितने भी बड़े-बड़े सिटीज में एक्स्ट्रा डॉक्टर लगे हुए हैं, उन्हें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भेजें और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का भी इलाज कराएं। वहां पी.एच.सी., सी.एच.सी. खाली हैं। सी.एच.सी. और पी.एच.सी. खोल तो देते हैं, लेकिन वहां पर डाक्टर उपलब्ध नहीं होते। मेरा आपसे यही निवेदन है कि पी.एच.सी. और सी.एच.सी. में डॉक्टर उपलब्ध कराएं ताकि हमारे क्षेत्र में फायदा हो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजिए। मैं दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि मैं आधा मिनट पहले घंटी बजाऊंगा और उसके बाद मैं दूसरा नाम बोलूंगा, फिर अंकित नहीं होगा। इसलिए आपकी जो भी डिमांड है या क्षेत्र की समस्या है, वह पहले बोल दें, फिर आपका जो समय बचे, उसमें जो भी बोलना चाहे, वह बोलो। आधा मिनट पहले घंटी बजाने के बाद आपका अंकित नहीं होगा। माननीय श्री जाकिर हुसैन गैसावत।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिये। सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से हर वर्ग को मिलनी चाहिये। हमारी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा की दिशा में फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट, निरोगी राजस्थान के तहत राइट टू हैल्थ कानून बनाकर अद्भुत कार्य किये गये थे।

msk/rtm/19.07.2024/1820/3n

आज प्रदेश की जनता उनको याद करती है। पिछले पांच साल के कार्यकाल के अन्दर दो साल कोरोना में बीतने के बाद भी। कोरोना जब आया तो पूरी दुनिया का हर व्यक्ति जूझ रहा था कि क्या उपाय होगा? हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने कोरोना में जो व्यवस्था की, वह बहुत ही सराहनीय है। उस समय उन्होंने हर विधान सभा सदस्य के सुझाव लिए, चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों या अन्य पार्टी के हों, कि आपको कहां-कहां क्या आवश्यकता है? आपकी क्या-क्या डिमांड है, क्या-क्या मांग है? सबको प्राथमिकता देते हुए पूरे कोरोना काल में बहुत ही अच्छे कार्य किये। सामने वाले भाई लोग कह रहे हैं कि भीलवाड़ा मॉडल की क्या बात करें। भीलवाड़ा मॉडल की बात तो नरेन्द्र मोदी जी ने भी की है। यह हंसने की बात नहीं है। उस समय जब कोरोना था तो अच्छे-अच्छे आदमी जूझ रहे थे कि क्या होगा? पैसा-टका सब धरा का धरा रह जाता। अपन सुबह देखते थे, शत-शत नमन, अलविदा, इस तरह के एसएमएस आते थे। इसलिए जो काम अच्छा किया है, उस काम को अच्छा बताना चाहिए। मोदी जी की तरह कोई थाली बजायी नहीं, थाली से क्या कोई कोरोना भगा? मोबाइल की टॉर्च से क्या कोरोना भगा? मोमबत्ती से क्या

कोरोना भगा? ...(व्यवधान)... मैं तो कहूं। आप देखो ना, गंगा नदी में कितनी लाशें पड़ी थीं। क्या वे किसी से संभलीं? लेकिन यह कुदरता का निजाम था, किसी के हाथ की बात नहीं थी। जो अच्छा काम करे, उसकी सराहना होनी चाहिए।

हमारे पूर्व मुख्य मंत्री जी ने चिकित्सा में जो बजट दिया, जो महत्वपूर्ण काम किया, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमारी सरकार ने राइट टू हैल्थ कानून बनाया, जिसमें हर इमरजेंसी में इलाज की फ्री सुविधा होगी। आपसे यह निवेदन है कि इस कानून को नियम बनाकर लागू किया जाये। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जो कि 25 लाख रुपये की योजना है, इसमें आप और हम सब सम्मिलित हैं। क्योंकि जब कभी गरीब के घर में कोई बीमारी होती है, हार्ट का ऑपरेशन होता है तो दो-पांच लाख रुपये में स्टेण्ट वगैरह डलते हैं, उस टाइम वह गरीब आदमी मकान बेचता है या ब्याज पर रुपये लेता है। मुझे खुद को पता है, मेरी मां के हार्ट की तकलीफ हो गयी थी। मैं सेल्बी हॉस्पिटल में गया था, चिरंजीवी योजना से पहले। हॉस्पिटल वालों ने पहले एक लाख रुपये जमा कराये और डिस्चार्ज के टाइम डेढ़ लाख रुपये लिये, तो ढाई-ढाई लाख रुपये, पांच-पांच लाख रुपये। ऐसी चिरंजीवी योजना पूरे भारत वर्ष के अन्दर बहुत ही महत्वपूर्ण योजना घोषित हुई। उस चिरंजीवी योजना से आज पूरे प्रदेश के अन्दर लाखों लोगों ने फायदा उठाया। इसमें 5 हजार करोड़ रुपये का इलाज हुआ और 50 लाख से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया और आप कहते हैं कि चिरंजीवी में किसको लाभ मिला है? मंत्री जी कहते हैं कि इसमें किसी को लाभ नहीं मिला है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो इंश्योरेंस हुए, पूरे राजस्थान में नागरिकों के 93 परसेंट इंश्योरेंस हुए, उसमें आप और हम सब शामिल हैं। इसके सामने राष्ट्रीय औसत इंश्योरेंस 42 परसेंटी है, यूपी में 16 परसेंट, महाराष्ट्र में 22, पंजाब में 25 और हरियाणा में 26, एमपी में 38, गुजरात में 44 परसेंट। चिरंजीवी योजना में साढ़े आठ सौ रुपये में इंश्योरेंस हुआ तो 25 लाख के इलाज के साथ 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा इसमें डला हुआ है। आप देखिये, एक महत्वपूर्ण योजना, जिसमें राजस्थान के 93 परसेंट परिवारों को जोड़कर आज आम आदमी को फायदा मिला है। इस तरह से महत्वपूर्ण योजना माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने चलायी थी। जब पांच साल सरकार थी तो 1674 सब-सेंटर, 710 पीएचसी, 325 सीएचसी, 67 उप जिला अस्पताल, 27 जिला अस्पताल और 10 सैटेलाइट अस्पताल खोले गये। यह सरकार की ऐतिहासिक सराहना है।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इससे पहले आपकी बीजेपी की सरकार थी तो मेडिकल हैल्थ के अन्दर 7 सब-सेंटर थे और पूर्ववर्ती सरकार में 1674 सब-सेन्टर खोले गये। पीएचसी से सीएचसी 60 थी, अभी 350 पीएचसी से सीएचसी खोली गयी है। पीएचसी 45 थी, हमारे समय 277 खोली गयी। आपने उप जिला चिकित्सा केन्द्र एक भी नहीं खोला। हमारी सरकार ने 65 उप जिला चिकित्सा केन्द्र खोले, जिसमें हमारा मकराना भी सम्मिलित

है। मैं पूर्व मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं।

आपने एक भी जिला अस्पताल नहीं खोला। हमारी सरकार ने 27 जिला अस्पताल खोले। पहले एक सैटेलाइट अस्पताल था, हमारी सरकार ने 13 सैटेलाइट अस्पताल खोले। उस टाइम 865 बेड थे, हमारी सरकार ने 11 हजार 700 हास्पिटल के बेड बढ़ाये। इसी तरह से आयुर्वेद में हमारी सरकार ने चिकित्सा को लेकर जो काम किया। पहले आयुष हैल्थ वेलनेस सेंटर जीरो था, हमारी सरकार ने 1 हजार आयुष हैल्थ वेलनेंस सेन्टर बनाये। आपकी सरकार में ब्लॉक आयुष हास्पिटल जीरो थे, हमारी सरकार ने 82 ब्लॉक आयुष हॉस्पिटल खोले। आपकी सरकार में होम्योपैथी औषधालय जीरो थे, हमारी सरकार ने 225 होम्योपैथी औषधालय खोले। आपकी सरकार में यूनानी औषधालय जीरो थे, हमारी सरकार ने 101 यूनानी हॉस्पिटल खोले। ये जो महत्वपूर्ण फैसले थे, वे हमारी सरकार ने लिये थे।

पिछली सरकार में एमबीबीएस की 650 व पीजी की 366 सीटे बढ़ीं, हमारी सरकार ने एमबीबीएस की 1980 व पीजी की 558 बढ़ायी हैं। ये चार गुना सीटें हमारी सरकार के द्वारा बढ़ायी गयी हैं। पिछली सरकार में जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ, आम आदमी उसको याद कर रहा है। वह बहुत ही सराहनीय बात है। मैं आपको ज्यादा बात नहीं कहकर, मंत्री जी वैसे तो हमारे जिले के ही हैं, खींवसर से हैं, मंत्री जी, मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा मकराना विधान सभा क्षेत्र जो कि मार्बल उद्योग का क्षेत्र है, वहां सात लाख की आबादी के साथ-साथ मकराना सिटी के अन्दर व गांवों से 30-40 हजार लोग कामकाज के लिए मार्बल की खानों में मजदूरी के लिए आते हैं। वहां उप जिला चिकित्सा केन्द्र पूर्ववर्ती सरकार ने खोल दिया था। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वहां जिला अस्पताल खोलें, ताकि लोगों को इसका और ज्यादा फायदा मिले। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक आईसीयू एम्बुलेंस का भी आप कष्ट करें। ट्रोमा सेंटर वहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खानों में आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। वहां पर ट्रोमा सेंटर नहीं है। पीएचसी रानीगांव, बेसूडी, मनाणा को सीएचसी बनाया जाये। उप स्वास्थ्य केन्द्र कोला डूंगरी सरनावरा, चावंडिया, राम्यया, इंडोखा को पीएचसी बनाया जाये और उप जिला अस्पताल मकराना सीएचसी, बोरावर गछीपुरा, बुडसू में, पूरे मकराना विधान सभा क्षेत्र में स्त्री विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है और न ही वहां पर कोई सर्जन है। वहां पर भी आप स्त्री विशेषज्ञ डॉक्टर लगायें। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप टेबल करें।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): अध्यक्ष जी, एक मिनट, डिमांड है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बजट घोषणा 2013 के अन्दर वहां पर एक पीएचसी स्वीकृत हुई थी, वहां पर आज तक भवन नहीं बनाया गया है। 2021 के अन्दर दानदाता जितेन्द्र सिंह, दिलीप सिंह ने जमीन भी दे दी, आप वहां भवन बनाने की स्वीकृति भी देवें।

मांग संख्या 28 में बीएससी नर्सिंग कॉलेज आप मकराना में खोलें और आयुर्वेदिक कॉलेज

भी खोलें। दूसरी बात यह थी कि आचार संहिता के समय में हॉस्टिपटल लिये गये थे, वे सम्पूर्ण नहीं हुए थे।

श्री अध्यक्षः आप टेबल कर दें, बाकी। श्री गोरधन।

श्री गोरधन (धोद): आपके जिले के ही हैं। आपके सदस्य ने ही कह दिया घोषणा हो गयी। आपकी खूब सारी हो गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मांग संख्या 27 और 28, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जैसे प्रतिपक्ष के माननीय नेताओं के द्वारा पहले तो यह किया जाता है कि साहब हमारी यह घोषणा हो गयी और यह कर दिया, वह कर दिया और फिर माननीय मंत्री जी से मांग करते हैं तो मैं सोचता हूं कि यह बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए।

mdp/rtm/19.07.2024/18:30/3o

हुआ नहीं, एक भी उप-जिला अस्पताल नहीं हुआ, एक भी पीएचसी नहीं हुई। मांगते तो हैं, लेकिन पहले कहते हैं कि हमारे तो सब कुछ हो गया, फिर मांगते हैं तो फिर गलत बात है। नहीं होता है तो मांगना चाहिए, मांगने में कहां दिक्कत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, क्योंकि हमारे ये सुरेश जी बैठे हैं और मंत्र फूंक देंगे, उधर से वहां चला गया था फुलेरा तक, सीधा ही मेरी बात पर आ जाता हूं। पहले मेरी मांग कर लेता हूं, उसके बाद समय बचेगा तो मुझको देना।

श्री अध्यक्षः टाइम सीमित है।

श्री गोरधन (धोद): सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री महोदय को, हमारे मुख्य मंत्री जी को, उप मुख्य मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि लोसन नगर पालिका में हमें उप जिला अस्पताल दिया, इसके लिए इनका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से पिछले पांच साल कांग्रेस की सरकार रही, उसमें कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि हमारे मेन रोड पर पीएचसी दूजोद है, उसको सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए। वहां जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, लगभग दस हजार की आबादी है, वहां पर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मेरा दूसरा आग्रह है कि हमारे पर्यटन की दृष्टि से हर्ष पंचायत है, वहां पर सीकर के बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बहुत सारे लोग आते-जाते रहते हैं, वहां पर एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि वहां पर एक पीएचसी की घोषणा की जाए।

इसके अलावा मेरा आग्रह है कि हमारे ग्राम पंचायत सरोड़ी में पीएचसी है, उसको भी सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए। उसी प्रकार से कुछ हमारे उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जैसे बीराना है, खाखोली है, सांवलोदा धायलान है, ये हमारी बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, वहां पर भी पीएचसी की घोषणा की जाए। इसी प्रकार से कुछ ऐसे राजस्व गांव हैं, जहां पर आज तक

कोई उप स्वास्थ्य केन्द्र भी नहीं बना, जैसे फतेह सिंह की ढाणी है, अर्जुनपुरा है, लाड़वा है, इनमें हमें उप स्वास्थ्य केन्द्र की बहुत महती आवश्यकता है। मंत्री महोदय, बहुत ही दयालु है और करने वाले भी है। पहले भी 2013-18 में इन्होंने ऊर्जा विभाग में बहुत सारे काम किए थे। ऐसा मेरा आग्रह है कि हमें कुछ भवन भी जो अभी बाकी पड़े हैं, उप स्वास्थ्य केन्द्रों के जैसे चिड़ासरा है, चिनाटू है, पूनपुरा है, मंत्री महोदय, हमें कुछ देते हैं, वैसे तो देते ही रहेंगे। मेरा विशेष आग्रह है कि इन पर विशेष ध्यान दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारा सीकर का जो श्रीकल्याण हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज, क्योंकि आज उसमें सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं की घोषणाएं हो चुकी हैं, फिर भी क्योंकि ये पूरे शेखावाटी बेल्ट को, विशेषकर तीन-चार जिलों को प्रभावित करता है, हमारा जो एसएमएस हॉस्पिटल है, उस पर यदि हम दबाव कम करना चाहते हैं तो हमें सीकर में सुविधाएं थोड़ी और बढ़ानी चाहिए। वहां पर संसाधन बढ़ाने चाहिए, जिससे एसएमएस पर दबाव कम रहे और वहां पर ही मरीजों को ठीक किया जा सके।

मेरा दूसरा आग्रह ये भी है कि जिस प्रकार हम कई बार देखते हैं कि जो जेनरिक दवाइयां देते हैं, उसमें जो गरीब व्यक्ति होते हैं या कम पढ़े-लिखे लोग होते हैं, उनको यह पता नहीं रहता की इसकी एमआरपी क्या है, कितना पैसा इसमें लेना चाहिए। मेरा आग्रह है कि जो भी कंपनियां दवाइयां देती हैं, वह उसमें उतनी ही एमआरपी लिखे, जितनी हमें कस्टमर से लेनी होती है।

एसएमएस में सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। हमारा यह बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। यह राजस्थान के लिए गौरव की बात है। इसमें बहुत सारे जिलों से मरीज आते हैं, लोग-बाग़ आते हैं। यहां पर जो सहायता केन्द्र बना हुआ है, उस सहायता केन्द्र को थोड़ा और बढ़ाएं। यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, जिनको वार्डों का पता नहीं रहता कि किधर जाना है, कौनसा डॉक्टर कहां देखता है? जो व्यक्ति कम पढ़े-लिखे होते हैं, उनको पता नहीं रहता। उनकी सहायतार्थ के रूप में अगर अटेंडेंट होता है तो उनकी सहायता हो सकती है।

अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा है कि हमें गांवों की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पीएचसी हैं, सीए चसी हैं, अगर वहां पर हम सुविधाएं ज्यादा कर देंगे तो वह शहरों की तरफ नहीं भागेंगे, जयपुर नहीं आना पड़ेगा या जो बड़ी सिटी है, वहां नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उन पर यदि हम थोड़ी सुविधाएं बढ़ाते हैं तो वहां पर ही मरीजों को देखा जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी वर्तमान स्थिति में बहुत सारे केसेज हार्ट अटैक के होते हैं, बहुत सारे कैंसर के होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे विडियो ऐसे वायरल होते हैं कि कोई डांस करता हुआ, कोई काम करता हुआ हार्ट अटैक से मर जाता है, कोई बैठा हुआ मर जाता है, कोई बाथरूम में मर जाता है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि हार्ट अटैक है, कैंसर रोग है, क्योंकि दोनों ही रोग ऐसे हैं जिनका

व्यक्ति को पहले पता नहीं चलता, तो इसके जो भी लक्षण होते हैं, मैं आग्रह करता हूं कि हमारे जो सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, गांवों में जाकर उनको थोड़ा पहले चैक करवाएं तो उनको हम पहले सूचना दे दें तो काफी लोगों को फायदा हो सकता है।

माननीय हमारे एक सदस्य ने कहा कि दस रुपये की जो पर्ची है, वह वास्तव में वापस चालू करनी चाहिए। दस रुपया कोई ज्यादा भी नहीं होता है। उसका एक रिकॉर्ड भी हो जाता है। उससे फायदा होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो भी काम करते हैं, वहां पर हमारी सुविधाएं, सरकार की तरफ हमको नहीं देखना पड़ता है, छोटी-मोटी सुविधाओं की हम पूर्ति कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि माननीय मंत्री महोदय हमारी मांगों पर ध्यान देंगे। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। वंदेमातरम।

श्री अध्यक्ष: श्री अमीन कागजी।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): माननीय अध्यक्ष जी, मुझे स्वास्थ्य सेवा में मांग संख्या 27 पर बोलने के लिए आपने इजाजत दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चिकित्सा और इलाज, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं चूंकि समय का अभाव है, पहले मैं अपनी डिमांड रख दूं क्योंकि बोलते-बोलते लास्ट में लोगों की डिमांड रह जाती है और पूरा भाषण हो जाता है।

मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि किशन पोल क्षेत्र जो मेरा है, इसमें पिछली सरकार के वक्त बजट दिया और कुछ तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपये के करीब मेरे विधायक कोटे से मैंने दिए। मोतीकटला डिस्पेंसरी के नाम से एक बिल्डिंग उस प्रीमाइसेस में बननी थी, उसका टेंडर नहीं हो पाया। वह पैसा मेरे विधायक कोटे से भी चला गया और सरकार ने भी अपनी तरफ से दिया। उसकी ओ एंड एम भी निकल गयी, लेकिन आज तक वह टेंडर हो नहीं पाया। मेरा आपसे आग्रह है कि इस ओर आप थोड़ा कंसीडर करें ताकि वह बिल्डिंग बन जाए क्योंकि उसकी ओपीडी बहुत स्पीड से बढ़ रही है। तकरीबन 1000 से 1200 की ओपीडी वहां है, उस पर दबाव है। उसको बनाने से हमारे एसएमएस पर भी लोड का फर्क पड़ेगा।

दूसरी तरफ, पिछली सरकार के वक्त 40 करोड़ रुपये की इजाजत के साथ एक सेटेलाइट हॉस्पिटल किशन पोल विधान सभा क्षेत्र के लिए सरकार ने हमें दिया, उसकी बिल्डिंग का काम चल रहा है। उसमें पद सृजित हो गये थे, उनके डॉक्टर्स अभी दूसरे हॉस्पिटल में बैठकर इलाज कर रहे हैं। जो पद आपने सृजित किये थे और जो स्टाफ बैठा हुआ है, उसमें 14 पद सृजित हुए थे, तकरीबन 6 से 7 डॉक्टर आते हैं, बाकी सीएमएचओ साहब ने दूसरी जगह लगा दिए, जबकि वहां की ओपीडी एक हजार से ज्यादा है। मेरा आपसे आग्रह है कि जिस हॉस्पिटल में ओपीडी ज्यादा रहे, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में जब ओपीडी बढ़ती है तो डाक्टर्स को इधर से उधर न किया जाए, उससे बुरा फर्क पड़ता है। लोग दूर-दराज जाने में, क्योंकि एसएमएस में जा नहीं सकते, एसएमएस ओवरलोड है। इसी को देखते हुए जब मैंने मुख्य मत्री अशोक गहलोत जी से आग्रह किया तो इमिजेटली पहले बजट में मुझे ये सेटेलाइट अस्पताल दिया था। जी, अंडर स्टाफ है, मतलब सेंक्शन पद हैं, परंतु दूसरी जगह लगा दिए।

Ans/rtm 18.40 3p 19.07.2024

तीसरी बात, नर्सिंग स्टाफ है, वहां जो स्वीकृत पद है, उनको दाएं बाएं कर दिए। एक हॉस्पिटल जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर था उसकी हमने पिछली सरकार के टाइम एक नई बिल्डिंग बनाई, हमने बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनाई, उसमें पद सृजित है, तकरीबन 2 या 3 डॉक्टर्स हैं, बाकी नर्सिंग स्टाफ है। उसमें जब ओपीडी चालू हुई तो इतना ट्रेमेंडस फर्क पड़ा कि करीब 400-500 के बीच डेली की ओपीडी हो गई। अभी पिछले तीन-चार महीने से देखने को मिल रहा है कि वहां जो डॉक्टर्स लगे हुए थे, वह पूरी तरह से गायब है। पुरानी बस्ती के नाम से प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसको आप दिखवा ले।

मैं बहुत ही गम्भीरता से एक आग्रह करना चाहता हूं, पहले बजट में चर्चा हो रही थी तब भी मैंने बताया था कि जयपुर में नशे का कारोबार बहुत स्पीड़ से बढ़ रहा है,हालांकि आज इसका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यह चीज इससे कोरिलेट करती है। आज की तारीख में बच्चे नशे में लिप्त हो रहे हैं, उनके लिए रिहेबिटेशन का काम नहीं हो रहा है। हमें उसमें कंसीडर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। परिवार खराब हो रहे हैं, नई पीढिया खराब हो रही है। जयपुर में नशे के कारोबार ने इतनी ज्यादा अपनी जड़ें फैलाई है। मैंने कई बार सीपी साहब से आग्रह किया है। जगह आइडेंटिफाई कर देते हैं, हम बता देते हैं कि यहां जाइये, इस मकान नम्बर पर जाइये, यह आदमी बेच रहा है। पिछले डेढ़ महीने में मैंने सीपी साहब से बात की, दो बार एसपी साहब से बात की, एक बार एडिशनल एसपी साहब से बात की, जगह चिह्नित करके बताई कि जाइये इस घर में यहां बिक रहा है। आप ताज्जुब करेंगे कि वहां पुलिस पहुंचने से पहले, वह अपनी दुकान बढ़ाकर भग जाता है। अब इसको क्या कहे, यह तो हम सब समझते हैं, हमारी समझ में है, लेकिन इस ओर आपको ध्यान देने की जरूरत है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी समय है।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। आपके सात मिनट थे, छह मिनट हो गए।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): मेरी विधान सभा का तो मैं बोल चुका। दो-तीन छोटे-छोटे सब्जेक्ट हैं।

श्री अध्यक्ष: तो फटाफट सब्जेक्ट पर आ जाओ।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में एक गुलर का बांध है, उसमें मेडिकल एंड हेल्थ, जो सीएचसी सेंटर हैं, उसमें डॉक्टर नहीं है, सांगानेर मैन बाजार में। चूंकि मुख्य मंत्री जी का एरिया है, वहां से मुख्य मंत्री जी चुनकर आए हैं। पिछले डेढ़ महीने में मैंने देखा है, इतने जबरदस्त कैंसर के मरीज सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, because of pollution, because of so many things. वहां वाटर में कंटेमिनेशन है पाल्युशन का। एसटीपीसीज जो चलने चाहिए वह नहीं चल रहे हैं। मैं डिमांड पर इसलिए कहना चाह रहा हूं कि यह मेडिकल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। सांगानेर के मरीज जयपुरिया में

आते हैं। चूंकि वहां सेटेलाइट हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है इसलिए उनको जयपुरिया आना पड़ता है। जयपुरिया की अगर आत बात करे, पिछले दिनों 14 तारीख को प्रसिद्ध अख़बार में एक खबर आई थी, जिसको मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। अगर कोई एंजियोग्राफी कराता है तो एंजियोप्लास्टी के लिए वहां फैसिलिटी नहीं है, उसको एसएमएस भेज देते हैं। जिस टाइम एंजियोग्राफी हो रही है, उसी टाइम एंजियोप्लास्टी होता है, लेकिन एंजियोप्लास्टी नहीं करेंगे। उसको एसएमएस रेफर कर देते हैं कि दूसरे दिन जाकर वहां कराइये। इस तरीके की चीज़ें है, उसको हमें देखने की जरूरत है।

जयपुरिया हॉस्पिटल का अभी माननीय कालीचरण जी सराफ ने भी कहा। उसके बारे में वह भी बात बताकर गए हैं। यह ऐसा सेन्ट्रलाइज हॉस्पिटल है जिससे मालवीय नगर, मानसरोवर, सांगानेर और टोंक रोड़ का एरिया कवर होता है। समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्षः श्री ताराचंद जैन।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): दूसरी छोटी सी बात, आपकी इजाजत हो तो।

श्री अध्यक्षः इजाजत देते देते ही तो दो मिनट ज्यादा दे दिए।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): मैं सिर्फ इतनी सी बात कहकर खतम करता हूं। चिरंजीवी योजना है इसके अन्दर तकरीबन 1200-1500 करोड़ रुपये साल का खर्चा था। चिरंजीवी योजना व आयुष्मान में एक बहुत बड़ा फर्क है, 25 लाख वर्सेज 5 लाख। अगर आप इसको देखे, आयुष्मान का जितना भी पैसा मिल रहा है, मंत्री जी वह आपको भारत सरकार से मिल रहा है। हमारा बहुत कम रेशो है इसके अन्दर। 27 हजार करोड़ का आपका बजट है, अगर एक हजार करोड़ भी...

श्री अध्यक्षः श्री ताराचंद जैन।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 व 27 पर बोलने का मौका दिया।

श्री अमीन कागजी (किशन पोल): आपकी चिरंजीवी पूरी कवर हो सकती है। आप विचार करे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 और 28 चिकित्सा एवं शिक्षा पर बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र की समस्याओं की ओर दिलाऊंगा।

(समयः बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

उदयपुर में महाराणा भूपाल चिकित्सालय है। पिछले 100 वर्षों से, महाराणा के समय से बना हुआ है। यह हॉस्पिटल केवल उदयपुर का नहीं, सम्भाग का उसमें नीमच, मंसोला, ठेठ उज्जैन तक के रोगी इस उदयपुर हॉस्पिटल में आते हैं। पिछली कांग्रेस के समय, एक तरफ महाराणा की बिल्डिंग बनी हुई है जो 100 वर्ष पुरानी है, दूसरी तरफ पन्नाधाय हॉस्पिटल दो मंजिला इमारात बनी हुई थी, 100 करोड़ रुपये व्यय करके, दो मंजिल पर और दो मंजिल

नई बना दी। दो मंजिल पूरी गिर गई, डेमेज हो गई। क्षतिग्रस्त करके पिछले साल सरकार ने जाते-जाते 3.11.2023 को 119 करोड़ का नया बजट, 100 करोड़ डूब गए, 113 करोड़ के आदेश दे दिए। आधा पैसा यूआईटी देवे और आधा पैसा एनएचएमपीआईपी स्कीम के तहत दिया जाए। मैंने उसकी छानबीन की, जिस इंजीनियर ने इस बिल्डिंग को बनवाया, उस बिल्डिंग को लीपापोती करके जांच करके, क्लीन सर्टिफिकेट दे दिया, फिर 120 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए। पैसे का ठिकाना नहीं है। सरकार जाते वक्त यह कागज निकालकर चली गई। मेरा चिकित्सा मंत्री जी से आग्रह है कि पिछला जो घोटाला हुआ उसकी जांच हो और नई राशि आवंटित करवाए। उस बिल्डिंग की कैपेसिटी 600 महिला रोगियों की है। 600 महिलाओं को इधर-उधर, कहीं ना कहीं एडजेस्ट करके, हॉस्पिटल चल रहा है। आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं, राशि तुरंत आवंटित की जाए।

मेरा निवेदन है कि उदयपुर हॉस्पिटल, जो सड़क बनी हुई थी, आज से 10 वर्ष पहले इस मार्ग को चौड़ा करने के लिए हॉस्पिटल से कम से कम 500 मीटर से ज्यादा सड़क के लिए जमीन ले ली और चिकित्सालय के लिए कम पड़ी। चिकित्सालय से लगी हुई बिल्डिंग, पशु चिकित्सालय की है। 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराना हॉस्पिटल है। जितना विस्तार इस हॉस्पिटल का हुआ है, यह बिल्डिंग बहुत थोड़ी पड़ रही है। उस समय यह तय किया गया था 2015/39/44/6.6.16 को, मुख्य मंत्री अनुसरण पशु चिकित्सालय का भवन, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर को देने के लिए विभाग की सहमति व्यक्त कर दी। एक्सटेंशन करना है तो पास वाले हॉस्पिटल की बड़ी जमीन है, वह लेनी पड़ेगी। पशु चिकित्सालय उदयपुर के मैन चेतक सड़क पर बना हुआ है। अगर उसको बड़ी तक शिफ्ट कर देते हैं तो उस हॉस्पिटल का भी विस्तार हो जाएगा। पशुपालक अपने पशुओं को लेकर पशु चिकित्सालय में आते हैं, बहुत बड़े चौराहे पर हॉस्पिटल स्थित है, जहां व्हीकल लाना ले जाना मुश्किल और पुशओं को उतारना मुश्किल। मेरा चिकित्सा मंत्री जी से आग्रह है कि कलक्टर को निर्देशित करके, इस मामले को निपटाकर, इस हॉस्पिटल का विस्तार करने के मार्ग को प्रशस्त करें।

उदयपुर में इतना बड़ा हॉस्पिटल है। महाविद्यालय में पोस्ट खाली है, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता मकरना से आते हैं, उन्होंने लम्बा-चौडा बखान तो कर दिया कि यह किया वह किया, यह नहीं बताया कि इतना खोल दिया, लेकिन इसमें डॉक्टर्स नहीं दिए, चिकित्साकर्मी नहीं है। खोल-खोलकर आप तो चले गए।

मैं सरकार को धन्यवाद अर्पित करूंगा कि हमारी सरकार ने आते ही 1500 चिकित्सकों की भर्ती की, 4 हजार नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की। इससे चिकित्सा में निश्चित रूप से पूरे राजस्थान को राहत मिलेगी।

VPS-RTM-19.07.2024-18.50-3q

मेरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए निवेदन है कि वहां पर नेफ्रोलॉजी का एक भी डाक्टर नहीं है, वे अभी रिटायर हो गये हैं। मैं आपको सारा बता रहा हूं कि मंदसौर से लेकर,

सारे उदयपुर सम्भाग के कम से कम 15 जिलों के पेशेंट उदयपुर हॉस्पिटल में आते हैं। इसी के साथ यह निवेदन है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पर्याप्त डाक्टर्स नहीं हैं। प्लास्टिक सर्जरी का डॉक्टर नहीं है, जी.आई. सर्जरी का डॉक्टर नहीं है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट नहीं है। वहां पर खाली एक आचार्य है तो उसमें भी नियंत्रक है ही नहीं, तो मेरा आपसे यह आग्रह है कि मैं अपने पत्र के माध्यम से भी आपको आग्रह करूंगा कि उदयपुर हॉस्पिटल के लिए कम से कम मेरा अंदाज है, मैं उसकी लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं। 266 पद नर्सिंग ऑफिसर्स के रिक्त है। वार्ड ब्वाय के 169 पद रिक्त है। महाराणा भूपाल चिकित्सालय में दो अधीक्षक के पद भी रिक्त है। इसके साथ महाराणा भूपाल चिकित्सालय में 50 रोगी मित्र लगाये जाने की आवश्यकता है। इसी तरह से कई पोस्टें खाली हैं।

इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उदयपुर के अन्दर एक हॉस्पिटल है जिसका नाम सुन्दर सिंह भंडारी जिला चिकित्सालय है, वह सारी सुविधा युक्त हॉस्पिटल बना हुआ है, 100 बेड का बिलकुल सुपर हॉस्पिटल है लेकिन स्टाफ के अभाव में, मात्र 15-20 परसेंट ही स्टाफ है और वहां पर 15-20 परसेंट ही रोगी आते हैं। 100 बेड का एकदम ए.सी. हॉस्पिटल है पर उसके अन्दर स्टाफ का अभाव है तो अगर वहां पर स्टाफ उपलब्ध करवा दिया जाता है तो इस महाराणा भूपाल हॉस्पिटल का लोड आधा हो जायेगा।

इसके साथ ही हमारा दूसरा सैटेलाइट हॉस्पिटल और है जिसका नाम पूर्व विधायक खेमराज कटारा के नाम से है तो उस हॉस्पिटल को भी जिला चिकित्सालय के समकक्ष बनाया जाये तो इस उदयपुर हॉस्पिटल की थोड़ी स्थिति ठीक हो सकती है।

इसी के साथ मैं शिक्षा मंत्रीजी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि चिरंजीवी योजना हमने शुरू की, तो यह बात सही है कि आपने घोषणा जरूर की है लेकिन मैं अपना खुद का ही एक किस्सा बताता हूं कि पहली बार हमने हर व्यक्ति को कहा कि 870 रुपये दो और आपका इलाज एक वर्ष के लिए फ्री हो जायेगा तो मैंने यह सोचा, मैं तो यह कल्पना ही नहीं करता था कि ऐसा होगा तो मैंने 1800 रुपये देकर इंश्योरेंस करवाया और इंश्योरेंस करवाने के बाद जब बीमारी का इलाज करवाने गये तो वहां पर कहा गया कि नहीं-नहीं, साहब, यह तो नहीं आता है। फिर आगे जाओ तो रोज हमारे पास पेशेंट आकर कहते थे कि चिरंजीवी के तहत हमारा इलाज करवाइये, तो मैंने भी कहा कि आप चिरंजीवी में जाओ तो आपका इलाज फ्री हो जायेगा। तो वे कहते थे कि छह महीने बाद हार्ट का ऑपरेशन होगा और पैर का ऑपरेशन चार महीने बाद होगा। हार्ट का ऑपरेशन छह महीने बाद होगा तो तब तक तो वह यमलोक पहुंच जायेगा। तो जब डॉक्टर्स से बात की तो उन्होंने कहा कि आठ-आठ, नौ-नो महीने से हमको पैसे ही नहीं दिये हैं तो हम करें क्या? इस तरह से उन्होंने घोषणाओं में दिन निकाले, वाहवाही लूटने में दिन निकाले और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस दिन सरकार जाने की तैयारी हो रही थी, उस दिन यह सारा किया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस एक मिनट के अन्दर शिक्षा की बात कहूंगा। मैं आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी से यह

आग्रह करूंगा कि शिक्षा के अन्दर उदयपुर शहर के अन्दर जितने टीचर चाहिए उससे चार गुणा, एक स्कूल जिसका नाम है फतेह स्कूल ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: यह शिक्षा की डिमांड नहीं है, चिकित्सा शिक्षा के बारे में ही आपको बोलना है।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): अच्छा, इसमें नहीं है? इस कागज में यह लिखा हुआ है। सॉरी, चिकित्सा शिक्षा लिखा हुआ है। कोई बात नहीं कल बोल दूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें।

श्री ताराचन्द जैन (उदयपुर): अब मेरा यह निवेदन है चिकित्सा मंत्रीजी से कि मैंने जितनी भी बातें रखी हैं, लिखित में आपको पत्र भी दूंगा तो एक तो हॉस्पिटल के अन्दर जो 100 करोड़ रुपये पिछली सरकार के समय में घोटाला हो गया, पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गयी है, तो आप उसकी जांच करायें। पहले भी जांच की लीपापोती हुई है। जिस एक्स.ईएन. ने उस बिल्डिंग को बनाया वह मेरे पास चार महीने पहले आया कि, साहब, मेरा ट्रांसफर करवा दो। मैंने कहा कि आप तो सस्पेंड है? उसने कहा कि मैं सस्पेंड नहीं हूं, मैं बहाल हो गया, तो मैंने कहा कि कितने पैसे दिये? उसने कहा कि, साहब, वह छोड़ो। तो इसलिए मेरा आपसे यह आग्रह है कि इस घोटाले की जांच करायें और जांच करवाकर दोषियों को दंडित करें और उदयपुर की समस्याओं का निराकरण करें।

माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री सभापति: डॉ. प्रियंका चौधरी।

डॉ. प्रियंका चौधरी (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 27 एवं 28 पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। समय कम है, मैं यह जानती हूं लेकिन जल्दी- जल्दी अपनी बात कहूंगी। मैंने यहां पर चर्चा सुनी और कोरोना के बारे में बात हुई थी तो मैं यह मानती हूं कि कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी मानव जाति के त्रासदी थी, जिसने न सिर्फ मानव जीवन का नाश किया बल्कि मानवीय संवेदनाओं का भी नाश किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह मानती हूं कि इस पर राजनीति न करे तो बेहतर है। यहां पर हम जानते हैं कि आदरणीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी ने पूर्व मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत की तारीफ की थी तो निश्चित रूप से कोई अच्छा काम किया होगा, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उस कोरोना के समय के अन्दर जो एम.पी. कोटा फ्रीज किया गया था वह पूरा का पूरा कोरोना के इलाज के लिए, जनता की भलाई के लिए, जनता के इलाज के लिए लगाया गया था। मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि बाड़मेर से जो हमारे सांसद थे वे हर पी.एच.सी. पर गये, हर सी.एच.सी. पर गये और वहां पर उन्होंने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर उपलब्ध करवाया और जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, मैं बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र की ही बात करूंगी, जो वहां के विधायक थे उन्होंने उस वक्त दस करोड़ रुपये का

सी.एस.आर. फंड से एक टेम्प्रेरी हॉस्पिटल बनाया जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। उसमें अगर किसी को दवाई मिलती थी तो उसके लिए भी उनसे फोन करवाना पड़ता था, उस इंजेक्शन के लिए भी फोन करवाना पड़ता था, तब ही वह उनको नसीब होता था। आदरणीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी की योजना को हमें नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान अन्न कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को घर बैठे मुफ्त राशन देने का काम किया तो यह कोरोना के अन्दर प्रधान मंत्रीजी ने किया था, तो इसमें हम राजनीति नहीं करें। थाली और ताली और मोबाइल की लाइट की जब बात आती है तो मैं यह मानती हूं कि इससे कोरोना तो ठीक नहीं होता है लेकिन उस वक्त एक सामूहिकता की जरूरत थी, एक जीवंतता की जरूरत थी क्योंकि उस वक्त मानवीय अवसाद एक बहुत बड़ी पीड़ा थी और मैं यह मानती हूं कि वह जो एक सामूहिकता का भाव आया तो हम सब कहीं न कहीं उसमें जुडे, चाहे किसी भी दल में थे या किसी भी क्षेत्र में थे।

मैं बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगी। मैं माननीय मंत्रीजी के ध्यान में यह लाना चाहूंगी कि बाड़मेर जिला हिंदुस्तान का, भारत का पांचवें नम्बर का सबसे बड़ा जिला है और उसका क्षेत्रफल 28,387 स्क्वायर किलोमीटर है। यहां पर जो जिला अस्पताल है, वह 1100 बेड का है जिसमें से अभी 500 बेड संचालित है और शीघ्र ही 600 बेड की आगे आने वाले समय में शुरूआत होना प्रस्तावित है। लेकिन जो हमारा बाड़मेर जिले का हॉस्पिटल है, वह हॉस्पिटल तो कम है और रेफरल हॉस्पिटल ज्यादा है क्योंकि यहां पर न से सीटी स्कैन की मशीन प्रोपर तरीके से काम करती है क्योंकि वह पीपीपी मोड पर दी गयी है। सोनोग्राफी की मशीन है पर रोजाना 500 सोनोग्राफी लिखी जाती है पर होती 200 ही है और 300 को वेटिंग में रखा जाता है तो दो-दो महीने की वेटिंग वहां पर है। मैं कैथ लैब की अगर बात बताऊं तो कैथ लैब के लिए 2022-23 में, पिछली सरकार में घोषणा की थी और उसमें प्रावधान भी किया था लेकिन कोई टेंडर नहीं हुआ और इसलिए आज दिन तक कोई कैथ लैब नहीं आयी जबकि इस वक्त सबसे ज्यादा हार्ट के पेशेंट्स हैं। एक कार्डियोलॉजिस्ट है जो 18 महीने से वहां पर है। ढाई हजार लोगों को अभी तक भर्ती किया गया है जिसमें से 80 परसेंट लोगों को एंजियोग्राफी की जरूरत थी लेकिन उनको भी रेफर करने की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि कैथ लैब नहीं है। जितने राजमेस के मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें से सिर्फ एक बाड़मेर मेडिकल कॉलेज ही ऐसा है जिसमें कैथ लैब की सुविधा नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहूंगी कि बाड़मेर जिला अस्पताल पर एक कैथ लैब की आवश्यकता है, एक एम.आर.आई. मशीन की सख्त आवश्यकता है। वहां का पानी बहुत ही भारी है, हार्ड वॉटर है, फ्लोरोसिस की समस्या वहां पर बहुत ज्यादा है, वहां पर सबसे ज्यादा समस्या कैंसर की है और हार्ट की है, तो मैं यह चाहती हूं कि बाड़मेर जिला हॉस्पिटल में एक न्यूरोलॉजी का विभाग भी शुरू किया जाये और ऑन्कोलॉजी का विभाग भी शुरू किया जाये ताकि वहां के लोगों को इलाज के लिए गुजरात नहीं जाना पड़े, जोधपुर एम्स में नहीं जाना पड़े।

मैं माननीय मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहूंगी कि जो सफाई की व्यवस्था है वह हर सरकारी हॉस्पिटल में खराब है लेकिन उसकी मॉनिटरिंग के लिए, मेनटिनेंस के लिए एक अलग व्यक्ति की, चाहे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति हो, उसको हायर करके उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि वह सारी व्यवस्था का ख्याल रख सके।

SSY/RTM/19.07.2024/19.00/4a

बाड़मेर के अन्दर करीब 30 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन मेरी जानकारी में यह आया है कि बायो मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल की कोई भी वहां सुविधा नहीं है। उस पर भी ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरी जो एक मांग है, वह भी बताना चाहूंगी। उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की जरूरत है अणदे का तला, जाणियों की ढाणी, हरुपनी खतों की ढाणी में तथा 2 पीएचसी हैं, उनको सीएचसी में क्रमोन्नत करवाने की मांग करती हूं, सनावड़ा और बेरी वाला तला को।

राजकीय नर्सिंग कॉलेज जो बाड़मेर में है, उसमें बेसिक बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स की 20 सीटों की स्वीकृति प्रदान करने की मैं मांग करती हूं ताकि वहां पर जो नर्सिंग कर्मी हैं, उनको बाहर नहीं जाना पड़े। वहीं ट्रेनिंग लेकर वह वहां ग्रामीणों को राहत दे सकें।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, धन्यवाद। श्री हाकम अली।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

मैं माननीय मंत्री महोदय का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने 27,600 करोड़ रुपये का जो बजट पेश किया है, लेकिन निवेदन यह रहेगा कि यह बजट पूरा इम्पलीमेंट हो। राजस्थान की जनता को इसका लाभ मिले।

मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान जयपुर एसएमएस से ही स्टार्ट कर देता हूं। जयपुर एसएमएस में राजस्थान, हरियाणा, गुजरात इन 3-4 स्टेटों के पेशेंट यहां आते हैं। आते वही हैं जो गरीब हैं। पैसे वाला कोई एसएमएस में नहीं आता, चाहे वह राजस्थान का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे गुजरात का हो।

पिछले दिनों मैंने मेरे बच्चे को एडमिट करा रखा था। मैं रात को वहां रुका था। यह हमारे सरकार के टाइम की बात है। मैं आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं। वहां तकरीबन 1500 से 1800 अटेंडेंट जो पेशेंट के साथ रहते हैं, वे बाहर खुले में सो रहे थे। रात को जब बारिश आनी शुरू हुई तो वे अपने-अपने जो भी बिस्तर थे, उसको लेकर बरामदे की तरफ भागे तो वहां बरामदे के अन्दर उनको सुरक्षा गार्डों ने घुसने नहीं दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये गरीब अब कहां जायेंगे इस रात में। मैंने उसी टाइम बाहर निकलकर माननीय मंत्री महोदय से बात की थी कि मंत्री महोदय, एसएमएस हॉस्पिटल का यह हाल है। मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम इसकी कोई व्यवस्था करेंगे। उसके बाद मैंने बॉम्बे एक भामाशाह से बात की। उसका मैने वीडियो बनाया। वह बनाकर के मैंने भामाशाह

को भेजा, भामाशाह मेरा मित्र था, उन्होंने कहा कि आप परमिशन लो और कल से काम चालू करो और यहां एक अच्छा शैड बनाओ और अच्छी व्यवस्था करो। फैन लगाओ, कूलर लगाओ और पीने के पानी की व्यवस्था करो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वह परमिशन मिलते-मिलते 6 महीने निकल गये। अभी जैसे श्रवण जी कह रहे थे कि आज वह मंत्री जी सदन में नहीं हैं।

माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन गरीबों की भावनाओं को देखते हुए, पैसे वाले कहीं भी इलाज करा सकते हैं, लेकिन एसएमएस में गरीब जायेगा। वह जो बाहर का नजारा है, उसको ध्यान में रखते हुए उनकी कोई व्यवस्था की जाये।

मैं पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र की डिमांड रख देता हूं। आपने अच्छा बजट पेश किया है। पिछली सरकार के टाइम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में उप जिला अस्पताल का भवन बन रहा है। आपसे निवेदन है कि आपने जिस भी संस्था को कार्यकारी एजेंसी बनाया है, उसको आदेश करके गुणवत्तापूर्वक बनायें। पिछले दिनों एक बीबीपुर गांव है, उसमें सीएचसी का भवन चल रहा था। गांव वालों ने जब वहां जाकर के देखा, पूरी मीडिया में वह चला था, आज तक पर, फर्स्ट इंडिया पर, सब पर वह वीडियो चला था। जो उन्होंने पीसीसी की थी, उसके अन्दर से गांव वालों ने हाथ से मिट्टी निकाल-निकाल करके बाहर फेंकी थी। मीडिया के जाने के बाद एनआरएचएम के अधिकारी गये और उसको पूरे को तुड़वाया गया। इसलिए ऐसा ना हो कि वहां गुणवत्तापूर्वक काम नहीं हो। मेरा यही निवेदन है कि गुणवत्तापूर्वक काम कराया जाये।

मेरे विधान सभा क्षेत्र से पाली-अंबाला हाई वे गुजरता है। उस पर एक रामगढ़ कस्बा है, शहर है, वहां नगरपालिका भी है, एसडीएम ऑफिस है, तहसीलदार कार्यालय है, बिजली बोर्ड का सब कार्यालय है। उस अस्पताल में भी 11 डाक्टर्स के पद हैं, आज की तारीख में 4 डॉक्टर हैं, 7 खाली हैं। वहां हाईवे पर रोज एक्सीडेंट होते हैं। आये दिन 2 या 3 कैजुअल्टी होती हैं। 10 से 12 लोग घायल होते हैं। जब उनको रामगढ़ अस्पताल में लेकर जाते हैं तो वहां कोई सुविधा नहीं मिलती है। उनको या तो चूरू जाना पड़ता है या उनको सीकर जाना पड़ता है और फिर सीकर से जयपुर। मेरा आपसे निवेदन है कि वे पद भरे जायें। अगर उस हाई वे पर एक ट्रोमा सेंटर खोल दिया जाये तो मैं समझता हूं कि दुर्घटनाओं में मरने वालों की कमी आयेगी और जो घायल हैं उनको जल्दी से इलाज मिलेगा।

फतेहपुर से भी 3 हाईवे गुजरते हैं। दिल्ली-बीकानेर, जयपुर-बीकानेर, अंबाला-पाली, वहां पहले से ट्रोमा सेंटर भी है, लेकिन ट्रोमा सेंटर के अन्दर पद नहीं हैं। मात्र 2 डॉक्टरों के भरोसे ट्रोमा सेंटर चल रहा है। बड़ा शहर है। 3 हाईवे गुजरते हैं। किसी न किसी हाईवे पर कोई न कोई एक्सीडेंट होते रहते हैं, इसलिए उसमें ट्रोमा सेंटर के नॉर्म्स के अनुसार पद सृजित करके वहां डॉक्टर लगाये जायें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछली सरकार के टाइम में पीएचसी की घोषणा हुई, चल रही है, डॉक्टर है, लेकिन भवन नहीं है। इतने दिन उसमें यह था कि जमीन नहीं थी। अब उन्होंने जमीन का पट्टा जारी कर दिया है। डिपार्टमेंट को भेज

दिया है। कायमसर और हरसावा बड़ा, इन 2 में पीएचसी के भवन नहीं हैं। इनके पीएचसी भवन के बजट देने की कृपा करें। आपकी मेहरबानी होगी। कुछ सब सेंटर्स हैं, उनके पहले पट्टे नहीं थे, अब डिपार्टमेंट को पट्टे मिल गये हैं। उनको भी आप सब सेंटर्स के लिए, भवन के लिए बजट स्वीकृत करें। हिरणा, कांगनसर, सदिमसर, गेंगासर, ढाणी चतरदास, रिणाऊ, बीबीपुर छोटा, सैणुसर, ढाणी सुण्डा, शेखीसर, उदनसरी, बागड़ोदा, बांठौद, आलमा, जुगलपुरा, गेंडुआ, ढाणी पूनिया, ये सब सेंटर्स बगैर भवन के चल रहे हैं। बराए मेहरबानी आप इनका बजट स्वीकृत करें।

एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि फतेहपुर और रामगढ़ शहर में 2 जनता क्लिनिक संचालित हैं। वे भी भवनहीन हैं। उनके भवन का बजट भी स्वीकृत करने की बराए मेहरबानी करें। कुछ भवन पुराने हैं, जर्जर हालत में हैं, उनको भी नया बनावें। ठेडी, कारंगा छोटा, जलालसर, ठिमोली, पालास, चांचीवाद बड़ा, चांचीवाद छोटा और बारी, इनमें जर्जर हालत में जो भवन हैं, उनको आप दुबारा से बनाने की स्वीकृति जारी करें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, एक मैं आपसे यह बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी चिंता का विषय कैंसर है। राजस्थान में हर साल करीब 1 लाख नये कैंसर मरीज सामने आते हैं। इनमें से 60 से 70 परसेंट मरीज थर्ड स्टेज में पहुंचने के बाद अस्पताल आते हैं। तब तक यह काबू के बाहर हो जाती है। इस कारण 2020 में 39 हजार और 2022 में 41 हजार लोगों की मृत्यु कैंसर से राज्य में हुई है। इस पर काबू पाने के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए।

मैं चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान एक और विशेष मुद्दे की ओर दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार द्वारा बेहतर मेडिकल सुविधाओं का भविष्य के लिए होनहार चिकित्सकों को तैयार करने के लिए राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी द्वारा 17 जिलों में 17 मेडिकल कॉलेज खोलकर उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज कमीशन से मान्यता दिलायी थी।

इन मेडिकल कॉलेजों में राजमेष के नियमों के तहत लगभग 700 चिकित्सक-शिक्षक कार्यरत हैं। इन पर राजस्थान सर्विस रुल्स लागू नहीं होने के कारण इनको ना तो डीए मिलता है, ना ही कोई ग्रेड सिस्टम है। इस कारण इन कॉलेजों में फैकल्टी नहीं मिल पाती है। ये चिकित्सक-शिक्षक गत कई वर्षों से राजस्थान सर्विस रुल्स, 1962 अडॉप्ट कराने हेतु प्रयासरत हैं। इनके अथक प्रयासों का ही परिणाम रहा है कि बजट,2024 में जिसमें माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा राजमेस में राजस्थान सर्विस रुल्स अडॉप्ट किये जाने की घोषणा की गयी। जिससे चिकित्सक-शिक्षकों में खुशी व्याप्त थी। यह नियम अडॉप्ट करने से राजमेस द्वारा संचालित 17 मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को भी राजकीय मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों की भांति ग्रेड पे, डीए इत्यादि सुविधाएं मिलना शुरू हो जायेगी।

श्री सभापति: श्री हरिसिंह रावत। (अनुपस्थित)

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): वित्त विभाग की टिप्पणी 129 के अनुसार 2017-22 के

अंतर्गत नियुक्त चिकित्सक-शिक्षकों को डाइंग कैडर, मरा हुआ कैडर मानते हुए।

श्री सभापतिः प्लीज, सहयोग करें। अंकित नहीं होगा।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): 000

श्री सभापतिः श्री गोपाल लाल शर्मा।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 एवं 28 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

मैं एक किंवदंती सुनाना चाहता हूं। हमारे पुरखों ने सुखी जीवन के सात सुख बताये हैं, मैं उन्हें यहां उद्धत करना चाहता हूं।

पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया,
तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी,
पंचम सुख स्वदेश में वासा, छठा सुख राज में पासा,
सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य हो जीवन।

हमारे पुरखों की इस किंवदंती में स्पष्ट होता है कि सभी सुखों में निरोगी होकर आरोग्य प्राप्त करना सर्वोपरि सुख है।

सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि विकसित राजस्थान, 2047 के अंतर्गत 5 वर्ष की कार्य योजना बनाकर सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है। इस योजना के 10 संकल्पों में से 8वां संकल्प मानव संसाधन, विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य।

माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने इस बजट में 1500 चिकित्सकों एवं 4000 नर्सेज के पद सृजित करने का निर्णय लिया है।

Spp/Rtm/19.07.2024/19:10/4b

सरकार ने RGHS का दायरा बढ़ाकर उसमें माता-पिता और सास-श्वसुर को भी जोड़ा है। चिकित्सा मद में राशि बढ़ायी है, मैं इसका स्वागत करता हूं। इस बजट का कुल 8.26 प्रतिशत अर्थात् 27,660 करोड़ रुपये चिकित्सा के लिये प्रावधान किया गया है, जो स्वागत योग्य है। प्रस्तुत बजट में आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा योजना में आगामी तीन वर्षों में 15 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान का निर्णय ऐतिहासिक है। मेरा विश्वास है कि यह निर्णय विकसित राजस्थान-2047 के अन्तर्गत सबके लिये स्वास्थ्य के लक्ष्य की पूर्ति में मील का पत्थर साबित होगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है मेडिकल के साथ-साथ आयुर्वेद व परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों को वर्तमान समय में संरक्षण की आवश्यकता है। मेडिकल चिकित्सा पद्धति व्यक्ति का अस्वस्थ होने के बाद इलाज करती है, लेकिन आयुर्वेद विज्ञान खानपान, आहार-विहार, दिनचर्या की ऐसी जीवन पद्धति का निर्देश देता है जिससे व्यक्ति अस्वस्थ ही न हो। आदर्श व परम्परागत जीवन पद्धति का महत्व विगत वर्षों में कोरोना महामारी में हम

सभी ने स्वयं अनुभव किया है।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मुख्य मंत्री भजनलाल जी शर्मा, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी और चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंहजी साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में, जो भीलवाड़ा से 100 किलोमीटर दूर है, वहां पर शिवचरण माथुर भी मुख्य मंत्री रहे थे, हमारी माण्डलगढ़ की जनता ने उनसे भी मांग की थी पर हमारे माण्डलगढ़ की मांग कभी पूरी नहीं की। पांच साल पहले मैं विधायक बना तो मैंने भी गहलोत साहब से बार-बार मांग की कि मेरा माण्डलगढ़ क्षेत्र दूर है, दो हाइवे निकल रहे हैं। वहां पर आप राजकीय जिला अस्पताल घोषित करो, परन्तु कुछ नहीं किया। 2021 में ट्रोमा सेंटर खोला था, परन्तु अब तक वहां पर कुछ भी धरातल पर काम नहीं हुआ। यह आपके सामने है और गहलोत साहब ने जो भी घोषणाएं कीं, वह सभी थोथी घोषणाएं थीं। मॉडल सी एच सी के लिये कहा था पर कोई भी मॉडल सी एच सी हमारे माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में नहीं खुली। मैं यशस्वी मुख्य मंत्री भजनलाल जी शर्मा को धन्यवाद देता हूं कि इस बजट में माण्डलगढ़ सामुदायिक अस्पताल को जिला उप अस्पताल में क्रमोन्नत किया। हमारे बिजोलिया कस्बे के अस्पताल को भी जिला उप अस्पताल में क्रमोन्नत किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और माण्डलगढ़ की जनता की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने हमारे यहां एक मॉडल सी एच सी की भी घोषणा की है और बिजोलिया, जो एक बहुत बड़ा कस्बा है, उसको नगरपालिका में भी क्रमोन्नत किया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं।

(समय :)

(श्री अर्जुनलाल जीनगर, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिये मैं कुछ मांगें रखना चाहता हूं। मेरे बडलियास व सलावटिया बहुत बड़े कस्बे हैं और वहां पी एच सी है, उनको मैं मॉडल सी एच सी में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं। बरून्दनी, नन्दराय व जलिन्द्री सी एच सी में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं। जोजवा, गेन्दलिया, कंकरोलिया घाटी व किशनगढ़ सब-सेंटर को पी एच सी में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं। बिगोद व बड़लियास दो बहुत बड़े केन्द्र हैं, यहां पर 108 एम्बुलैंस की भी मांग करता हूं। मेरे बड़लियास कस्बे में 40 साल पुराना अस्पताल का भवन जर्जर हो चुका है, उसको भी नये भवन में शिफ्ट करने की मांग करता हूं। भैरूखेड़ा, गोविन्दपुरा, गन्धेरी, देवली, दांतड़ा छोटा व चौहली में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग करता हूं। मेरे क्षेत्र में जो भी अस्पताल है, उनमें डॉक्टर नहीं हैं, कम्पाउंडर नहीं है और इलाज के लिये सभी दवाइयों की बहुत कमी है। मैं मांग करता हूं कि वहां पर डॉक्टर और कम्पाउंडर लगाकर सभी सुविधाएं पूर्ण करें। मैं मांग करता हूं कि मेरे भीलवाड़ा जिले का जो अस्पताल है, वहां मेडिकल कॉलेज भी है। भीलवाड़ा अस्पताल में हमारे हृदय रोग का कोई डॉक्टर नहीं है, वहां पर हृदय रोग का वार्ड खोलने और डॉक्टर लगाने की मांग करता हूं। भीलवाड़ा जिले में कैंसर अस्पताल बनाने की मांग करता हूं। आजकल कैंसर

बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। घर-घर और गांव-गांव में कैंसर के मरीज हैं, वह गरीब आदमी हैं, किसान क्षेत्र है तो मैं मांग करता हूं भीलवाड़ा की कैंसर हॉस्पिटल की मांग भी पूरी करें।

माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के समय में कोटा के जे.के.लोन अस्पताल में जैसी दुखान्तिका की घटना हुई थी, ऐसी घटनाएं आमजन के विश्वास को भंग करती है। पूर्व में हुई ऐसी घटनाओं की जांच व दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही का क्या हुआ? यह भी विचारणीय विषय है।

माननीय सभापति महोदय, मैं चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाले चिकित्सकों के लिये एक ही बात कहता हूं। इस धरती पर ईश्वर को साकार रूप में देखना है तो पहले है माता-पिता और दूसरे हैं चिकित्सक, जो हर संकट की घड़ी में हमेशा साथ देते हैं। हमारे कोरोना का समय आया था तब परिवार वाले दूर हो गये थे पर डॉक्टर और कम्पाउंडरों ने इलाज किया था। वह हर समय मरीज के साथ खड़े थे। चिकित्सा जैसे पवित्र पेशे में आमजन का विश्वास बना रहे। हमारे विकसित राजस्थान-2047 में सबके लिये स्वास्थ्य को समय से पूर्व प्राप्त करें। मैं एक बार पुन: हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी और हमारे चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंहजी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे क्षेत्र में बहुत पुरानी मांग थी उनको आपने पूरा किया। जय हिन्द। जय भारत। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री विकास चौधरी।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मांग संख्या 27 व 28 पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। WHO के अनुसार स्वास्थ्य का मतलब शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण की स्थिति है। इसी को देखते हुये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने विश्व के विकसित यूरोपियन देशों की तर्ज पर राइट टू हैल्थ स्वास्थ्य का अधिकार का कानून देने का कार्य इस राजस्थान की जनता को किया। माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य के गरीब लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में 25 लाख रुपये तक की मुख्य मंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना उपलब्ध करायी। गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित सहित सभी वर्गों के चिकित्सकीय भार को कम किया। पर वर्तमान सरकार ने इस बजट में केवल इस योजना का नाम बदलकर मुख्य मंत्री आयुष्मान योजना करने के अलावा कुछ नहीं किया। पूर्ववर्ती सरकार ने हमारी विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया। साथ ही नवीन भवन के लिये 40 करोड़ की राशि स्वीकृत की, परन्तु सात महीने बने इस सरकार को हो गये, ना तो निर्माण का कार्य चालू हुआ, न ही स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया गया और इस बजट में रिवाइज करके उसी बजट को यहां इम्प्लीमेंट किया गया। मैं तो किशनगढ़ के उन भामाशाहों को यहां धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन भामाशाहों की वजह से कम से कम किशनगढ़ का अस्पताल चल तो रहा है। आम भाषा में किशनगढ़ के अस्पताल को रेफरल अस्पताल कहते हैं कि जो मरीज आयेगा, आने से पहले उसको रेफर कर दिया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, आज हॉस्पिटल में ट्रोमा सेंटर है, लेकिन ट्रोमा में आर्थो डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर, मेडिकल आफिसर के साथ-साथ नर्सिंग स्टॉफ नहीं है। लगभग स्वीकृत पदों की तुलना में आधे से भी कम पदों पर नर्सिंग कार्मिक उपलब्ध हैं। यही हाल हमारे हरमाड़ा, बोराड़ा, अराई सामुदायिक केन्द्रों का है, जहां पांच बजे से पहले ही ताला लगाकर डॉक्टर भाग जाते हैं। वैसे डॉक्टर हैं नहीं। शहरी क्षेत्रों में भी चैनपुरिया स्वास्थ्य केन्द्र की स्थिति भी विकट है। पूर्ववर्ती सरकार व भामाशाहों द्वारा सोनोग्राफी की मशीन उस जिला अस्पताल में उपलब्ध करायी गयी, लेकिन डॉक्टर नहीं होने की वजह से आज साल भर से अधिक समय होने के बाद भी वहां सोनोग्राफी नहीं हो रही है। मेरी सदन के माध्यम से सरकार से मांग है कि इन समस्याओं को दुरुस्त करे एवं अस्पताल में सी.टी.स्केन व एम आर आई की सुविधा उपलब्ध करायें।

माननीय सभापति महोदय, वहां आज गायनिक वार्ड की स्थिति बड़ी नाजुक है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से आह्वान करूंगा कि 100 बैड वहां पर बढ़ाये जायें। कार्डिक विंग की सेवाओं का विस्तार किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां खाद्य मंत्रीजी भी बैठे हैं, स्वास्थ्य मंत्रीजी भी बैठे हैं। हम जानते हैं और हमारी आम कहावत है '- 'जैसा खावे अन्न, वैसा होये मन' 'जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी।' अर्थात् अच्छे स्वास्थ्य के लिये अच्छा आहार, भोजन अति आवश्यक है परंतु खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही है। हाल में आपने देखा होगा बड़ी कम्पनियों में नकली घी, तेल, मावा बहुतायत से मिल रहा है, लेकिन इस सरकार से राजस्थान की जनता पानी मांगती है तो पानी नहीं दे रहे हैं। नकली घी दे रहे हैं। मैं तो, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार में बैठे हुये मंत्रियों से यही मांग करता हूं कि-

दो न्याय अगर तो आधा दो,
इसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल पांच ग्राम।
रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खायेंगे,
परिजन पर असी न उठायेंगे।

इस पूंजीपति सरकार का श्रेय इन बड़ी कम्पनियों को है, इसी कारण धड़ल्ले से वह माल बेच रही है और हमारे नौजवानों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि यह स्लो पोइजन हमारे आने वाले भविष्य को खराब करने का काम कर रही है।

MLS/RTM/19.07.2024/19:20/4c

आप देख रहे हैं, नौजवानों में लकवा, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी प्राण घातक बीमारियां अपनी जड़ें जमा रही हैं। इसकी वजह खाद्य पदार्थ हैं। मानव संसाधनों काविनाश की ओर बढ़ना इस ओर दिखाई दे रहा है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ `'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान चलाया। खाद्य सुरक्षा निदेशालय का अलग से गठन किया। मैं आपके

माध्यम से सरकार के मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि फूड सेफ्टी इंस्पेक्टरों की ज्वॉइनिंग आप नहीं दे पा रहे हैं, उनकी ज्वॉइनिंग दें।

सभापति जी, इस राजस्थान में कोरोना काल में जहां एक ओर देश के प्रधान मंत्री जी ताली और थाली बजा रहे थे, दूसरी ओर कांग्रेस की सरकार ने भीलवाड़ा मॉडल पेश किया। मैं खुले मन से कहना चाहता हूं कि कोविशील्ड वैक्सीन सरकार द्वारा जबरदस्ती थोपी गयी, वह प्राण घातक वैक्सीन है। इसी कोविशील्ड वैक्सीन की कम्पनी ने सबसे ज्यादा इस मोदी सरकार को चन्दा दिया और हमारे जैसे नौजवानों के साथ कुठाराघात किया।

इस कम्पनी ने माना है, ब्रिटिश कोर्ट में स्वीकार किया है कि वैक्सीन के कारण थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, टीटीएस जैसे दुर्लभ साइड इफेक्ट हो रहे हैं। पोस्ट कोविड, युवाओं के हार्ट आज कमजोर हो गये हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूं और इस इक्कीसवीं सदी के राजस्थान के सबसे भाग्यशाली भजनलाल जी से भी निवेदन करता हूं कि आप इन नौजवानों के लिए शिविर लगाएं, उनके लिए अभियान चलाएं कि उनके हार्ट की जांच हो।

सभापति महोदय, मेरे किशनगढ़ में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। इस पेड़ पर लगे हुए ये हजारों एविल के इंजेक्शंस, जो 5 या 7 रुपये में मिल जाते हैं, आज 250-300 रुपये में मिल रहे हैं। कल मैंने नशे पर बात रखी। मैंने काली गैंग की बात की। आज उस काली गैंग के लोग और उसके सरगना मुझे सोशल मीडिया पर धमकी दे रहे हैं, लेकिन यह किसान का बेटा यहां बड़ी मजबूती से चुनकर आया है, उस काली गैंग से डरने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, आज आप हमारा संरक्षण करें या न करें, लेकिन यह किसान का बेटा किशनगढ़ की जनता के आशीर्वाद से चुनकर आया है। यह डरने वाला नहीं है। इस पेड़ पर लगे इन इंजेक्शनों को मैं सदन के पटल पर रखता हूं। मेरा मन तो विचलित होता है, उन युवाओं की नसों में एविल के नाम से जो ड्रग्स दी जा रही हैं, लगातार इस काली गैंग के लोग हम पर हमला बोल रहे हैं, उन लोगों को पकड़ने का काम करें।

मैंने प्रण लिया है, मेरे चुनावी घोषणा पत्र का पहला बिन्दु इन ड्रग माफियाओं के खिलाफ है। मैं सरकार से मांग करता हूं, किशनगढ़ में राजकीय नर्सिंग अस्पताल की स्थापना की जाये, राजकीय नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाये व अस्पतालों में नर्सिंग पदों और डॉक्टरों की भर्ती की जाये। किशनगढ़ जैसी जगह पर सोनोग्राफी नहीं हो रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी डबल इंजन की सरकार है, माननीय मंत्री जी हमें कहकर गये थे श्रम व रोजगार मंत्रालय से हम आपको जल्द ही अस्पताल देंगे, आज डबल इंजन की सरकार को दस बरस से ज्यादा हो गये, न तो अस्पताल की जगह आवण्टित हुई और न वहां काम हुआ।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): मैं कार्डियक इकाई को दुरुस्त करने के लिए आपसे निवेदन करूंगा। आदरणीय सभापति जी, मंत्री जी सदन के पटल पर रखी हुई मांगों को पूरा

करेंगे, यह मुझे और किशनगढ़ की जनता को विश्वास है, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार। पांच मिनट में अपनी बात पूरी करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मजेदार बात यह है कि उधर से बोलने वाले प्रत्येक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि यह सरकार कुछ नहीं देने वाली, कुछ नहीं करने वाली, फिर भी इतनी लम्बी-लम्बी लिस्टें देकर जा रहे हैं। धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, आम नागरिक को जीवन से मरण तक अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। इस विषय पर जब हम बात कर रहे हैं, सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हम स्वास्थ्य केन्द्र मांग रहे हैं, उप-स्वास्थ्य केन्द्र मांग रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मांग रहे हैं और ये स्वीकृत भी हो रहे हैं। राजस्थान में उप-स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी नहीं है, खूब होंगे, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी कमी उन भवनों में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की है। उसके लिए सरकार सबसे महत्त्वपूर्ण फैसला करे। सरकार डॉक्टरों की, नर्सिंग स्टाफ की भर्ती करे, जिससे राजस्थान की जनता को डॉक्टर्स उपलब्ध हों और जिससे राजस्थान की गरीब जनता को उनका लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, एक ड्रग इंस्पेक्टर हर जिले में होता है और इस मेडिकल स्टाफ को लेकर, जो सबसे गम्भीर मुद्दा है, नकली दवाइयों की जो बात हो रही है, नशीली दवाइयों की जो बात हो रही है, ये पूरे जिले में मंथली ले-लेकर, पैसे ले-लेकर इनकी व्यवस्था को मैनेज करते हैं, इसलिए इन पर गम्भीरता से मॉनीटरिंग करें, नियंत्रण करें। माननीय सभापति महोदय, जिस स्थान से मैं आता हूं, वह हरियाणा बॉर्डर पर है। हमारी चिरंजीवी योजना, जिसका नाम चाहे कुछ भी रखें, और मैं तो कहता हूं, किसी योजना का नाम कभी किसी भी सरकार को नहीं बदलना चाहिये, जनता के दिमाग में एक बार नाम जो जमता है, वह उसी योजना के नाम से जाना जाता है, इसलिए नहीं बदला जाये।

जहां हम रह रहे हैं, वहां अगर हमें चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो हम भागकर हिसार, हरियाणा में पहुंचते हैं। अत: मैं निवेदन करता हूं कि हमारी यह जो चिरंजीवी योजना है, इसे राजस्थान के पास लगने वाले किसी भी अदर स्टेट के जो अस्पताल हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाये। जैसे गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और जो भी प्रदेश हमारे नजदीक हैं, वहां के चन्द हॉस्पिटलों को इसमें शामिल किया जाये ताकि जनता को उसका भी लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, जो हमारे राजकीय चिकित्सालयों के भवन निर्माण होते हैं, चाहे सीएचसी बने, चाहे पीएचसी बने, चाहे उप-स्वास्थ्य केन्द्र बने, उस पर हमारे मेडिकल विभाग का कोई नियंत्रण नहीं होता है। एक सिविल डिपार्टमेंट बना दिया, वह उसका निर्माण करता है। उसके बाद सिर्फ उसे सुपुर्द किया जाता है, उसकी कोई

मॉनीटरिंग नहीं होती। बाद में भुगतता मेडिकल डिपार्टमेंट है। अतः मेडिकल डिपार्टमेंट का उन पर नियंत्रण होना चाहिये।

उप-स्वास्थ्य केन्द्र और स्वास्थ्य केन्द्रों पर जो भी डॉक्टर्स हैं, उनकी उपलब्धता सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक सुनिश्चित की जाये। इस बीच हमारे उप-स्वास्थ्य केन्द्र खुले रहें, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टर्स रहें। अगर हम इन पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो चाहे आप कितने भी स्वास्थ्य केन्द्र खोलें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे रामसरा ताल या समस्त पीएचसी में सब पर जांच की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये। जांच के बिना वहां डॉक्टर सिर्फ रैफर करने का काम करते हैं। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं करते। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी चूरू मेडिकल कॉलेज है। वहां हमारे शिक्षक, प्रोफेसर्स के रूप में जो डॉक्टर्स हैं, उनके 82 पद खाली हैं, पैरा मेडिकल के 81 पद खाली हैं। इसके बाद हम कैसे मान सकते हैं कि हमारी शिक्षा भी अच्छी होगी, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा?

माननीय सभापति महोदय, मेरे उप-जिला अस्पताल राजगढ़ में गाइनी के डॉक्टर नहीं हैं, सर्जन नहीं हैं, स्टोरेज नहीं है, ट्रॉमा सैंटर निर्मित हो चुका है, उसे सुचारू नहीं किया गया है, उसे सुचारू किया जाये। सोनोग्राफी मशीन पर परमानेंट डॉक्टर लगाया जाये। माननीय मंत्री महोदय, आप गम्भीरता से गौर करें, एक पूरे राजस्थान की समस्या है, हर विधान सभा क्षेत्र में एक शहरी पीएचसी एनआरएचएम के माध्यम से खुली है, उस पर स्टाफ का कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी संविदा पर कर्मचारी नहीं हैं और न ही रैगुलर स्टाफ है। अतः वहां पर स्टाफ की व्यवस्था करने की कोशिश करें।

चान्दकोटी पीएचसी, रामपुरा पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करें। नेशल, बैरासर, भगेला उप-स्वास्थ्य केन्द्र को पीएचसी में क्रमोन्नत करें। सभापति महोदय, भटोड़, लुद्दी, थान मठूई में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के भरसक प्रयास करें। मेरा एक और सुझाव है, चिरंजीवी योजना में जो लोग लाभान्वित नहीं हैं, जिनका कार्ड नहीं बना, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वे जब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, उनके कार्ड बनाने की बहुत जटिल प्रक्रिया है। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस अस्पताल में वे जाएं, उसी अस्पताल के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन हो और उन्हें तुरन्त चिकित्सा का लाभ मिले, उनका इलाज हो, उनको ट्रैक्टर के माध्यम से कहीं नहीं जाना पड़े।

श्री सभापतिः श्री मनोज मेघवाल।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सबसे बड़ा इश्यू है। हरियाणा प्रदेश से लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से मेडिकल रिपोर्ट लगाकर फर्जी 307 का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारे सरकारी हॉस्पिटलों की मेडिकल जांच को ही माना जाये, जिससे जनता के प्रति ये फर्जी 307 के मुकदमे नहीं हों। धन्यवाद।

श्री सभापतिः मनोज जी, पांच मिनट में अपनी बात पूरी करें।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): सभापति महोदय, धन्यवाद। अभी जो बजट पेश किया गया, उसमें थोड़ी सी निराशा और मैं तो कहूंगा बहुत ज्यादा निराशा इसलिए है कि जो सब-सैंटरों को, पीएचसी को क्रमोन्नत करने की दो पेज में एक छोटी सी लिस्ट दी गयी है, उसमें अगर देखें तो नाम लगभग उन्हीं विधान सभा क्षेत्रों के हैं, जहां सत्ताधारी पक्ष के विधायक हैं।

mkd/rtm/19.07.2024/19:30/4d

इस तरह का जो भेदभाव हुआ, उससे न केवल हमको बल्कि जनता को भी बहुत निराशा है। बीमारी पूछ कर नहीं आती है कि इस एरिया में सत्ताधारी पार्टी का विधायक है, इसलिए यहां ज्यादा बीमारी आयेगी। यहां विपक्ष का विधायक है तो यहां कम आयेगी। कम से कम 19-20 हो तो वह समझ में आता है, लेकिन एकदम से नेगलेट करना, उन विधान सभा क्षेत्रों को जहां विपक्ष के विधायक हैं, यह मेरी समझ से बाहर है।

अभी भी बजट सत्र चल रहा है, यदि इस ओर थोड़ा ध्यान दिया जाये और उन क्षेत्रों में जहां क्रमोन्नत करने की जरूरत है, वहां क्रमोन्नत किये जाये तो अच्छी बात होगी।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो कातर छोटी, जो उप तहसील मुख्यालय है, वहां की पीएचसी को क्रमोन्नत किया जाये तो आस पास के बहुत से गांवों को लाभ मिल सकता है। सबसे पुरानी पीएचसी है सडुछोटी। यह बहुत पुरानी पीएचसी है। जब राजस्थान में बहुत कम पीएचसीज हुआ करती थीं, उस समय की है। उसको यदि क्रमोन्नत किया जाये तो उससे भी आस-पास के गांवों को लाभ मिलेगा। बहुत से बड़े गांवों में सब-सेंटर है। अब वे गांव भी पांच-पांच हजार की आबादी के हो गये हैं। उन सब-सेंटरों को पीएचसी में क्रमोन्नत करें। चाहे लोडसर हो, चरला हो, सरोटिया हो, गिरवरसर हो तो इन गांवों को भी लाभ मिले और आस-पास के लोगों को भी चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सके। बहुत से ऐसे भवन हैं, जिनका निर्माण करना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि उन सब-सेंटरों को खुले हुए दो-दो, तीन-तीन साल हो गये हैं, कुछ बन गये हैं, कुछ अभी भी बाकी हैं।

पूरे राजस्थान में हर साल भवन निर्माण होते हैं तो उनमें हर विधान सभा क्षेत्र को बराबरी से रखा जाये। विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ और बीदासर ब्लॉक दोनों है, उनमें भी भवन विहीन सब-सेंटर हैं, उनको भी क्रमोन्नत किया जाये। बीदासर उप खण्ड मुख्यालय है, जहां सीएचसी है, उसकी बैड क्षमता को बढ़ाकर कम से कम 100 बैड का किया जाये, ताकि 50 हजार की आबादी को लाभ मिले। उस कस्बे को भी लाभ मिले, आस-पास के गांवों को भी लाभ मिले। सुजानगढ़ उप जिला चिकित्सालय की भी बैड क्षमता बढ़ाई जाये। वह करीब डेढ़ लाख की आबादी का शहर है। इसको 150 बैड से बढ़ाकर कम से कम 300 बैड प्रस्तावित किया जाता है तो यहां पर बहुत बड़ा लाभ होगा। अभी भर्तियों की बात की है कि 1500 डॉक्टरों और 4000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती आने वाले समय में होगी।

मेरा आग्रह है कि इसमें दो डॉक्टरों के पद प्राथमिकता से ज्यादा सृजित किये जाये। एक सोनोग्राफी का और एक एनेस्थेसिया का, क्योंकि इनके बिना हॉस्पिटल अधूरा है। यदि

एनेस्थेसिया का डॉक्टर नहीं होगा तो सर्जन डॉक्टर कितने ही बैठ रहे, स्टाफ कितना भी बैठा रहे, बिना ए एनेस्थेसिया के वह काम नहीं कर सकता है, वह आपरेशन नहीं कर सकता है। इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। उनको भर्ती में प्राथमिकता दी जाये।

दूसरा, जो सोनोलोजिस्ट है। उनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। उनके बिना बहुत बड़ी समस्या होती है। महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है, उनको बाहर सोनोग्राफी के लिए भेजा जाता है तो सोनोग्राफी डॉक्टरों की भी प्राथमिकता से जितनी ज्यादा हो सके नई भर्ती में करायें ताकि जो अन्य डॉक्टर हैं, उनका भी पूरा लाभ मिल सके। जिनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। अभी 17 सदस्य और हैं।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि कैमरा मैन को यह कहो कि फोटो तो थोड़ा ढंग से दिखावे। विधान सभा क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि एमएलए साहब बीमार हो गये हैं क्या। फोटो सहीं ढंग से नहीं आ रही है। कैमरा मैन को आदेशित करें।

श्री सभापतिः कैमरा मैन को समाचार दे दें। श्री रमीला खड़िया। आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती रमीला खड़ीया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 28 पर आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र की मुद्दे की बात करूंगी। हमारी पिछली सरकार ने 100 बैड का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र था, उसको 150 बैड का किया।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत पुराना अस्पताल बना हुआ था। वह अस्पताल राजा-महाराजाओं के समय का कोई ठिकाना था, उस भवन में चलाया जा रहा था। फिर रेल के डिब्बे की तरह क्रमोन्नत होता गया और कमरे बनते गये। उसी अस्पताल के लिए हमारी सरकार गहलोत साहब ने 1 करोड़ 11 लाख की लागत से भवन को स्वीकृत किया और बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। उसका शिलान्यास भी कांग्रेस और बीजेपी सभी ने मिलकर किया। उस भवन का उद्घाटन भी 02.10.2023 को किया। उस पुराने हॉस्पिटल को नये हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया।

मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं, यहां विभाग के अधिकारी भी हैं, उसको दिखवाकर और उसकी जांच करके, वह गम्भीर हालात में, जर्जर अवस्था में था, उसको जल्दी से बनाकर उस नये भवन में शिफ्ट करने का कष्ट करें।

मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी पिछली सरकार में गहलोत साहब के टाइम पर ट्रोमा सेन्टर, जो गुजरात की सीमा से लगते हुए हाइवे पर है। वहां ट्रोमा सेंटर भी खुला था। आये दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आये दिन घटनाएं घट रही हैं। मंत्री जी, जब भी आप रिप्लाई दें तो इस ट्रोमा सेंटर का कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र सज्जनगढ़ भीलकुआ का जिक्र करें। यह मेरी आपसे मांग रखती हूं।

मैं आपसे कहना चाहती हूं कि उप स्वास्थ्य केन्द्र, सज्जनगढ़ में पिछली सरकार के द्वारा राशि स्वीकृत करने के बाद भी आज तक इस कार्य को किया नहीं है। किन ठेकेदारों ने इसकी ठेकेदारी ली। उन ठेकेदारों ने जिस तरह से बिलों में तो बिलों में लेना इनकी परेशानी है। यह हमारी जनता की परेशानी नहीं है। इसलिए जिन अधिकारियों व ठेकेदारों ने आज तक, हमारे इन आठ उप स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वीकृत करने के निर्देश दें और उनको कराया जाये।

मैं यह कहना चाहती हूं कि ग्राम पंचायत पाटन में भवन बन रहा है। उस ठेकेदार ने काम चालू भी कर दिया, छत डाल दी, उसके बाद आज तक खिड़की, दरवाजे और नीचे का पत्थर नहीं लगाया है। इसी तरह से उकाला के भवन की भी ऐसी की ऐसी हालत है। ठेकेदार कॉलम खड़े करके गया, आज तक वापस नहीं आया। ऐसे ठेकेदारों के लिए जांच कमेटी बिठाकर तत्काल प्रभाव से जांच की जाये। इन्होंने यह किस तरह से किया है। आज हमारी जनता इसको देख रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री उदयलाल भड़ाना।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।

मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी को, मुख्य मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो आम जनता को राहत देने के लिए, आम जनता की भलाई के लिए, आम जनता की मदद के लिए 27 हजार 700 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव पारित किया।

Bhs/Rtm/19.7.24/19.40/4e

उसके लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी और चिकित्सा मंत्री जी और वित्त मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत आभार।

मैं एक बात आपको सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सुबह से आज चिकित्सा के ऊपर बहस हो रही है सभी अपने-अपने विचार रख रहे हैं भीलवाड़ा मॉडल की बार-बार बात की जा रही है तो मैं अगर आपका आदेश हो तो मैं भीलवाड़ा मॉडल पर कुछ अपने मन की बात रखना चाहता हूं। हो सकता है अगर मैं इसकी डिटेल दूंगा तो मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगे रह जायेंगी तो मैं चिकित्सा मंत्री जी को लिखित में दे दूंगा लेकिन इस सदन में सभी पार्टियों के सभी सम्मानित माननीय विधायकगण विराजमान हैं, भीलवाड़ा मॉडल के बारे में सुबह से मैं सुन रहा हूं दस-पन्द्रह बार बोला गया। भीलवाड़ा मॉडल भीलवाड़ा के जो तत्कालीन कलेक्टर थे राजेन्द्र जी भट्ट उनकी सूझ-बूझ प्रशासनिक पकड़ उनकी वजह से भीलवाड़ा मॉडल का नाम हुआ और वहां की स्वयंसेवी संस्थाएं वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, सब लोगों की मेहनत से, सब लोगों की ताकत से वह काम हुआ और भीलवाड़ा का नाम हुआ।

आपको बताना चाहता हूं कि भीलवाड़ा में पहला कोरोना केस भी भीलवाड़ा में ही आया था और भीलवाड़ा के तत्कालीन कलेक्टर राजेन्द्र जी की प्रशासनिक पकड़ की वजह से और जैसे मैं विपक्ष में था या मैं सत्ता पक्ष में नहीं था फिर भी मैंने उस कोरोना काल में करीब तीन सौ बार राजेन्द्र जी भट्ट को फोन किया तो उन्होंने 295 काम मेरे किये। कभी उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह कांग्रेस पार्टी का कार्यकता है, इसका काम करना है, यह बीजेपी का है, इसका नहीं करना। उन्होंने सब लोगों को साथ लेकर काम किया और वहां पर जो सामाजिक समितियां बनी हुई हैं संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के माध्यम से सभी स्वयंसेवी संस्थाओं वालों ने भी बहुत मदद की।

मैं भी एक संस्था से जुड़ा हुआ हूं वन्दे मातरम सेवा संस्थान, उससे अभी भी मैं आज की तारीख में 25-30 यूनिट ब्लड रोज लोगों को दिलाता हूं यहां जयपुर में रहने के बावजूद भी और 21 तारीख को भी रक्तदान शिविर है। मैं जाऊंगा यहां से और करीब 21 सौ यूनिट उसकी होगी तो बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं कोई रक्तदान शिविर लगाती है कोई गैस के सिलेंडर दिलाती है। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान हथेली में रख कर के मदद की और उस वक्त के जो तत्कालीन विधायक थे, सांसद थे उनके बजट से जो खाद्य सामग्री लोगों को आपूर्ति की, उसके ऊपर गहलोत जी की फोटो लगा कर लोगों को यह कहा गया कि यह गहलोत साहब के द्वारा दिया जा रहा है। जब उनको यह कहा कि यह गहलोत मॉडल है और जब उन्होंने मानने से इंकार कर दिया कि यह गहलोत मॉडल नहीं है यह भीलवाड़ा मॉडल है यह कलेक्टर राजेन्द्र भट्ट जी की सूझ-बूझ से यह कार्यक्रम हुआ है तो उन्हीं राजेन्द्र जी भट्ट को पांच दिन बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया और आज की तारीख में वो उदयपुर में सम्भागीय आयुक्त हैं। केवल और केवल कलेक्टर महोदय और वहां की आम जनता की वजह से ही भीलवाड़ा मॉडल बना था न कि किसी पार्टी के किसी नेता की। अगर चाहते तो भीलवाड़ा मॉडल पूरा राजस्थान मॉडल बन सकता था क्योंकि राजस्थान में मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत थे।

भीलवाड़ा में कलेक्टर की वजह से और आम जनता की वजह से भीलवाड़ा मॉडल बना। राजस्थान भी बन सकता था। वहां के तत्कालीन कलेक्टर...(व्यवधान)... एक मिनट आप रुकिये। शान्त रहें।

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य। हाकम जी, डिस्टर्ब नहीं करें किसी को। गलत बात है यह। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बीच में नहीं बोलें।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): भीलवाड़ा की लोकल जनता ने मदद की उसकी वजह से काम हुआ और कोरोना काल में मेरी बात सुनो, कोरोना काल में जो सुविधाएं सांसदों के भत्तों के पैसे काटे उसके ऊपर गहलोत साहब की फोटो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वह राशन वितरण किया जिससे कि उनको सरपंच का चुनाव लड़ने में अपनी पार्टी का प्रचार करने में फायदा हुआ। ये हमारे भीलवाड़ा के विधायक बैठे हैं इनको पूछो इनके पैसे काटे गये। क्या इनको वह किट दिया गया अपने क्षेत्र में बांटने के लिए, नहीं दिया गया। अपने कांग्रेस के

कार्यकर्ताओं के द्वारा ही वह किट क्षेत्र में वितरित किये गये और मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी अगर चाहते तो पूरे राजस्थान को राजस्थान मॉडल बना सकते थे। उस भीलवाड़ा मॉडल में भीलवाड़ा के आम लोगों का और भीलवाड़ा जनप्रतिनिधि का सहयोग था क्योंकि अधिकारी किसी पार्टी का नहीं होता है, बैठे हैं अधिकारी यहां पर ये कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस के हिसाब से काम करते हैं और भाजपा की सरकार आती है तो भाजपा के हिसाब से करते हैं। अधिकारी किसी पार्टी का कार्यकर्ता या सदस्य नहीं होता है प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक कार्य करता है।

मैं सदन के माध्यम से मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भीलवाड़ा जिले को चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कुछ दिया और भीलवाड़ा में एक मेडिकल कॉलेज भी है और मैं सदन के माध्यम से एक मांग भी करता हूं कि भीलवाड़ा जयपुर से काफी दूर है। उदयपुर में बहुत सुविधाएं हैं चिकित्सा मंत्री एक प्रस्ताव बना कर दिल्ली सरकार को भेजें और एक एम्स की स्थापना हो भीलवाड़ा में। जोधपुर में एम्स है, जयपुर में है तो वहां पर भी एक एम्स की शुरूआत की जाये जिससे कि आम लोगों का उससे भला हो सके और मुख्य मंत्री जी ने अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उस एक घंटे में अगर कोई व्यक्ति उस मरीज को होस्पिटल पहुंचाता है तो उसमें पहुंचाने में अच्छा नागरिक योजना के तहत पांच हजार रुपये से बढ़ा कर मुख्य मंत्री जी ने दस हजार रुपये किये उसके लिए भी मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद।

भीलवाड़ा में मेडिकल कॉलेज में जो कमियां हैं उनके बारे में मैं आज बताना चाहता हूं। ईएसआई होस्पिटल में ऑपरेशन की सुविधा चालू करें क्योंकि यह औद्योगिक क्षेत्र है भीलवाड़ा एक टैक्सटाइल नगरी है वहां पर बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। बाहर के लोग कम से कम एक से डेढ़ लाख लोग भीलवाड़ा जिले में निवासरत हैं जिनका आधार कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं केवल वो फैक्ट्रियों में काम करते हैं अगर ईएसआई होस्पिटल के माध्यम से उनके ऑपरेशन की सुविधा चालू की जाये तो यह बहुत अच्छा काम रहेगा। एक सुपर स्पेशियलिटी शहर के अन्दर एमजीएच में शुरू करें क्योंकि मेडिकल कॉलेज थोड़ा दूर है और एक बिल्डिंग एमजी होस्पिटल में बनायी जाये तो भीलवाड़ा शहरवासियों का भला हो सके। एमजी होस्पिटल में बिल्डिंग छोटी पड़ने के कारण जच्चा-बच्चा मातृ शिशु सेवा का एक विस्तार आवश्यक है एक वार्ड और हो तो लोगों का भला हो सकेगा। सीटी स्केन की मशीन बारह साल पुरानी है अगर यह नयी मशीन लगती है तो आम लोगों का भला होगा और मदद होगी। कैथ लैब की शुरूआत की जाये और हृदय रोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत कराया जाये। जैसा कि गोपाल जी ने कहा कि केन्सर सेन्टर की स्थापना करायी जाये क्योंकि आज आये दिन पेस्टीसाइड्स छिड़कते हैं फसलों पर जिससे केन्सर के रोगी बढ़ रहे हैं। अगर एक केन्सर सेन्टर की स्थापना की जाती है तो भीलवाड़ा जिले के आस-पास के लोगों का भला होगा। न्यूरो सर्जन का अगर एक पद स्वीकृत करते हैं और पैरा मेडिकल कोर्सेज की शुरूआत करते हैं और ईसीजी टेक्निशियन का कोर्स नेत्र सहायक का कोर्स और डायलिसिस टेक्निशियन का

कोर्स अगर शुरू करते हैं, मेडिकल कॉलेज में स्थित है लेकिन अगर यह पद स्वीकृत करते हैं तो लोगों को फायदा मिलेगा।

महात्मा गांधी होस्पिटल, भीलवाड़ा में 1100 प्रकार की दवाइयां हैं जिनको बढ़ा कर अगर 1500 प्रकार की दवाइयां की जाये और सर्जिकल सहित 2000 तरह की की जाये तो लोगों को राहत प्रदान होगी।

मैं माण्डल विधान सभा क्षेत्र की कुछ अपनी मांग रखता हूं। माण्डल विधान सभा क्षेत्र में एक उप जिला चिकित्सालय है जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है इनके जो रिक्त पद हैं उनकी पूर्ति की जाये। चिकित्सा मंत्री से निवेदन है कि जो भी कमी है उनकी पूर्ति करें और एक सीटी स्केन की सुविधा अगर मिल जाये तो यह माण्डल वासियों के लिए अच्छा होगा और उनका भला होगा। नेत्र चिकित्सक की सेवा शुरू की जाये। माण्डल व करेड़ा में ट्रोमा सेन्टर खोला जाये क्योंकि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के ऊपर होने के कारण आये दिन एक्सीडेंट होते हैं। अगर एक ट्रोमा सेन्टर खुलता है तो वहां के लोगों की भलाई होगी और उनकी मदद होगी और माण्डल में नवजात शिशु वार्ड आईसीयू में दस वार्ड की सेवाएं शुरू की जाती है तो माण्डल के लोगों का भला होगा और उनकी सेवा से फायदा होगा। माण्डल व करेड़ा में बीएससी नर्सिंग कॉलेज खोला जाये। पालड़ी स्थित बीएससी नर्सिंग कॉलेज जल्द शुरू किया जाये क्योंकि उसकी बिल्डिंग बन रही है। छात्रावास होस्टल की सेवा भी शुरू की जाये। भीलवाड़ा में एक एम्स की स्थापना होनी चाहिये क्योंकि औद्योगिक नगरी होने के कारण आस-पास के जिलों को भी फायदा होगा और वहां पर डेढ़ लाख लोग दूसरे जिलों के, दूसरे प्रदेशों के वहां निवासरत हैं। भीलवाड़ा जिले के साथ-साथ इन लोगों को भी बीमारी में फायदा होगा। सीएचसी सुहाणा, ज्ञानगढ़, बागौर और करेड़ा, भगवानपुरा में डॉक्टर्स की कमी है इन रिक्त पदों की पूर्ति करायी जाये जिससे कि आम जन की सेवा में कोई कमी नहीं रहे। 721 प्रकार की दवाइयों को बढ़ा कर एक हजार दवाइयां की जाये। बागोर और करेड़ा में सोनोग्राफी सेवाएं शुरू की जाये। बागौर और करेड़ा कस्बे में नया भवन होस्पिटल तीन किलोमीटर दूर जंगल में होने के कारण ग्रामीणों को आ रही समस्या को देखते हुए अस्थायी डिस्पेंसरी दोनों कस्बों के गांव के अन्दर खोली जाये जिससे लोगों को फायदा होगा क्योंकि पिछली सरकार ने होस्पिटल तो बनाये लेकिन तीन किलोमीटर दूर बना दिये जहां लोग डरते हैं। दोनों कस्बों में वहां होस्पिटल है और उनके अस्थायी स्तर पर अगर दो-दो डॉक्टर बैठा दिये जायें तो लोगों को प्राथमिक इलाज की सुविधा वहां हो सकेगी और बड़ी बीमारी में वो दूर जाने के लिए भी तैयार हैं।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। राम-राम।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री उमेश मीणा। पांच मिनट में अपनी बात पूरी करें।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): सबसे पहले सदन को जोहार। सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र की

जनता की ओर से आपको खूब-खूब धन्यवाद और जोहार करना चाहूंगा। अभी यहां पर पक्ष और विपक्ष में काफी चर्चा हो रही थी और मैं सोच रहा था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की क्या मांग रखूं क्योंकि हमारा आदिवासी क्षेत्र हमेशा वहां पिछड़ा है और पिछड़े के रूप में ही देखा जाता है तो पहली जो मेरी मांग है जो युवाओं की मांग है, डूंगरपुर जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे एक नर्सिंग कॉलेज वहां डूंगरपुर में खोला जाये और इसके साथ ही पैरा मेडिकल सुविधा भी बढ़ाई जाये क्योंकि हमारे वहां पर हमारे क्षेत्र में महिलाओं में शिक्षा का अभाव है और महिलाओं से जुडी बीमारियां अधिक हैं इसलिये चिकित्सा सुविधा विकसित करने की आवश्यकता है इसलिये सभापति महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि मेरे डूंगरपुर जिले में नर्सिंग कॉलेज और पैरा मेडिकल की सुविधा की जाए...

Kas/rtm/19.07.2024/19.50/4f

आसपुर विधान सभा क्षेत्र में भी एक नर्सिंग कॉलेज खोला जाये, यह मैं मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आसपुर विधान सभा क्षेत्र में पिछली सरकार ने ट्रोमा सेंटर खोला तो है, लेकिन वहां स्टाफ नहीं है, इस वजह से वह बंद पडा हुआ है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आसपुर ट्रोमा सेंटर में स्टाफ लगाकर सुचारु रूप से चालू कराया जाये। आसपुर विधान सभा क्षेत्र में साबला ब्लॉक में निठावा, रीछा और साबला में सीएचसी, पीएचसी बनी हुई है, लेकिन बड़े दु:ख की बात है कि वहां बड़ा सीएचसी हॉस्पिटल है, लेकिन वहां अभी तक मोर्चरी नहीं है। इस कारण से जब अचानक से हमारे आदिवासियों की कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके पोस्टमार्टम के लिये या तो आसपुर जाना पड़ता है या डूंगरपुर जाना पड़ता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे वहां एक मोर्चरी निर्माण करायी जाये।

इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई सब सेंटर ऐसे हैं जिनके भवन आजादी से पहले के बने हुए लगते हैं। वहां सब सेंटर पर सीएचओ बैठता है, वहां गांव के बीमार लोग जाते हैं तो उस सब सेंटर को देखकर ही वापस चले जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं नया सदस्य हूं, मुझे दो मिनट बोलने का मौका दीजिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा पर विचार

श्री उमेश मीणा (आसपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि मेरे ऐरिये में जो सीएचसी और पीएचसी हैं, इनमें स्टाफ की और डाक्टरों की कमी है। मेरे साबला में दो सीएचसी में एक भी डाक्टर नहीं है। 5 पीएचसी में डाक्टर ना के बराबर हैं, 3-4 पीएचसी में तो जीरो है। यही स्थिति आसुपर में है, आसपुर, रामगढ़, पूछपुर, तीनों सीएचसी में जीरो पोस्ट है और सीनियर नर्सिंग भी नहीं है। दौड़ा में भी यही स्थिति है।

माननीय सभापति महोदय, अगर मेरे को ज्यादा समय नहीं दिया जाये तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैं मेरे रिक्त पदों वाली लिस्ट टेबल पर रख दूं।

श्री सभापति: आप मंत्री जी को दे दो। श्री पूसाराम गोदारा।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 पर बोलने का मौका दिया, सबसे पहले मैं यह बात कहना चाहूंगा कि जो बजट पेश हुआ है, उसमें वास्तव में विपक्ष के सदस्यों का जो दर्द झलक रहा है, वह सही है। बजट में समदृष्टि नहीं रखी गई है। मेरी विधान सभा में पिछली अशोक गहलोत जी की सरकार ने जिला हॉस्पिटल खोला, सीएचसी खोली और एक पीएचसी खोली। भवन के लिये 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किये, उसको काट कर नये सिरे से घोषणा की गई है, उसमें 30 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है, इस बजट में यह इनाम मेरी विधान सभा को मिला है। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो मिला है, वह तो ठीक है। आज की स्थिति में मेरी विधान सभा के जिला हॉस्पिटल में 43 पद हैं। माननीय मंत्री महोदय, ध्यान से सुने, जिसमें से मात्र 21 पदों पर डाक्टर हैं, 22 पद खाली हैं। इसमें 4 पद वरिष्ठ विशेषज्ञों के हैं, 11 पद कनिष्ठ विशेषज्ञों के हैं, पैथोलॉजी का खाली है, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी के 5 पद खाली हैं। जो 21 डाक्टर हैं, वह भी समय पर हॉस्पिटल में नहीं मिलते, इस कारण पूरी जनता परेशान होती है और लगातार हम लोगों को शिकायत मिलती है। समय के लिये डाक्टरों को पाबंद किया जाये कि वह नियमित रूप से हॉस्पिटल आएं और अपने क्वार्टर पर कम से कम मरीज देखें।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा हमारी राजस्थान की पूर्व गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना शुरू की, जिसमें 25 लाख रुपये तक का इलाज, हालांकि आपने उसका नाम बदल दिया, लेकिन मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 25 लाख तक की जांच का बजट में एनाउंस नहीं है, हालांकि अलग से स्टेटमेंट जरूर आया है कि यह जारी रहेगा। दवा और जांच फ्री सबसे पहले हमारी तत्कालीन गहलोत सरकार ने किया। पिछली सरकार ने बहुत से जिला हॉस्पिटल खोले, मोहल्ला क्लिनिक भी खोली और सीएचसी, पीएचसी और सब सेंटर खोले। पिछली सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की पीएचसी में पहली बार लगभग 95 परसेंट पद भरे। वह डाक्टर आज गांवों में हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण नहीं है, अब नियंत्रण खतम हो गया है।

डाक्टर वहां रहते नहीं, पता नहीं कहां जाते हैं, जबकि नियुक्ति उनकी वहां है। उनको पाबंद किया जाये कि ग्रामीण क्षेत्र की पीएचसी में समय पर जाये, यह सुनिश्चित मंत्री महोदय आपको करना है। कहने का मकसद यह है कि आधुनिक मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराये बगैर इन सीएचसी, पीएचसी और जिला हॉस्पिटलों का कोई मतलब नहीं है। नर्सिंग स्टाफ, फार्मेसिस्ट और लैब टेक्निशियन के पदों की मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थिति उप जिला हॉस्पिटल जैसी है। वहां डाक्टर के पद खाली हैं। माननीय मंत्री महोदय, वहां सोनोग्राफी नहीं होती है, क्योंकि पूरे जिले में रेडियोलॉजिस्ट के दो पद सिर्फ भर्ती हॉस्पिटल चूरू में हैं, इसके अलावा कोई रेडियोलॉजिस्ट हमारे जिले में नहीं है, जिला हॉस्पिटल में भी नहीं है। इसका बहुत गलत मैसेज जाता है। वहां ईएनटी की मशीन नहीं है, एमआरआई की व्यवस्था नहीं है, सिटी स्केन की व्यवस्था नहीं है, जबकि तीसरा सत्र चल रहा है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह व्यवस्थाएं अतिशीघ्र कराई जाएं। जिला हॉस्पिटल तो कम से कम इस तरह सुनियोजित होने चाहिये कि वह रेफरल हॉस्पिटल न बने।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में सीएचसी पडियारा में माननीय मंत्री महोदय 15 हजार की आबादी है, वहां 5 पोस्ट स्वीकृत हैं, एक भी डाक्टर नहीं है। वहां जिला कलेक्टर ने एक आदमी को व्यवस्थार्थ लगा रखा है। 6 महीने से सारी पोस्टें खाली हैं, सिर्फ नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चल रहा है। कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ विशेषज्ञ, फार्मासिस्ट, कनिष्ठ सहायक, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर भी नहीं हैं। यह बहुत पुरानी सीएचसी है। इसके अलावा सीएचसी पडियारा में डिजिटल एक्स-रे मशीन नहीं है, फुल ऑटोमेटिक सीवीसी मशीन भी नहीं है। सीएचसी दाउसर दो साल पहले खुली, उसमें दो पद कनिष्ठ विशेषज्ञ के खाली हैं, सिर्फ 3 एमओ हैं। इसके अलावा डिजिटल एक्स-रे मशीन और सीवीसी मशीन भी नहीं है। एक मॉडल सीएचसी राजलदेसर नगरपालिका, तहसील में है, वहां 5 पदों में 3 डाक्टर हैं, 2 खाली हैं। एक गायनिक डाक्टर है, इतने बड़े हॉस्पिटल में गायनिक का होना बहुत जरूरी है। गायनिक लगी हुई है, लेकिन वह 2 साल से जब से लगी है, डेपुटेशन पर चुरू हॉस्पिटल में बैठी है।

msk/rtm/19.07.2024/20.00/4g

बहुत बड़े खेद का विषय है कि जिला स्तर का हॉस्पिटल है, उसमें यह स्थिति है। इसके अलावा पुरानी बिल्डिंग है। उसमें मरम्मत की आवश्यकता है। पानी भरता है। अब की बार लाखों रुपये की दवाई खराब हो गयी। इसलिए रिपेयर का बजट भी दिया जाये। इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में छापर नगरपालिका है, उसमें पहले सिटी डिस्पेंसरी थी। आज उस सिटी डिस्पेंसरी का ही स्टॉफ है। सीएचसी का भवन बनना जरूर शुरू हो गया है, लेकिन स्टॉफ नहीं है। नर्सिंग स्टॉफ के पांचों के पाचों पद खाली हैं। तीन डॉक्टर हैं, एक नर्सिंग आफिसर है, एक एएनएम है। इसके अलावा तमाम हॉस्पिटल खाली है। मेरा निवेदन है कि इनको भरा जाये।

श्री सभापतिः विराजिये।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): साहब, मैं मेरी मांग एक मिनट में बोलूंगा। लाछासर पीएचसी, जो कि कम से कम 10 हजार की आबादी कस्बा है, उसको सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाये। सीतासर लोहा, अबदसर, सब-सेंटरों को पीएचसी में क्रमोन्नत किया जाये। क्योंकि वहां 10 किलोमीटर में कोई हॉस्पिटल नहीं है। पीएचसी सिमसिया में 2022 में स्वीकृत हुआ, लेकिन अभी तक भवन नहीं बना है, पैसा स्वीकृत है, कार्य शुरू कराया जाये। रतनगढ़ की सभी पीएचसी पर एक-एक फुल ऑटोमेटिक एनालाइजर की खरीद व सीबीसी मशीन की आवश्यकता है। (समय समाप्ति सूचक घंटी)आपने मुझे बहुत कम समय दिया, फिर भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: सोहन लाल नायक, पांच मिनट में आप बात पूरी करें।

श्री सोहन लाल नायक (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने के आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। रायसिंहनगर सीएचसी को उप जिला चिकित्सालय बनाया जाये। हमारा क्षेत्र पाकिस्तान का सीमान्त क्षेत्र है। यहां आये दिन कैजुअलटी होती रहती है। हमारे नजदीक कोई बड़ी चिकित्सा सुविधा नहीं है। रायसिंहनगर से गंगानगर 75 किलोमीटर और बीकानेर 150 किलोमीटर है। उसके बीच में कोई भी राजकीय सुविधा नहीं है, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत परेशानी होती है। मेरे क्षेत्र की सीएचसी विजयनगर में मात्र दो डॉक्टर हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सीएचसी की प्रतिदिन की 700 की ओपीडी है और किस तरह उन मरीजों का इलाज होता है, यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इससे रोगियों को बहुत कठिनाइयां होती हैं। पर्याप्त डॉक्टरों की नियुक्ति करने की कृपा करें। सीएचसी रायसिंहनगर एवं पीएचसी विजयनगर में अल्ट्रा-सोनोग्राफी मशीनों की व्यवस्था नहीं है। रायसिंहनगर सीएचसी के अन्दर 14.04.2006 को एमपी लेड द्वारा एक अल्टा-सोनोग्राफी मशीन स्थापित की गयी थी। वह 10.06.2011 को बन्द हो गयी और बीच में किसी विशेषज्ञ के न होने से, पद पर नियुक्ति न होने से उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सीएचसी पर आप सोनोग्राफी के विशेषज्ञों के पद स्थापित करें। विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों के, नर्सिंग स्टाफ के पद बहुत रिक्त हैं, जिससे वहां के क्षेत्र के लोगों को बहुत तकलीफ होती है। उनका इलाज नहीं हो पाता। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि इनके पदों की जल्दी पूर्ति कर लोगों को स्वास्थ्य का लाभ दिलायें।

सीएचसी रायसिंहनगर में ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं है। पूरे विधान सभा क्षेत्र में ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं है और ब्लड की जब भी जरूरत पड़ती है, चाहे वह एक्सीडेंट का मामला हो, चाहे किसी ऑपरेशन का मामला हो तो 75 किलोमीटर, गंगानगर से पहले ब्लड की व्यवस्था नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र में एक सीएचसी पर आप ब्लड बैंक की व्यवस्था करें। माननीय सभापति महोदय, पिछले छह-सात महीने में

रायसिंहनगर के जो भी प्राथमिक सीएचसी चिकित्सालय हैं, उनमें क्षय रोगियों के लिए दवाओं की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि क्षय रोगियों की दवाई की व्यवस्था करायें। अगर उनकी डोज बीच में टूट जाती है तो उनको इलाज का कोई फायदा नहीं होता है। वहां दवाओं की व्यवस्था की जाये।

माननीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के बहुत साथी बार-बार कह रहे थे कि भीलवाड़ा मॉडल तो ऐसा ही है। मेरा निवेदन है कि कोरोना में हमारे प्रधान सेवक जी ने ताली, थाली वगैरह बजवा कर क्या इलाज करवाया? राजस्थान सरकार ने भीलवाड़ा मॉडल बनाकर पूरे राजस्थान को कोरोना से बचाया। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि कोरोना के अन्दर बनारस, यमुना जैसी नदियों में लाशें तैर रही थीं, उस वक्त हमारे प्रधान सेवक सो रहे थे। (समय समाप्ति सूचक घंटी) धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापतिः श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 व 28 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। किसी भी प्रदेश की प्रगति, उन्नति के लिए बेहतर प्रबंध होना चाहिए, उस प्रदेश की जनता स्वस्थ हो, सब कुछ सही। जनता निरोगी होगी तो प्रदेश प्रगति करेगा। इसी को आधार मानकर राजस्थान के मुख्य मंत्री आदरणीय भजन लाल जी और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में प्रदेश को समृद्धशाली बनाया जा सके। एक वित्तीय वर्ष के लिए 27 हजार करोड़ से भी अधिक रखना एक सराहनीय कदम है। चिकित्सा सुविधा विस्तार के लिए पूरे प्रदेश का 8.26 बजट निर्धारित करना ऐतिहासिक कदम है। मोदी जी की सरकार द्वारा आयुष्मान योजना शुरू की गयी थी। पिछले पांच वर्ष में कांग्रेस सरकार ने योजना को लागू नहीं किया। जनता के साथ में धोखा हुआ। अब भजन लाल सरकार ने वापस योजना लागू की है। जनता को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जैसी योजना लागू करना प्रदेश के लिए अच्छी बात है। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक मॉडल सीएचसी की स्थापना करना।

चिकित्सा सुविधा को लेकर बजट 2024-25 में प्रदेश को बेहतर सुविधा मिली है। मेरे क्षेत्र में भी सीएचसी, पीएचसी सिणधरी का हॉस्पिटल 30 बेड से 50 बेड का, उप जिला अस्पताल, ये सारी सुविधा पूरे राजस्थान में दी हैं। मेरी आदरणीय मंत्री महोदय से मांग रहेगी कि जो पद रिक्त पड़े हैं, पूरे राजस्थान में हैं। सिवाना उप जिला अस्पताल समेत 45 पद डॉक्टरों के खाली हैं। सिणधरी में ट्रोमा सेंटर की महत्ती आवश्यकता है। मैंने मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन किया है, आपसे भी निवेदन करना रहा हूं। सिवाना विधान सभा क्षेत्र में पिछले 20 साल से महिला डॉक्टर नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर की पोस्टिंग हो जाती है, पर वह पीजी करने के लिए छुट्टी लेकर या कहीं जाकर बैठ जाते हैं, वहां ड्यूटी नहीं करते हैं, उन पर भी थोड़ा ध्यान देंगे तो जनता को राहत मिलेगी।

मेरी मांग है, चारणों की ढाणी, सिणधरी में पीएचसी की आवश्यकता है। डीडे, समदड़ी

में, तेलवाड़ा, सिवाना में, ये अतिआवश्यक हैं। 35 राजस्व गांव वंचित हैं। उनमें सब-सेंटर की मांग रखता हूं। नवीन ग्राम-पंचायतों में सब-सेंटर स्वीकृत हैं। भवन नहीं हैं, उनके लिए भी भवन की सुविधा हो। 26 से ज्यादा एएनएम पद रिक्त पड़े हैं। उनको भी भरने की कोशिश करें। नये भवनों में चिकित्सा उपकरणों की, आज सेक्रेटरी साहब भी बता रहे थे कि समदड़ी और सिवाना में उपकरण बाकी थे, वे स्वीकृत हो गये। मोकलसर और होड़ू पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाये। सिवाना आयुर्वेदिक अस्पताल को जिला अस्पताल किया जाये। भारत के लौह पुरुष प्रधान मंत्री जी ने चिकित्सा सुविधा के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज दिये। आजादी के 70 साल बाद भी हर जिले पर मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, हमारा जिला बालोतरा नया जिला बना है। ...(व्यवधान)... मैं आपको बाद में बताऊंगा। बताऊंगा कि आपने क्या किया है? मैं बताऊंगा, पहले डिमांड रखने दो, फिर मैं आप वाला सारा बताऊंगा। बाड़मेर जिले में मेडिकल कॉलेज है, अब बालोतरा अलग जिला बन गया है, इसमें मेरी मांग रहेगी कि मेडिकल कॉलेज बन जाये तो ज्यादा सुविधा मिले।

mdp/rtm/19.07.2024/20:10/4h

श्री सभापति: हाकम अली जी, ...(व्यवधान)... हर बार नहीं।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): मेरा एक निवेदन और रहेगा कि आप जनसंख्या के आधार पर नहीं भौगोलिक स्थिति, पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर के अन्दर एक हॉस्पिटल 25 या 30 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं माननीय मंत्री निवेदन करुंगा कि वहां जनसंख्या का आधार नहीं लेकर भू-भाग का आधार पर लेकर वहां पीएचसी और सब-सेन्टर ज्यादा देने की आवश्यकता है। जब तक वह नहीं होगी तब तक जनता को सुविधा नहीं मिलेगी।

बरसात का समय है, इस वजह से हर पीएचसी पर स्नेक बाइट इंजेक्शन होना अति-आवश्यक है। बरसात के समय में यह जरूरी है। एक निवेदन और रहेगा कि अभी एक माननीय सदस्य एम्बुलेंस की बात कर रहे थे, लेकिन जो ये गवर्नमेंट व्हीकल होते हैं, चाहे चिकित्सा विभाग में हों, शिक्षा में हों या किसी दूसरे विभाग में हों, वह इतनी जल्दी एक-दो साल में ही नकारा कैसे हो जाते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल की गाड़ी होती है या किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास में गाड़ी होती है, वह पांच साल, सात साल, दस साल चलती है, एक या डेढ़ साल के अन्दर सरकारी जितने भी वाहन होते हैं नकारा होकर खड़े हो जाते हैं। इसके लिए मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कौनसा व्हीकल किस वजह से हुआ है। एम्बुलेंस सही समय पर नहीं आती तो मरीज के लिए बड़ी दुविधा होती है।

माननीय मंत्री महोदय, मेरा एक निवेदन रहेगा कि खाद्य में मिलावट को रोकने के लिए अभी तक कोई कारगर उपाय नहीं मिला है। खाद्य सामग्री में, दूध में सब में मिलावट होती है, उसको रोकने के लिए अच्छा प्रबंध करें ताकि मिलावट से जनता को राहत मिल सके। अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि आपने क्या किया, क्या दिया? हम वहां बैठे थे, आपकी

सरकार ने, बाड़मेर, जैसलमेर में मैं एक व्यक्ति भाजपा का विधायक था, एक भी चीज नहीं दी आप लोगों ने। हमारी सरकार ने तो कोई भेदभाव नहीं रखा है ...(व्यवधान)... सबके साथ में न्याय करने का काम किया है।

श्री सभापतिः विराजिए। आप विराजिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): आपने सेंक्शन हुआ काम भी रोकने का काम किया होगा। मैं एक-एक चीज गिना दूंगा। कोरोना की बात कर रहे है आप। कोरोना में होटलों में जाकर विराजे थे। आपने एक टीम बनाई थी, वीसी में भी मैं बोला था। टाइम का मुझे ध्यान है। एक कमेटी बनाकर सेक्रेट्री से लगाकर मंत्री, एक नंबर आपने दिये थे, नंबर के हिसाब से कोई टेलीफोन उठाने वाला नहीं था। वीसी में मैंने मुख्य मंत्री जी को कहा था कि ये गुमराह करने के लिए नंबर क्यों दिए? महाराष्ट्र से लगाकर, दक्षिण से लगाकर गुजरात से जो बॉर्डर पर आकर लोग रुके हुए थे, आपका सेक्रेट्री या कोई मंत्री उनका टेलीफोन उठाने वाला नहीं था, एक भी जगह। ये जरूर कार्य आपने किया था कि विधायकों से पैसा लेकर सामग्री इकट्ठा करके फोटो लगाकर अपने कार्यकर्ता को बैठने के लिए भेजा था और वह भी पूरा जो जनता के पास में जाना चाहिए था, वह नहीं गया। ऐसे-ऐसे काम किए। अभी जो बता रहे थे मांग कर रहे हैं, माननीय सदस्य बता रहे थे कि हमारे 95 परसेंट पद भरे हुए हैं। भरे हुए हैं तो मांग किसलिए कर रहे हैं? थोथी घोषणा करके, लास्ट मूवमेंट में आपने ऐसी-ऐसी घोषणा कर दी, कुछ भी नहीं दे सके। एम्दे की मेम्दा, मेम्दा को उघाड़े माथे, मोबाइल बांटने का कार्य किया। किस तरीके का कार्य किया? कोई कसर नहीं छोड़ी। ईमानदारीपूर्वक बजट में जो कार्य करना चाहिए, उसको नहीं किया। भगवान आपका भला करे। इसी वजह से वहां विराजे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है।

मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह जो बजट पेश किया है, 36 कौम, हर विभाग को दिया है। हर गांव को, हर चीज को छुआ है और बिलकुल ईमानदारी से काम होगा और किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री जयकृष्ण पटेल। श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी।

श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (नोखा): आदरणीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा के लिए यह जो परिवर्तन बजट 2024-25 के पृष्ठ संख्या 67 के पैरा संख्या 60 में जिला चिकित्सालय की घोषणा की गयी है, यह घोषणा तो विगत सरकार की बजट घोषणा में पूर्व में की जा चुकी थी। उक्त घोषणा के क्रम में जिला चिकित्सालय नोखा के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो चुकी है, लेकिन खेद का विषय है कि जिला चिकित्सालय की स्वीकृति जारी होने के बाद भी जिला चिकित्सालय का निर्माण नहीं होने से नोखा की जनता आज भी वांछित चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तरस रही है। जब चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी जैसी मूलभूत सुविधाओं पर भी हम समय पर काम नहीं कर पा रहे हैं तो मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं कि हम लोग यहां कौनसे

विकास का काम करेंगे। सबसे पहले हमारे विकास का काम स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगी कि जिला चिकित्सालय नोख के भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 13 सितम्बर, 2023 को ही विगत सरकार ने जारी कर दी थी। इस स्वीकृति के अनुसरण में वर्तमान सरकार ने जिला चिकित्सालय नोखा के भवन निर्माण की निविदा पर दिनांक 14 फरवरी, 2024 को जारी की थी, परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण व शर्मनाक है कि उक्त निविदा महज एक शिकायती पत्र के आधार पर वर्तमान सरकार ने दिनांक 5 मार्च 2024 को अपरिहार्य कारणों का हवाला देकर निरस्त कर दी।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहूंगी कि सरकार उन अपरिहार्य कारणों का खुलासा करते हुए, जिनके चलते जिला चिकित्सालय नोखा के निर्माण की प्रक्रिया को रोका गया है, अविलंब चिकित्सालय के निर्माण हेतु निविदा जारी करके तत्काल चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र नोखा के साथ न्याय करें। जिला चिकित्सालय नोखा के निर्माण हेतु राज्य सरकार ने नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए सक्षम स्तर से निर्णय लेकर जब पूर्व में ही स्वीकृति जारी कर दी थी तो चिकित्सालय निर्माण प्रक्रिया रुकवा कर फिर से परिवर्तित बजट 2024-25 में इसकी मिथ्या घोषणा करने का क्या औचित्य है? क्या सरकार घोषणा-घोषणा का खेल ही खेलती रहेगी या जनता की मूलभूत सुविधाओं का विकास भी ध्यान में लेगी।

माननीय सभापति महोदय, यह अत्यंत खेदजनक है कि नोखा की जनता को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से महरूम रखने के इरादे से नोखा की जनता से राजनीतिक द्वेषता रखने वाले कुछ लोगों द्वारा शासन-प्रशासन को लिखे गये महज शिकायती पत्र के आधार पर जिला चिकित्सालय नोखा की टेंडर प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों का हवाला देकर सरकार ने रोक दिया। यह नोखा व बीकानेर की जनता की चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ा है। जनता के साथ घोर अन्याय हुआ है। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री सभापति: श्री जयकृष्ण।

श्री जयकृष्ण पटेल (बागीदोरा): धन्यवाद, सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर आनंदपुरी, बागीदोरा, गांगडतलाई, तीन ब्लॉक पड़ते हैं। आनंदपुरी ब्लॉक के अन्दर कुल 96 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से मात्र एक सर्जन है और 39 पद रिक्त हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हमारे जो स्वीकृत रिक्त पद हैं, उनको जल्दी से भरा जाए।

माननीय सभापति महोदय, हमारा दूसरा ब्लॉक बागीदोरा पड़ता है, जिसके अन्दर सर्जन के 14 पद रिक्त हैं, रेडियोलॉजिस्ट के 4 पद रिक्त हैं, फार्मासिस्ट के 5 और कुल एएनएम के 19 और सीएचओ के 9 पद रिक्त हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि सभी जितने भी विशेषज्ञ व डाक्टर के पद हैं, जल्दी से जल्दी भरे जाएं। हमारे

तीनों ब्लॉक्स के अन्दर दो उप जिला स्वास्थ्य केन्द्र हैं। उसके अन्दर सीबीसी मशीन नहीं है। सीबीसी मशीन आप लगाएं, ताकि वहां की जनता को खून की जांच कराने के लिए जिला मुख्यालय तक नहीं आना पड़े।

Ans/rtm 20.20 4j 19.07.2024

हमारे नजदीक गुजरात सीमावर्ती इलाक़े का अस्पताल है, वहां पर जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हमारा दुरस्थ इलाका है। अगर किसी महिला की डिलिवरी का पीरियड हो या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वहां जो 108 लगी हुई है उसकी हालत बहुत खराब है, आने जाने में समस्या है। मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 108 तीनों ब्लाक पर उपलब्ध करवाई जाए1

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हू कि हमारे वहां सोनोग्राफी व एक्सरे के लिए गुजरात व मध्यप्रदेश के इलाक़ों में जाना पड़ता है, जिससे रोगियों को समस्या होती है। मैं मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि वहां एक्सरे व सोनोग्राफी मशीन लगाई जाए।

हमारे वहां पीएचसी से सीएचसी के लिए चांदवाड़ा, बुडवा, बागीदोरा, फलवा इलाका है उस इलाक़े में पीएचसी है उसका सीएचसी में क्रमोन्नत करने के लिए मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि 7 हजार सीएचओ जो रिजल्ट के अन्दर पेंडिग में पड़े हैं, 2011 में नर्सिंग की भर्ती हुई थी, उसके अन्दर 11 हजार नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन अभी तक 41 हजार 14 पेंडिग पड़ी है, उन भर्तियों के बारे में भी सोचने की जरूरत है। यह मांग पूरी की जाए।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हू कि सीएचओ की भर्ती में नियमित केडर है, उसमें सीएचओ को स्थाई किया जाए। जो सीएचओ लगे हैं उनको स्थाई किया जाए। हमारे वहां पर तीन विधान सभा में 450 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जिसके अन्दर 180 लगे हुए हैं, बाकी सारे रिक्त हैं। मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि सीएचओ के रिक्त पद हैं वे भी जल्दी से जल्दी भरें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि 13 हजार कोविड़ में सहायक थे जिन्होंने विकट परिस्थिति में, जब हम ताली बजाओ, थाली बजाओ कर रहे थे, उस समय उन लोगों ने हमारे साथ यहां लोगों की जान बचाई। विकट परिस्थिति में साथ देने वाले कार्मिक थे, उनकी तरफ गत सरकार का या अभी वाली सरकार का ध्यान नहीं गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मात्र एक मिनट, सभापति महोदय। उन्होंने जो सेवाएं दीं, उसके लिए बोनस अंक का प्रावधान किया जाए। कोविड के अन्दर सीएचओ थे उनको कहीं ना कहीं लाभ मिले, आप कोई ऐसी योजना बनाएं, जो मांग है वह मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय तक पहुंचा रहा

हूं।

सभापति महोदय, हमारे शिव क्षेत्र में संभाग मुख्यालय है। संभाग मुख्यालय होने के बाद मेरी विधान सभा में तीन ब्लाक हैं, वहां चिकित्सा और शिक्षा की बात करूँ तो वहां जीएनएम के लिए एक भी कालेज नहीं है। आपके माध्यम से मैं बागीदोरा ब्लाक में एक जीएनएम नर्सिंग कॉलेज खोलने की मांग रखता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझ बोलने का मौका दिया, उसके लिए जुहार, अभिनंदन, जय जुहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, आप सबकी जय, जय भील।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री डूंगरराम गेदर।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 27 व 28 पर मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत साहब का, जिन्होनें पूरे देश में राजस्थान को राइट टू हैल्थ कानून देकर, राजस्थान को पहला राज्य बनाया जहां राइट टू हेल्थ कानून दिया।

मैं पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने राजस्थान में निशुल्क यूनिवर्सल हैल्थ केयर उपलब्ध कराकर देश का पहला राज्य बनाने का काम किया। निरोगी राजस्थान का नारा का पूरे देश में देकर, कोविड के प्रबंधन में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, किसी को दवाई की कमी नहीं आने देंगे, इस तरह के प्रबंध अगर किसी ने किए तो राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने किए।

सत्ता पक्ष में बैठे नेता आज भले ही कुछ भी कहें, लेकिन मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब का बहुत बड़ा दिल था, विपक्ष के लोगों ने मांग की कि विधायक निधि का बढ़ाया जाए, तो विपक्ष से पूछकर कि बताओ विधायक निधि कितनी करें, विपक्ष ने कहा कि 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करो। विपक्ष से पूछकर, विपक्ष की बात मानते हुए 5 करोड़ विधायक निधि करने का अगर काम किया तो अशोक गहलोत साहब ने किया।

सभापति महोदय, में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सूरतगढ़ बहुत बड़ा कस्बा, सामरिक कस्बा है। सूरतगढ़ में आज भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, सूरतगढ़ को उप जिला अस्पताल की जरूरत है, इसके लिए मैं मांग करता हूं। सूरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन जर्जर अवस्था में है, आज वह परेशानी का सबब बना हुआ है, आज नया भवन बनाने की जरूरत है।

सूरतगढ़ सीएचसी के अन्दर सोनोग्राफी मशीन है लेकिन डॉक्टर नहीं है। सूरगतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बहुत सी पीएचसीज जैसे डाबा, ठुकराना, देवदासपुरा, बीरवाना पीएचसीज हैं, उनको सीएचसी करने की मांग आपके माध्यम से करना चाहता हूं। सूरतगढ कस्बा है उससे श्री गंगानगर जिला हैडक्वार्टर 70 किलोमीटर दूर है, बीकानेर जिला हैडक्वार्टर 170 किलोमीटर दूर है, हनुमानगढ़ जिला हैडक्वार्टर भी 170 किलोमीटर दूर है, इसलिए ये सारे के सारे काम वहां होना अतिआवश्यक हैं।

सूरतगढ़ में राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने की मांग करता हूं। अभी सत्ता पक्ष के नेता बहुत सारी बातें कर रहे थे। बाबा साहेब ने कहा है कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे लागू करने वाले लोगों की नीयत अगर साफ नहीं है तो वह बुरा से बुरा संविधान साबित हो सकता है।

जितने भी सवालों के जवाब आते हैं, आपके मंत्री महोदय उन सब सवालों के जवाब में यही कह पाते हैं कि पिछली सरकार ने यह नहीं किया, पैसा पूरा नहीं लगा पाए, इस कारण योजना पूरी नहीं हो पाई। मैं कहना चाहता हूं कि मार्च में आम बजट की घोषणा होती है और 1 अप्रैल से आम बजट लागू होता है। अक्टूबर, 2023 में आचार संहिता लग गई, उसके बाद नई सरकार बनने के बाद दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, चार महीने का बजट सत्ता पक्ष के लोगों को लगाना था, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम कर रहे हैं।

पिछले चार महीनों में आपने क्या किया। नये ज़िलों के गठन की बात आई तो आप कहते हैं कि रिव्यू कमेटी बना दी। महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल की बात आई तो आपने कहा कि रिव्यू कमेटी बना दी, कॉलेज खोलने की बात आई, आपने कहा कि रिव्यू कमेटी बना दी। नई नगरपालिकाएं बनाईं, आपने कहा कि रिव्यू कमेटी बना दी। पिछले 6 महीने से आप जांच ही जांच कर रहे हैं। पानी की जगह पानी नहीं है। जेजेएम योजना में ठेकेदारों के पास पैसा नहीं है। बिजली विभाग के पास सामान नहीं है। सड़क ठेकेदारों को देने के लिए पैसा नहीं है। भाखडा गंगनहर, आईजीएनपी में खालों के लिए पैसा आप लोग अभी भी नहीं दे पाए हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की योजना में, राजस्थान प्रदेश में पिछले ढाई साल से, प्रधान मंत्री आवास योजना के मकान नहीं आए। पिछले ढ़ाई साल से कैटल शेड के मैटेरियल का पैसा आज तक नहीं आया।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय नेता प्रतिपक्ष, डिमांड पर बहस हो रही है और वह...

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): आप लोग बार-बार बदलते हैं। यानी मज़दूरों को मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। इसकी शिकायत या तो सरपंच से करता है या एमएलए से करता है।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): चिकित्सा में भी मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): राजस्थान में सारी की सारी योजनाएं शुरू करने का काम किया वह अशोक गहलोत साहब ने किया। यदि राजस्थान में फ्री दवाइयों की शुरूआत किसी ने की तो अशोक गहलोत साहब ने की। फ्री जांचों की सुविधा अगर किसी ने की तो वह अशोक गहलोत साहब ने की।

श्री राजेन्द्र (महवा): सभापति महोदय, मांग संख्या 27 व 28 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। गरीब की सेवा, किसान का सम्मान, नारी

शक्ति वंदन, मध्यम वर्ग के साथ निवेश से युवाओं को रोजगार का अवसर, सुशासन से संबद्ध भारत, श्रमिक को सशक्त और वंचित को वरीयता, यह सब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। जब से देश के प्रधानमंत्री जी बने हैं, तब से यह काम सुचारु रूप से लागू है।

VPS-RTM-19.07.2024-20.30-4k

जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यहां पर चर्चा चल रही है तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। स्वास्थ्य मंत्रीजी भी यहां पर बैठे हैं, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए आपने राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। निश्चित रूप से वे कारगर साबित होंगी, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने प्रदेश के साथ ही मेरे महवा विधान सभा क्षेत्र के लिए बहुत सारी घोषणाएं कीं, लेकिन आज डेढ़-दो साल हो गये, उसके बावजूद भी वहां पर कोई काम नहीं हुआ। आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सी.एच.सी. की घोषणा की है और निश्चित रूप से दस दिन के अन्दर ही प्रशासन के अधिकारियों ने जगह देखकर चिह्नित भी कर लिया कि वह सी.एच.सी. कहां पर बनेगी। पूर्ववर्ती सरकार में जिला अस्पताल में विधायक कोटे, वहां के जो विधायक थे, उन्होंने एक सोनोग्राफी की मशीन खरीदी जिसकी बाजार की लागत 15 से 20 लाख रुपये थी लेकिन 55 लाख रुपये में उस मशीन को खरीदा गया और सबसे बड़ी बात यह रही कि दो साल पहले जब उस मशीन को खरीदा गया तो वह दो साल से लगातार अभी भी बंद है और जब हमारी सरकार आयी तो उसके बाद हमने उसको चालू करने का काम किया। घोषणाएं बहुत की पिछली सरकार ने लेकिन घोषणाओं पर अमल नहीं किया, वे खाली लोक-लुभावनी घोषणाएं थीं। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में बहुत सारी चीजों की जो डिमांड जनता के बीच में रखी, वह निश्चित रूप से पूरी होगी। ये विपक्ष वाले यह कहते हैं कि गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना थी लेकिन हम जब गांवों में रहते हैं, गांवों के लोग हमसे यह पूछते हैं कि साहब, मेरे इलाज में पांच लाख रुपये का खर्चा आया लेकिन हॉस्पिटल वाले सरकार को पच्चीस-पच्चीस, तीस-तीस लाख रुपये का बिल पेश करते थे और सरकार से पैसे उठाने का काम करते थे, जनता को गुमराह करने का अशोक गहलोत की सरकार ने काम किया तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी जो सरकार है, निश्चित रूप से मेरे विधान सभा क्षेत्र का जिला अस्पताल जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है महवा, वहां पर पर डे एक लाख रुपये की जांचें होती हैं। पूर्ववर्ती सरकार के समय में हॉस्पिटल में एक भी जांच नहीं होती थी, सब प्राइवेट लैब में वहां पर जांच हुआ करती थी तो मैं मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि महवा आगरा-जयपुर के बीच में पड़ता है इसलिए मेरे जिला अस्पताल को रेफरल अस्पताल घोषित किया जाये, एक ब्लड बैंक की स्थापना भी वहां पर की जाये। सलीमपुर एक बहुत बड़ा मुख्यालय है, ग्राम पंचायत है, वहां पर एक पी.एच.सी. की भी घोषणा आपके मार्फत होनी चाहिए। मण्डावर एक अलग से उप खंड है,

वहां पर अभी सी.एच.सी. है तो मेरी यह मांग है कि उस सी.एच.सी. को उप जिला अस्पताल में आप क्रमोन्नत करें।

मैं मेरी सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार का यह बजट पूरे प्रदेश को सभी विभागों में दिया है, निश्चित रूप से पांच वर्ष तक पूरी दीन-हीन गरीब जनता के हितों का यह बजट है और निश्चित रूप से हम इसमें पूरी तरह से कामयाब रहेंगे। मैं पुनः माननीय सभापति महोदय, आपसे यही कहूंगा कि आपने मेरे को समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्रीमती गीता बरवड़।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे संख्या 27 के तहत बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। 'पहला सुख निरोगी काया', माननीय सभापति महोदय, स्वस्थ नागरिक राष्ट्र और समाज की सम्पत्ति है। हैल्थ इज वैल्थ, अच्छे स्वास्थ्य को सबसे बड़ी सम्पत्ति माना गया है। अपने नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार का परम कर्तव्य और मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार नई-नई योजनाएं बनाकर आम जन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सदैव प्रयासरत रही है।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार, गहलोत सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किये हैं। मुख्य मंत्री मुफ्त दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपये का मुफ्त इलाज, दस लाख का दुर्घटना बीमा और कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में जाने से पहले यह सोचता नहीं था कि यह इलाज के पैसे कहां से आएंगे, यह ऑपरेशन के पैसे कहां से आएंगे और आज की तारीख में गरीब तबके के सारे व्यक्ति परेशान हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस सदन के माध्यम से चिकित्सा मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की दूरदराज, दूरस्थ एवं आबादी के लिहाज से बड़ी ग्राम पंचायतें सोइला, खबासपुरा, सालवाकलां, सालवाखुर्द, अरटियाकलां में वर्तमान में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करवाने की मांग करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रतिदिन 100 से ज्यादा ओ.पी.डी. रहती है और केन्द्रों पर पर्याप्त स्टाफ नहीं होने पर मरीजों की लाइनें लगी रहती हैं। ग्राम पंचायत रूदिया, पालड़ी, रणावता, रामड़ावास, सियारा, बुचेटी में संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की मांग करती हूं और ग्राम पंचायत मंडली, चाणना, नांगलवास, डंढोरा में सब सेंटर खोलने की मांग करती हूं जिससे समय पर आमजन को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहूंगी कि उक्त संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करवाने हेतु बिंदुवार निम्नानुसार

प्रस्तावित करती हूं। जो ग्राम पंचायतें एवं आस-पास की ढाणियों की कुल आबादी 15 हजार से 16 हजार तक है जिसमें मात्र ए.एन.एम. या सी.एच.ओ. ही कार्यरत है। इन ग्राम पंचायतों के लोगों को आपात स्थिति में चिकित्सा सुविधा हेतु करीब 45 किलोमीटर की परिधि में जाना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, उक्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए इन ग्राम पंचायतों की पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में एवं सब सेंटर को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करायें।

माननीय सभापति महोदय, उक्त जिला अस्पताल, भोपालगढ़ में डाक्टरों की कुल 18 पोस्ट है, जिनमें से केवल मात्र सात डाक्टर ही लगे हुए हैं। 21 पोस्ट टोटल रिक्त हैं तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करती हूं कि रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरवाने की कृपा करें और मरीजों को सुविधा, निजात दिलायें।

साथ ही एक एनेस्थीसिया डाक्टर की पोस्ट भी रिक्त है जिसको जल्दी से जल्दी भरवाने की कृपा करें ताकि डिलिवरी यहां पर ही भोपालगढ़ में हो सके।

श्री सभापतिः आप विराजिये।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): जोधपुर रेफर नहीं करना पड़े।

श्री सभापतिः आप यह मंत्रीजी को दे दें।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, उक्त जिला अस्पताल भोपालगढ़ में 28 डाक्टरों के नियमानुसार सरकारी आवासों का निर्माण किया जाये ताकि सारे डाक्टर हैडक्वार्टर पर ही रहें, जिससे आम जन को अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके।

श्री सभापतिः श्री हंसराज मीना। आप विराजिये।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, भोपालगढ़ में पिछली सरकार में ट्रोमा सेंटर बनवाया गया था लेकिन अभी तक ट्रोमा सेंटर में जो इक्विपमेंट होते हैं, वे नहीं लगाये गये हैं, उनको लगवाने की कृपा करें।

श्री सभापतिः विराजिये। आप मंत्रीजी को लिस्ट दे दें।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट। भोलपागढ़ में दो ब्लॉक है, भोपालगढ़ और बावड़ी। बावड़ी ब्लॉक में ट्रोमा सेंटर नहीं होने से परेशानियां आती हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आप अपनी सूची दे दें मंत्रीजी को।

श्री हंसराज मीना (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की मांग संख्या 27 एवं 28 पर चर्चा करने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और माननीय वित्त मंत्रीजी का कि जिन्होंने बजट में प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए करीब 27660 करोड़ रुपये यानी, 8.26 प्रतिशत हिस्सा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं

पर खर्च करने का निर्णय लिया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री का कि उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में यह वहां के लोगों की एक लम्बे समय से मांग थी और विगत पन्द्रह वर्षों से लोग यह मांग कर रहे थे, सपोटरा सी.एच.सी. को जो उप जिला अस्पताल घोषित किया है। साथ ही मंडरायल करौली जिले का वह क्षेत्र है जो पूरा चम्बल नदी के किनारे है और वह एक दुर्गम इलाका है, वहां पर उप जिला अस्पताल के लिए भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में, चाहे वह मंडरायल का उप जिला चिकित्सालय हो, जहां पर 22 पद स्वीकृत है, उनमें से केवल 7 पद भरे गये हैं और 15 पद रिक्त है तो उन रिक्त पदों को भरने की मैं मांग करता हूं। चाहे वह मंडरायल हो, चाहे सपोटरा हो या फिर हाड़ौती, कुडगांव, करणपुर जो मेरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अन्दर जो चिकित्सकों के पद खाली हैं, उनको भरने की मैं मांग करता हूं।

साथ में मेरे विधान सभा क्षेत्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्दर क्योंकि महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के पद कहीं भी भरे हुए नहीं हैं, सर्जन का पद भी भरा हुआ नहीं है तो मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि आने वाले समय में माननीय चिकित्सा मंत्री मेरे विधान सभा क्षेत्र में इन पदों को भरने की घोषणा करें।

SSY/RTM/19.07.2024/20.40/4l

साथ में, इसी तरह जो जमीन की सच्चाई है, अभी कुछ दिनों पहले मेरे वहां पर ऐसे पति-पत्नी जो दोनों डॉक्टर थे, उनसे मेरी चर्चा हुई थी। उनसे मैंने कहा कि आप दोनों यहां सपोटरा या मंडरायल में आकर अपनी जॉब कीजिये। लोगों की सेवा कीजिये। मैं बताना चाहूंगा कि जो भी डॉक्टर हैं, वह ज्यादातर सिटी या जिले स्तर पर रहना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में या दूरस्थ इलाकों में कोई भी व्यक्ति, कोई भी डॉक्टर जाना नहीं चाहता है। उनका दूरस्थ क्षेत्र को लेकर जिस तरह का रिएक्शन था, चाहे सरकारी नौकरी छोड़ देंगे लेकिन उस दूरस्थ क्षेत्र में जाना वह पसंद नहीं करेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री जी से मांग करता हूं कि आप एक ऐसी ठोस पालिसी बनायें, जिसके कारण उन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में, जो डांग का इलाका है, ऐसे इलाकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर लोगों को सुविधा उपलब्ध करायी है, उनमें चिकित्सकों के पद भरे जायें। जिससे लोगों को सुविधाएं मिलें।

माननीय सभापति महोदय, क्षेत्र में जो जांच की मशीनें हैं, उनकी यह स्थिति है कि या तो वह सुचारु रूप से चल ही नहीं रही हैं या उनके पद चाहे सोनोलॉजिस्ट हों, सब पद रिक्त पड़े हुए हैं।

सपोस्टरा में पूर्व में ट्रोमा सेंटर स्वीकृत किया गया था। लेकिन वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि उनमें भवन निर्माण एवं स्टाफ की

स्वीकृति प्रदान की जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में नारोली डांग बड़ा कस्बा है। जहां पीएचसी है। वहां लोगों की भीड़ रहती है। मैं उस पीएचसी को सीएचसी घोषित करने की मांग करता हूं। महाराजपुरा, निवेरा, चौड़ा गांव में पीएचसी घोषित कराने की मांग करता हूं। साथ में करणपुर जो सपोटरा विधान सभा का दूरस्थ इलाका है। जहां पर विगत दिनों में 5 से 6 महिलाओं की मृत्यु हुई है। वह मृत्यु इस वजह से हुई है कि डिलिवरी के बाद में जिस तरह से पीपीएच की समस्या हुई है, वहां से करौली पहुंचने में 70 से 75 किलो मीटर की दूरी होती है। मेरी आपके मार्फत यह मांग है कि करणपुर के अन्दर ब्लड स्टोरेज यूनिट खोलने की घोषणा की जाये।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। थावरचन्द मीणा।

श्री थावर चन्द (धरियावद): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद, मैं मांग संख्या 27 और 28 पर बात रखूंगा। उससे पहले मैं वर्तमान सरकार को धन्यवाद दूंगा कि आपने धरियावद में उप जिला स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रस्ताव दिया है। साथ में आपने प्रतापगढ़ में ट्रोमा सेंटर खोला है। उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करुंगा कि यह हमारे लिए बहुत जरूरी था।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व की सरकार ने हमारे को सेटेलाइट हॉस्पिटल दिया। उसके लिए धन्यवाद करुंगा। वह सेटेलाइट हॉस्पिटल अभी बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन उसके साथ सीएचसी धरियावद में हॉस्पिटल के आसपास जमीन आवंटित हुई है, वह कम है। वह 5 बीघा मिली थी, अगर उसको 10 बीघा कर दी जाती है तो वहां पर बहुत सारी और भी सुविधा हो सकती है। सीएचसी धरियावद में 8 वार्ड ब्वाय के पद रिक्त हैं। उन्हें जल्द भरने की मांग करता हूं। नवीन भवन निर्माण में स्टोर रूम के निर्माण की भी मांग करता हूं।

सीएचसी धरियावद में सहकारिता दवाई भंडार का निर्माण करवाया जाये, जिससे कि कम कीमत पर वहां के लोगों को दवाई उपलब्ध हो सके। नवीन सीएचसी भवन में कैंटीन की सुविधा, धर्मशाला का निर्माण, पार्किंग की सुविधा, डॉक्टर एवं नर्स आवास का निर्माण किया जाये।

सीएचसी मुंगाना में बाउंड्री करवायी जाये। डॉक्टर एवं स्टाफ के आवास का निर्माण किया जाये। उप स्वास्थ्य केन्द्र दांतलिया में बाउंड्री का निर्माण किया जाये। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केसियावाद में बाउंड्री का निर्माण किया जाये। उप स्वास्थ्य केन्द्र चारणिया में बाउंड्री वाल का निर्माण किया जाये। साथ में, लसाडिया ब्लॉक के अन्दर अधिकतर पद खाली हैं, उन्हें भरवाने की मांग करता हूं। झिलारा के अन्दर एक सीएचसी है, लेकिन झिलारा में उसके अन्दर मोर्चरी नहीं है। कभी भी कोई डैथ हो जाती है तो पीएम करवाने के लिए हमें अधिकतर सलूम्बर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि धरियावद के अन्दर एक नर्सिंग कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज खोलने की कोई एक मांग हमारी पूरी की जाये। ताकि वहां के जो नौजवान आदिवासी भाई और बहनें हैं, उनको बाहर नहीं जाना पड़े। मैं आपके माध्यम से एक मिनट का समय और लूंगा।

मैं यह चाहूंगा कि हमारे वहां पर एनएचएम में आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो मेरे साथी कार्य कर रहे हैं, उसके अंतर्गत लगे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, सीएचओ जो दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सब सेंटर स्तर तक हैल्थ सेवा देते हैं, जो गैर संक्रामक रोगों को देखभाल से लेकर शिशु माता की देखभाल, भारत सरकार व राज्य सरकार की योजना से जुड़े कार्य को करते हैं। जिससे हैल्थ बैनेफिट हो रहे हैं। इन कार्मिकों की 2-3 जरूरी मांग हैं। एक तो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का कैडर 4800 पे ग्रेड जल्द से जल्द नियमित किया जाये। सीएचओ को जो अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि जो 15 हजार मिलती है, उसमें उच्च अधिकारियों द्वारा बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जाता है। इसलिए इस राशि को मूल वेतन में मर्ज किया जाये।

टीएसपी क्षेत्र के, अर्थात हार्ड टू रीच क्षेत्र में कार्यरत सीएचओ को महाराष्ट्र सरकार द्वारा 15 हजार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उसी प्रकार टीएसपी क्षेत्र के सीएचओ को भी राशि प्रदान की जाये।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका पुनः धन्यवाद करता हूं।

श्री सभापतिः श्री ललित यादव।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

पहला सुख निरोगी काया, इस सब्जेक्ट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। स्वास्थ्य जीवन है। स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य से परे ना उन्नति, अमन है। स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ समाज है। स्वस्थ समाज से विकसित राज्य है। विकसित देश बनाओ, चलो मिलकर आयुर्वेद को अपनाओ। आओ समझें अब असलियत, ना कम होने पाये शारीरिक मेहनत, अच्छे स्वास्थ्य के बिना सब व्यर्थ है। आज बनी सेहत सबसे बड़ी जरूरत है। मैं समझता हूं कि हम सबको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, पिछली सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान के उन तमाम गरीब व्यक्तियों के बारे में चिन्ता की और 25 लाख तक का इलाज फ्री देने का काम किया। राजस्थान में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने 25 लाख रुपये तक का इलाज का लाभ लिया। जो गवर्नमेंट अस्पतालों में लाइनों में खड़े रहते थे, वहां सुविधा का अभाव मिलता था। उनको निजी अस्पतालों में इलाज का अवसर दिया। आदरणीय अशोक गहलोत जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, उसके साथ-साथ जो 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा दिया, मैं

बहुत सारे साथियों को जानता हूं, जिनकी पारिवारिक हालत बहुत कमजोर थी। उनकी दुर्घटना में जान चली गयी। जान जाने के बाद, महज 7 या 10 दिन के अन्दर उनके खाते में 5 लाख रुपये सरकार ने डालने का काम किया। ऐसी महत्वपूर्ण योजना को मैं अभी समझता हूं कि हमें चालू रखना चाहिए। विकसित देशों की तर्ज पर उन्होंने यह काम किया था। राइट टू हैल्थ जैसा कानून लेकर के आये। जिससे प्रत्येक व्यक्ति का इलाज सुनिश्चित हो सके। ऐसा काम किया था।

सभापति महोदय, इस बजट में सरकार ने केवल स्कीमों का नाम बदलने का काम किया है। आप लोगों को स्कीमों के नाम बदलने में महारत हासिल है। मुख्य मंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का नाम आपने आयुष्मान योजना करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि योजना का नाम भले ही कुछ करो, लेकिन राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को इलाज मिल सके, राजस्थान के प्रत्येक उस अंतिम छोर के व्यक्ति को इलाज मिल सके, ऐसी योजना आप बनाओ कि कोई इलाज से वंचित ना रह सके। ऐसा काम आप लोग करें।

जब तक आम जन के स्वास्थ्य से सरोकार रखता है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार की तरह ही आप भी कोई योजना लेकर के आओ। आपकी भी तारीफ इसी सदन में खड़ा होकर के ललित यादव इससे भी तेज आवाज से करेगा। लेकिन आप लोग नहीं करोगे। आप स्वास्थ्य पर चिंता नहीं करोगे तो आपके खिलाफ बोलने का काम भी हम लोग करेंगे।

पूर्ववर्ती सरकार ने, पिछली सरकार जो थी, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के ऊपर पूंजीगत व्यय में 11 परसेंट खर्च करने का प्रावधान रखा था। आपने तो 9 परसेंट ही रखा है। आपने कम करने का काम किया है। लगता है पूंजीवादी सोच की सरकार महलों में बैठकर के काम किया है।

सभापति महोदय, मैं 7 मिनट बोलना चाह रहा हूं, बोलने दो। सरकार को चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरा एक सुझाव है कि हॉलिस्टिक बनानी चाहिए और पोषण आहार का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए पब्लिक हैल्थ मैनेजमेंट कॉडर की स्थापना करनी चाहिए।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक नर्सिंग महाविद्यालय की भी घोषणा आपको करनी चाहिए। मेरे मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र के हैडक्वार्टर का जो सीएचसी है, वह 1993 से अब तक केवल 30 बेड का अस्पताल है। वहां पर लोगों का इलाज उपलब्ध कराने के लिए आप लोग उसको उप जिला अस्पताल का दर्जा दें, क्योंकि वहां 400, 450 और 500 तक की ओपीडी होती है।

Spp/Rtm/19.07.2024/20.50/4m

मेरे शाहजहांपुर में जो अस्पताल है, वह सी.एच.सी. है, हाईवे के नजदीक लगता हुआ है

और रोज दुर्घटनाएं होती हैं, उसको भी सरकार उप जिला अस्पताल बनाने का काम करे। मेरे ततारपुर में सी.एच.सी. है, उसको भी अपग्रेड करने का काम आप लोग करें। मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शाहजहांपुर के अन्दर जो सी.एच.सी. है, उसको ट्रोमा सेंटर बनाने का काम करें और शाहजहांपुर में जहां पहले अस्पताल चलता था, वह किसी दानदाता ने दान दिया था। हम लोग उसके लिये भी वापस विचार करें, जिससे कि वह हमारे काम आ सके। मैं एक बार पूरे सदन का ध्यान चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, हम खाद्य सामग्री के ऊपर जरूर चिंता करें। पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था कि बड़े-बड़े DMART, सोढ़ानी स्वीट, रावत कचौरी जैसे प्रतिष्ठानों की बड़ी-बड़ी दुकानें खोल रखी हैं और जहर बेच रहे हैं। हम सब लोग चिन्ता इस बात की करें अगर कोई व्यक्ति किसी के गोली मार देता है तो वह वहीं मरकर ढेर हो जाता है। यह तो रोज मारने का काम कर रहे हैं। यह रोज जहर खिला रहे हैं। सरकार इस पर चिन्ता करे और सरकार कानून बनाये। कानून बनाकर कड़ी से कड़ी सज़ा देने का काम करे। आई पी सी की गंभीर धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज करने का काम करें। क्योंकि जब तक सरकार इनके लिये कोई कानून नहीं बनायेगी, मैं समझता हूं लोग इसी प्रकार जहर बेचते रहेंगे। इनके ऊपर जुर्माना भी कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। मैंने पढ़ा है पिछले दिनों 97-98 लोगों की जांच हुई और केवल 80 लाख के समथिंग उन पर जुर्माना किया है, तो एक लाख से भी कम जुर्माना करने का सरकार ने काम किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार इस पर विचार करने का काम करे। एक सी एच ओ. कम्युयनिटी हैल्थ आफिसर को भी आप नियमित करने का काम करें। केन्द्र सरकार की भी इसमें गाइड लाइन आयी है कि इनको परमानेंट करने का काम किया जाये। मेरा आपसे एक और निवेदन है कि आपकी भी बात करूंगा। मैं एक मांग करूंगा मेरे मुण्डावर में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं जिसमें सीनियर नर्सिंग आफिसर 10 पद हैं, नर्सिंग आफिसर, फार्मासिस्ट, एल एच वी, वार्ड ब्वॉय जैसे बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। इन सब पदों को भरने का काम करें । ..(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आपका हो गया, विराजें। श्री छोटूसिंह भाटी। ..(व्यवधान)..

श्री ललित यादव (मुण्डावर): जिससे कि वहां पर इलाज की सुविधा मिल सके और आमजन को, गरीब आदमी को इलाज का अभाव नहीं झेलना पड़े। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री छोटूसिंहजी।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 व 28 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपका बहुत बहुत साधुवाद व बहुत बहुत आभार। ..(व्यवधान)..

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व

मांग संख्या 28 – चिकित्सा शिक्षा पर विचार

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें हम पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस राजस्थान प्रदेश की आठ करोड़ जनता का कैसे स्वस्थ जीवन व्यतीत करवायें। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आज के इस बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने और माननीय चिकित्सा मंत्री ने पूरे बजट का 8.26 प्रतिशत इस चिकित्सा बजट के अन्दर घोषणा की, इसके लिये आपको बहुत-बहुत साधुवाद व धन्यवाद।

मान्यवर, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 2013 से लेकर 2018 तक मैं इसी विधान सभा भवन के सदन के अन्दर विधायक था और उस समय इस पवित्र सदन में जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र के बडोडा गांव में एक पी एच सी की घोषणा हुई थी। माननीय प्रतिपक्ष के नेता पूरे पांच साल बीत गये वहां एक कमरा भी नहीं बनाया। यह राजनीति की। आपकी राजनीति ऐसे विभाग पर नहीं होनी चाहिये। मानव जीवन से जुड़ा हुआ यह विभाग है। यह स्वस्थ रखने वाला एक विभाग है। माननीय सभापति महोदय, बहुत कुछ मांगें होती हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं लेकिन चिकित्सा विभाग एक ऐसा विभाग है, जिससे आमजन उसकी व्याकुल स्थिति के समय वह किस परिस्थिति के अन्दर हॉस्पिटल जाता है और वहां जाने के बाद उसको भर्ती के लिये कोई कमरा भी नहीं मिलता है तो उसको क्या महसूस होता होगा।

(समय :   )

(श्री फूलसिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

उस गांव में कांग्रेस के भी सदस्य हैं, बीजेपी के भी हैं तो फिर माननीय उसमें राजनीतिकरण क्यों हुआ? यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपने भी बहुत कुछ काम किये होंगे और यदि अच्छे काम किये होते तो आपको यह अवसर नहीं मिलता। हमको अच्छे काम करने का अवसर मिला है और हम पांच साल लगातार यह बता देंगे कि आम अवाम का जो यह बजट बना है, यह आमजन के लिये अच्छा होगा और हम सब मिलकर इसका फायदा आम जनता तक पहुंचायेंगे।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा तो नहीं बोलता। यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर एक सीमांत क्षेत्र है। एक दीवार बनकर यह पूरे राजस्थान की पश्चिमी दीवार के रूप में खड़ा है और वहां मूलभूत चिकित्सा की सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं तो बड़ा

अफसोस होता है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं और माननीय उप मुख्य मंत्रीजी को और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी को, कि मेरे यहां लाखा गांव एक ऐसा गांव है जो बिलकुल सीमांत पर है, वहां पर पी एच सी की घोषणा की गयी।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही आजकल नशे की प्रवृत्ति नवयुवकों के अन्दर आई हुई है। आपने 25 बैड का नशामुक्ति का भी एक केन्द्र खोला है, इसके लिये भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सी कमियां जैसलमेर में और भी हैं। मैं गांव का नाम नहीं लेता बहुत सारी कमियां हैं। कोई मरीज को पी एच सी में आने के लिये कम से कम 30-40 किलोमीटर आना पड़ता है और मेरा गांव पूनम नगर है जिसमें मैं रहता हूं। 20 साल हो गये वहां पी एच सी बनी हुई है और आज तक सी एच सी नहीं हुई। वह 50 गांवों से घिरा हुआ एक सेंटर गांव है लेकिन वहां सी एच सी नहीं होने के कारण कई लोगों को जैसलमेर जाना पड़ता है। जैसलमेर की दूरी आप समझ लो 80-100 किलोमीटर है, क्योकि मेरा खुद का क्षेत्र है वह 350 किलोमीटर वृत्ताकार का एरिया है। उसमें मैं एकमात्र विधायक हूं। मैं माननीय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सीमांत और भौगोलिक स्थिति को देखते हुये जैसलमेर जिले को चिकित्सा के अन्दर विशेष पैकेज देने की आप घोषणा करें। बहुत सारी ढाणियां और गांव ऐसे हैं, जहां अभी उप स्वास्थ्य केन्द्र भी वहां नहीं हैं और न ही वहां पर स्टॉफ रहना चाहता है। उसका कारण यह भी है कि सीमांत क्षेत्र में बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं। चाहे वह पानी सम्बन्धी हो, बिजली सम्बन्धी हो, मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिलती हैं, इसलिये नहीं रहना चाहते।

(समय :   )

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि पहाड़ी इलाके में जैस कर्मचारियों को पहाड़ी भत्ता दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से सीमांत के गांव चाहे वह बाड़मेर हो, चाहे गंगानगर हो, चाहे जैसलमेर हो, उन लोगों को विशेष पैकेज दिया जाये। इससे वहां पर डॉक्टर्स का ठहराव होगा, ए एन एम का भी ठहराव होगा, शिक्षकों का भी ठहराव होगा, क्योंकि वह ढाणियों में रहते हैं। आदरणीय मेरा निवेदन है जैसलमेर के लिये विशेष प्रकार के पैकेज की घोषणा करें। यही नहीं मेरा जैसलमेर मुख्यालय का हॉस्पिटल है, वह बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन वहां पर भी आदरणीय आज यदि देखा जाये तो वहां पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, नेत्र रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, नाक, कान और गले का कोई डॉक्टर नहीं है, पैथोलॉजी का डॉक्टर नहीं है, मनोरोग का कोई डॉक्टर नहीं है और यहां तक कि नर्सिंगकर्मी भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय दो मिनट ज्यादा हो गये।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप टेबल कर दो।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट आप दो। बंदे की

थोड़ी बात सुनो, आदरणीय, सीमांत क्षेत्र से आता हू।

श्री अध्यक्ष: आधे मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): सीमांत का रहने वाला हूं। अपनी व्यथा बताना चाहता हूं। यह भी नहीं, यह मेरी मांग है ताकि वह इसका समाधान करें। साथ में आदरणीय मैं निवेदन करना चाहता हूं। कल एक माननीय सदस्य ने लीक से हटकर पूरे राजस्थान में जातिगत माहौल खड़ा करने का प्रयास किया है, यह अशोभनीय है। क्षत्रियों का इतिहास दुनिया जानती है। किसी भी समाज को इस प्रकार से टार्गेट करते रहना यह स्वीकार्य नहीं है। ...(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: श्री भगवाना राम जी, पांच मिनट हैं, आप बोलिये।

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): किस प्रकार की हिदायत दी जाये। यह पवित्र सदन है इसमें नहीं बोलना भी गुनाह है और असत्य बोलना भी गुनाह है। सत्य के लिये बोलेंगे और आपसे निवेदन करेंगे आदरणीय व्यवस्थाओं को देखते हुये जैसलमेर के लिये विशेष पैकेज की घोषणा की जाये ताकि वहां चिकित्सा व्यवस्था हो सके। आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री भगवाना राम।

श्री भगवाना राम सैनी (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने चिकित्सा और स्वास्थ्य पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। साथ ही मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे पूर्व मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र को बहुत कुछ दिया। इसके लिये उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही उदयपुरवाटी को चार सी एच सी, पी एच सी और सब-सेंटर इतने दिये हैं, बहुत कुछ दिया है। लेकिन हमारे माननीय सभापति महोदय, हमारे स्वास्थ्य मंत्रीजी यह सोचेंगे कि कुछ मांगा नहीं। दो केड एवं भांवरेसी पी एच सी है और एक मणकचास है।

MLS/RTM/19.07.2024/21:00/4n

शानदार भवन हैं। अगर उन्हें पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि उदयपुवाटी में 4 सीचएचसी हैं, उनमें उदयपुरवाटी में पांच पद रिक्त हैं, पौंख में दो पद रिक्त हैं, गुढा गोड़जी में दो पद रिक्त हैं और बड़ागांव में तीन पद रिक्त हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, 5-6 लाख की आबादी वाला यह उदयपुरवाटी, इसमें एक भी फिजीशियन का पद भरा नहीं है। एक भी फिजीशियन नहीं है आज की तारीख में। कितना दुर्भाग्य है, मैं ग्रामीण एरिया से आता हूं।

अभी हमारे धोद से गोरधन जी बोल रहे थे, उन्होंने गांव की बात की, अगर गांव में थोड़ी सी चिकित्सा सुविधा ठीक हो जायेगी तो बहुत सुधार होगा। उनको बहुत तकलीफ होती है। शहरों में तो फिर भी मिल जाती है, लेकिन गांवों में आदमी को सुविधा बहुत कम मिलती है। अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, ज्यादा मेरी डिमांड नहीं है, थोड़ा सा सुधार हो

जाये, ग्रामीण पीएचसी, सीएचसी में थोड़ा सा सुधार हो जाये तो बहुत बड़ा लाभ होता है गरीब आदमी को। जैसे जांच का विषय है, वहां मशीनें हैं, वह जांच वहां होती है, उसी से काम चल जाता है, कुछ मशीनें खराब पड़ी हैं, थोड़ा सा निवेदन है कि यदि मशीनों में सुधार हो जाये तो लोगों को सीधा लाभ होता है।

दूसरा यह है कि ग्रामीण एरिया में डॉक्टर जांच करते हैं, यह ध्यान देने की बात है कि मरीज जांच के लिए जाता है 8 बजे और जांच के लिए उसे टाइम दे दिया जाता है 1 बजे का। पेशेंट एक बजे तक कैसे रुकेगा? जैसे हम प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं तो जांच की रिपोर्ट एक घण्टे में दे देते हैं और मरीज दिखाकर आ जाता है। हमारे सरकारी अस्पतालों में जांच का समय 12 बजे या 1 बजे देते हैं, इतनी देर में आपके डॉक्टर घर चले जाते हैं। फिर वही दुकानदारी शुरू हो जाती है। इससे बड़ा नुकसान होता है ग्रामीण एरिया में। मेरी मांग है कि आप छोटे से आदेश से यह जांच एक घण्टे में क्यों नहीं करके दे सकते? अपन भी तो दे सकते हैं। अगर समय पर जांच मिल जाये तो लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा।

दूसरी, मेरी एक बहुत बड़ी डिमांड है। उदयपुरवाटी नगरपालिका, जहां 60-70 हजार की जनसंख्या है और दो स्टेट हाईवेज हैं, जयपुर से वाया उदयपुरवाटी झुंझुनूं और एक नागौर-जोधपुर से दिल्ली। बहुत बड़े एक्सीडेंट होते हैं वहां। कुछ दिन पहले वहां मनसा माता में 7 मौतें हुई थीं एक साथ और गुढा गोड़जी में 10-11 मौतें हुई थीं। हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने ट्वीट करके शोक प्रकट किया था। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि वहां हमारा ट्रोमा सेंटर बनकर तैयार हो गया है, शानदार भवन तैयार हो गया है, सिर्फ संसाधन हों तो वहां बहुत से लोगों की जान बचायी जा सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मंत्री महोदय थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि वहां कई सालों से डिमांड है और बहुत बड़ा कस्बा है, वहां एक्सीडेंट होते हैं तो उन्हें सीकर या जयपुर लाया जाता है। वहां आस-पास में मरीज को दिखाने की कोई ऐसी जगह नहीं है। बड़ा मन करके, यह टोमा सेंटर तो बहुत जल्दी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और तो खैर ठीक है सारा काम।

एक डॉक्टरों की जो प्रैजेंस है, उपस्थिति है, वह ठीक नहीं है। जो डॉक्टर लगे हुए हैं, वे भी टाइम पर नहीं आते। समय के लिए सीसीटीवी कैमराज वगैरह जो मशीनें हैं, उनका प्रावधान कर दें तो अच्छा रहेगा।

सही मायने में यह होता है कि रात को जब पेशेंट या डिलीवरी जाती है तो देखने की बात तो दूर रही डॉक्टर लोग खोलते भी नहीं हैं। मैं सिर्फ इतना सा निवेदन करूंगा कि वहां उन लोगों को डिलीवरी वगैरह के लिए पाबन्द करें। इससे लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा होगी। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रशान्त शर्मा।

श्री प्रशान्त शर्मा (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुदान की मांग संख्या 27 व 28 पर विचार रखने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अंग्रेजी

में कहा जाता है, "When your health is good, only then you can experience true happiness." माननीय अध्यक्ष जी, वैश्विक महामारी कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है तथा इन चुनौतियों का सामना करने के पश्चात् विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ-साथ देश और प्रदेश की सरकारों ने इस ओर गम्भीरता से ध्यान देना प्रारम्भ किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गत विधान सभा चुनाव और लगातार सतत जन सम्पर्क के दौरान लोगों के सुख-दुःख में शामिल होते समय मैंने यह अनुभव किया कि कोरोना महामारी के पश्चात् युवा, मध्यम एवं अल्पायु वर्ग में भी इन दिनों साइलेंट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियां आमतौर से बढ़ रही हैं, साथ ही पोस्ट कोविड का प्रभाव भी लोगों में देखने को मिल रहा है। यह स्थिति निश्चय ही चिन्ताजनक है। इस विषय में मेरा आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी से यह आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजकीय चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर आम व्यक्तियों के रक्त एवं स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच करवाकर उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सजग व जागरूक बनाया जाना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र आमेर के विषय में मेरा आग्रह है कि आमेर के विभिन्न सैटेलाइट एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला प्रसूति रोग विशेषज्ञ नियुक्त किये जाएं तथा इस स्तर के तमाम अस्पतालों में सोनोग्राफी और अन्य जांचों की व्यवस्था आवश्यक रूप से किये जाने की मैं मांग करता हूं। आमेर का सैटेलाइट अस्पताल पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग में चल रहा है, इसलिए वहां अधिक निर्माण नहीं हो सकता। अतः मैं वहां एक नवीन भवन की मांग भी करता हूं।

इसके अतिरिक्त अचरोल स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भूमि आवण्टन किया जा चुका है, पर भवन निर्माण अभी तक नहीं हो सका है तथा यह अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वाले भवन में ही संचालित है। गत सरकार के बजट में जयपुर के चारों ओर सैटेलाइट अस्पताल बनाने की घोषणा की गयी थी, तब अचरोल का नाम भी सैटेलाइट अस्पताल के रूप में घोषित हुआ था, किन्तु नयी सरकार के गठन के उपरान्त इसमें अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई।

मेरे विधान सभा क्षेत्र आमेर से होकर दिल्ली, बीकानेर आदि राजमार्ग गुजरते हैं, यहां एक ट्रोमा हॉस्पिटल की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि चंदवाजी में एक ट्रोमा हॉस्पिटल की स्थापना की जाये। इसके साथ ही, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ 24 घण्टे उपलब्ध कराने की भी आपसे मांग करता हूं।

साथ ही, विधान सभा क्षेत्र के सभी उप-स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैटेलाइट हॉस्पिटल में चिकित्साधिकारी, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, हड्डी रोग विशेषज्ञ, महिला प्रसूतिविशेषज्ञ, हृदय रोग, अस्थमा रोग, सीनियर नर्सिंग अधिकारी, नर्सिंग अधिकारी, एएनएम, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉयज आदि रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति दिलवाने की भी मांग करता हूं।

मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आमेर में ब्लॉक सीएमएचओ खण्ड कार्यालय के भी

भवन उपलब्ध नहीं हैं। इस हेतु भूमि आवण्टन भी नहीं हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र आमेर में तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहित चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र आमेर में लगभग 20 उप-स्वास्थ्य केन्द्र भी भवन रहित हैं। कृपया, इनके लिए भवन की व्यवस्था हो। उप-स्वास्थ्य केन्द्र कांठ व भीलपुर में भवनों की मरम्मत हेतु चिकित्सा बजट जारी किया जाये।

पूर्ववर्ती सरकार ने राइट टू हैल्थ कानून बनाया, जिससे इमरजेंसी में फ्री इलाज मिल सके। मुख्य मंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी लागू की। वर्तमान में माननीय मुख्य मंत्री जी के नाम से ''मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना'' की घोषणा की गयी, लेकिन उसमें वित्तीय सीमा के बारे में भ्रम की स्थिति है, उसे स्पष्ट किया जाना चाहिये।

कुल-मिलाकर हम यह जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में अच्छा कार्य किया, वर्तमान सरकार भी चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि करे। अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करने के लिए एक बार पुन: मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हरलाल सहारण।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय मंत्री जी ने मुझे 10 मिनट दिये हैं, इसलिए कृपया 10 मिनट बोलूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे मांग संख्या 27 व 28 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, स्वस्थ शरीर ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है, इसलिए कहा गया है, ''पहला सुख नीरोगी काया।''

mkd/rtm/19.07.2024/21:10/4o

धन्यवाद चिकित्सा मंत्री जी को, जिन्होंने इस बजट में प्रदेश के नागरिकों का स्वास्थ्य सुखी एवं खुशहाल हो, इसके लिए कई क्रांतिकारी घोषणा की है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी को, जिन्होंने बजट में प्रदेश की चिकित्सा सुविधा के लिए करीब 27 हजार 660 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यानी, पूरे बजट का 8.26 प्रतिशत का प्रावधान किया है, पहली बार ऐसा बजट हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, ठीक इसी प्रकार बजट वर्ष 2024-25 के पेज नम्बर 64 पर पैरा नम्बर 73 में प्रदेश की सुविधाओं के विस्तार हेतु मुख्य मंत्री आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य मिशन प्रारम्भ करने की घोषणा की है, जिसमें आगामी तीन वर्षों में 15 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। चिकित्सा संस्थाओं की क्रमोन्नति, भवन निर्माण व रख-रखाव जैसे कई मिशन प्रदेश भर में हो सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, बजट वर्ष 2024-25 के पेज नम्बर 66 पर पैरा नम्बर 73 में चूरू स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी हॉस्पिटल खोलने की घोषणा की। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री भजनलाल जी का, वित्त मंत्री जी का, चिकित्सा मंत्री जी का धन्यवाद

करूंगा। चूरू में कई वर्षों से मांग थी और बड़ी-बड़ी घोषणा करने वाले कह रहे हैं, उसके बाद यह सुविधा हुई है। चूरू शहर की पुरानी मांग पूरी की है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में बजट देकर राहत प्रदान करेंगे।

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही हैं, हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा, जिस दिन अख़बार की सुर्खियों में एक्सीडेंट नहीं छपता होगा। आंकड़े के अनुसार 2023 में प्रदेश में 24,705 दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 11,700 लोगों की मृत्यु हुई है।

अध्यक्ष महोदय, आज जब सदन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही है तो हमें वैश्विक महामारी कोरोना के कालखण्ड को नहीं भूलना चाहिए। समूचे मानव जीवन पर संकट मंडरा रहा था। कई देशों की इकॉनोमी तबाही के कगार पर पहुंच गई थी। बड़े शक्तिशाली देशों ने कोरोना में घुटने टेक दिये थे लेकिन हिन्दुस्तान ने कोरोना की जैसी विपरीत परिस्थिति में भी घुटने नहीं टेके और सभी देशवासियों ने बीमारी का डटकर मुकाबला किया।

अध्यक्ष महोदय, कोरोना के समय अपने जीवन की परवाह किये बिना डॉक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ आदि कर्मियों ने 24 घंटे मानव सेवा की। कोरोना योद्धाओं ने मेहनत की। जिससे लाखों लोगों का जीवन बचना सम्भव हुआ। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में अस्पतालों में सभी तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया और कोरोना योद्धाओं को हौसला कभी टूटने नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी थी। जब ऑक्सीजन की कमी थी तब चूरू में प्लांट नहीं था, न एक सिलेंडर था, उस समय माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री राजेन्द्र राठौड़ ने राजस्थान में एक ऐसा सरकारी हॉस्पिटल था, जिसमें 72 लाख की लागत से अपनी जेब से, अपने सहयोग से चाइना से प्लांट लाकर लगाया था। उसका नाम था पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेन्द्र राठौड़। राजस्थान में किसी भी सरकारी अस्पताल में पहला प्लांट चूरू में लगा, जिन्दगी बची, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

आम तौर पर वैक्सीन में वर्षों लग जाते थे। इतने कम समय में दो मेक इन इंडिया वैक्सीन तैयार कर कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोक लगाने में सफलता पाई। भारत ने वैक्सीन का अभियान चलाया व जरूरतमंद देशों को वैक्सीन दी लेकिन बड़े दुर्भागय की बात है कि विपक्षी दल वैक्सीन के नाम पर जनता को गुमराह कर कोरोना की आपदा को अवसर बनाया।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने 2014 से पहले, ये बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, 2014 से पहले आजादी के 70 साल बाद में 7 एम्स का निर्माण किया, जबकि मोदी जी ने 23 कर दिये। 2014 में भारत में 400 मेडिकल कॉलेज थे, मोदी जी ने बढ़ाकर 700 कर दिये हैं। 2014 में एमबीबीएस की पचास हजार सीटें थीं, एक लाख कर दीं। राजस्थान में 2014 से पहले 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 24 हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में चिकित्सा पर चर्चा करने के दौरान चिकित्सा मंत्री जी के

सामने मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगे रखना चाहूंगा। खासोली में पीएचसी को क्रमोन्नत किया जाये। आसलखेड़ी, कुणसीसर, रायपुरिया में पीएचसी को क्रमोन्नत किया जाये। चूरू मेडिकल कॉलेज में राजमेस में 2015 में बिल्डिंग बनाने के कार्य स्वीकृत हुए थे, उसके बाद 2018 में शिक्षण संस्था शुरू हो गई, लेकिन बिल्डिंग व्यवस्था नहीं होने से शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है। मेरी मांग है कि बिल्डिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। एजेंसी व ठेकेदार को भुगतान के अभाव में काम बन्द पडा है। चूरू मेडिकल हॉस्पिटल का कार्य धीमी गति से चल रहा है। ये कार्य किये जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने बार-बार मोदी जी के नाम पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः हो गया, धन्यवाद। श्री भीम राज भाटी। आप पांच मिनट में बात पूरी करें।

श्री भीम राज भाटी (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं दो मिनट में ही खत्म कर दूंगा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सोचता हूं, आई थिंक आई एम द लास्ट।

श्री अध्यक्षः नहीं, एक और हैं। मुझे उत्तर भी दिलवाना है।

श्री भीम राज भाटी (पाली): एक और हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पाली शहर में आधा शहर एक तरफ है, वहां एक सेठ रूपचंद जी सर्राफ का हॉस्पिटल है, वहां अच्छे इक्विपमेंट सप्लाई करके, उस हॉस्पिटल को क्रमोन्नत कर दिया जाये तो आधे शहर को बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी। वह नाड़ी मोहल्ले में स्थित है।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि पाली डिविजन हैड क्वार्टर डिक्लेयर हो चुका है। डिविजन हैड क्वार्टर पर, हालांकि मुझे नहीं मांगना चाहिए, मैं खुद रोटेरीयन हूं, रोटरी ने पाली हॉस्पिटल के लिए बहुत काम किया है लेकिन पाली हॉस्पिटल, बांगड़ हॉस्पिटल के लिए एक वैल एक्यूपाइड एयर कंडीशन एम्बुलेंस यदि चिकित्सा मंत्री उपलब्ध करा दे, राज्य सरकार उपलब्ध करा दें तो बहुत बड़ी कृपा होगी।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक चेंडा, हमारे रोहट क्षेत्र में चौराई एरिया है, उस चौराई एरिया के सेंटर में एक चेंडा गांव है, उस चेंडा गांव में सबसे पुरानी पीएचसी है। जब राज्य सरकार ऑलरेडी एक पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत कर रही है तो उस चेंडा की पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक बॉर्डर पर गांव हैं, बाड़मेर, जालोर और पाली के बॉर्डर पर गांव है, पाथी और हंजावा, उस पाथी और हंजावा में चिकित्सा की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। उस पाथी गांव में चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करा दी जाये तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं तो मंत्री महोदय के गांव खींवसर हर महीने जाता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बांगड़ हॉस्पिटल में हालत यह है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन उस हॉस्पिटल में किसी अच्छे डॉक्टर को रहने नहीं दिया जाता है। पिछले कई

सालों से यही स्थिति बनी हुई है। कोई भी मरीज जाता है, किसी भी छोटे-मोटे दर्द में भी मरीज जाता है तो उसको सीधे रेफर कर दिया जाता है। लोगों ने उसका नाम रेफरल हॉस्पिटल रख दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उस बांगड़ हॉस्पिटल में जो ब्लड बैंक है, उस ब्लड बैंक में इतना भ्रष्टाचार है। अपन पर्ची की बात करते हैं। मुझे पर्ची की बात नहीं करनी चाहिए लेकिन उस बांगड़ हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में पर्ची के सिवाय किसी भी जरूररतमन्द को ब्लड नहीं दिया जाता है। उस ब्लड बैंक में बड़े-बड़े लोग, वहां पाली में लोग घर पर दवाइयां सप्लाई करते हैं, दवाइयां बांगड हास्पिटल की हैं, दवाइयां इंडियन रेड क्रोस सोसायटी की, बिना डॉक्टर की पर्ची पर लोग अपने खुद के निजी निवास से लोगों को दवाइयां बांटते हैं और लाइन लगाकर दवाइयां बांटते हैं। वे दवाइयां बांटकर उसका कोई लाभ लेने की चेष्टा करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं ये बांगड़ हॉस्पिटल में कई मशीनें खराब पड़ी हैं। मैंने अभी क्वेश्चन किया था, उनकी लिस्ट आई है। बड़ी-बड़ी 15-20 मशीनें खराब पड़ी हैं। कई समय से खराब पड़ी है। उन मशीनों को जान-बूझकर ठीक नहीं कराया जा रहा है। इसलिए नहीं ठीक कराया जा रहा कि डॉक्टर बाहर के निजी चिकित्सालय हैं, उन निजी चिकित्सालय पर चिट्ठी लिख देते हैं, उस निजी चिकित्सालय से मरीज अपने टेस्ट कराकर रिपोर्ट ले आये, तो निजी हॉस्पिटल को पनपाने के लिए बांगड़ हॉस्पिटल की मशीनों को खराब कर रखा है। उनको ठीक करने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है।

एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई सबसे दर्दनाक बात यह है, हम कोरोना की बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में कोरोना के समय में रेमडेसिविर इंजेक्शन और सांप काटने के जो इंजेक्शन है, उन्हें खुले आम लोग अपनी जेबों में लेकर घूमते थे और बड़े से बड़े अधिक से अधिक पैसे लेकर उन रेमडेसिविर इंजेक्शनों एवं सांप काटने के इंजेक्शनों को लगाने का काम कर रहे थे।

एक छोटा निवेदन और है। मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी की वजह से, मेडिकल कॉलेज की सीटें घटा दी गई हैं। इसलिए मैं आपके मार्फत चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि स्टाफ की कमी की पूर्ति कर दें तो वे सीटें कम न हों। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री मनीष यादव।

Bhs/Rtm/19.7.24/21.20/4p

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा बोलने का आपने अवसर दिया, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि स्वास्थ्य का जो राजस्थान का ढांचा है उसको लेकर के हमको इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं राजधानी का रहने वाला हूं और लम्बे समय से एसएमएस जैसा जो प्रदेश

का हमारा सबसे बड़ा अस्पताल है उस अस्पताल के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। एक ऐसा अस्पताल मैं कहूंगा कि एशिया में सबसे ज्यादा अगर वर्ष में कोई ओपीडी होगी तो हमारे एसएमएस अस्पताल की होगी। बहुत जगहों से इलाज कराने अलग-अलग राज्यों से लोग भी हमारे यहां पर इलाज कराने आते हैं और एक अच्छा हमारे अस्पताल का लम्बे समय से जो हमारे एसएमएस होस्पिटल का, सरकारें भले ही किसी की हो, किसी की आये, किसी की जाये लेकिन हमारा जो अस्पताल है उसका नाम पूरे देश में है।

आज हम आये दिन देखते हैं न्यूज पेपर में भी कई बार पढ़ते हैं कि मरीज और चिकित्सक के बीच में कोई छोटी-मोटी बात हो गई, सरकार और चिकित्सक के बीच में या जो हमारे एसएमएस अस्पताल के विशेषज्ञ हैं या फिर वहां का अस्पताल का प्रशासन है उनके बीच में कोई बात हो गई तो कई बार हड़ताल की स्थिति बन जाती है, प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा जाती है और एसएमएस जैसा अस्पताल भी प्रभावित होता है। बहुत सारे मरीज ऐसी स्थिति में ऐसे हालात में जिस इच्छा के साथ इलाज कराने आते हैं उनको निराशा महसूस होती है।

मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान इसलिये आकर्षित करना चाहता हूं कि यह किसी सरकार ने अच्छा किया या किसी सरकार ने गलत किया, किसने बजट कितना दिया, कितना नहीं दिया लेकिन यह प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है क्योंकि हमारे लिए बहुत आवश्यक है इसलिये हम सब लोगों को इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि चिकित्सक और सरकार के बीच में हमेशा एक ऐसे समन्वय की स्थापना की जाए जिससे मरीज को कभी सफर नहीं करना पड़े, प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था चरमराये नहीं। ये हालात इसलिये भी कई बार बिगड़ जाते हैं क्योंकि बहुत सारा मैं आये दिन देखता हूं कि हमारे एसएमएस अस्पताल की ओपीडी प्रत्येक दिन दस हजार के लगभग रहती है वहां पर चिकित्सा सेवाएं बहुत अच्छी हैं लेकिन और पद बढ़ाये जायें ताकि हमारा जो अस्पताल है वह और अच्छे से बने।

अध्यक्ष महोदय, आज अगर पूरे जयपुर का हम देखेंगे तो ट्रेफिक व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, कई बार आपात स्थिति में मरीज पहुंच नहीं पाता है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे जयपुर के सराउंडिंग जो राजमार्ग हैं उन पर भी हमको ट्रोमा होस्पिटल की स्थापना करनी चाहिये जिससे आपातकाल स्थिति में अगर कोई मरीज आ गया और वह एक्सीडेंट केस है, इमरजेंसी में शहर में आकर के ट्रेफिक में फंस जाता है तो ऐसे हालात के बारे में आने वाले समय में इसकी चर्चा हमको करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मोटे रूप से मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र पर चर्चा करना चाहूंगा। मेरे शाहपुरा का उप जिला अस्पताल जिसकी ओपीडी लगभग दो हजार है और वहां पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिये वो बहुत पर्याप्त नहीं हैं। पिछली सरकार के बजट में और इस सरकार के बजट में भी ट्रोमा अस्पताल का जिक्र है। अभी उसका अस्तित्व नहीं है, वह बन नहीं पाया है उसकी शुरूआत भी नहीं हुई है। हमारे अस्पताल में बहुत सारी घटनाएं भी कई बार हो जाती हैं तो वहां पर पुलिस चौकी की स्थापना को लेकर भी मंत्री महोदय, आपका ध्यान

आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे वहां पर ब्लड बैंक खुले। हमारे शाहपुरा अस्पताल में ब्लड बैंक बनना बहुत आवश्यक है। हमारे विधान सभा क्षेत्र के तिगरिया में जो उप स्वास्थ्य केन्द्र है उसको पीएचसी में क्रमोन्नत किया जाये। हमारे अमरसर जो हमारे स्टेट हाईवे पर है बहुत बड़ा स्थान है सीएचसी है, उसको वहां की परिस्थिति को देखते हुए उप जिला चिकित्सालय बनाया जाये। हमारे खोरा लाडखानी पीएचसी को सीएचसी में बदला जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): एक मिनट, अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष: आधा मिनट।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): हमारे जो शाहपुरा के चिकित्सा के जो पद रिक्त हैं हमारे वहां पीएचसी और सीएचसी एसडीएच में चिकित्सा अधिकारियों के 81 पद स्वीकृत हैं जिनमें 16 पद रिक्त हैं, आप जल्द से जल्द उनका अच्छे चिकित्सकों का पदस्थापन करा करके वहां जनता को लाभ दें। हमारे वहां पर नवीन नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएं क्योंकि यह जयपुर ग्रामीण का बहुत लम्बा क्षेत्र है जहां पर बेहद आवश्यकता है कि वहां पर नर्सिंग कॉलेज खुले। हमारे अमरसर में एक एएनएम ट्रेनिंग सेन्टर है जिसका भवन जर्जर है उस भवन का जीर्णोद्धार जल्द से जल्द किया जाए और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार की चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिये उसको लेकर के प्रदेश की सरकार को बहुत गम्भीर होकर के उस पर काम करना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मैं मंत्री जी को जवाब देने के लिए कहूं, माननीय मंत्री जी, एक मिनट, उसके पहले मैं दोनों दलों के सचेतक, हमारे संसदीय मंत्री और यहां के विपक्ष के नेता से आग्रह करूंगा कि जो लोग कम से कम चर्चा में भाग ले रहे हैं वो उत्तर सुनने के लिए तो रुकें और अधिकांश लोग चले गये, अब देखिये जितनी संख्या में सदस्य बोले, उत्तर सुनने के लिए बहुत कम हैं तो यह दोनों सुनिश्चित करें कि आगे से अधिक से अधिक लोग रहें और सारे मंत्री लोग तो कम से कम उस समय यहां पर आयें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपके आदेश की पालना होगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज एक मैराथन डिमाण्ड्स पर डिबेट हुई, सुझाव आये और हमारे काफी वरिष्ठ लोग थे यहां पर। सराफ साहब जो खुद हैल्थ मिनिस्टर रहे हुए हैं और हमारी कई लेडीज, कई डॉक्टर्स भी थे, तो मैं स्वागत करता हूं आपके सुझाव और आपकी पार्टी और हमारी पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि ह्युमन सफरिंग को कैसे हटायें और चाहे कोई भी पार्टी पावर में आये हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिये, to help human suffering. बिजली नहीं हो, पानी नहीं हो तो आदमी फिर भी मैनेज कर सकता है कई दिन तक लेकिन एक सांस ऐसी चीज होती है कि वह कुछ क्षण में अगर बॉडी फंक्शन नहीं करे तो एक

अमूल्य जीवन चला जाता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी जनता की कृपा से, हमारी पार्टी की वजह से मैंने करीबन चार-पांच मंत्रालय बहुत डिफिकल्ट मंत्रालय मैंने हैड किये जैसे दो बार बिजली उसके बाद इंडस्ट्रीज है, स्पोर्ट्स है, फोरेस्ट है लेकिन यह सबसे चैलेंजिंग डिपार्टमेंट मैंने देखा। इसमें बहुत कुछ हो सकता है। इसके अन्दर ह्युमन सफरिंग को मिटाने का एक हम सबको मौका मिलता है जो कि मैं सोचता हूं कि एक हमारी ड्यूटी है एज लेजिस्लेटर्स, एज मिनिस्टर्स। अभी कई लोगों ने बोला यह स्वीकार किया कि पहला सुख निरोगी काया। यह सब स्वीकार करते हैं कि माया से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, राज में वो पाशा से भी इम्पोर्टेंट होता है। विदेश में वाशा से भी इम्पोर्टेंट होता है और एक बहुत ही सटीक कोटेशन हमारे प्रधान मंत्री का है जो कई बार उन्होंने दोहराया कि 'जान है तो जहान है' और गांधी जी का एक कोटेशन है, 'It is health that is real wealth, and not pieces of gold and silver.”

अध्यक्ष महोदय, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग भी है, विषय भी है और आप लोगों के जरिये 516 कट मोशंस प्राप्त हुए जिनका पूर्ण जवाब मेरा विभाग ऑलरेडी दे चुका है। ये आपके जितने भी सुझाव हैं इनको गम्भीरता से लिया जायेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्ध में अब एक्चुअली इतने लोगों ने, आज बहुत लोग बोले अब पहले मैं एक बार मेरा भाषण दे दूं उसके बाद थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से करूंगा मैं।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि जो हमारा बजट एक्सपेंस है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस चिकित्सा विभाग को प्राथमिकता देते हुए और एक बहुत भारी जिम्मेदारी शोल्डर करने के लिए उन्होंने 27,660 करोड़ रुपये for the financial year 2024-25 हमें दिये जो कि 8.26 प्रतिशत पूरे बजट का हिस्सा है।

Kas/rtm/19.07.2024/21.30/4q

हमारा इंडिया का नेशनल एवरेज 6.18 परसेंट है, हमारा 8.26 है, जिसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। 2023-24 में कांग्रेस का लास्ट बजट था। लास्ट बजट का मतलब है कि आप फाइनल ओवर्स खेल रहे थे और हिट आउट कर रहे थे, उसमें आपने 23,972 करोड़ रुपये दिये। हमारा फर्स्ट ओवर, हमने दिये 27,660 करोड़। हमने 3,687 करोड़ रुपये ज्यादा दिये, यानी आपके लास्ट बजट से 15 प्रतिशत ज्यादा हमारे पहले बजट में दिये, यह हमारी सरकार की सीरियसनेस बताती है कि हम कितनी गंभीरता से हमारी पब्लिक हैल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं।

2024-25 में थोड़ा स्पिलओवर भी हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि इसमें 20 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेंगे, 13 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बेड बढ़ाकर 300 कर दिये जायेंगे, 7 सैटेलाइट हॉस्पिटल बनेंगे, 56 सब डिविजनल हॉस्पिटल बनेंगे, 88 सीएचसी बनेंगी, 460 पीएचसी बनेंगी, 2092 सब सेंटर बनेंगे, 10 ट्रोमा सेंटर बनेंगे, 352 बीपीएचयू बनेंगी, 33 आईपीएचएल बनेंगे डिस्ट्रिक्ट

हॉस्पिटल 1.75 करोड़ के और बीपीएचयू 1 करोड़ की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम हर विधान सभा को एक मॉडल सीएचसी देंगे, जिसमें 32 से बढ़कर 97 जांचें होंगी और वहां पर हम आपको स्पेशलिस्ट देंगे। चाहे आप कांग्रेस के हों, चाहे आदिवासी पार्टी के हों, कोई भी हों, यह सबको दिये जायेंगे। बीपीएचयू एक लेबोरेट्री है लगभग 1 करोड़ रुपये की, इसमें उपकरण भी होंगे, 12 लोगों का पर्मानेंट स्टाफ भी होगा और लगभग 70-75 लाख रुपये की बिल्डिंग होगी। हर पंचायत समिति में एक सीएचसी को दिये जायेंगे, चाहे वह कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो। आपके ब्लॉक में अगर दो सीएचसी हैं, तो एक को मिलेगा। आपको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, निर्दलियों को भी मिलेगा, सबको मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, अभी कई लोगों ने कहा कि हमारे हॉस्पिटल की छत गिर रही है, यह हो रहा है, 150 करोड़ रुपये हम रिपेयर-मेंटीनेंस में देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने लास्ट ईयर में मेंटीनेंस ऑफ हॉस्पिटल एण्ड बिल्डिंग के लिये सिर्फ 5 करोड़ रुपये अलॉट किये थे। 25 एंबुलेंस एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम 1 करोड़ की खरीदी जा रही हैं। 39 बेसिक लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस भी अभी ली जा रही हैं। जयपुर जो हमारी राजधानी है, जयपुर में 1951 में 4 लाख आबादी थी, उस समय स्टेट टाइम से एस.एम.एस. हॉस्पिटल आया। 1991 में 17.41 जनसंख्या हो गई और 2024 में अभी हमारे जयपुर की 43 लाख आबादी है। हमारे कांवटिया, गणगौरी, जेके लॉन, जनाना, महिला, सैटेलाइट हॉस्पिटल पर आबादी का बहुत भारी प्रेशर है, फुट फॉल बहुत ज्यादा है। इसलिए हम एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सैटेलाइट टाइप का 150 बेड का सांगानेर में बनायेंगे। 2 नये सैटेलाइट हॉस्पिटल झोटवाड़ा और विद्याधर नगर में बनेंगे। अरबन सीएचसी मानसरोवर में बनेगी, इससे प्रेशर थोड़ा ईज ऑफ होगा।

आईपीडी टॉवर कांग्रेस का बोया हुआ बीज है, आपने इसका आइडिया कंसीव किया, यह बहुत अच्छा है, इसके लिये आपको धन्यवाद देंगे, लेकिन आपने जो इसकी प्लानिंग की थी और जो वितीय संसाधन दिया था, 14 फ्लोर के बाद उसका काम अटक गया, जबकि बनने थे 24 फ्लोर, ऊपर हैलीपैड, कांफ्रेंस हॉल। 14 से 24 जो 10 फ्लोर थे, यह आईपीडी के हाई पेईंग थे, जो एक्चुअली इसको रनिंग के लिये इन्कम देते। आपने 300 की पार्किंग तय की थी। 300 तो वहां जो लोग काम करते हैं, उनसे ही पूर्ति हो जायेगी। हमारी सरकार आई, तब काम रुका हुआ था और जेडीए 100 करोड़ रुपये मांग रही थी कि 14 फ्लोर तक का हमारा 100 करोड़ का बकाया दे दो, इससे ज्यादा हम काम नहीं कर सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 200 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिये, इससे हम उसको 24 मंजिल तक ले जायेंगे। वहां पर 1200 की पार्किंग देंगे, पूरे एस.एम.एस. की पार्किंग वहां आ जायेगी। आप देखते हैं कि एस.एम.एस में गलियों से, पीछे से आते हैं, इतनी भीड़ रहती है कि पेशेंट का कभी रश इन करना पड़ता है तो वहां पर ट्रेफिक जाम भी हो जाता है। इसमें हम स्काई वॉक बनायेंगे, हर बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से ऊपर से ब्रिज से कनेक्ट होगी ताकि पेशेंट को नीचे-

ऊपर ना करना पड़े, यह हमारा एक कांप्रेहेंसिव प्लान है। इसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने 200 करोड़ रुपये हमें इस बजट में दे दिये हैं। यह इतने महीनों से बंद पडा हुआ था, उसका कार्य अब शुरू होने वाला है। मेडिकल इमरजेंसी ऐसी होती है, हम एयर एंबुलेंस से भी टाई-अप करेंगे। आज बगरू में गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है तो एस.एम.एस. में आने में कितना टाइम लग जाता है? कुछ स्कूल वगैरह में हम चोपर सर्विस आइडेंटिफाई करेंगे। जिंदगी अमूल्य है, किसी को 70-80 हजार रुपये भी चोपर के देने पड़े तो वह चोपर सीधा आईपीडी टॉवर पर लैंड करेगा। यह आईपीडी टॉवर का प्रोजेक्ट 1300 की पार्किंग स्काई वॉक के साथ होगा। आपने इसमें इक्युप्मेंट के लिये भी बजट नहीं दिया। आपने सोचा भी नहीं कि यह बिल्डिंग बनेगी तो इसमें मशीनें तो लगेंगी ही, उसका कोई प्रावधान नहीं था। खैर,कोई बात नहीं, आपने सर्टेन लेवल तक किया, हम उसको कम्प्लीट करेंगे। इसको कम्प्लीट कर के इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल आईपीडी टॉवर होगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पिछले पांच साल में आरयूएचएस में क्या हुआ। ना तो इन्होंने ट्रेनिंग दी, ना इन्होंने डाक्टर नियुक्त किये। यह 750 बेड का हॉस्पिटल है। जब हम कहते हैं कि हमें जयपुर के हब ऐरिया से प्रेशर को ईज ऑफ करना है, तो आरयूएचएस इज द आइडियल प्लेस, बहुत शानदार है। मुख्य मंत्री जी खुद गये और मुझे फोन पर बोले कि इतनी बढ़िया चीज ऐसे ही पडी हुई है। अन्दर फाइव स्टार की जैसी फैसेलिटीज है। आपने कोविड के समय एज ए इमरजेंसी उसको काम में लिया ही था।

कोविड के बारे में भी मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं, आपने कहा कि कोविड में हमने यह किया, यह किया, क्या आप इस चीज का ध्यान रखते हैं कि पूरे विश्व में प्रशंसा की गई थी, जिस तरीके से मोदी जी ने रेमडिसिवर और कोविड की वैक्सीन इंडिया में दी। अमरीका में शोर्टेज चल रही थी, लेकिन हमारे देश में वैक्सीन उपलब्ध कराई गई।

आरयूएचएस 750 बेड का है। इसमें मुख्य मंत्री जी ने तुरंत 200 करोड़ रुपये दिये। इससे पूरे आरयूएचएस में जान आ जायेगी और वह एस.एम.एस. से भी ज्यादा एलीट हॉस्पिटल होगा। आज शहर इतना बड़ा हो गया है, चाकसू से लेकर आमेर क्रॉस कर गया।

msk/rtm/19.07.2024/2140/5a

वहां बगरू से लेकर आप देखेंगे तो आगरा रोड पर कानोता तक चला गया। हमारे पेरिफेरी में अब बड़ा फ्लेक्सिव हॉस्पिटल आरयूएचएस, अब हमें लग रहा है कि हमारा सपना साकार होगा। हमने इसके अन्दर ऑलरेडी 16 स्पेशलिस्ट पोस्ट कर दिये हैं। हमने वहां पर गायनी, पिडियाट्रिशन, ट्रोमा सेंटर के लोग, आईसीयू, ऑगर्न ट्रांसप्लांट और डायलासिस, ये सब स्पेशिलियटी जल्दी से जल्दी शुरू होनी वाली हैं। आरयूएचएस के आने से हमें बहुत लाभ होगा। चाहे कोई भी सरकार आये। हमें भौगोलिक दृष्टि से भी फायदा मिलेगा, क्योंकि एक अच्छा हॉस्पिटल आ जायेगा।

जो सबसे भारी समस्या है। मैंने आप सब लोगों की बात सुनी। सबसे मेजर ईशूज जो

आपने पाइंटआउट किये, आप कहेंगे तो मेरे पास हर सदस्य ने जो बोला है, उनके पाइंट्स मैंने नोट कर लिये हैं। थोड़ा चाय-पानी पीने गया, कोई एकाध मिस हो गया हो तो वह अलग बात है। मैंने आपके सब पाइंट्स नोट कर लिये और उनको मैं एड्रेस करूंगा। यह नहीं कि डिमांड खतम हो जायेगी तो कचरेदान में फेंक दूंगा। सबको एड्रेस करुंगा। आपकी मेजर चिन्ताएं क्या थीं? सबसे मेजर चिन्ता थी कि हमारे पद रिक्त हैं। Right or Wrong? सबने कहा पद रिक्त हैं। यह इस डिपार्टमेंट का सबसे भारी रोग है, नंबर वन। नंबर टू, उपकरण नहीं हैं। नंबर थ्री, आपने बोला कि बिल्डिंग्स की हालत खराब है। अध्यक्ष महोदय, आपको अचंभा होगा कि प्रश्न काल में हमारे प्रश्न आये थे। मैं निम्बाहेड़ा का उदाहरण देता हूं। हमारे माननीय सदस्य कृपलानी जी ने कहा कि हमारा जो निम्बाहेड़ा हॉस्पिटल है, उसके अन्दर हमें ट्रोमा सेंटर चाहिए। मैंने, सब मेजरमेंट होना चाहिए, 100 किलोमीटर की दूरी पर। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के नॉर्म्स हैं कि कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो 50 किलोमीटर के अन्दर ट्रोमा सेंटर होना चाहिए, यानी की डिस्टेंस 100 किलोमीटर की। इनका कहीं 52 था, कहीं 60 किलोमीटर पर तीन ट्रोमा सेंटर्स थे। अध्यक्ष महोदय, एक ट्रोमा सेंटर में छह पद थे, छह में से वहां पर एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। Zero out of six. सेकण्ड ट्रोमा सेंटर के अन्दर छह स्वीकृत पद थे, वहां पर एक जना भी नहीं लगा था। तीसरा जो ट्रोमा सेंटर था, उसके अन्दर एक पद था, out of six. अब आप लोग कहते हैं कि ट्रोमा सेंटर बना दें। हम एक योजनाबद्ध तरीके से आबादी को देखते हुए, हम यह भी चाहते हैं कि पश्चिम राजस्थान है, जहां आबादी कम है, दूरी बहुत ज्यादा है, वहां थोड़ा स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, इनका जो मरूस्थलीय एरिया है, हमें एक सिस्टेमेटिक-वे से पूरी प्लानिंग करनी होगी। हम करेंगे तो जो भी नेक्स्ट सरकार आयेगी, आप उसको inherit करेंगे। आप अच्छा करेंगे तो हम inherit करेंगे। हमें कलेक्टिवली सोचना चाहिए कि हमारे इस प्रदेश का भला कैसे हो?

रिक्रूटमेंट के अन्दर, जो कि टॉप प्रायोरिटी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहां एक तो रिक्रूटमेंट हो और दूसरा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही हो। अध्यक्ष महोदय, हकीकत है कि सब लोग सिफारिश करके अच्छी जगह पर जाकर, जहां दस पद हैं, वहां बीस लोग बैठ जाते हैं और गांव के अन्दर जहां दस पद हैं, वहां तीन लोग मिलते हैं। यह हकीकत है और इसके दोषी हम सब हैं, and we have to take collective responsibility. अभी हम 50 हजार पद भर रहे हैं। इसका मैं आपको विवरण दूंगा और आपको चरणबद्ध विवरण दूंगा। हमने ऑलरेडी नेत्र सहायक 109, डेंटल चिकित्सक 67, ईसीजी टेक्निशियन 155, लैब टेक्निनियन 1888 और असिसटेंट रेडियोलॉजिस्ट 863, हम 3082 लोगों को ऑलरेडी रिक्रूटमेंट कर सके हैं। ये जो पूरे 50 हजार रिक्रूटमेंट होंगे।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): 50 हजार का?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यूनुस जी, यह तो मैं खाली 3 हजार का बता रहा हूं। अभी 47 हजार का और बताऊंगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): चार लाख का हिसाब मिल रहा है, याद रखना है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जूली जी, आप चार लाख में से 50 हजार काट देना। फिगर रिवाइज कर लेना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 50 हजार पर तो एग्री हूं। 50 हजार तो हो जायेंगे, पर बाकी साढ़े तीन में दिक्कत है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप शुभचिन्तक की तरह बात करेंगे तो हो जायेंगे। ये जितने भी हैं, हम राजस्थान पोर्टल पर डाल रहे हैं। कम्प्यूटर वरीयता देखेगा और हर आदमी को, जिसको नौकरी मिली है, उससे 50 जिलों की प्रायोरिटी मांगी। उसके बाद में जहां रिक्त होगा, वहां ही जायेगा। हमारी प्रोब्लम रिक्त पद से आ रहा है। They must वो, इनकी पहली नौकरी है, इनको जाना पड़ेगा, जहां पर हमारे पद नहीं है। दूसरा फार्मासिस्ट 2453, अगस्त माह में नौकरी में आ जायेंगे, एएनएम 4847, ये भी अगस्त में नौकरी में आ जायेंगे। नर्सिंग ऑफिसर्स 8750, ये अक्टूबर के अंत में आ जायेंगे। मेडिकल ऑफिसर 1220, मेडिकल ऑफिसर (डेंटल) 2009 दिसम्बर में आ जायेंगे। कइयों का डिग्री का सत्यापन करना है, उनको ले लिया, खाली डिग्री का वेरिफिकेशन करना है। ये 17 हजार 570 पद हैं, ये दिसम्बर तक नौकरी में आ जायेंगे। इसके बाद एनएचएम के अन्दर 21 हजार 562 लोगों को ले रहे हैं। 10 हजार 657 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गये हैं और 10 हजार 905 का इस वित्तीय वर्ष के अन्दर रिक्रूटमेंट भी हो जायेगा। 21 हजार 562, इसके अतिरिक्त मेडिकल एजुकेशन के अन्दर असिस्टेंट प्रोफेसर 1460, फूड सेफ्टी आफिसर। कई लोगों ने कहा कि यह खाना जहर है, जो लोग पकवान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम स्टाफ मोर-देन-डबल कर रहे हैं ताकि हमारी चैकिंग और हमारी विजिलेंसी थोड़ी तेज हो जाये। क्योंकि सऊदी अरब के अन्दर कोई अगर मिलावाटी खाना देता है तो उसकी गर्दन काटते हैं, उसका मतलब, it is considered as a murder. हम ये पद एक्स्ट्रा ले रहे हैं ताकि हमारी चैकिंग लिस्ट ज्यादा हो। आप कह रहे हैं कि सब जगह है। हमारे जितने हैं, हम उससे मोर-देन-डबल ले रहे हैं।

इसके बाद बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी 1500 मेडिकल ऑफिसर्स दिये हैं और 4 हजार नर्सिंग स्टाफ दिये हैं, ये मिलाकर टोटल 52 हजार हमारे इम्प्लॉइज आ जायेंगे। इसके अतिरिक्त यूटीबी में आयेंगे, वे अलग हैं। जो एक गंभीर समस्या आप सब लोगों ने एड्रेस की थी, उसको होपफुली अच्छी तरह रिजॉल्व कर देंगे।

एक ईश्यू जो आप लोग रेज करते हैं। आप कहते हैं, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि नाम बदल दिया, यह कर दिया। आप प्लीज एक चीज अंडरस्टेण्ड करिये, यह जो योजना थी, it was conceived by the BJP, इसका नाम भामाशाह योजना था। आप कहते हैं कि योजना का नाम क्यों बदलते रहते हैं तो आपने उसको क्यों बदला? भामाशाह में न तो किसी का नाम है, न किसी का निशान है, भामाशाह योजना को चलने देते। आपने

उसको चिरंजीवी कर दिया।

mdp/rtm/19.07.2024/21:50/5b

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष जी, आप इन दोनों को नाम के लिए पाबंद कर दीजिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री जी, पहले आप लोगों ने बदल दिया। आयुष्मान थी, ...(व्यवधान)... वसुन्धरा जी ने भामाशाह कर दिया।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आयुष्मान बाद में आयी है। देखिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब समय बदल गया है। अब प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइजेज का जमाना आ गया है। उदाहरण दूंगा कि एसएमएस के अन्दर सीटी स्केन, एमआरआई, जितनी भी मशीने हैं, सराफ साहब जानते हैं, वह हमने आउटसोर्स की है। उसकी मशीनें बंद ही नहीं होती क्योंकि उसका फुटफाल ज्यादा है। जब मशीनें बंद नहीं होती हैं, 24 घंटे चलती है तो वह 9000 की एमआरआई हमें 2500 में देता है, यानी कि आपको या तो आउटसोर्स कीजिए या एम्पनेल्ड हॉस्पिटल को बढ़ाओ, शिथिलता प्रदान करके। अब आप कहते हैं कि बस का, ट्रांसपोर्ट का है। सरकारी बसों से तो आप ट्रांसपोर्ट पूरा नहीं कर सकते हैं। आपको प्राइवेट भी चाहिए तो, in the same way private participation is very important. इस योजना को हम बहुत बड़ा दायरा दे रहे हैं। जब यह योजना बढ़ेगी तो आपके पास चॉइस है। क्या चोइस है कि मेरी चोइस का डाक्टर और मेरी चोइस का हॉस्पिटल। अभी मेरे दो ऑपरेशन हुए थे, मैंने दुर्लभ जी में कराये। कई प्रेस वालों ने कहा कि, साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मंत्री हो और प्राइवेट हॉस्पिटल में। मैंने कहा कि मेरा सर्जन था, मुझे उस पर विश्वास था, चाहे वह किसी भी हॉस्पिटल में हो, I went to my surgeon. तो आपका डॉक्टर, आपका हॉस्पिटल दोनों चॉइस मिलेगी और यह योजना जितनी बड़ी होगी, अपने सरकारी हॉस्पिट्ल्स का बोझ हटेगा। अगर ये हॉस्पिटल ज्यादा बढ़िया काम करेंगे तो आप सरकारी में क्यों अवेल करेंगे। यह बहुत इम्पोर्टेंट कदम है कि लोग हमारे हॉस्पिटल में उसमें जाकर रहें।

अब एक भ्रम फैला दिया कि चिरंजीवी योजना बंद कर दी। किसने बंद की? नाम बदला हुआ है, मा योजना किया, चल रही है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आपने रोंग एडवरटाइजमेंट किया। आपने कहा 25 लाख, अध्यक्ष महोदय, एक जने को 15 लाख रुपये मिले हैं, केवल एक।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मंत्री जी, बता दीजिए कि टोटल पांच साल में 25 लाख किसी को दिया या नहीं दिया?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 15 लाख मेक्सिमम दिया, बस। सच्चाई तो सुनिए। अध्यक्ष महोदय, 2023 में जब इनकी सरकार थी, जीरो टू 50 हजार, कितने बेनिफिशयरी थे, 1 लाख 62 हजार परिवार, 50 हजार से 1 लाख कितने थे, 83 हजार, आधे

हो गये। 1 लाख से 3 लाख कितने थे, 40 हजार। 3 लाख से 5 लाख कितने थे, केवल 1 हजार 747 और 5 लाख से 10 लाख कितने थे, 454 और 10 लाख से 15 लाख कितने थे, ओनली 48, और एक था 14 लाख। आप लोगों ने जो ये मार्केटिंग की है, this is false marketing. चलिए कोई बात नहीं, कम से कम आपने भामाशाह योजना को चालू रख दिया। अध्यक्ष महोदय, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जब 2021 में चिरंजीवी योजना लांच की थी, इसका दायरा था दस लाख, ओनली 10 लाख, जब चुनाव आया 2023 में तो आपने इसको बढ़ाकर कर दिया 25 लाख, it was an election gimmick.

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, अपनी सीट पर आ जाइए।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हम इस योजना का दायरा बढ़ा रहे हैं। यहां पर पहले रात को रुकना पड़ता था। कैंसर पेशेंट्स का अब खाली डे-केयर पैकेज है। रात का उनका खर्चा होता था, it was a day care package. माननीय चौमूं से आने वाली सदस्या, I hope you are hearing me. मैंने आपको बोला था, मेरा भाषण जरूर सुनना, so I am happy to see you here. बच्चों का पीडियाट्रिक्स का पैकेज हमने नया बनाकर दिया है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूरी होने तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्षः क्या सदन का समय कार्यसूची पूरी होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

कार्यसूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व

मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा पर विचार

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एम्पेनलमेंट लॉजह जो हमारे हैं, हमारे जो रूल्स हैं, उसका हम दायरा बढ़ाना चाह रहे है कि एम्पेनलमेंट वाले हॉस्पिट्ल्स बढ़ें। आपकी चिरंजीवी, मा योजना, इनसे एक बहुत भारी बेनेफिट हुआ। प्राइवेट एंटरप्राइजेज के कितने हॉस्पिटल आ गये। मैं नागौर के पास रहने वाला हूं। नागौर छोटा-सा टाउन, एमआरआई आदि कराने के लिए बीकानेर, जोधपुर जाना पड़ता था। इस बार मैं गया हर हॉस्पिटल पर लिखा है एमआरआई, सीटी स्कैन, ये इस योजना की वजह से है। आपको भी श्रेय है, हमें भी श्रेय है। ये एक तरीके से प्राइवेट एंटरप्राइजेज को प्रमोट करता है। हमारे अधिकारी आईएएस,आरएएस, अभी दो महीने पहले गये थे, सब स्टेट्स की इन्होंने स्टडी की, सब मॉडल्स इन्होंने देखे। वह कई संशोधन ला रहे हैं, जिससे इसकी पोर्टेबिलिटी

बढ़ जायेगी। उससे क्या होगा कि अदर स्टेट्स के लोग भी राजस्थान में आकर इलाज करा सकेंगे। इससे दो चीजें होंगी। एक तो क्या होगा कि हमारे हॉस्पिट्ल्स की कमाई बढ़ेगी, कमाई बढ़ेगी तो हमारा टेक्स रेवेन्यू कलेक्शन होगा। दूसरा, मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ेगा। मेडिकल टूरिज्म और रिलेजस टूरिज्म, दो बहुत भारी टूरिज्म के अंग हैं। जितने भी चीजे हैं, एम्पनलमेंट नार्म्स को रिलेक्स किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर हम लोग जो मिडिल इनकम क्लास के लोग हैं, हम सब जितने भी लोग हैं, इंश्योरेंस कराते हैं यहां पर क्या है, Government is the donor. आपका, insurance company is handling it, और हॉस्पिटल इलाज कर रहा है। जैसा नार्मल इंश्योरेंस में होता है, यही है इसके अन्दर। बहुत कम रेट्स के अन्दर पूरी फैमिल का हो जाता है।

अब मैं आता हूं ये जो आयुष्मान भारत योजना है, ये भी हमारे मोदी जी की योजना है। इसमें 5 लाख रुपये, आप जब चिरंजीवी की बात करते हैं, उसमें आपके मोदी जी के 5 लाख पहले आ जाते थे। आप पहले वह लेकर अपने बैंक में खाता भर लेते थे। हमें आशा है अभी अनाउंस होगा बजट और हमें पूरी आशा है कि हमारे सुनने में आया है कि 70 साल की उम्र से ज्यादा जितने भी लोगों का इलाज होगा, वह भी आयुष्मान में, यह हमारे को पता चला, अनाउंस नहीं हुआ है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में अनाउंस कर दिया।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वेरी गुड। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आता हूं हमारे ग्रास रूट लेवल पर, गांवों के अन्दर। 70 प्रतिशत लोग हमारे गांवों में रहते हैं। ग्रास रूट लेवल के अन्दर जो आयुष्मान आरोग्य मन्दिर हैं, हमारे सब-सेंटर्स और पीएचसी में ये लग रहे हैं। इसके अन्दर 11500 सब-सेंटर और पीएचसी को कवर कर लिया है और टोटल 19877 हैं। इसके अन्दर अभी आपके 5261 डॉक्टर लग चुके हैं। इन डॉक्टर्स की तनख्वाह होगी विथ बेनेफिट्स 40 हजार। अब आप ये इमेजिन कीजिए आपके सीएचसी पर 40 हजार का एक डॉक्टर बैठा हुआ है और इनकी पूर्ति हम अगले चार-पांच महीने में भर्ती करके टेली का सिस्टम है, जिसमें उस डॉक्टर से बात करके गांव वाले अपनी दवाइयों का कर सकते हैं। इसके अन्दर आप अपने बिलकुल लोवर लेवल हॉस्पिटल के अन्दर, आप एक्चुअली एक डॉक्टर दे रहे हैं। ये भी आपके करीबन 5261 काम कर रहे हैं और 12 तरही सेवाएं देंगे, even at the level of Sub-Centers. पहले नर्स क्या करती थी? बुखार लेती थी, थोड़ा ब्लड प्रेशर लेती थी। 12 सेवाएं मिलेगी। ये बहुत बड़ी स्कीम है, जो बिलकुल ही ग्रास रूट के अन्दर आप अपनी मेडिकल असिस्टेंस पहुंचा सकेंगे। इसको कहते हैं टेली कंसल्टेशन। ये बहुत बड़ी चीज है। इसके अन्दर हम अगले 6 महीने में एलईडी टीवी देंगे, एक पीसी टेबलेट देंगे, डेस्कटॉप देंगे, वेबकेम देंगे, प्रिंटर देंगे और हाई स्पीड इंटरनेट देंगे ताकि वह टेली कंसलटेशन कर सके।

अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर हम कुछ स्पेशियलिटीज बढ़ा रहे हैं। इसके अन्दर मेंटल

हैल्थ, ईएनटी, आंखों का ओपथोमोलोजिस्ट, फिर जो ओल्ड लोगों की दवाइयां और ट्रीटमेंट, ये सब चीजें और पेडियाट्रिक, ये सब एकस्ट्रा तरीके से आप इमेजिन कीजिए आपके सब-सेंटर पर पहुंच जायेगी। मैं सोचता हूं कि ये अपनी जनता के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। हमारे 1 लाख 30 हजार हैल्थ मेला हुए, जिसमें सब-सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, 6 महीने में और 50 लोग इसमें स्क्रीन्ड हुए और लाभान्वित हुए। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 49 बड़े हॉस्पिटल में एक रामाश्रय वार्ड खोला है हमने।

Ans/rtm 22.00 5c 19.07.2024

जिसके अन्दर बुजुर्ग लोग, दस लोगों का कमरा होगा, उसके अन्दर टॉयलेट होगा, उसके अन्दर घंटी वाला सिस्टम होगा, कुछ मशीन होगी, जिससे उनका रिहेबिटेशन किया जाए, इसका नाम राम आश्रय रखा गया है। स्पेशली फिजियो उसका अटेंडटेंट होगा, फ्री दवाई मिलेगी। हमने 100 दिन के कार्यक्रम में मानसिक सेवाओं का विस्तार किया है। स्टेट मेंटल हेल्थ अथोरिटी कंसीटयूट हुई है, नोटिफाईड अथोरिटी और टास्क फोर्स। विकसित भारत संकल्प यात्रा, राजस्थान को नम्बर वन स्थान दिया गया है, पूरे इंडिया में।

मां वाउचर योजना। यह लेडीज के लिए खुशखबरी है। वाउचर दिया जाएगा। कोई भी लेडी जो गर्भवती है, फाइव मंथ, सिक्स मंथ है, गाँवों के अन्दर सोनोग्राफी मशीन नहीं है, फीटस को देख सके, चैक कर सके, तो वाउचर दिया जाएगा। जहां नीयरेस्ट सोनाग्राफी मशीन है, वह वहां पर जाएगी, वह वाउचर के थ्रु एक बार अल्ट्रासाउण्ड कराएगी। डॉक्टर अगर सोचता है कि इनको एक बार नाइन मंथ से पहले और जरूरत होगी, तो डॉक्टर की रिकमंडेशन पर सैकण्ड वाउचर गर्भवती महिलाओं को दिया जाएगा। यह क्यूआर कोड से चल रहा है।

मुख्यमंत्री बाल स्वास्थ्य सम्बल योजना। मुख्य मंत्री जी ने 60 करोड़ रुपये बजट में दिए हैं, दुर्लभ बीमारियों के लिए जो बहुत महंगी होती है। Muscular dystrophy, उसके लिए व्हील चेयर की जरूरत होती है, बहुत गम्भीर बीमारी है। 22 करोड़ रुपये जे.के. लोन को दिए हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को, वहां उनको जो भी उपकरण लगाने हैं, सब बच्चे वहीं आते हैं।

कई लोगों ने डॉक्टर के बारे में रेज किया था, डॉक्टर नहीं होते, घर चले जाते हैं। कई डॉक्टर तो एक्स्ट्रा इमोल्यूमेंट लेते हैं कि हम प्राइवेट प्रेक्टिस नहीं करेंगे। मैंने निर्देश दिए हमारी एसीएस को करीब दो महीने पहले कि हर हॉस्पिटल में चाहे वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे उससे बड़ा हॉस्पिटल हो, चाहे एसडीएच हो, चाहे पीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो, सब जगह बायोमेट्रिक होगा, जो भी आएगा फिंगर प्रिंट से एंटर करेगा और जाएगा। हर कमरे के अन्दर सीसीटीवी कैमरा लगेगा, so that we can monitor, कि डॉक्टर कितने बजे आया और कितने बजे गया, क्या उसने अटेंडेंस की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अन्दर बायोमेट्रिक और सीसीटीवी 96 परसेंट लग गए हैं। आप भले ही वेरीफाई कर लेना अपने-अपने एरिया में। एसडीएच हैं, वहां पर 99 परसेंट बायोमैट्रिक और 100

परसेंट सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। सेटेलाइट हॉस्पिटल में 62 परसेंट लगे हैं। अभी पीएचसी, सीएचसी में आगे बढ़ेगे, उसको करेंगे। अगर आप देखते हैं कि आपके एरिया में इसको नहीं लगाया है, कोई ना कोई तरीके से ट्राई करेंगे, आप हमें उसकी सूचना देंगे, हम इस पर कड़ी कार्यवाही देंगे।

आभा पीएम योजना। आयुष भारत हेल्थ अकाउण्ट। हर सिटीजन के पास एक हेल्थ कार्ड होगा, पेपर लेस होगा, वह अपना पूरा ट्रेक डाउन कर सकेंगे, किसी डॉक्टर के पास जाए तो कि इन्होंने क्या प्रेस्क्रिप्शन दिया था, नहीं तो यह होता है ना कि मेरी पर्ची गुम गई, तो कार्ड के ऊपर उनका पूरा डेटा आ जाएगा।

इसके बाद आईएचएमएस, इंटीग्रेटेड हेल्थ मैकेनिज्म सिस्टम, इसके अन्दर डिजिटल हेल्थ का लॉकर होगा, सिस्टम होगा, कोई भी हॉस्पिटल होगा उसके थ्रू सब डॉक्टर्स की हिस्ट्री ट्रेक डाउन कर लेगा।

आपने देखा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट का कितना बड़ा हंगामा हुआ। उसके अन्दर 2020 से आपकी सरकार के टाइम एडवाइजरी कमेटी ओथोराइजेशन कमेटी को डिजाल्व कर दिया गया। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ थे उनको हटा दिया। सेकण्ड आईएएस ऑफिसर था, उसको हटा दिया और एक ग्रुप ऑफ लॉ उस पर बैठकर, उस पर यह एनओसीज का धंधा शुरू किया। हमारी सरकार ने इसको पकड़ा। हमारे डॉक्टर्स ने पकड़ा। उन्होंने जाकर एसीबी को शिकायत की, नहीं तो पता नहीं यह कब तक हो चलता। हमने सबको सस्पेण्ड किया, टर्मिनेट किया। हम एक नई सोटो कमेटी बनाकर, ताकि यह आइंदा नहीं हो, जैसे नीट का किया था वैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट का भी किया।

अभी कई माननीय सदस्य ने adulterated food के बारे में बात की थी। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान हमने शुरू किया है। आपने अख़बार में पढ़ा होगा, इसमें बहुत बड़ी-बड़ी रिच कम्पनी को भी हमने इसके दायरे में लिया। उसमें बहुत हंगामा हुआ, उन्होंने पॉलिटिकल पूल यूज करने का इंफ्ल्युज किया, हमने उनको नहीं छोड़ा। 11 फूड सेफ्टी लैब और 7 तैयार होने वाले हैं। माइक्रोबॉयोलोजी लैब है, जिससे टेस्टिंग बेहतर रहेगी। पिछले सात महीने में 8 हजार इंस्पेक्शन किए हैं। 18 हजार सेम्पल्स जिसमें 1500 पकड़े गए, 4 करोड़ रुपये की पेनल्टी और 100 कैसेज लांच हुए। अभी हम लगभग 300 नये ऑफिसर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, जिससे हमारी स्ट्रेन्थ, हमारा दायरा बढ़े। हमारे पास जितने एम्प्लॉइज हैं, उससे हमारी डबल चैकिंग हो। लगभग 298 रिक्रूटमेंट भी शीघ्र होने वाले हैं।

हमारे जितने भी संभागीय हैड क्वार्टर्स हैं, उसके अन्दर मेडिकल कॉलेजेज हैं, वहां डेडीकेटेड वैन्स हैं, वह उस डिस्ट्रिक्ट में जाती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो ग्रामीण एरिया में है, मैंने मेरे डिपार्टमेंट को भी बोला कि मेरी यह प्रायोरिटी है। 70 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, उसमें से 45 प्रतिशत लेडीज है। हम नेता लोग शादी, गम में जाते हैं। लेडीज की डेथ होती है तो क्या कॉज होता है, सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर। हम वैन्स को इक्युप कर रहे हैं, गांव के अन्दर लेडीज का फ्री चेकअप। लेडीज की टीम हो, मेमोग्राफी

कराकर अरली स्टेज में डिडेक्ट करे। इस अभियान को हम बहुत बड़ा रूप देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे गांव-गांव में, हमारी जो बहनें हैं, बच्चियां हैं, माताएं हैं, उनकी लम्बी उम्र हो और अरली स्टेज पर यह कैंसर पकड़ा जाए। अभी तक 8 लाख लेडीज का डिविजनल हैडक्वाटर की वैन से चेकअप हो चुका है।

सिकल सेल, एक ट्राइबल बीमारी है। इसके अन्दर 31 लाख लोगों की स्क्रिनिंग हो गई है। 0 से 40 साल की उम्र में एनीमिया हो जाता है। किसी के सिकल सेल की बीमारी हो, उसकी शादी सिकल सेल किसी दूसरे के साथ नहीं होनी चाहिए। कार्ड में स्लॉट बनाए हैं, जब मेच करोंगे तो वह मेच नहीं करेंगे। गरीब आदमी को यह सब चीज़ें मालूम नहीं है। सिकल सेल गम्भीर बीमारी है, इसको भी सरकार सीरियस ले रही है।

बालिका सम्बल योजना। किसी के एक से दो लड़की हो और वह ऑपरेशन करा ले तो उन बच्चियों को 30-30 हजार रुपये मिलेंगे और 21 साल की उम्र में उनको डेढ़ लाख रुपये की राशि दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास माननीय सदस्यों के आए हुए हैं। आप मुझे अनुमति दे, सराफ साहब ने भी कई चीज़ें बोली, आपने आरयूएचएस के बारे में बोला, मैंने आपको बता ही दिया। हमारे चोमू एमएलए साहिबा को भ्रम था चिरंजीवी योजना बंद कर दी, उसको ऐसे कर दिया, वह भी मैंने आपको एक्स्प्लेन कर दिया। आईपीटी टॉवर के बारे में भी आपको गलतफहमी थी वह भी मैंने क्लियर कर दिया।

VPS-RTM-19.07.2024-22.10-5d

ताराचन्दजी जैन ने भी अपने चिकित्सालय के लिए कहा, ऐसे कितने ही इश्यूज हैं, पैरा मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, रिक्त पद, सबको देखेंगे। आपके हमीर सिंहजी भायल, आपके समरजीत सिंहजी ने भी अभी विचार व्यक्त किया था, इनके मेडिकल कॉलेज के लिए, ब्लड बैंक के लिए और जैसा कि अभी यूनुस खानजी ने भी बोला। अभी मेडिकल कॉलेज जो हैं 30 कम्प्लीट कर रहे हैं, उसके बाद अगले वित्तीय वर्ष में तीन और होंगे और उसके बाद में जो नये जिले बने हैं, उनको लिया जायेगा। उसके बाद में लिया जायेगा, यह मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है न? विक्रम सिंहजी ने ट्रोमा सेंटर की बात करी, मनोज न्यांगलीजी ने नर्सिंग स्टाफ, ड्रग्स इंस्पेक्टर की बात की जो मैंने आपको बता ही दिया। श्रीमती रमीलाजी खड़ीया ने रिपेयर एड मेनटिनेंस के लिए कहा तो मैंने आपको बोला है कि आपके यहां पर कोई बल्डिंग जर्जर हो रही है तो हम उसको रिपेयर करवाएंगे, हमारे पास फंड्स हैं, हम उसको रिपेयर करवाएंगे। डॉ. प्रियंकाजी ने बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में कहा। पी.एच.सी. से सी.एच.सी. का बोला और श्री हाकम अलीजी ने भी कई सुझाव दिये हैं। ट्रोमा सेंटर का, वहां पर भवन नहीं है, तो जहां-जहां पर कोई चीज एप्रूव्ड है, भवन नहीं है तो हम भवन बनाएंगे। जर्जर हालत में है, खराब है तो उसको हम रिपेयर करवाएंगे। श्री गोपाल लाल शर्मा ने माण्डलगढ़ के बारे में बोला कि वहां पर मॉडल सी.एच.सी. हो तो मॉडल सी.एच.सी. का मैंने

आपको बता ही दिया है और बी.पी.एच.यू. का भी मैंने आपको बता दिया, लैब बनेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मोटा-मोटी रूप से आपको यही अर्ज है कि अभी विधान सभा चल रही है तो मैंने आपके सब पाइंट्स लिख लिये हैं, तो थोड़ा विश्राम के टाइम में आप आ जाओ तो एग्जेक्टली अपन अधिकारी से बात कर लें बजाए कि मैं आपसे कुछ बोलूं, let us get down to the brass tacks on to this thing, और अपन बैठकर, अधिकारी से बात करके आपकी जो भी समस्या है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्षः हो गया?

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने सुझाव दिये। जब विपक्ष सुझाव देता है ...(व्यवधान)...

श्री विकास चौधरी (किशनगढ़): मैंने जो कहा उसके बारे में आपने एक शब्द नहीं बोला। ...(व्यवधान)...

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप सुनिये।...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः अब हो गया। आप बैठिये। मंत्रीजी ने उत्तर दे दिया। आप बैठिये। बैठे-बैठे नहीं बोलें। जवाब आ गया। आपको जो बोलना था, आप बोल लिये। ...(व्यवधान)...

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एम.एल.ए. साहब, सुनिये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोविड वैक्सीन से, हमारी जनसंख्या कितनी ज्यादा है जो ऑफ्टर इफेक्ट्स इंडिया में हुए हैं उससे चार गुना ज्यादा अमेरिका में हुए हैं, आप फिगर निकाल कर देख लो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः बैठिये। माननीय मंत्रीजी, अब आप समाप्त करिये। आपका जब नम्बर था, आप बोल लिये, उसके बाद आप शांत रहिये। जवाब सुनिये, यह बहस नहीं है।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लास्ट में आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके जो सुझाव है, विपक्ष के सुझाव आते हैं, आप कोसते भी हैं हमें तो यह तो हमारे लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस होता है, हमारी भी आंखें खुलती हैं, हम भी अलर्ट हो जाते हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है और आपके बीच में हम उपलब्ध हैं और इसमें आप यह पाल मत बांध लेना कि विपक्ष और पक्ष इस तरह से है, पर मैंने एक चीज शुरू में भी कही थी कि ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः हो गया। माननीय मंत्रीजी, हो गया। आप बैठिये। अंकित नहीं होगा। हो गया। अब कुछ नहीं। ...(व्यवधान)...

डॉ. शिखा मील बराला (चोमू): 000

श्री अध्यक्षः आप बैठिये। ...(व्यवधान)...

मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,18,18,31,78,000/- (एक खरब अठारह अरब अठारह करोड़ इकतीस लाख अठहत्तर हजार)

तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 54,55,03,08,000/- (चौवन अरब पचपन करोड़ तीन लाख आठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक शनिवार, दिनांक 20 जुलाई 2024 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.14 बजे शनिवार, दिनांक 20 जुलाई 2024 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

....

परिशिष्ट 1
मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :-

श्री केसाराम चौधरी (वि.सं.35)

1. सेवारत चिकित्सकों का पृथक केडर गठन करने एवं इन्हें चतुर्थ डी.ए.सी.पी. के ग्रेड पे 9500/- (पे-मेट्रिक्स L-23) का लाभ दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं.159)

2. अमृत कौर अस्पताल बयाना, सी.एच.सी. टाटगढ़, सी.एच.सी. जवाजा, पी.एच.सी. बडाखेड़ा, पी.एच.सी. राजियावास, किशनपुरा एवं सभी सब-सेण्टरों पर चिकित्सकों जी.एन.एम. एवं ए.एन.एम. के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री समाराम (वि.सं.175)

3. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाडा-आबू की ग्राम पंचायत कोरस, किनराली एवं पाबा में नए सी.एच.सी. व पी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सोहन लाल नायक (वि.सं.186)

4. विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर की सी.एच.सी. को उप-जिला अस्पताल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं.72)

5. प्रदेश के सेवारत चिकित्सकों का पृथक केडर गठित करने एवं सेवारत चिकित्सकों को चतुर्थ डी.ए.सी.पी. ग्रेड पे – 9500/- (पे मेट्रिक्स L-23) का लाभ देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अनिल कुमार शर्मा (वि.सं.05)

6. प्रदेश में सेवारत चिकित्सकों को केन्द्र सरकार के चिकित्सकों की तरह चतुर्थ डी.ए.सी.पी. की ग्रेड पे- 9500/- (पे मेट्रिक्स L-23) का लाभ दिए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

7. प्रदेश में सेवारत चिकित्सकों का केडर निर्माण के लिए अन्य संवर्गों (R.A.S., R.P.S., RAc.S.) की तरह राज्य सेवा में प्रवेश की RPSC की वरिष्ठता सूची को ही पदोन्नति का आधार बनाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

8. सरदार शहर में स्वीकृत ट्रोमा सेण्टर को शीघ्रातिशीघ्र चालू करवाकर जनता को लाभ पहुँचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. ऋतु बनावत (वि.सं.24)

9. बयाना व रूपवास में महिला चिकित्सक को स्त्री रोग विशेषज्ञ लगाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. विधान सभा क्षेत्र बयाना के कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. विधान सभा क्षेत्र बयाना में ग्रामीण क्षेत्रों की P.H.C. में चिकित्सकों की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित मीना (वि.सं.142)

12. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के देवकी पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में एवं शाहबाद सी.एच.सी. को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

13. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की पीएचसी. देवरी, केलावन पी.एच.सी. में एम.टी.सी. वार्ड पुनः चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (वि.सं.98)

14. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत गिरवा के ग्राम नाई के नाई अस्पताल को सेटेलाईट अस्पताल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोरधन (वि.सं.47)

15. विधान सभा क्षेत्र धोंद की ग्राम पंचायत खारखोली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. विधान सभा क्षेत्र धोद की ग्राम पंचायत हर्ब में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं.168)

17. जिला चिकित्सालय निम्बाहेड़ा पर मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र (MCH यूनिट) खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

18. जिला चिकित्सालय निम्बाहेड़ा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छोटी सादड़ी में ट्रोमा सेण्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छोटी सादड़ी को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. जिला चिकित्सालय निम्बाहेड़ा को 150 बेड से 300 बेड में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल मीणा (वि.सं.10)

22. प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सुविधाओं को और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में टोडा, गांवडापाल ईडाणा व पीपादर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

24. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के जिला मुख्यालय पर जिला चिकित्सा भवन निर्माण को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के समस्त सी.एच.सी., पी.एच.सी. व उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सु.खेड़ा के नवीन भवन निर्माण के लिए बजट स्वीकृत करवाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (वि.सं.08)

27. शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नोहर को शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र नोहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फेफाना के जर्जर व पुराने भवन की जगह नये भवन निर्माण करवाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. राजकीय उप-जिला चिकित्सालय नोहर को 100 बेड से 150 बेड एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पल्लू को 30 बेड से 50 बेड करने की आवश्यकतापर चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र नोहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुईयां, मन्दरपुरा, धानसिया को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र मालासर, जबरासर, थालडका व दलपतपुरा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. राजकीय उप-जिला चिकित्सालय नोहर में सोनोग्राफी जांच मशीन स्थापित किए जाने एवं चिकित्सालय भवन व चिकित्सक आवास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण (वि.सं.140)

32. प्रदेश में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ एवं पैरा-मेडीकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरने एवं अस्पताल के भवनों के निर्माण एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रोहित बौहरा (वि.सं.139)</u>

33. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के उप-जिला अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ व चिकित्सक की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं.94)</u>

34. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में संचालित पी.एच.सी. एवं सी.एच.सी. में रिक्त पदों को भरने एवं उपकरण उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री केसाराम चौधरी (वि.सं.35)</u>

35. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन की ग्राम पंचायत रडावास में संचालित सुखालय हॉस्पिटल भूमि, भवन एवं मेडीकल स्ट्रूमेंट सहित सरकार को लौटाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

36. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन में पी.एच.सी. का भवन बनाकर दानदाता देने को तैयार है, अतः ग्राम जेतपुरा में पी.एच.सी. स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. मारवाड़-जंक्शन के ग्राम पंचायत डायलाना कल्ला में उप-स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने पर भामाशाह द्वारा पीएचसी का पूर्ण भवन दानदाता द्वारा बनाकर देने के संबंध में चर्चा के लिए।

38. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन की पी.एच.सी. में डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं.101)</u>

39. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बालेसर को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. शेरगढ़ मुख्यालय में ट्रोमा सेण्टर स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में उप-स्वास्थ्य केन्द्र कनोडिया पुरोहितान, बेलवा खत्रियां, उटाम्बर, सोलंकिया तला, रायसर, भूंगरा, खिरजां तिबना, सुवालिया एवं बस्तवा सुण्डा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. प्रदेश में कार्यरत मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना (दवा) के अन्तर्गत मशीन विद मेन (कम्प्यूटर ऑपरेटर) को संविदा सेवा रूल्स 2022 में स्वीकृत 2532 पदों पर नियुक्ति पत्र जारी करवाने एवं उक्त कार्मिकों के फिक्स मानदेय में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नाथडाऊ, सोमेसर एवं चाबा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)

44. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के बोरून्दा में महादेव नगर, बीजासनी में जेलवा, चौढ़ा में विष्णु नगर, पिचीयाक में झुरली, जसवन्तपुरा में बांजडगढ़, ओलवी में छोलपुर खुर्द, चांदलाव में विष्णु की ढाणी में नए उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में नव क्रमोन्नत पी.एच.सी. हरियाढाणा के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में शिव नगरी वार्ड नंबर 25, बाग़ की ढाणी वार्ड नंबर 19, आदर्श भगरिया वार्ड नंबर 18, पतालियावास वार्ड नंबर 5, पोलियावास वार्ड नंबर 22, इन्द्रा कॉलोनी वार्ड नंबर 9, भैरूसागर, सिलरी रोड़ आदर्श कॉलोनी वार्ड नंबर 18 रेल्वे स्टेशन रोड वार्ड नंबर 9, कृष्णा कॉलोनी वार्ड नंबर 32, इन्द्रा कॉलोनी वार्ड नंबर 27, न्यू बस स्टैण्ड वार्ड नंबर 35, उचियारड़ा बेरा वार्ड नंबर 34 एवं महादेव नगर में जनता क्लिनिक की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री थावर चन्द (वि.सं.75)

47. जिला प्रतापगढ़ में स्थित सभी ग्राम पंचायतों में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. विधान सभा क्षेत्र धरियावद के मुगाना, धरियावद, लसाडिया एवं भभराना में सोनोग्राफी मशीन शीघ्र प्रारंभ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धरियावद में ब्लड बैंक खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र धरियावद के सी.एच.सी., पी.एच.सी. में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र जोशी (वि.सं.82)

51. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय चिकित्सालय फिदुसर चौपड़ को सिलिकोसिस विशेषज्ञ अस्पताल के रूप में समुचित पद और जांच, एम्बुलेन्स सुविधा युक्त विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के सभी एड-पोस्ट पी.एच.सी., सी.एच.सी.वार क्रमोन्नयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के सेटेलाईट अस्पताल चौ.हा.बोर्ड एवं राजबाग सूरसागर को 24 घण्टे सातों दिन आमजन के लिए कार्यरत स्टेटस में लाने में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए स्तर अनुरूप संसाधन और पर्यवेक्षण की सुचारू व्यवस्था की अविलम्बनीय आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के मिल्कमेन कॉलोनी एवं सुभाष नगर, पाक विस्थापित अम्बेडकर कॉलोनी, कालीबेरी, चौ.हा.बोर्ड सेक्टर 11 से 25 क्षेत्र में एवं पश्चिमी पाल रोड़ योजना के नगरों के लिए चार नवीन पी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जोधपुर में विगत 5 वर्षों में संविदाकर्मी कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा की गयी अनियमितताओं और खाद्य पदार्थों के सैम्पलिंग और जांच रिपोर्ट के प्रकरणों में की गयी अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)</u>

56. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर चिकित्सा संस्थान कम होने से चाड़ों की ढाणी, भूकाभगतसिंह, तेलवाड़ा एवं ढीढस में पी.एच.सी. खोलने के साथ पी.एच.सी. मोकलसर एवं होडु को सी.एच.सी. करवाने तथा नए सब-सेण्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

57. नव स्वीकृत पी.एच.सी. भवन सिणेर, इन्द्राणा, डन्डाली में अतिरिक्त बजट स्वीकृत कर चारदीवारी, इन्टरलॉकिंग खरंजा एवं परिसर का सुधार कार्य किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

58. नव क्रमोन्नत सी.एच.सी. पादरू का भवन, उप जिला अस्पताल, सिवाना का भवन एवं सी.एच.सी. सिवाना, समदड़ी में जो नई बिल्डिंग बनी उसमें 20 लाख के उपकरणों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. सिवाना उप जिला अस्पताल के रिक्त पदों को भरने एवं महिला चिकित्सक की 25 वर्षों से की जा रही मांग को पूरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. सिवाना क्षेत्र में जो सब-सेण्टर पी.एच.सी. में क्रमोन्नत हुए उनके सब-सेण्टर को क्षेत्र में ही चिकित्सा सुविधा से वंचित गांवों में खोलने एवं ए.एन.एम.एक स्थान पर दो या तीन है, उनको खाली पड़े सब-सेण्टरों में पदस्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं.17)</u>

61. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के चिकित्सालयों में सी.टी.स्केन, सोनोग्राफी मशीन एवं एम.आर.आई. मशीन स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा में टर्सरी कैंसर केयर सेण्टर निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा में कैथ लेब निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा में ऑर्थोस्कॉपी उपकरणों के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं.113)</u>

65. चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाने, दवाईयों की कीमत पर नियंत्रण एवं समय पर उपचार की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं.48)</u>

66. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में चिकित्सा विभाग के कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं.51)</u>

67. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में पॉच पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में सेमलपुरा चौराहा, रिठोला चौराहा व नरपत की खेड़ी के आस-पास ट्रोमा सेण्टर की स्थापना किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में चिकित्साधिकारी व कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. सांवरिया जी सामान्य जिला चिकित्सालय में हार्ट व न्यूरो विभाग खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में आठ सब सेण्टर को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं.48)</u>

72. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अकलेरा व असनावर में बेड बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73. एन.एच.एम. में संविदा पर सेक्टर हेल्थ सुपरवाईजर का मानदेय बढ़ाने व सी.एस.आर. रूल्स 2022 के अन्तर्गत नियमितीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में पी.एच.सी. को सी.एच.सी. व सब सेण्टर को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनोहरथाना को उप जिला चिकित्सालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं.04)</u>

76. अजमेर दक्षिण के धोला भाटा स्थित राजकीय नगर स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र के भवन के निर्माण हेतु DMFT फण्ड से बजट उपलब्ध होने के बावजूद भी कार्य नहीं कराए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में एन.यू.आर.एच.एम. के तहत निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चन्द्रवरदायी एवं शहरी स्वास्थ्य केन्द्र नाका महार में

संविदा चिकित्सकों के पद समाप्त कर नियमित चिकित्सकों के पद सृजित कर नियुक्त किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. अजमेर शहर के सेटेलाईट अस्पताल, आदर्श नगर के चिकित्सालय परिसर में स्थित रिक्त भू-भाग पर चिकित्सक एवं नर्सिंगकर्मियों के स्टाफ क्वार्टर्स बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में सीटीवीएस सर्जरी विभाग में फैकल्टी लगाई जाए, जिससे बाईपास सर्जरी के साथ ही पी.जी. कोर्स भी चालू किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80. अजमेर मेडीकल कॉलेज के अन्तर्गत आने वाले जिला चिकित्सालय आदर्श नगर को अधिक सुविधाएं प्रदान कर विकसित करने एवं जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय पर रोगियों का भार कम किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)</u>

81. विधान सभा क्षेत्र आहोर के कुआरडा, सुमेरगढ़खेडा, गुडा-रामा रसियावास कलां में उप-स्वास्थ्य केन्द्र एवं आईपुरा, अजीतपुरा, मेडा-उपरला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र आहोर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भाद्राजुन, भवरानी, गुड़ाबालोतान, चांदराई हरजी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र आहोर के सी.एच.सी. आहोर, सियाण, बागरा एवं पी.एच.सी. भाद्राजुन, उम्मेदपुर, शंखवाली में चिकित्सक के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. विधान सभा क्षेत्र आहोर में क्रमोन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नोरवा एवं क्रमोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भूती में भवन निर्माण के लिए बजट आवंटित करवाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र आहोर में उपखण्ड स्तर पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने एवं इसमें ब्लड बैंक यूनिट, आई.सी.यू. सेण्टर एवं ट्रोमा सेण्टर की स्वीकृति दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.**80**)</u>

86. राजसमन्द के कमला नेहरू राजकीय चिकित्सालय कांकरोली को उप नगरीय (सेटेलाईट) चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. राजसमन्द जिले के पुठोल एवं आत्मा गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. आर.के. राजकीय चिकित्सालय, राजसमन्द में तरल ऑक्सीजन भण्डारण केन्द्र की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. आर.के. जिला चिकित्सालय, राजसमन्द को बहु विशेषज्ञता चिकित्सा संस्थान के रूप में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए पर्याप्त सुविधायुक्त भवन निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री उमेश मीणा (वि.सं.23)</u>

91. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप-जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरने व सुविधाओं को और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. डूँगरपुर जिले में विधान सभा क्षेत्र आसपुर के चिकित्सा विभाग में समस्त पी.एच.सी. व सी.एच.सी. में रिक्त चिकित्सकों के पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

94. जिला-डूँगरपुर के हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय में साफ-सफाई की उचित व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के दोवड़ा, आसपुर, साबला में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 104 व 108 एम्बुलेन्स को शीघ्र बदलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हरिसिंह रावत (वि.सं.193)</u>

96. विधान सभा क्षेत्र भीम के उप-जिला चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. उप-जिला चिकित्सालय भीम के परिसर में चिकित्सकों, मंत्रालयिक कार्मिकों व अन्य स्टाफ के लिए आवासीय भवन का निर्माण करवाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र भीम में संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप-जिला चिकित्सालयों में सभी संवर्ग के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री सोहन लाल नायक (वि.सं.186)</u>

100. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के प्राथमिक चिकित्सालयों एवं राजकीय सामुदायिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं नर्सिंगकर्मियों की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101. सी.एच.सी. रायसिंहनगर में अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने एवं विशेषज्ञ नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (वि.सं.132)</u>

102. प्रदेश में कार्यरत चिकित्सकों का केडर निर्माण में RAS, RPS की भांति राज्य सेवा में प्रवेश के समय की RPSC की वरिष्ठता सूची को ही केडर और पदौन्नति का आधार बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. प्रदेश के कार्यरत चिकित्सकों को चतुर्थ DACP की ग्रेड-पे 9500/- (पे-मेट्रिक्स 23) का बजट में प्रावधान किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री रोहित बौहरा (वि.सं.139)</u>

104. प्रदेश के सेवारत चिकित्सकों को चतुर्थ DACP की ग्रेड-पे 9500/- (पे-मेट्रिक्स 23) का बजट में प्रावधान किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

105. प्रदेश में कार्यरत चिकित्सकों का केडर निर्माण में RAS, RPS की भांति राज्य सेवा में प्रवेश के समय की RPSC की वरिष्ठता सूची को ही केडर और पदौन्नति का आधार बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं.150)</u>

106. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के ढीगाल एवं डूंडलोद पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं.72)</u>

107. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के वीरमाना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

108. सूरतगढ़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन जर्जर होने से हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिए।

109. सूरतगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप-जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के समस्त चिकित्सा केन्द्रों में पर्याप्त रूप से स्टाफ का पदस्थापन करने तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फूल सिंह मीणा (वि.सं.98)

111. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत बच्दार की पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ) (वि.सं.112)

112. सुजानगढ़ के उप-जिला चिकित्सालय में मर्ज ट्रोमा सेण्टर को पृथक कर पुन: चालू कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)

113. राज्य सरकार और अरिस्दा संघ के मध्य वर्ष 2011 व 2017 में हुए समझौते के उपरांत भी अभी तक सेवारत चिकित्सकों का पृथक केडर का गठन नहीं किए जाने एवं DACP ग्रेड-पे 9500/- स्वीकार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

कुमारी रीटा चौधरी (वि.सं.138)

114. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा के उप-स्वास्थ्य केन्द्र कोलिण्डा, जाबासर व सिरियासर कलां को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. सुरेश धाकड़ (वि.सं.182)

115. राज्य सरकार द्वारा राज्य में चिकित्सकों के पृथक केडर हेतु वर्ष 2011 व 2017 के समझौते के बावजूद केडर का गठन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

116. राज्य सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सकों (ग्रुप-2) को केन्द्र व अन्य राज्यों (दिल्ली, बिहार आदि) की तर्ज पर मेडीकल कॉलेज चिकित्सकों की तरह चतुर्थ DACP ग्रेड-पे 9500/- प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ) (वि.सं.112)

117. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के ग्राम मलसीसर, चरला, सारोठिया, गिरवरसर के उप-स्वास्थ्य केन्द्रों को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

118. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के ग्राम सडू छोटी व कातर छोटी उप तहसील मुख्यालय की पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)

119. बृजसुन्दर शर्मा अस्पताल एवं विधान सभा क्षेत्र बून्दी में स्थापित सीएचसी व पीएचसी में चिकित्सकों और मेडीकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. राज्य में सी.एच.सी./पी.एच.सी. चिकित्सा स्तर में सुधार हेतु चिकित्सकीय उपकरणों की उपलब्धता के संबंध में चर्चा के लिए।

121. राज्य में नि:शुल्क दवा/जॉंच योजना में समुचित तथा समस्त दवाओं/जॉंचों की उपलब्धता के संबंध में चर्चा के लिए।

122. चिरंजीवी योजना के अन्तर्गत समुचित इलाज की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं.22)</u>

123. विधान सभा क्षेत्र माण्डल की ग्राम पंचायत निम्बाहेड़ा जाटान, उप-स्वास्थ्य केन्द्र में मोर्चरी की व्यवस्था कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. विधान सभा क्षेत्र माण्डल के ग्राम बागौर में पुराने हॉस्पिटल को पुन: संचालित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में करेड़ा उप-स्वास्थ्य केन्द्र को पुन: पुराने भवन में संचालित कर ग्रामीणों को राहत प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में संचालित अस्पतालों में चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

127. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आवश्यकतानुसार उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं.61)</u>

128. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डूमरोली (नीमराणा) को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

129. उप-स्वास्थ्य केन्द्र गादोज को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

130. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में वंचित गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. जिला अस्पताल बहरोड़ में DR System With X-Ray मशीन एवं SR System For X-Ray मशीन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. जिला अस्पताल बहरोड़ में मोक्ष वाहिनी वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रशान्त शर्मा (वि.सं.95)

133. सेटेलाईट हॉस्पिटल आमेर में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अचरोल में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने एवं आवश्यक उपकरणों को उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135. विधान सभा क्षेत्र आमेर के चन्दवाजी में ट्रोमा अस्पताल खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

136. विधान सभा क्षेत्र आमेर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौंप को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137. विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्राम पंचायत जयरामपुरा व आकेड़ा डूंगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खॉं (वि.सं.197)

138. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में ट्रोमा सेण्टर में पद सृजित करने एवं चिरंजीवी योजना में सुधार करने एवं भवन विहीन पी.एच.सी.,सी.एच.सी. एवं सब सेण्टरों के भवन निर्माण के लिए बजट स्वीकृत करवाने के लिए विभागीय पहले करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कुलदीप (वि.सं.33)

139. राज्य में चिकित्सकों के पृथक केडर हेतु वर्ष 2011 व 2017 में समझौते के बावजूद भी केडर निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

140. प्रदेश में चिकित्सकों को केन्द्र व अन्य राज्यों (दिल्ली, बिहार आदि) की तर्ज पर मेडीकल कॉलेज चिकित्सकों की तरह चतुर्थ DACP प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)

141. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के सभी राजकीय अस्पतालों में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के बनेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप-जिला स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

143. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के रायला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

144. राजकीय जिला अस्पताल शाहपुरा में ब्लड बैंक व ट्रोमा सेण्टर स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

145. जिला अस्पताल शाहपुरा में एनेस्थेसिया एवं सोनोग्राफी के चिकित्सक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अरूण चौधरी (वि.सं.11)

146. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के कालूड़ी, आसोतरा, ग्वालनाड़ा, कुड़ी, नेबरी एवं मूल की ढाणी में नए पी.एच.सी. खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की ग्राम पंचायत असाडा, पारलू एवं किरनोद में पी.एच.सी. को सी.एच.सी.में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

148. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में स्वीकृत चांदेसरा, टापरा तथा थोब ग्राम पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के कल्याणपुर स्थित राजकीय राजाराम चिकित्सालय में ट्रोमा सेण्टर खोलने एवं चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

150. राजकीय नाहटा चिकित्सालय बालोतरा को 300 बेड में क्रमोन्नत करने एवं उसी अनुरूप स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लादु लाल पितलिया (वि.सं.144)

151. प्रदेश के ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों को केन्द्र व अन्य राज्यों (दिल्ली, बिहार आदि) की तर्ज पर मेडीकल कॉलेज चिकित्सकों की तरह चतुर्थ DACP प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

152. राज्य में चिकित्सकों के पृथक केडर हेतु वर्ष 2011 व 2017 के समझौते के बावजूद केडर निर्माण लंबित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

153. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

155. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पूसाराम गोदारा (वि.सं.91)

156. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ की सी.एच.सी. छापर में रिक्त पदों को भरने एवं नया उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के जिला चिकित्सालय में सभी विशेषज्ञों/चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने एवं पर्याप्त उपकरण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री यूनुस खान (वि.सं.121)

158. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में बजट वर्ष 2017-18 की घोषणा के अनुसार राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना में शय्याओं की क्षमता 300 बेड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र साल्ट रोड़ डीडवाना में पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

160. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में ग्राम शेरानीआबाद में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण की स्वीकृत करने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

161. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में गरदेज्याबासनी, बुड़ोद, आस की ढाणी, खुनखुना गांव, लाडाबास में स्वास्थ्य उप केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में ग्राम निम्बी कलां व बालिया में उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्द्रा (वि.सं.20)

163. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में सभी रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

164. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के बौंली में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और NRHM द्वारा चल रहे सम्पूर्ण निर्माणाधीन कार्यों की जांच के संबंध में चर्चा के लिए।

165. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम डूंगरवाला के स्पाईनल मस्कुलर एसट्रॉपी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का नि:शुल्क ईलाज करने के संबंध में चर्चा के लिए।

166. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के सुकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोडलाई, सांचोली व बिच्छोच में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जुबेर खान (वि.सं.65)

167. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र साहड़ोली (अलवर) का भवन निर्माण हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

168. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ एवं गोविन्दगढ़ (अलवर) के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगांवा में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के गोविन्दगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में शिशु चिकित्सक को पदस्थापित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के गोविन्दगढ़ में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सोनोग्राफी मशीन स्थापित करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री बहादुर सिंह (वि.सं.99)</u>

172. भुसावर चिकित्सालय पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

173. वैर चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर महिला चिकित्सक नियुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

174. विधान सभा क्षेत्र वैर के भुसावर चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन लगवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

175. वैर व भुसावर चिकित्सालयों के रिक्त पदों पर चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ का पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री कँवरलाल (वि.सं.26)</u>

176. राज्य सरकार द्वारा राज्य में चिकित्सकों के पृथक केडर हेतु वर्ष 2011 व 2017 के समझौते के अनुसार आज दिनांक तक चिकित्सकों के पृथक केडर का गठन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

177. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) के चिकित्सकों को केन्द्र व अन्य राज्यों (दिल्ली, बिहार आदि) की तर्ज पर मेडीकल कॉलेज चिकित्सकों की तरह चतुर्थ DACP देने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री शंकरलाल डेचा (वि.सं.158)</u>

178. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) के चिकित्सकों को केन्द्र व अन्य राज्यों (दिल्ली, बिहार आदि) की तर्ज पर मेडीकल कॉलेज चिकित्सकों की तरह चतुर्थ DACP देने के संबंध में चर्चा के लिए।

179. राज्य सरकार द्वारा राज्य में चिकित्सकों के पृथक केडर हेतु वर्ष 2011 व 2017 के समझौते के अनुसार आज दिनांक तक चिकित्सकों के पृथक केडर का गठन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मांगेलाल मीना (वि.सं.117)</u>

180. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के सी.एच.सी. राजगढ़ में सोनोलॉजिस्ट चिकित्सक के पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

181. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में सी.एच.सी. लक्ष्मणगढ़ को 50 बेड से 100 बेड में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

182. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गढ़ीसवाईराम को 30 बेड से 50 बेड में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
183. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मिनास को 30 बेड से 50 बेड में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
184. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ़ को क्रमोन्नत कर जिला चिकित्सालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री कालूराम (वि.सं.31)</u>

185. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) के चिकित्सकों को केन्द्र व अन्य राज्यों (दिल्ली, बिहार आदि) की तर्ज पर मेडीकल कॉलेज चिकित्सकों की तरह चतुर्थ DACP देने के संबंध में चर्चा के लिए।
186. सरकार द्वारा राज्य में चिकित्सकों के पृथक केडर हेतु वर्ष 2011 व 2017 के समझौते के अनुसार केडर का गठन शीघ्र करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री कैलाश चन्द वर्मा (वि.सं.36)</u>

187. राज्य सरकार द्वारा किए गए समझौते के आधार पर सेवारत चिकित्सकों का पृथक केडर बनाने एवं दिल्ली, बिहार आदि व अन्य राज्यों की तर्ज पर मेडीकल कॉलेज चिकित्सकों की भांति DACP स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अर्जुन लाल जीनगर (वि.सं.13)</u>

188. स्वास्थ्य विभाग में भवन विहीन चिकित्सालयों तथा उप-केन्द्रों के नवीन भवन एवं क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत कराने की राशि उपलब्ध करवाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
189. विधान सभा क्षेत्र कपासन के उप-जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
190. उप-स्वास्थ्य केन्द्र भीमगढ़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने एवं उप-स्वास्थ्य केन्द्र सुरपुर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डा. ऋतु बनावत (वि.सं.24)</u>

191. विधान सभा क्षेत्र बयाना की बंध वारेण पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में व मिल्समा, पुरा मालोनी, वीरमपुरा, समोगर, दाहिना ओर सामरी के उप-स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

192. विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूदावल सी.एच.सी. को मॉडल सी.एच.सी. बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अजय सिंह (वि.सं.02)</u>

193. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम पुन्दलोता एवं जाखेड़ा की पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

194. डेगाना उप जिला चिकित्सालय में ट्रोमा सेण्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

195. डेगाना के उप जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

196. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम आधोजाई, मुण्डेलपुरा, पण्डवाला, रावलियास एवं बाज्यासर में उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

197. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम चुई, आंतरोली कलां, बिखरनिया कलां एवं चान्दारूण में पी.एच.सी. स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री कालूराम (वि.सं.31)</u>

198. झालावाड़ मेडीकल कॉलेज में आवश्यक नए विभाग खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)</u>

199. विधान सभा क्षेत्र शिव में उप-स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

200. विधान सभा क्षेत्र शिव के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शिव को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

201. विधान सभा क्षेत्र शिव में चिकित्सा विभाग में रिक्त पड़े पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री चेतन पटेल कोलाना (वि.सं.53)</u>

202. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में चिकित्सकों व स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

203. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

204. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भवन नवनिर्माण कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

205. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोगरा (वि.सं.39)

206. डूंगरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्साधिकारी एवं नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

207. पूर्ववर्ती सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को निरन्तर रखकर 25 लाख के नि:शुल्क ईलाज योजना में नए अस्पतालों को जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

208. जिला चिकित्सालय डूंगरपुर में वार्डों एवं शौचालयों को साफ-सफाई हेतु सफाई कर्मचारियों को सफाई करने हेतु पाबन्द करवाया जाकर ठेकेदारों को भी सफाई करवाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

209. विधान सभा क्षेत्र डूँगरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिच्छीवाड़ा में नये मोर्चरी भवन का निर्माण कराए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

210. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में वर्ष 2022-23 बजट घोषणा में स्वीकृत ट्रोमा सेण्टर बिच्छीवाड़ा का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण कराए जाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़) (वि.सं.112)

211. प्रदेश में कार्यरत चिकित्सकों के केडर निर्माण में RAS, RPS की तरह राज्य सेवा में प्रवेश के समय RPSC की वरिष्ठता सूची को ही केडर निर्माण और पदोन्नति का आधार बनाए जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (वि.सं.30)

212. प्रदेश के सभी चिकित्सा केन्द्रों पर रिक्त नर्सिंग स्टाफ, पैरा मेडीकल स्टाफ आदि पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

213. जयपुर शहर के मालवीय नगर सेक्टर नम्बर-3 के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दन्त चिकित्सक के रिक्त पद पर पदस्थापन के संबंध में चर्चा के लिए।

214. जयपुर के मालवीय नगर सेक्टर नंबर-6 के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर महिला चिकित्सक के अतिरिक्त पद की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

215. विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

216. प्रदेश के चिकित्सा केन्द्रों पर नए चिकित्सकों के पद सृजित कर पदस्थापन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (वि.सं.62)

217. विधान सभा क्षेत्र मकराना के कोलाडूंगरी, सरनावड़ा, रामसिया एवं इन्दौखा उप-स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

218. विधान सभा क्षेत्र मकराना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिण्डालिया (मकराना) के भवन निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

219. उप जिला अस्पताल मकराना सी.एच.सी. बोरावड़, गच्छीपुरा व बुडसू में स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

220. विधान सभा क्षेत्र मकराना के राणीगांव, बेसरोली एवं मनाणा पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

221. उप जिला अस्पताल मकराना को जिला अस्पताल (ट्रोमा सेण्टर सहित) में क्रमोन्नत करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मनीष यादव (वि.सं.111)

222. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के उप-स्वास्थ्य केन्द्र तिगरिया को पीएचसी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

223. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में शाहपुरा उप-जिला चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

224. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के अमरसर में सी.एच.सी. को उप-जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

225. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में पी.एच.सी. खोरालाडरवानी को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

226. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित मीना (वि.सं.142)

227. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में शाहबाद उपखण्ड पर उप-जिला स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

228. प्रदेश में निर्धन व्यक्तियों को सस्ती दर पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

229. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के आदिवासी क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भंवरगढ़ को ट्रोमा सेण्टर में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री विकास चौधरी (वि.सं.148)

230. राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल की आपातकालीन ईकाई एवं ट्रोमा सेण्टर की व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने के साथ ही कार्डियक ईकाई भी स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ललित यादव (वि.सं.143)

231. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहजहांपुर में बेड की संख्या 30 से 50 करने एवं रिक्त पड़े 15 पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

232. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 बेड से 50 बेड करने एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ पदस्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं.176)

233. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीकृत विभिन्न जांच सुविधाएं नियमित रूप से उपलब्ध कराने के लिए खराब मशीनों को बदलवाने/सही कराने और जांच हेतु पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

234. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पड़े चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ व अन्य विभिन्न पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

235. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के ग्राम अंबाला, ईरली, हीचड़, बधाखेड़ी, उम्मेदपुरा में नए उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने तथा ग्राम शिव नगर ढाणी नरसिंहपुरा, सरकन्द्रया के उप-स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

236. विधान सभा क्षेत्र खानपुर की खानपुर तहसील में उप जिला चिकित्सालय एवं बकानी में सेटेलाईट चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

237. झालावाड़ जिले के उप-स्वास्थ्य केन्द्र तीनधार, बढ़ाई, सलावद, आगरिया, कुशलपुरा, किशनपुरा को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने तथा सारोला में 30 से 50 बेड और रटलाई में 30 से 50 बेड क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रतन देवासी (वि.सं.122)

238. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के रानीवाड़ा उपखण्ड मुख्यालय पर ट्रोमा सेण्टर खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

239. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीवाड़ा, जिला-सांचौर को उप जिला स्तर का चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

240. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पांचला, सांकड, करवाडा, बड़गांव, मालवाडा, कागमाला व राजीकावास को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

241. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त कार्मिकों के पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

242. विधान सभा क्षेत्र रानीवाडा के स्वास्थ्य केन्द्र रानीवाडा व जसवन्तपुरा में आवश्यक संसाधनों की कमी को पूरा करने एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जसवन्तपुरा में शय्याओं की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री समरजीत सिंह (वि.सं.174)</u>

243. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित चिकित्सालय को उप जिला चिकित्सालय बनाने एवं रिक्त पदों को भरने व संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

244. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित उप जिला चिकित्सालय में डायलिसिस मशीनें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

245. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के सी.एच.सी. में चिकित्सकों व पैरा मेडीकल के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

246. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के रामसीन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के जल्द निर्माण कार्य शुरू करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

247. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पड़े पदों को स्थायी रूप से भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री शंकरलाल डेचा (वि.सं.158)</u>

248. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में ओजी तहसील की सी.एच.सी. पर मोर्चरी स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती सुशीला रामेश्वर डूडी (वि.सं.185)</u>

249. जिला अस्पताल नोखा के भवन निर्माण हेतु पुनः निविदा जारी कर यथाशीघ्र जिला चिकित्सालय नोखा के भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री महेन्द्र पाल मीना (वि.सं.115)</u>

250. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नेशनल हाईवे नंबर-148 पर रायसर भावनी के पास ट्रोमा अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

251. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विभिन्न चिकित्सा भवनों की मरम्मत के संबंध में चर्चा के लिए।

252. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में उप-स्वास्थ्य केन्द्र/सी.एच.सी. खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

253. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

254. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में उप-जिला चिकित्सालयों में जिला चिकित्सालयों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शिमला देवी (वि.सं.163)

255. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के चिकित्सा संस्थानों में जांच का दायरा बढ़ाने व सोनोग्राफी की सुविधा सुलभ कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

256. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के चिकित्सा संस्थानों में रिक्त चल रहे चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ के पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

257. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में चिकित्सा संस्थानों के भवन निर्माण/मरम्मत कार्यों हेतु बजट आवंटन के संबंध में चर्चा के लिए।

258. नवगठित जिला अनूपगढ़ में जिला अस्पताल के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।

259. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के सुचारू रूप से संचालन के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जेठानन्द व्यास (वि.सं.66)

260. राज्य सरकार द्वारा राज्य में चिकित्सकों के पृथक केडर हेतु वर्ष 2011 व 2017 के समझौते के अनुसार केडर गठन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

261. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) के चिकित्सकों को केन्द्र व अन्य राज्यों (दिल्ली, बिहार आदि) की तर्ज पर मेडिकल कॉलेज चिकित्सकों की तरह चतुर्थ DACP (ग्रेड-पे 9500/-) प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

262. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में जनता क्लिनिक के संचालन एवं नवीन अतिरिक्त जनता क्लिनिक स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

263. बीकानेर के पी.बी.एम. चिकित्सालय में हृदय रोग चिकित्सा विभाग में जांच सुविधाएं बढ़ाने एवं शल्य चिकित्सक की नियुक्ति के संबंध में चर्चा के लिए।

264. गंगाशहर सेटेलाईट चिकित्सालय में नर्सिंग स्टाफ एवं चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

डॉ. प्रियंका चौधरी (वि.सं.96)

265. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में अणदे का तला ग्राम पंचायत जाखड़ों की ढाणी ब्लॉक बाड़मेर तथा जाणियों की ढाणी, ग्राम पंचायत मुढों की ढाणी एवं मुले का तला ग्राम पंचायत गंगासरा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

266. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सनावड़ा एवं बेरिवाला तला को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री गोपाल लाल शर्मा (वि.सं.44)</u>

267. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में स्थित सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

268. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की ग्राम पंचायत बड़लियास और नन्दराय में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

269. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की ग्राम पंचायत किशनगढ़ और ककरोलिया घाटी में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

270. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के ग्राम भेरूखेड़ा, गोविंदपुरा, गंधेरी और चौंहली में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

271. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में स्थित सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए पर्याप्त सुविधा युक्त भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)</u>

272. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मेडिकल जांचों के लिए HUB AND SPOKE MODEL इन हाउस केपेसिटी बिल्डिंग (Building) उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

273. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के शहरी क्षेत्रों में जनता क्लिनिक नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

274. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के MBS अस्पताल में एम.आर.आई. एवं सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

275. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के खनन क्षेत्रों में सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की पहचान हेतु कैम्प आयोजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

276. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में राष्ट्रीय वृद्धजन सेवा कार्यक्रम के तहत मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ सहित ग्राम पंचायत स्तर पर कैम्प आयोजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डॉ. शिखा मील बराला (वि.सं.162)

277. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

278. चौमूं में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–जाटावाली के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

279. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के कालाडेरा कस्बे की सीएचसी के लिए नये भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

280. प्रदेश में MAA योजना (मु.म. आयुष्मान आरोग्य) में प्रसव पैकेज (डिलीवरी) को प्राईवेट अस्पतालों से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डॉ. शैलेश सिंह (वि.सं.164)

281. विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर के उप.स्वा. केन्द्र लॉकी(कुम्हेर) को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयकृष्ण पटेल (वि.सं.116)

282. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में आनन्दपुरी में स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

283. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में उप स्वास्थ्य केन्द्रों में मूलभूत सुविधाओं हेतु मशीनरी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

284. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

285. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में रोगी वाहनों (108/104) की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल सी.एल.प्रेमी बैरवा (वि.सं.52)

286. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के लबान एवं पीपल्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झालीजी का बराना एवं बड़ाखेड़ा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

287. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समीधी और बलकासा के भवन निर्माण हेतु बजट स्वीकृत करवाकर जल्द निर्माण कार्य आरंभ करवाने एवं चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

288. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

289. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के करवर से जैतपुर-तलवास मार्ग और करवर से समीधी मार्ग पर रोगियों की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष मील (वि.सं.179)

290. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के प्रा.स्वा. केन्द्र कांसरड़ा (खण्डेला) पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

291. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के उप स्वास्थ्य केन्द्र लांपुवा (खण्डेला) को .एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

292. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के बावड़ी, केरपुरा एवं पीपलोदा का बास में नवीन प्रा.स्वा. केन्द्र (पी.एच.सी.) खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विनोद कुमार (वि.सं.153)

293. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के रावतसर शहरी क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

294. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोलूवाला में 30 बेड की सी.एच.सी. को 70 बेड में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

295. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में उप स्वास्थ्य केन्द्र उम्मेवाला, रामपुरा, चाईया एवं धन्नासर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गंधेली एवं जाखड़ावाली को सामुदायिक केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

296. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के रावतसर में स्थित सी.एच.सी. को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

297. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीलीबंगा में 30 बेड की सी.एच.सी. को 70 बेड में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कान्ति प्रसाद (वि.सं.29)

298. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में पी.एच.सी/सी.एच.सी. के भवन निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत भी सभी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

299. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामबिलास (वि.सं.135)

300. विधान सभा क्षेत्र लालसोट में लालसोट कस्बे में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्यामपुरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री लक्ष्मण राम (वि.सं.141)</u>

301. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जसनगर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

302. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पादूकलां को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेण को सामुदायिक लिये।

303. स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

304. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के मेड़ता शहर स्थित पुराने अस्पताल को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं.131)</u>

305. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के शहीद राजमल मीणा राजकीय चिकित्सालय बारां के जर्जर भवन का नया निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

306. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू स्थित शहीद राजमल मीणा चिकित्सालय में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

307. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में शहीद राजमल मीणा चिकित्सालय में नया ट्रोमा सेंटर खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

308. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में गायत्री नगर में पी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री <u>अंशुमान सिंह भाटी (वि.सं. 01)</u>

309. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के ग्रामीण अंचल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्रों में पद रिक्त होने से जनता में व्याप्त रोष से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

310. बीकानेर शहर के मुख्य चिकित्सालयों (पी.बी.एम. वगैरह) में चिकित्सक एवं पैरा-चिकित्सक कर्मचारी तथा तकनीकी कर्मचारियों के पद रिक्त होने से जनता में व्याप्त रोष से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

311. उप जिला चिकित्सालय कोलायत व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गजनेर में रेडियोलॉजिस्ट के पद रिक्त होने से जनता में उपजे रोष के संबंध में चर्चा के लिये।

312. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किल्चू आर.डी. 820, बरसलपुर एवं बीकमपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

313. बी.सी.एम.ओ. कार्यालय कोलायत व बज्जू में भवन निर्माण में आ रही समस्या पर चर्चा के लिये।

<u>श्री घनश्याम (वि.सं. 50)</u>

314. गंगापुर सिटी जिले के सभी चिकित्सालयों में एंटी-रैबीज के इंजेक्शन के अभाव में हो रही असुविधा के संबंध में चर्चा के लिये।

315. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी के पी.एच.सी. एवं सी.एच.सी. चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

316. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टॉफ के रिक्त पदों को अविलम्ब भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री भागचन्द टांकड़ा (वि.सं. 106)</u>

317. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में स्थित उप जिला चिकित्सालय बांदीकुई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसवा, उप स्वास्थ्य केन्द्र कोलवा, केसरीसिंहपुरा, पीचूपाड़ा खुर्द, भांवता, गुल्लाना, कोलाना, पण्डितपुरा, अगावली, झाझीरामपुरा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अरनिया एवं बडियाल कलां को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

318. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में स्थित उप जिला चिकित्सालय बांदीकुई में ब्लड बैंक खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री गुरवीर सिंह (वि.सं. 42)</u>

319. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में मिर्जेवाला सी.एच.सी. में डिजीटल-एक्स-रे मशीन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

320. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के एस.डी.एच. में अल्ट्रा-साऊण्ड मशीन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

321. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर जिला चिकित्सालय में 124 स्लाइड्स की सी.टी. स्कैन मशीन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

322. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की चुनावद सी.एच.सी. में डिजीटल-एक्स-रे मशीन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री भीम राज भाटी (वि.सं. 107)</u>

323. बांगड़ अस्पताल, पाली द्वारा मरीजों को जोधपुर रैफर करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

324. बांगड़ अस्पताल, पाली में चिकित्सकों द्वारा बाहरी निजी जांच चिकित्सालयों से जांच के लिये प्रेरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

325. ब्लड बैंक बांगड अस्पताल पाली में जरूरतमंद मरीजों को ब्लड उपलब्ध करवाने के मामले में भेदभाव एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

326. बांगड़ अस्पताल, पाली में खराब चिकित्सा उपकरणों को दुरस्त करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अतुल भंसाली (वि.सं. 03)

327. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर के सभी स्तर के सरकारी अस्पतालों में उनके स्तर अनुरूप समस्त संसाधनों की उपलब्धता करवाने और सेटेलाइट और जिला अस्पताल को 24 घण्टे खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

328. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में एयरफोर्स क्षेत्र, रोटरी सर्किल से डीजल शेड़ के क्षेत्र में, सरदारपुरा ए.बी.सी.डी. रोड़ सम्पूर्ण क्षेत्र में एवं शास्त्री नगर परिक्षेत्र में नवीन पी.एच.सी. खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

329. चिरंजीवी एवं आर.जी.एच.एस. योजनान्तर्गत भुगतान के प्रमाणीकरण के लिए लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करवाने एवं प्रकरण अनावश्यक लंबित नहीं रहे, इस हेतु प्रक्रियागत सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

330. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर के राजकीय सेटेलाईट चिकित्सालय नवचौकिया, जोधपुर में तकनीक अड़चन से अटके सेटेलाईट स्तर अनुरूप विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जनहित में अविलम्ब स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

331. सी.एम. एण्ड एच.ओ. जोधपुर कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में गत पांच वर्षो में प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा नियुक्त संविदाकर्मियों की नियुक्ति, उनके द्वारा धारित दायित्वों एवं इतर दायित्वों में, भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के विषयों की उच्च स्तरीय जांच करवाने एवं ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त संविदाकर्मियों को अविलम्ब बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (वि.सं. 123)

332. प्रदेश में चिरंजीवी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (वि.सं. 102)

333. जयपुर स्थित जयसिंहपुरा खोर में सैटेलाइट हॉस्पिटल खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

334. जयपुर स्थित गणगौरी हॉस्पिटल में व्याप्त अनियमितताओं की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

335. जयपुर शहर स्थित गणगौरी हॉस्पिटल में स्मार्ट-सिटी के तहत हुए कार्यों में अनियमितताओं की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र (वि.सं. 128)

336. विधान सभा क्षेत्र महुवा के जिला अस्पताल, चार सी.एच.सी. तथा आधा दर्जन पी.एच.सी. तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टॉफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

337. विधान सभा क्षेत्र महुवा के जिला अस्पताल को रैफरल हॉस्पिटल घोषित करने तथा ब्लड बैंक स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हरलाल सहारण (वि.सं. 191)</u>

338. प्रदेश में लैब सहायक के समकक्ष संविदा पर लगे दन्त सहायक जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सेवायें दे रहे हैं, उनका कैडर बनाकर नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

339. राज्य सरकार द्वारा राज्य में चिकित्सकों के पृथक कैडर हेतु वर्ष 2011 व 2017 के समझौते के अनुसार कैडर गठित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

340. राज्य सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण व दुरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों को केन्द्र व अन्य राज्यों (दिल्ली, बिहार आदि) की तर्ज पर मेडिकल कॉलेज चिकित्सकों की तरह चतुर्थ डीएसीपी (ग्रेड-पे-9500) प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

341. विधान सभा क्षेत्र चुरू के कुणसीसर उप स्वास्थ्य केन्द्र को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

342. विधान सभा क्षेत्र चुरू के पी.एच.सी., खाखोली को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>सुश्री नौक्षम (वि.सं. 86)</u>

343. विधान सभा क्षेत्र कामां के कामां सरकारी अस्पताल में एमआरआई एवं सीटी-स्कैन मशीन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

344. विधान सभा क्षेत्र कामां के गोपालगढ़ अस्पताल में डॉक्टर व नर्सिंग स्टॉफ लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

345. विधान सभा क्षेत्र कामां के कामां अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन, सोनोलोजिस्ट का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री जब्बर सिंह सांखला (वि.सं. 57)</u>

346. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के कंवलियास (हुरड़ा) पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

347. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के ब्रा. की सरेरी (आसीन्द) पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

348. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के बरसनी तहसील आसिन्द के सब-सेन्टर को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

349. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द की भादसी तहसील बदनोर सब-सेन्टर को पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

350. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द की आसीन्द अस्पताल को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अभिमन्यु (वि.सं.07)</u>

351. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के संगरिया एवं टिब्बी में अस्पतालों में डॉक्टर व नर्सिंगकर्मी को पदस्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

352. विधान सभा क्षेत्र संगरिया की ग्राम पंचायत सुरेवाला में सी.एच.सी. की अविलम्ब स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री भीम राज भाटी (वि.सं.107)</u>

353. विधान सभा क्षेत्र पाली की चेन्डा पी.एच;सी. को मॉडर्न सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री पूसाराम गोदारा (वि.सं.91)</u>

354. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में नयी पीएचसी. खोलने एवं पर्याप्त मात्रा में स्टाफ की नियुक्ति के संबंध में।

355. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ के कस्बा पड़िहारा की सीएचसी में चिकित्सकोंके रिक्त पदों को भरने एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं.131)</u>

356. विधान सभा क्षेत्र बारां अटरू में शहीद राजमल मीणा चिकित्सालय में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री थावर चन्द (वि.सं.75)</u>

357. प्रदेश के एन.एच.एम. में आयुष्मान भारत के अन्तर्गत कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की प्रमुख मांगों के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)</u>

358. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) के चिकित्सकों को केन्द्र व अन्य राज्यों (दिल्ली, बिहार आदि) की तर्ज पर मेडिकल कॉलेज चिकित्सकों की भांति चतुर्थ डी.ए.सी.पी. (ग्रेड-पे 9500/-) दिए जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)</u>

359. विधान सभा क्षेत्र शिव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट 2

मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 28 - **चिकित्सा शिक्षा** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

<u>श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं. 159)</u>

1. जिला ब्यावर में मेडिकल कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री सोहन लाल नायक (वि.सं. 186)</u>

2. प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के लैक्चरर्स की सेवानिवृत्ति आयु बढाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>डॉ. ऋतु बनावत (वि.सं. 24)</u>

3. विधान सभा क्षेत्र बयाना में राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री ललित मीना (वि.सं. 142)</u>

4. मेडिकल कॉलेज बारां को प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं. 168)</u>

5. निम्बाहेड़ा उपखण्ड मुख्यालय पर ए.एन.एम. नर्सिंग स्कूल खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।
6. नर्सिंग कॉलेज, निम्बाहेड़ा में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. निम्बाहेड़ा उपखण्ड मुख्यालय पर पैरा मेडिकल कोर्सेज संचालित करने के संबंध में चर्चा के लिये।
8. छोटी सादड़ी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र (टीएसपी) में ए.एन.एम. अथवा जी.एन.एम. नर्सिंग स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. निम्बाहेड़ा उपखण्ड मुख्यालय पर जी.एन.एम. नर्सिंग स्कूल खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री अमृतलाल मीणा (वि.सं. 10)</u>

10. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर जिला मुख्यालय पर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
11. प्रदेश में बढ़ते निजी चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय से अभिभावकों पर बढ़ रहे आर्थिक भार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
12. प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को गुणवत्तायुक्त एवं सुविधायुक्त बनाने के लिए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
13. प्रदेश में राजकीय चिकित्सा विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए सीटें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. राजकीय महाराणा भूपाल चिकित्सालय, उदयपुर में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>**श्री अमित चाचाण (वि.सं. 08)**</u>

15. विधान सभा क्षेत्र नोहर में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>**श्री लक्ष्मण (वि.सं. 140)**</u>

16. प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी के विभिन्न श्रेणी एवं बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेजों में टीचिंग स्टॉफ के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>**श्री रोहित बौहरा (वि.सं. 139)**</u>

17. निजी मेडिकल कॉलेजों में फीस नहीं बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>**श्री केसाराम चौधरी (वि.सं. 35)**</u>

18. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम सिरयारी में नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>**श्री बाबूसिंह राठौड़ (वि.सं. 101)**</u>

19. डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज जोधपुर में पीजी की सीटें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
20. मेडिकल कॉलेज से समबद्ध अस्पतालों के आपातकालीन इकाइयों में वरिष्ठ चिकित्सकों, विशेषज्ञों, सीनियर रेजीडेन्ट एवं रेजीडेन्ट की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जयपुर मुख्यालय से नियंत्रित केन्द्रीकृत सीसीटीवी तंत्र की स्थापना प्रत्येक आपातकालीन इकाई में करने की विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>**श्री अर्जुन लाल (वि.सं. 12)**</u>

21. प्रदेश में चिकित्सा सुविधा के सुधार हेतु पैरा मेडिकल/नर्सिंग कॉलेज की नवीन संस्थान प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर खोलने एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज संस्थानों में चिकित्सा शिक्षा के रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
22. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के बिलाड़ा/पीपाड़ शहर में राजकीय पैरा-मेडिकल/नर्सिंग/फॉर्मेसी/डेंटल डिप्लोमा विषय के संस्थान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>**श्री थावर चन्द (वि.सं. 75)**</u>

23. विधान सभा क्षेत्र धरियावद के धरियावद में नर्सिंग कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>**श्री देवेन्द्र जोशी (वि.सं. 82)**</u>

24. रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट, जोधपुर को अर्जेन्ट टेम्परेरी बेसिस पैटर्न पर नियुक्त चिकित्सकों के भरोसे चलाये जाने की औपचारिकता से कैंसर रोगियों के उपचार के लिए

प्रभावी केन्द्र के रूप में विकास करने के लिए आवश्यक पद स्वीकृत कर पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के संलग्न सभी चिकित्सालयों में गत पांच वर्षों में उपकरणों की खरीद प्रक्रिया की, आवश्यकता का प्रतिपादन, बजट प्रावधान, खरीद प्रक्रिया की ऑडिट, खरीद के बाद उपकरण का उपयोग और लाभान्वित संख्या सहित सभी बिन्दुओं की उच्च स्तरीय जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
26. डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के साथ एम्स का एम.ओ.यू. करके विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के चिकित्सालयों में शोध प्रशिक्षणार्थी चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
27. डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के संलग्न सभी चिकित्सालयों में एम्स की तर्ज पर रोगियों को अनावश्यक कष्टों से बचाने के लिए जांच रिपोर्ट्स को पंजीकृत रोगी के मोबाइल पर आनलाईन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
28. डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर संलग्न उम्मेद अस्पताल, जोधपुर में सी.टी. स्कैन, रंगीन सोनोग्राफी के दो उपकरण मय पद स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं. 190)</u>

29. बालोतरा जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
30. सिवाना उप जिला अस्पताल में नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री अशोक कुमार कोठारी (वि.सं. 17)</u>

31. विजयराजे सिंधिया राजकीय मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा में विद्यार्थियों हेतु एक नवीन हॉस्टल निर्माण एवं पुराने हॉस्टल को फर्नीचरयुक्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
32. विजयराजे सिंधिया राजकीय मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा में मेडिकल स्टुडेंट हेतु नवीन मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।
33. विजयराजे सिंधिया राजकीय मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा में चिकित्सकों हेतु आधुनिक सुविधायुक्त नवीन आवास निर्माण के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं. 113)</u>

34. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर की नियुक्ति एवं कैथ-लैब की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (वि.सं. 51)

35. विधान सभा क्षेत्र चित्तौडगढ़ के मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर कक्षा आरम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
36. विधान सभा क्षेत्र चित्तौडगढ़ के मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
37. मेडिकल कॉलेज चित्तौडगढ़ में कैंसर यूनिट एवं बर्न यूनिट की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।
38. विधान सभा क्षेत्र चित्तौडगढ़ के जिला चिकित्सालय में गार्डन को विकसित कर पर्याप्त बैठक व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (वि.सं. 04)

39. प्रदेश में मेडिकल चिकित्सा शिक्षा को और सुदृढ करने हेतु अजमेर स्थित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
40. अजमेर दक्षिण में स्थित आदर्श नगर जिला चिकित्सालय में नवीन नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।
41. प्रदेश के साथ ही अजमेर के निजी नर्सिंग कॉलेज राजस्थान हॉस्पीटल स्कूल ऑफ नर्सिंग में विद्यार्थियों से पूरी फीस वसूलने के बावजूद नियमित कक्षाऐं आयोजित न कर घर बैठे नर्सिंग कोर्स कराये जाने के लिये अतिरिक्त पैसों की मांग किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
42. जयपुर के अतिरिक्त प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर एवं पैरा-मेडिकल स्टॉफ की अत्यधिक कमी होने के कारण कॉलेजों की मान्यता पर संकट उत्पन्न होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।
43. अजमेर में जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक बनाये जाने के साथ ही ऑकोलोजी विभाग बनाया जाने के अतिरिक्त यूरोलॉजी विभाग में चल रहे एम.सी.एच. कोर्स के लिए एन.एम.सी. के नियमन के अनुसार फैकल्टी लगायी जाये जिससे यहां एम.सी.एच. कर रहे विद्यार्थियों को रिकगनिशन (संबद्धता) की समस्या से निजात दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं. 54)

44. विधान सभा क्षेत्र आहोर में नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए प्राप्त आवेदन के संबंध में चर्चा के लिये।
45. विधान सभा क्षेत्र आहोर में अतिरिक्त नर्सिंग कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
46. प्रदेश में प्राईवेट नर्सिंग कॉलेज खोलने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

47. जालोर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति, उसके लिए आवंटित बजट एवं इसकी टेण्डर प्रक्रिया के संबंध में चर्चा के लिये।
48. जालोर जिले में मेडिकल कॉलेज के कार्य को शुरू करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं. 80)</u>

49. राजसमन्द जिला मुख्यालय पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।
50. राजसमन्द जिला मुख्यालय पर दन्त चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।
51. राजकीय एवं राजमेस चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नात्तक एवं स्नातकोत्तर प्रवेश की सीटों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
52. राजमेस द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में विशेषज्ञों की कमी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
53. राजसमन्द जिला मुख्यालय पर राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री हरिसिंह रावत (वि.सं. 193)</u>

54. विधान सभा क्षेत्र भीम में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं. 150)</u>

55. जिला अस्पताल नवलगढ़ में राजकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं. 72)</u>

56. सूरतगढ में राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।
57. प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के छात्रावासों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
58. प्रदेश के प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों द्वारा छात्रों से सुविधाओं के नाम पर की जा रही वसूली के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री फूल सिंह मीणा (वि.सं. 98)</u>

59. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा की क्षतिग्रस्त बिल्डिंग्स के भवनों की मरम्मत करवाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं. 192)</u>

60. विधान सभा क्षेत्र बून्दी में सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं के उपकरणों की जल्द से जल्द उपलब्धता के संबंध में चर्चा के लिए।
61. विधान सभा क्षेत्र बून्दी के मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

62. मेडिकल कॉलेज, बून्दी में पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री उदयलाल भडाणा (वि.सं. 22)

63. मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा में ग्रामीण परिवेश के गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान करने हेतु छात्र प्रवेश क्षमता (सीटों) को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
64. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में मेडिकल कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।
65. विधान सभा क्षेत्र माण्डल के करेड़ा क्षेत्र में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।
66. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं. 61)

67. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नर्सिंग कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।
68. जिला कोटपूतली के बहरोड़ में मेडिकल कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खां (वि.सं. 197)

69. मेडिकल कॉलेज, सीकर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अरूण चौधरी (वि.सं. 11)

70. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा में नर्सिंग संस्थान (जीएनएम) खोलने की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।
71. बालोतरा जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
72. उदयपुर स्थित मेडिकल कॉलेज के अन्तर्गत चल रहे नर्सिंग कॉलेज को मान्यता न होने के उपरान्त भी विद्यार्थियों को पढ़ाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
73. प्रदेश के अधिकांश निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा छात्रों को जबरन अनुतीर्ण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री यूनुस खान (वि.सं. 121)

74. नवगठित जिला मुख्यालय डीडवाना में मेडिकल कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
75. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में नर्सिंग कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (वि.सं. 65)

76. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के पंचायत समिति मुख्यालय गोविन्दगढ़ (अलवर) में नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।
77. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में स्वीकृत नर्सिंग इंस्टीट्यूट (ढाढ़ोली ग्राम में निर्मित) को शुरू करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>डॉ. ऋतु बनावत (वि.सं. 24)</u>

78. बयाना में ए.एन.एम. एवं जी.एन.एम. प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
79. बयाना में डी.फॉर्मा कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री लालाराम बैरवा (वि.सं. 145)</u>

80. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के जिला मुख्यालय शाहपुरा में नर्सिंग कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं. 126)</u>

81. प्रदेश के सरकारी बड़े अस्पतालों में सहायक प्रोफेसर व अन्य चिकित्सकों की इमरजेन्सी में उपस्थिति सुनिश्चित करने के सबंध में चर्चा के लिये।
82. विधान सभा क्षेत्र शिव में नर्सिंग कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।
83. विधान सभा क्षेत्र शिव में मेडिकल कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।
84. जोधपुर संभाग के समस्त मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों को भरने व अतिरिक्त पद सृजित करने के संबंध में चर्चा के लिये।
85. जोधपुर संभाग में मेडिकल कॉलेज के प्रिन्सीपल एवं प्रोफेसरों को कॉलेज कैम्पस में ही रहने हेतु सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री गणेश घोगरा (वि.सं. 39)</u>

86. मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में अध्ययनरत विद्यार्थियों के साथ रेगिंग के मामलों को रोकने एवं उच्च स्तरीय समिति गठित कर पीड़ित छात्रों को न्याय दिलवाने एवं राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजों में इसकी सख्ती से पालना करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
87. मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में फैकल्टी एवं नर्सिंग स्टॉफ की खाली सीटें भरने के संबंध में चर्चा के लिये।
88. मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में नर्सिंग स्टॉफ के नये पद स्वीकृत कर जल्द से जल्द राजमेस या अन्य ऐजेन्सी के मार्फत भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
89. मेडिकल कॉलेज के प्रिन्सीपल एवं प्रोफेसरों को कॉलेज कैम्पस में ही रहने हेतु पाबन्द किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री कालीचरण सराफ (वि.सं. 30)</u>

90. प्रदेश के सबसे बड़े बच्चों के हॉस्पीटल जे.के. लोन हॉस्पीटल, जयपुर में एस.एम.एस. हॉस्पीटल, जयपुर की तर्ज पर आई.पी.डी. टॉवर बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
91. एस.एम.एस. हॉस्पीटल, जयपुर में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. जयपुर के जयपुरिया हॉस्पीटल में बैड्स की संख्या में हुई बढ़ोतरी के अनुरूप चिकित्सकों के नए पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
93. जयपुर के जयपुरिया हॉस्पीटल में बैड्स की संख्या में हुई बढ़ोतरी के अनुरूप नर्सिंग स्टॉफ, पैरा-मेडिकल स्टॉफ के नए पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
94. प्रदेश के बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल जे.के. लोन हॉस्पीटल, जयपुर में बैड्स बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री मनीष यादव (वि.सं. 111)</u>

95. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के खेजरोली में नवीन नर्सिंग कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
96. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के अमरसर में ए.एन.एम. ट्रैनिंग सेन्टर में भवन का जीर्णोद्वार करने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
97. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में मेडिकल कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
98. एस.एम.एस. अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री ललित मीना (वि.सं. 142)</u>

99. बारां नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में सीटों के आवंटन पर विभागवार विचार-विमर्श करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री विकास चौधरी (वि.सं. 148)</u>

100. चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किशनगढ़ में राजकीय नर्सिंग कॉलेज की स्थापना तथा रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री ललित यादव (वि.सं. 143)</u>

101. चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुण्डावर में राजकीय नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं. 176)</u>

102. मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में सुपर स्पेशियेलिटी सेवाओं के विस्तार एवं रिक्त पड़े पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
103. मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में वर्षों से निर्माणाधीन अधूरे, टर्शरी केयर सेन्टर और ट्रोमा सेन्टर का कार्य पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
104. मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में यू.जी. की सीटें बढ़ाने और पी.जी. में फार्माकोलॉजी, आई-स्पेशिएलिटी, मानसिक रोग एवं स्किन रोगों के पाठ्यक्रम खोलकर सीटें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
105. झालावाड़ जिले की खानपुर तहसील में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, झालावाड़ में संविदा अथवा ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त किये जाने वाले अस्थाई कर्मियों की भर्ती भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शिता से किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री रतन देवासी (वि.सं. 122)</u>

107. उपखण्ड मुख्यालय रानीवाड़ा पर नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री लादु लाल पितलिया (वि.सं. 144)</u>

108. नीट पीजी एवं नीट एमएस में प्रवेशित बेड स्पेशिलिटी एवं सुपर स्पेशिलिटी विभागों में सीनियर रेजीडेन्ट एवं सहायक आचार्य पद हेतु राज्य सरकार में कार्यरत स्पेशिलिटी चिकित्सकों को जो एक वर्ष के लिए आवंटित किया जाता है को राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक स्थास्थ्य केन्द्र से इन चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति चिकित्सा शिक्षा विभाग में नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री महेन्द्र पाल मीना (वि.सं. 115)</u>

109. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नर्सिंग कॉलेज खोलने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती शिमला देवी (वि.सं. 163)</u>

111. नवगठित जिला अनूपगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री जेठानन्द व्यास (वि.सं. 66)</u>

112. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पश्चिम) में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पश्चिम) में चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>डॉ. प्रियंका चौधरी (वि.सं. 96)</u>

114. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में स्थित राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय, बाड़मेर में पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग डिग्री कोर्स प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं. 28)</u>

115. मेडिकल कॉलेज कोटा के सम्बद्ध चिकित्सालयों में शैय्यायें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एम.बी.बी.एस./एम.डी. की सीटों को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में नये नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयकृष्ण पटेल (वि.सं. 116)

118. विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा में गांगड़तलाई में नर्सिंग कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।
119. विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा में मेडिकल कॉलेज खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (वि.सं. 52)

120. चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों में फार्मासिस्ट ग्रेड प्रथम एवं फार्मासिस्ट अधीक्षक के पदों का सृजन कर फार्मासिस्टों की पदोन्नति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री विनोद कुमार (वि.सं. 153)

121. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के पीलीबंगा एवं रावतसर में नर्सिंग ए.एन.एम. जनरल नर्सिंग महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामबिलास (वि.सं. 135)

122. विधान सभा क्षेत्र लालसोट के रामगढ़ पचवारा कस्बे में एक नवीन पैरा-मेडिकल कॉलेज खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अतुल भंसाली (वि.सं. 03)

123. डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर से संलग्न समस्त चिकित्सालयों में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नियुक्त समस्त प्रकार के कार्मिकों की नियुक्ति प्रक्रिया एवं ऐसे कार्मिकों की पदानुरूप वांछित योग्यता सहित इनके उपस्थिति और इनके विरूद्ध शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
124. जोधपुर प्राचीन शहर के नजदीक होने के कारण महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर में हृदय रोग विशेषज्ञ सहित एक स्थाई यूनिट आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
125. डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर से संलग्न समस्त मथुरादास माथुर चिकित्सालय में टुकड़ों-टुकड़ों में विकास कार्य होने से उत्पन्न अव्यवस्थाओं के निदान के लिए एक सुदीर्घ समेकित योजना बनाकर चरणबद्ध बजट उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
126. डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर में गम्भीर एवं असाध्य रोगों के विशेषज्ञों के पास अत्यधिक रोगी दबाव होने से उपज रही समस्याओं के निदान के लिए गंभीर एवं असाध्य रोगों के विशेषज्ञों के पदो को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
127. डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जोधपुर एवं संलग्न चिकित्सालय समूह में आपातकालीन इकाई में केवल मात्र रेजीडेन्ट एवं नर्सिंग कर्मियों के भरोसे चलने की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अभिमन्यु (वि.सं. 07)</u>

128. हनुमानगढ़ मेडिकल महाविद्यालय को सुचारू रूप से चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री भीम राज भाटी (वि.सं. 107)</u>

129. मेडिकल कॉलेज, पाली में स्टॉफ की कमी की वजह से विभिन्न विषयों की सीटें कम करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

<u>डॉ. प्रियंका चौधरी (वि.सं. 96)</u>

130. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के राजकीय मेडिकल कॉलेज व सम्बद्ध अस्पताल में जनहितार्थ कैथ लैब, एम.आर.आई. मशीन, उच्च क्षमता की सीटी स्कैन तथा डायलिसिस मशीन स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं. 28)</u>

131. मेडिकल कॉलेज, कोटा से सम्बद्ध चिकित्सालय में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।